

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 07 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

07.03.2017/1100/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3658

श्री इन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, यह स्थगित प्रश्न है और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन-जिन विभागों के पास अधिग्रहण की हुई भूमि है, उनके पास तो इस भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध है। उसको इकट्ठा करने में इतनी देर लगेगी, यह समझ से परे की बात है। सूचना मांगी गई है कि कितनी भूमि बेकार पड़ी है जिसका सरकार ने अधिग्रहण किया है, कंपनसेशन के रूप में पैसा दिया है। क्या माननीय मंत्री जी जल्दी-से-जल्दी या इसी सत्र में मुझे यह सूचना प्रदान करेंगे। दूसरे, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि अधिग्रहण की हुई भूमि जो बेकार पड़ी है, उसकी डिसपोजल नीति क्या है? वह तो बता ही सकते हैं; उसके लिए तो सूचना एकत्रित करने की भी ज़रूरत नहीं है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है कि माननीय सदस्यों को विस्तृत तौर पर पूरी सूचना दी जाए। अगर आप देखें, यह प्रश्न ही ऐसा है कि आज तक का ब्योरा मांगा गया है यानी 1952 से लेकर अब तक का। अगर माननीय सदस्य 3 सालों का ब्योरा पूछते तो हम 3 सालों की सूचना दे सकते हैं। आज तक कितनी ज़मीन अधिग्रहण की और किस-किस परपज़ के लिए की है, यह बहुत ही विस्तृत सूचना है। मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि यह सूचना अब क्या, अगले सेशन तक भी नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 3 सालों की सूचना, जो कि नियम के मुताबिक अलाऊड है, वह मांगें। यह सूचना तो ऐसी है कि जब से हिमाचल बना है, तब से लेकर आज तक कितनी भूमि अधिग्रहण की, किस परपज़ के लिए की और क्या कुछ भूमि वापिस हो गई है। इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है कि जो ज़मीन इस्तेमाल नहीं हुई है, क्या उसको वापिस किया जाएगा? जब किसी को भूमि का मुआवज़ा दे दिया जाता है तो उस ज़मीन को, जो सरप्लस हो जाती है, वह पब्लिक परपज़ के लिए दूसरे काम में इस्तेमाल की जा सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा और आपसे तथा विधान सभा सचिवालय से भी रिक्वैस्ट करूंगा कि ये 3 सालों की सूचना मांगें। जब से हिमाचल बना, तब से लेकर आज तक की सूचना एकत्रित करना बड़ा मुश्किल है।

श्री इन्द्र सिंह : सर, जो विदिन रूल्ज परमिटिड है, जो नियमों के मुताबिक परमिटिड है, आप उसको तो दीजिए।

जारी ...श्री गर्ग जी

07/03/2017/1105/RG/AS/1

प्रश्न सं. 3658--- क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले यह पता तो चले कि सरप्लस कितनी भूमि है और जिस भूमि को यूटीलाईज नहीं किया गया है। जब उसका अधिग्रहण हुआ, तो उसकी भी कोई लिमिटेशन होती है। Limitation Act will apply to these cases. तो इसलिए जब सूचना है ही नहीं, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यह सूचना दी जाए। हर विभाग से हमने यह मांगा हुआ है और उनको इन्डीविजुअल तौर पर ऐक्वायर करने के लिए पब्लिक परपज़ के लिए भूमि दी हुई है, लेकिन अगर तीन साल की सूचना माननीय सदस्य मांगेंगे, तो हम निश्चित तौर पर देंगे। इसलिए अभी भी यह प्रश्न स्थगित रखा जाए।

प्रश्न समाप्त

07/03/2017/1105/RG/AS/2

प्रश्न सं. 3732

डॉ. राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रश्न पूछा है वह बहुत महत्वपूर्ण है और सूचना भी इन्होंने विस्तार से दी है। प्रदेश में चील का बहुत भारी जंगल है और उसके अंदर बिरोजा निकालने का काम लगातार चलता रहता है। अब बिरोजा निकालने के कारण स्थिति यह हो गई है कि 90% जंगलों में जो आप तक लगा रहे हैं और जो इसके स्पेसीफाइड रूल्ज हैं जो कॉपी आपने हमें दी है, उन रूल्ज की वॉयोलेशन करके वे तक लगाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मेरे मोबाईल में भी इसकी फोटोज़ एवं विडियोज हैं। तो इस प्रकार से जो नियमावली है उसकी पूरी तरह से उल्लंघना हो रही है

जिसके कारण थोड़ी सी भी आग लगने की सूरत में जंगल में सारे पेड़ गिर जाते हैं चाहे वह पेड़ 100-50 या 20 साल का है। केवल और केवल इसके कारण से सारे पेड़ों का नुकसान हो रहा है। एक बार आग लगती है, हवा चलती है और उसके पश्चात सारे पेड़ गिर जाते हैं। फिर कॉरपोरेशन उन सड़े हुए पेड़ों को उठाती रहती है और प्रदेश की सम्पदा को इससे नुकसान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर के 'ख' भाग में लिखा है कि हमने तीन वर्षों में जंगलों में नियमों के अनुपालना न करने के 14,456 मामलों को पकड़ा है और इनमें 45,96,199/- रुपये का जुर्माना किया। तीन साल में 45 लाख क्या है?, एक रेंज में ही 45,00,000/- रुपये का नुकसान ही एक साल में वन विभाग के इस बिरोजा के गलत तरीके से निकालने के कारण हो जाता है। दूसरा, उत्तर के (क) भाग के अनुलग्नक 'ग' में पृष्ठ 123 पर जो इसके रूलज एण्ड रेग्युलेशनज हैं उसमें लिखा है 'Number of blazes per tree' के अन्तर्गत लिखते हैं 1.2 to 1.9 m girth, one blaze of 10 cm wide is eligible और उसके बाद above 1.9 m girth, two blazes 10 cm are recommended और उसके ऊपर भी लिखते हैं कि up to the height of breast, हमारी छाती की ऊंचाई तक ही यह परमिटेड है। 10-10 फुट तक 15-15 ब्लेज़ एक-एक पेड़ में लगे हुए हैं और इसमें भी आप लिख रहे हैं कि There should be a gap of 10 c.m. in each blaze.

07/03/2017/1105/RG/AS/3

Speaker: Dr. Rajeev Bindal, please, be brief in your supplementary. बहुत लम्बी सप्लीमेंट्री मत कीजिए। You don't have to read from here. You have to speak in short.

डॉ. राजीव बिन्दल : इसमें क्या ब्रीफ होना है? इन्होंने जो मुझे दिया है उसीमें से मैं पूछ रहा हूँ।

Speaker: Please, ask in brief. This is a speech.

डॉ. राजीव बिन्दल : यह जो इन्होंने डिटेल दी है उसी में से पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष : यह डिटेल तो इनको पता है। आप ब्रीफ में प्रश्न करें। इतनी लंबी स्पीच न दें।

डॉ. राजीव बिन्दल : आप ही पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, रूल्ज की जो वॉयोलेशन हो रही है मैं वह बता रहा हूं कि दस फुट की ऊंचाई तक 12-12 और 15-15 ब्लेज लगाए जा रहे हैं और पूरे जंगल बरबाद कर दिए हैं और ये कह रहे हैं कि हमने केवल 45,00,000/- रुपये का जुर्माना किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो इतने ज्यादा ब्लेज लग रहे हैं इसका क्या कारण है और वन विभाग का स्टाफ जब वहां मौजूद है तो

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

07/03/2017/1110/MS/DC/1

प्रश्न संख्या: 3732 क्रमागत---डॉ0 राजीव बिन्दल जारी----

तो वह इसकी इन्सपैक्शन क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि जब ब्लेज लगेगा और कोई व्यक्ति बिरोजा इकट्ठा करने के लिए आएगा तो वह आपका ऑथोराइज्ड लाइसेंसड व्यक्ति होगा। तो क्या वजह है कि इतने ज्यादा जंगलों में पेड़ों का इतना नुकसान हो रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं?

वन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात की है कि बड़े अवैध रूप से उसमें कट एण्ड पिल मैथड हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। हमारा जो स्टाफ है वह बाकायदा सही ढंग से, -(व्यवधान)-मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नियम 1981 के मुताबिक जो बिरोजा निकालते हैं उसकी उल्लंघना हो रही है। मैं आपको बता दूं कि उसकी कोई उल्लंघना नहीं हो रही है। कानूनी तौर पर ही दिनांक 23/10/2002 के जो रूल हैं उनके मुताबिक ही बिरोजा निकाला जाता है। पिछले तीन सालों से नियमों की अनुपालना, जैसा आपने पढ़कर बता दिया कि 14,456 ऐसे मामले आए हैं जिनको इतना फाइन हुआ है। यह फाइन इनका कम होता है ज्यादा नहीं होता है। कानून के मुताबिक जो फाइन किया जाता है उसी के मुताबिक उनसे पैसा रिकवर किया जाता है। जहां तक

प्राइवेट जंगलों की आप बात कर रहे हैं कि उसमें आग लगती है और वे जल जाते हैं लेकिन वे उनको कट एण्ड मोशन से ही काटते हैं। हम तो एरियल वाला जिसमें 32 टक या लाइनें लगती हैं उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। उससे ज्यादा जो लगाते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। प्राइवेट जंगल वाले पुराने सिस्टम को अपनाते हैं not the Forest Department.

Speaker:- You speak Dr. Rajiv Bindal.

07/03/2017/1110/MS/DC/2

डॉ० राजीव बिन्दल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2002, आप ही ने जो मुझे पेपर दिया है Resin Tapping Instruction and Rules, this is Chapter -13 और उसके पेज नम्बर 3 के ऊपर जो इन्सट्रक्शन्ज हैं उनकी टोटल वायलेशन हो रही है। मैं इसको निश्चित रूप से कह रहा हूँ और सरकारी जंगल की बात कर रहा हूँ तथा आप जो बता रहे हैं उस रिल मैथड की बात कर रहा हूँ। रिल मैथड में 10 सेंटीमीटर का जो गैप है वह भी नहीं है और ब्रैस्ट से ऊपर कटिंग हो रही है और 2 टक लगने चाहिए उसके बजाए 10 और 12 लग रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप अगर किसी एक केस में 100-200 या 500 रुपये जुर्माना करते हैं तो वायलेशन नहीं रूकती है। वह दूसरी, तीसरी या चौथी जगह फिर वायलेशन कर रहा है। यह समस्या का समाधान नहीं है। क्या आप इसको रोकने के लिए कोई और कदम उठाएंगे? दूसरे, जो प्राइवेट जंगल हैं उनके अंदर भी इस मैथड को आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे क्योंकि जो कप मैथड है वह पुराना हो गया और उससे डैमेज ज्यादा होता है। यह आपकी रिसर्च बता रही है कि वह नहीं होना चाहिए। क्या उसको भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे?

वन मंत्री: अध्यक्ष जी, जो विधायक महोदय ने फरमाया है कि यह जो मैथड है इसके मुताबिक जंगलों में गलत हो रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। आपने पहली बार मेरे जेहन में यह बात लाई है। अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो हम बाकायदा इसकी जांच करवाएंगे ताकि आगे के लिए ऐसी बात न हो। जहां तक प्राइवेट जंगलों की बात कर रहे हैं उनको कानूनी तौर पर तो बंधित नहीं किया जा सकता लेकिन उनसे मिचुअल अंडरस्टैंडिंग से

बात करके हम कोशिश करेंगे कि वे भी इस सांईटिफिक मैथड को एप्लाई करें ताकि भविष्य में ऐसा नुकसान न हो।

श्री रिखी राम कौंडल श्री जे०एस० द्वारा----

07.03.2017/1115/जेके/डी०सी०/1

प्रश्न संख्या: 3732:----जारी-----

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, घ-भाग के उत्तर में Resin & Turpentine Factory जो कि बिरोजा की फेक्टरी है एक नाहन में और एक बिलासपुर में है। वर्ष 2013-14 में इसकी आमदन करोड़ों में 10.66 करोड़ हुई, वर्ष 2014-15 में 7.96 करोड़ और वर्ष 2015-16 में 2.11 करोड़ हुई। इसी ढंग से नाहन में भी आमदनी घटती रही है। क्या माननीय मंत्री जी बतलाएंगे कि ये वही जंगल है, वही बिरोजा वहीं से निकलता है तो इसकी आमदन कम क्यों हुई ? क्या माननीय मंत्री जी इसका कारण बतलाने की कृपा करेंगे?

वन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जैसे गाय दूध देती है तो एक साल बाद, दो साल बाद उसका दूध कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो पेड़ है उनकी भी जो यील्ड है वह कम होनी शुरू हो जाती है। उनमें भी कोई लगातार 100 साल के लिए ही बिरोजा नहीं रहता है। उनकी यील्ड भी कम होनी शुरू हो जाती है। जंगल में हमारे पास लिमिट दरख्त हैं। उनके मुताबिक ही हम बिरोजा निकालते हैं। हम कच्चे पेड़ से बिरोजा नहीं निकालते जैसे कि प्राईवेट वाले निकाल लेते हैं, वैसे हम नहीं करते हैं। जो बैस्ट पोसिबल होगा उसी में से यह बिरोजा सांईटिफिक वे से निकाला जाता है।

Speaker: Next Question Shri Maheshwar Singh Ji. --- (interruption) --- .No, please. I have already given three supplementaries and more than three supplementaries are not allowed . This question cannot continue for long time. --- (interruption) --- No, not at all.

07.03.2017/1115/जेके/डी0सी0/2

प्रश्न संख्या: 3733

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई उसमें यह बताया गया है कि अमृत योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के लिए 31 करोड़ 69 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें प्रथम किश्त 6.8 करोड़ नगर परिषद को मिल चुकी है और वे इसको निर्मूल भी कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो निर्मूल की गई है, उसमें से जो अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है, जैसे तो आपने पूरी सूची लगाई है। एक सब-वे ढालपुर मैदान में भुट्टी चौक के पास बनना था उसका अनुमानित खर्चा 40 लाख आंका गया लेकिन उसके स्थान पर 50 परसेंट से भी अधिक 25 लाख रूपया लोक निर्माण विभाग डिविजन-2 को दे दिया गया है। इसी प्रकार जो आपकी पेयजल सम्बन्धी योजनाएं ऑग्युमेंटेशन की खलाड़ा नाला से लेकर उसका प्राक्कलन 4 करोड़ के करीब है। उसका भी 50 प्रतिशत 2 करोड़ आई0पी0एच0 डिविजन कुल्लू के पास है। तीसरी योजना जो सब-वे ब्रिज बनना है सुल्तानपुर से लेकर उस सब-वे ब्रिज का पहले इन्होंने 40 लाख का एस्टिमेट दिया लेकिन बाद में एक्सियन इलैक्ट्रिकल डिविजन है, उसने कहा कि 40 लाख में तैयार नहीं होगा हम रिवाईज्ड एस्टिमेट भेजेंगे। इस प्रकार की आदत विभागों को पड़ी है कि जो जमा राशि होती है, डिपोजिट वर्क्स होते हैं वे चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो या किसी अन्य विभाग के हो उसमें विलम्ब करते हैं। बार-बार ऐस्टिमेट मांगने के बावजूद यानि दो रिमाईंडर भेजने के बावजूद एक्सियन मैकेनिकल ने अभी तक ऐस्टिमेट नहीं दिया है। पी0डब्ल्यू0डी0 में पैसा होने के बावजूद और आई0पी0एच0 के पास भी 50 प्रतिशत पैसा प्राप्त होने के बावजूद वे भी अभी तक इसके टेण्डर कॉल नहीं कर पाए हैं। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि अगर 70 प्रतिशत खर्च नहीं हुआ तो इसका कुप्रभाव वर्ष 2017-18 में पड़ेगा। तब तक कोई पैसा नहीं मिलेगा। मैं सुझाव भी देना चाहूंगा और आग्रह भी करना चाहूंगा कि मंत्री जी हस्तक्षेप कर जो आपके अर्बन डिवैल्पमेंट विभाग के उच्चाधिकारी हैं उनको कहें ताकि वे इन विभागों से सम्पर्क कर इनको सुनिश्चित करवाया

जाए कि ये जल्दी से जल्दी एस्टिमेट दें ताकि यह धनराशि खर्च हो। इतना कह कर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसका उत्तर दें।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

07.03.2017/1120/SS-AG/1

प्रश्न संख्या: 3733 क्रमागत

शहरी विकास मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जब तक इस पैसे की 70 परसेंट यूटिलाइजेशन नहीं हो जायेगी तो प्रदेश को अमृत मिशन में दूसरी किस्त प्राप्त नहीं होगी। इसमें आई0पी0एच0 और पी0डब्ल्यू0डी0 मकैनिकल की तरफ से थोड़ी देरी हुई है। हमने कुल्लू अमृत मिशन के लिए डिप्टी कमिश्नर, कुल्लू को नोडल ऑफिसर बनाया है और प्रदेश स्तर पर डायरेक्टर (अर्बन डिवेलपमेंट) हैं तो मैं इनको निर्देश दूंगा कि इसकी यूटिलाइजेशन जल्द हो, जल्दी से टैंडर होकर काम शुरू हो। इसके लिए विभाग के जो डायरेक्टर हैं वे स्वयं जाकर इसको देखेंगे और जो अधिकारी वहां पर हैं उनको निर्देश देंगे कि जल्द-से-जल्द इनके टैंडर को कॉल किया जाए।

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को आश्वासन देने के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जैसे 31 करोड़ 59 लाख रुपया इस वर्ष के लिए है और जब तक यह पूर्णतः यूटिलाइज नहीं होगा तो 2017-18 का पैसा रिलीज नहीं होगा। क्या इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार यह पैसा यूटिलाइज हो सके ताकि 2017-18 की किस्त हमें 2017-18 के मिडल ईयर तक ही मिल जाए।

शहरी विकास मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो योजनाएं अमृत मिशन में नगर परिषद्, कुल्लू ने प्रस्तावित की हैं उसमें 24 ऐसी स्कीम्ज़ हैं जिनमें फॉरैस्ट लैंड भी अट्रैक्ट होती थी। उनका केस भी बना दिया गया है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो 31.59 करोड़

रूपया आया है उसका यूटिलाइजेशन इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करें ताकि अगली राशि को हम प्राप्त कर लें और जिस औचित्य से इस स्कीम को लाया गया है वह पूरा हो। क्योंकि कुल्लू पहले इसमें शामिल नहीं था सिर्फ यह धार्मिक नगरी और टूरिज्म डेस्टिनेशन होने के कारण अमृत मिशन के जो नॉर्म्स थे उस वजह से इसमें आया है तो उसके चलते कोई विलम्ब न हो इसको सुनिश्चित करेंगे। यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ।

07.03.2017/1120/SS-AG/2

प्रश्न संख्या: 3734

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है उससे चम्बा ज़िला में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की दयनीय स्थिति नज़र आ रही है। 120 पोस्टें जो इनकी प्रोजेक्ट में हैं उसमें से 53 वेकेंट हैं और 28 पोस्टें जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की हैं उसमें से 17 वेकेंट हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो सी०डी०पी०ओ० की पोस्टें हैं उसमें सलूणी में न सी०डी०पी०ओ० है, न सीनियर असिस्टेंट है, न सी०ए० है तो यह प्रोजेक्ट कैसे चलेगा?

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है उसमें न डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है, न सुपरिटेण्डेंट है, न सीनियर असिस्टेंट है। पांच में से चार क्लर्क नहीं हैं। Social Justice and Empowerment Department is very important department with respect to public. जितनी आपकी पेंशन आती हैं, जितनी आपकी घरों के लिए एप्लीकेशनज़ आती हैं, यहीं आती हैं और सलूणी का तो यह हाल है कि वहां न तहसील वेलफेयर ऑफिसर है और न ही क्लर्क है यानी ताला लगा हुआ है। डलहौजी में तीन पोस्टें हैं और तीनों वेकेंट हैं और अध्यक्ष महोदय, यह सूचना थोड़ी-सी गलत है क्योंकि डलहौजी में तहसील वेलफेयर ऑफिसर पोस्टिड है मगर आपने उसको चम्बा के दफ्तर में बिठाकर रखा हुआ है। आपका न वहां काम चल रहा है और न यहां चल रहा है। तो अध्यक्ष महोदय मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए इन पोस्टों को भरने का क्या प्रयास किया जायेगा? आप रेशनलाइजेशन से करेंगे या कैसे करेंगे? You cannot

have 50 per cent posts vacant in the district. In the District Welfare Office out of 12, you have eight posts vacant. और चार जो हैं वे ड्राइवर और प्यून हैं । How do you expect the Social Justice and Empowerment Department to work?

जारी श्रीमती के0एस0

07.03.2017/1125/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्या:3734 जारी----

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो चिन्ता आदरणीय सदस्या ने जताई है । I entirely agree with that. The staffing pattern of any office should be minimum of 80 per cent to make it functional and efficient so that the work of social welfare goes on smoothly. अभी कुछ थोड़े से फीगर्ज देना चाहूंगा When the Government took over we had shortfall of 808 Supervisors which was a very big shortfall in the department. We started very methodically. We tried to complete the shortfall of the vacant posts across the State of Himachal. Even now, we have shortfall of 159 posts which will be soon filled up.

Regarding Salooni and Dalhousie, the Hon'ble Member is absolutely right. Neither she has a TWO there nor there is Clerk, Senior Assistant and Peon. I have tried to see as to why this thing has happened to the areas of Chamba, Bharmour and Lahaul & Spiti. Despite postings there many time these people manage somehow or the other and real problem comes up to the department. But I assure the Member that within a month or so at least 80 per cent of your staff will be made up because I have gone through it very closely and all these people who have tried to evade their postings will be posted there.

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि इन्होंने सलूनी और डलहौजी की बात की, मैंने आपको कहा कि डलहौजी में जो तहसील वैल्फेयर ऑफिसर पोस्टिड है, उसको चम्बा में बिठाकर रखा है। एक तो क्या उसको इमिजिएटली डलहौजी भेजेंगे? दूसरे, आपको डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर ऑफिसर जो कि प्रोमोशन से होता है, उसको लगाने में क्या तकलीफ़ है?

Social Justice & Empowerment Minister: Hon'ble Speaker, Sir, I assure the Hon'ble Member that whatever suggestion she has given will be done.

07.03.2017/1125/केएस/एजी/2

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया था, उसको पढ़ रहा था और जब इन्होंने अभी उत्तर प्रारम्भ किया तो कहा कि जब हमने टेकओवर किया उस समय पर बड़ी पोस्टें खाली थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने डेट्स भी दी हैं since when these posts are vacant. ये कब की हैं? Most of the posts are vacant since 2013 when you had already taken over. So, don't mislead the House?

Social Justice & Empowerment Minister: Hon'ble Speaker, Sir, I only saw the figures when I took over. I will check up if they are starting with 2013 irrespective of the fact that they are from whichever time. It took us quite a bit of an exercise to fulfil these posts. Even today we are battling those many cases which have gone to the court. It is not because of any establishment that has gone wrong, but because of the people going to the court on various technical details that DPRs not being held in time and sometimes somebody is not going to join a particular place. That is how these things have occurred. It is not because of anybody's fault. I will personally review this position for both the Directorates i.e. WCD as well as SOMA and whatever is the balance posting that will be done.

Continued by AS in English . . .

7.3.2017/1130/av/as/1

प्रश्न संख्या : 3734----- क्रमागत

Prof. Prem Kumar Dhumal: Speaker, Sir, my suggestion was to the Hon'ble Minister is only, instead of reading the whole record, just read the record that you have provided in the answer to this Question. Where you have mentioned the dates i.e. 13th, 14th, 15th, 16th and January 17th.

Social Justice and Empowerment Minister: Hon'ble Speaker, Sir, the posts that have been created, the Question says rather, how many posts were created for the district, the total posts that were created are: 120 posts for the Chamba district under the Directorate of Woman and Child Development, out of which 53 posts are lying vacant. 28 Nos. of posts have been created under Directorate of SC, OBC and Minority Affairs i.e. SOMA in district Chamba, out of which 17 posts are lying vacant. These details have been given in part 'A' and 'B' of the answer accordingly. Now, if you go into the details of these, I can read out the whole information. In Chamba district, though there are 8 CDPOs, 6 are in position, even today. CDPOs out of 78 only 13 are vacant and that will be made up by direct recruitment. Some from the Department itself and mostly from the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur. I personally feel that there is a need to have DPC soon. I will say to the Director to do it soon.

Prof. Prem Kumar Dhumal: Speaker, Sir, what I had pointed out was just read the headings, name of the post, sanctioned, filled, vacant and if vacant then since when. You read this column only later on in your office and you will come to realize that your statement was not on facts.

Speaker:- You precisely say.

7.3.2017/1130/av/as/2

Social Justice and Empowerment Minister: Hon'ble Speaker, Sir, Hon'ble Member has pointed out about the vacancies. Some posts are vacant since November 2016 and some are vacant from 2014, 2015. As advised by the Hon'ble Member, I will go over this whole thing again if there will be any anomaly that will be sorted out. Total numbers of posts are 757. We cannot make any more than that. So far, we have filled 579 and only 178 post are lying vacant. Steps are being taken to make sure that these vacancies, which are lying vacant, will be filled soon. If there is any mistake that will be rectify and the information will be send to the Hon'ble Member.

7.3.2017/1130/av/as/3

प्रश्न संख्या : 3735

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, जब से टी0सी0पी0 ऐक्ट लागू हुआ है हमारे यहां लोगों की परेशानियां बढ़ी है। क्या सरकार इन क्षेत्रों को जनहित में इस ऐक्ट के प्रावधानों से बाहर रखने पर विचार करेगी?

श्री वर्मा द्वारा जारी

07/03/2017/1135/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

प्रश्न संख्या: 3735 जारी.....

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बैजनाथ और पपरोला दिनांक 7-7-2014 को प्लानिंग एरिया डिक्लेयर हुआ था। इसमें जो अति ग्रामीण क्षेत्र आ गये हैं, उनको इससे बाहर करने के लिए विभाग विचार कर रहा है और शीघ्र ही उनको टी0सी0पी0 एक्ट से बाहर किया जायेगा। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके जो मूल निवासी हैं, अगर वे अपनी भूमि पर निर्माण करना चाहते हैं, तो उनको तीन मंजिल तक मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसाकि अभी-अभी मंत्री महोदय ने कहा कि इस पर विचार करेंगे कि इन क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जायेगा, अर्थात् ये साडा क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर आप इस प्रकार पिक-एण्ड-चूज़ करेंगे, तो यह कैसे चलेगा। इस तरह की डिमाण्ड कई जगह से आयेगी। मैं स्पेसिफिक वर्शन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब से इन क्षेत्रों को साडा में लिया गया है, इन क्षेत्रों में कौन-कौन-सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं? यदि इसका जवाब अभी आपके पास न हो तो आप इसके बारे में बाद में भी जानकारी दे सकते हैं। ताकि हम भी विचार करें कि हमारे क्षेत्र को भी साडा से बाहर निकाला जाये, जैसे मनिकर्ण और कसोल से भी इस तरह की मांग आ रही है। जब आप इनके विकास के लिए फूटी कौड़ी नहीं लगाओगे तो मांग आना तो स्वभाविक ही है। इनको अधिसूचित करने का विचार तो इसलिए किया गया था, ताकि ये क्षेत्र विकसित हो सकें, लेकिन जब आप पैसा ही नहीं दे रहे हैं, तो ये विकसित कहां से होंगे? क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी कि इन क्षेत्रों को भी विकास के लिए पैसा दिया जाये?

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह साडा का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न इन्होंने टाउन एण्ड कंट्री विभाग के लिए पूछा गया था, जिसके तहत प्लानिंग एरिया डिक्लेयर हुआ है। साडा स्पेशल एरिया डेवैल्पमेंट अथोरिटी है, जिसको उस जिला के जिलाधीश देखते हैं। साडा और टी0सी0पी0 की इंप्लीमेंटेशन में भिन्नता है। यह सही है कि टी0सी0पी0 एक्ट, कई जगह पर जहां लागू हुआ है, उसमें अति-ग्रामीण क्षेत्र आ गये हैं, जहां पर ऐसे क्षेत्र आ गये होंगे, वहां अगर उनको डि-नोटिफाई करना पड़ा, तो उस पर जरूर विचार किया जायेगा।

07/03/2017/1135/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

प्रश्न संख्या: 3736

श्री बम्बर ठाकुर: अनुपस्थित।

07/03/2017/1135/टी0सी0वी0/ए0एस0/3

प्रश्न संख्या: 3737

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये सरकार बड़ी संवेदनशील, पारदर्शी, उत्तरदायी और सबका कल्याण करने वाली है। अध्यक्ष महोदय, पिछले साढ़े चार वर्षों में जब भी हमारे प्रश्न लगे, तो ज्यादातर में यही जवाब आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मेरा पहले भी एक सवाल था, जिसका पौने 2 साल के बाद जवाब मिला। मैंने प्रश्न पूछा था कि प्रदेश से बाहर कितने अधिवक्ताओं को केस लड़ने के लिए हायर किया था या उनको फीस दी गई थी? इन्होंने स्पेसिफिक पिरियड एक साल का तो दे दिया, लेकिन लीज़ पर कितनी भूमि दी गई, किस-किस को दी गई, उनके नाम व पते सहित सारा ब्योरा दिया जाये? क्या जिस काम के लिए वह भूमि ली गई है, क्या वह किया गया है? क्या उसको आगे बेचा/किराये पर दिया जा सकता है? आपके नियम बने हुए होंगे, आपको उसकी प्रतिलिपि ले करनी है, इसमें सोचने वाली क्या बात है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश होती है कि विस्तृत जवाब दिया जाये। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे,

श्रीमती एन0एस0 - - - द्वारा जारी।

07/03/2017/1140/ ns/dc /1

प्रश्न संख्या: 3737 -- क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ----- जारी

दिनांक 1 जनवरी, 2013 से 15 फरवरी, 2017 तक सरकार द्वारा किन-किन संस्थाओं, सभाओं, सरकारी संस्थाओं व इंडिविजुअलों को कितनी-कितनी भूमि किस-किस उद्देश्य हेतु लीज़ पर दी गई है, ब्योरा वर्षवार लाभार्थियों के नाम सहित दें। इसके लिए सूचना एकत्रित की जा रही है। इसमें कई एक्स-सर्विसमैन ऐसे हैं जिनको दो-दो बिस्वा जमीन 10-10 साल के पट्टे पर देते हैं। यह जमीन कुछ संस्थाओं, सोसाईटीज़ को दी गई है। सारी सूचना एकत्रित की जा रही है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि यह प्रश्न पोस्टपोंड है। यह प्रश्न 20-25 दिन पहले ही पहुंचा है। हमने सारी सूचना मंगवाई है। हमारी कोशिश होगी अगर इस सेशन के अंदर यह सूचना आ जाए तो विस्तृत तौर पर दे देंगे। अगर नहीं आई तो फिर यह सूचना मानसून सेशन में दे देंगे। हम इनको पूरी बाकायदा डिटेल्ड सूचना देना चाहते हैं। हम इनको अधूरी सूचना नहीं देना चाहते हैं इसलिए हम इसका पूरा ब्योरा इकट्टा कर रहे हैं।

07/03/2017/1140/ ns/dc /2

प्रश्न संख्या : 3738

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : इस योजना के Investment Clearance का मामला भारत सरकार के पास लम्बित है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस योजना में 45 लाख की देनदारी है। इस कार्य का पूर्ण होना भारत सरकार द्वारा Investment Clearance देने, Flood Management Programme कार्यक्रम में सम्मिलित करने व पर्याप्त धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार से इसके बारे में पत्र-व्यवहार किया जाए और दोबारा से रिक्वेस्ट की जाए ताकि इस योजना का जो काम रुका पड़ा है वह जल्दी-से-जल्दी शुरू हो जाए।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कहा है वह सही है। मैं यह कहना चाहूँगी कि आपका यह काम जितना जल्दी हो सकेगा इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से मामला उठाना पड़ता है। अगर केंद्र सरकार से धन जल्दी उपलब्ध हो जाए तो हम इस काम को जल्दी करने की कोशिश करेंगे।

07/03/2017/1140/ ns/dc /3

प्रश्न संख्या: 3739

डॉ० राजीव सैजल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि प्रदेश में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ब्लड रिलेशन के बाहर यह सुविधा प्रदेश के बाहर हासिल करने के लिए मरीजों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि डॉ० राकेश चौहान (विशेषज्ञ) को प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजा गया है। इन्होंने यह भी कहा है कि मिनीमम तीन साल का प्रशिक्षण उसके लिए अनिवार्य है जिसको शल्य क्रिया यानि किडनी ट्रांसप्लांट करनी है उसको मिनीमम तीन साल का प्रशिक्षण हासिल होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आपने डॉ० राकेश चौहान को प्रशिक्षण पर कब भेजा और वे कब वापिस आएंगे तथा प्रदेश में यह सुविधा कब शुरू कर दी जाएगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि अभी ऑर्गेन ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी हिमाचल में किसी भी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध नहीं है।

क्योंकि इसके लिए जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग रिक्र्यावर्ड है वह हमारे पास अभी नहीं है। ह्यूमैन ऑर्गेन ट्रांसप्लांट एक्ट 1994 के तहत यह प्रोवीज़न किया गया है कि कोई भी डॉक्टर जो सुपर स्पेशलिस्ट है उसको कम-से-कम तीन साल तक जहां यह सुविधा उपलब्ध है, काम करना पड़ता है।

Eng--श्री आर०के०एस०---- द्वारा जारी ।

07/03/2017/1145/RKS/DC/1

प्रश्न संख्या: 3739.....जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री:जारी

after completing his course और उसके बाद अगर इन्डिपेंडेंटली कीडनी ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांसप्लांट के खुद ऑपरेशन परफॉर्म किए हो only than he is eligible to conduct this organ transplant in the Pradesh. हमने राकेश चौहान को इसके लिए पी.जी. आई. के लिए स्पॉसर्ड किया है। तीन साल की ट्रेनिंग करने के बाद, सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं उसके बाद भी उसे अपने आप ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, तभी वहां का एच.ओ.डी. सर्टिफिकेट देगा that he has independently performed the operations of kidney transplant or liver transplant. उसके बाद हम उसकी यहां पोस्टिंग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए बहुत ही एक्सपर्टिज़ की जरूरत है। अभी हमारे उत्तर भारत में सिर्फ पी.जी.आई. या एम्स में यह सुविधा उपलब्ध है। दूसरे किसी मैडिकल कॉलेज में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि उसकी ट्रेनिंग के बाद हम यह सुविधा आई.जी.एम.सी. में उपलब्ध करवाएंगे।

डॉ० राजीव सैजल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अनुमानित कितने वर्ष में यह सुविधा प्रदेश में प्रारम्भ करने का विचार है?

Health and Family Welfare Minister: Sir, it will be our endure to start this facility after three years provided he completes successful training and performs independently operations in PGI, only then we will be able to start this facility in IGMC.

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन्होंने हिमाचल प्रदेश के बड़े मैडिकल कॉलेजिज़, आई.जी.एस.सी. या टांडा में इस सुविधा हेतु बाहर से डॉक्टर लाने के लिए, जिन्होंने ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म किए हों और वे इलिजिबल हों, कोई टैंडर इनवाइट किए हैं, ताकि वे यहां पर अपनी सर्विसिज़ दे सकें?

07/03/2017/1145/RKS/DC/2

क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह ऑपरेशन पी.जी.आई. और एम्स में ही हो रहे हों। फॉरटीज़, मैक्स, गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली में भी यह ऑपरेशन हो रहे हैं। गंगाराम हॉस्पिटल में जगत सिंह नेगी, विधायक, शिलाई का ऑपरेशन आज से कई वर्ष पहले हो चुका है। मैं स्वयं वहां पर गया हूं। इन सभी अस्पतालों में ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर जब तक राकेश चौहान एलिजिबल नहीं हो जाता, वहां का एच.ओ.डी. उनको सर्टिफिकेट नहीं दे देता कि इसने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, तो क्या यह सुविधा हिमाचल प्रदेश को कभी मिलेगी या नहीं?

Health and Family Welfare Minister: Sir, I request the Hon'ble Member, if he has any such doctor in his knowledge we are ready to take his services. लेकिन अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हमारी कोशिश होगी कि हम इसके लिए पोस्ट भी एड्वर्टाइज़ कर देंगे परन्तु अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मैंने आपको सरकारी संस्थान पी.जी.आई. और एम्स के बारे में बताया है, गंगा राम अस्पताल प्राइवेट है। इसलिए हमने डायरेक्टर पी.जी.आई. को चिट्ठी लिखी है कि यदि कोई डॉक्टर आई.जी.एम.सी. आने को तैयार है तो हम उनकी सेवाएं लेने को तैयार हैं। परन्तु डायरेक्टर ने कहा कि हमारे पास कोई भी डॉक्टर शिमला जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कोशिश है कि जब तक राकेश चौहान ट्रेनिंग करें इसके बीच में अगर कोई एलिजिबल डॉक्टर मिल जाता है तो

we would be happy to give him appointment and start this facility in IGMC and Dr. Rajendra Prasad Medical College, Kangra at Tanda.

श्री एस० एल० एस० द्वारा जारी...

07.03.2017/1150/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 3739...क्रमागत

श्री सतपाल सिंह सत्ती: सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनकी जानकारी में कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट करने के एक्सपर्ट हैं और वह हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं? अगर कोई ऐसी जानकारी इनको मिलती है, तो क्या उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके हम उनको यहां पर लाने की बात कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी जानकारी विभाग के पास है?

अध्यक्ष : यह तो मंत्री जी ने कह दिया कि आप ऐसे डॉक्टर के बारे में बताएं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई भी डॉक्टर यहां आने को तैयार नहीं है। यह ठीक है कि हमारे डॉक्टर AIIIMS में काम कर रहे हैं और PGI में HOD लगे हुए हैं। We are proud of them but they are reluctant to come and serve in Himachal Pradesh. अगर आपके ध्यान में कोई डॉक्टर होगा तो हम निश्चित तौर पर उसकी सेवाओं को शीघ्रताशीघ्र लेने की कोशिश करेंगे।

समाप्त

07.03.2017/1150/SLS-AG-2

प्रश्न संख्या : 3740

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, वह पूरी नहीं बल्कि अधूरी है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि नाचन विधान सभा क्षेत्र के अंदर SCCP के तहत 9 नहीं बल्कि 11 सड़कें पिछले 3 सालों में डाली गई हैं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से सहमत हूँ कि यह बात सही है कि कुछ सड़कों में वन भूमि आने के कारण उन सड़कों पर काम नहीं किया जा सकता और कुछ सड़कों के लिए भूमि गिफ्टिड न होने के कारण भी उन पर काम नहीं किया जा सकता। लेकिन 2 ऐसी सड़कें हैं जो इन 9 सड़कों में शामिल नहीं की गई हैं। उनमें एक नेरी से छनेरी सड़क भी SCCP में डाली गई है और दूसरी सड़क कमाहू से छम्बा है जिसे SCCP में डाला गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इन सड़कों के बीच में कोई भी वन भूमि नहीं आती है; सारी-की-सारी सड़क में लोगों की अपनी प्राइवेट लैंड आती है। गिफ्टिड लैंड को दिए हुए भी लगभग एक साल का समय हो चुका है। जब एक साल का समय इसमें हो चुका है और वहां पर कोई वन भूमि नहीं आती तो क्या कारण है कि उन सड़कों का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो 9 के बजाये 11 सड़कें माननीय सदस्य ने बताई हैं उनमें 2 सड़कें, जो इन्होंने बताई हैं, वह भी शामिल कर दी जाएंगी। यदि उनमें किसी भी प्रकार की कोई टैक्निकल डिफिकल्टी नहीं है, जैसे कि वन भूमि या किसी की प्राइवेट लैंड का झगड़ा, तो उनके लिए इसी सेशन के दौरान शीघ्रातिशीघ्र फंड भी दिए जाएंगे और वह शीघ्रातिशीघ्र बना दी जाएंगी। मैं माननीय सदन को बता देना चाहता हूँ कि अब हमने गाइडलाइज भी बदलने का प्रयास किया है और मैं शीघ्र ही सभी माननीय सदस्यों को स्वयं भी बुलाना चाहूंगा ताकि इस फंड का ठीक तरीके से इस्तेमाल हो और हम कहीं पर भी यह न सोचें कि संतुलन नहीं है।

जारी ...श्री गर्ग जी

07/03/2017/1155/RG/AG/1

प्रश्न सं. 3740--क्रमागत

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री---क्रमागत

इसी आशय से मैं समझता हूँ कि इस फण्ड का इस्तेमाल होना चाहिए और माननीय सदस्य ने जो दो सड़कें बताई हैं उनको इसमें शामिल कर दिया जाएगा।

07/03/2017/1155/RG/AG/2

प्रश्न सं. 3741

श्री बी.के. चौहान : अध्यक्ष महोदय, इस उत्तर में मंत्री महोदय ने माना है कि 78 रिक्त पदों में से आज तक केवल 18 विशेषज्ञों के पद ही चम्बा में भरे गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शेष 60 पद कब तक भर दिए जाएंगे?

Health & Family Welfare Minister: Sir, so far as the Regional Hospital, Chamba is concerned, all posts have been filled up. But so far as Pandit Jawaharlal Nehru Medical College, Chamba is concerned, we are holding interviews. You are lucky that we have got so many posts of Assistant Professor, Registrar and Casualty Medical Officer. Sir, we are trying our best to see that this Medical College is also made functional from this year provided we get adequate teaching faculties.

श्री बी.के. चौहान : यह सिर्फ चम्बा के लिए नहीं है, यह सारे प्रदेश के लिए थीं जिनमें से 60 पद रिक्त हैं। Now, they have amalgamated the Chamba Medical Hospital with the Medical College. तो क्या इा मर्जर के बाद ये नए पद सृजित करेंगे for the remaining hospitals of the district where specialists are not there.

Health & Family Welfare Minister: Sir, the total sanctioned posts in the Medical College and Hospital, Chamba are 78. Out of these 78 posts, 42 posts are clinical, 18 posts are filled up and for rest of the posts interviews are being conducted besides one post of DPH working as Medical Officer of

Health. Three posts of Casualty Medical Officers are also filled up. The Doctors have been posted as Assistant Professor/Registrar in the hospital. Detail of the specialist Doctors/discipline and the hospital-wise at district Chamba has been given in the reply. The Principal and MS have gone to Delhi to conduct walk-in interview so that we could get very few Doctors for this College.

07/03/2017/1155/RG/AG/3

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने मैडिकल कॉलेज के लिए बहुत प्रयास किया और अखण्ड चण्डी पैलेस जहां कॉलेज रन करता था, वह हैण्ड ओवर भी कर दिया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगी कि चम्बा अस्पताल में बाकी डॉक्टरों तो इन्होंने फिर भी प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन वहां रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और जो रेडियोलॉजिस्ट है वह भरमौर में बैठा हुआ है और भरमौर में कोई मशीन नहीं है। तो क्या ये भरमौर के रेडियोलॉजिस्ट को चम्बा अस्पताल में पोस्ट करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर रेडियोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि अल्ट्रासाउन्ड की रिपोर्ट सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट ही दे सकता है और सीटी स्केन की रिपोर्ट भी रेडियोलॉजिस्ट ही देता है। हमारी कोशिश होगी कि शीघ्रातिशीघ्र रेडियोलॉजिस्ट वहां लगाया जाए। अगर वह उपलब्ध नहीं होता है, तो भरमौर के रेडियोलॉजिस्ट को हम चम्बा में डिप्यूट कर देंगे।

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

07/03/2017/1200/MS/AS/1

प्रश्न संख्या: 3741 क्रमागत---

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने शायद सितम्बर या अक्टूबर महीने में चम्बा जिला का दौरा किया था और वहाँ पर आपको काफी बड़ा डैपुटेशन इस जिला के अस्पताल के बारे में बात करने के लिए मिला था। श्रीमती आशा कुमारी जी ने और श्री बी०के० चौहान जी ने खाली पदों के बारे में आपको बता दिया है। वहाँ जो डैपुटेशन आपसे मिला उन्होंने आपके समक्ष यह कहा कि सारे डॉक्टर जो इस समय इन-प्लेस हैं वे सारे बाहर प्रैक्टिस करते हैं और आपने यह कहा कि जो आपने लिस्ट दी है, इस पर मैं शिमला जाकर जांच करके तुरन्त ऐक्शन लूंगा। आज छः महीने का समय बीत जाने के उपरान्त भी उस अस्पताल की स्थिति वैसी-की-वैसी है। मैंने वहाँ दौरा किया था। सारे-के-सारे केसिज वहाँ से टांडा को रेफर किए जाते हैं। ये जो स्थिति वहाँ पैदा हुई है और आपके समक्ष भी बात आई है क्या इसके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष जी, यह बात ठीक है कि जब मैं चम्बा गया था तो कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि चम्बा में जो डॉक्टर लगाए गए हैं वे कुछ पठानकोट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और छुट्टी पर चले गए हैं। मैंने उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट सी०एम०ओ० और मेडिकल सुप्रिन्टेंडेंट चम्बा से मंगवाई थी और उसके मुताबिक शाँ-काँज नोटिस भी उनको दे दिए गए हैं **The State will take stern action against those people who are indulging in private practice, either at Chamba or at Pathankot. I assure the House that action, in accordance with the rules, will taken against them.**

प्रश्नकाल समाप्त

07/03/2017/1200/MS/AS/2

कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्ष: अब कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित कागजातों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जोकि इस प्रकार हैं:-

i) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2013-14 (01-04-2013 से 31-03-2014 तक) (विलम्ब के कारणों सहित); और

ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2015-16 (01-04-2015 से 31-03-2016 तक)।

अध्यक्ष: अब माननीय शहरी विकास मंत्री कुछ कागजात सभा पटल रखेंगे।

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 38 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) स्कीम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0-(3)-13/2015 दिनांक 23.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.02.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

07/03/2017/1200/MS/AS/3

अध्यक्ष: अब माननीय सहकारिता मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

सहकारिता मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: आयु0-क-(3)-2/2014 दिनांक 22.08.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.09.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

07/03/2017/1200/MS/AS/4

सदन की समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष: अब श्री मोहन लाल ब्राक्ट, सदस्य, कल्याण समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से (वर्ष 2016-17) समिति का 33वां मूल प्रतिवेदन जोकि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ।

07/03/2017/1200/MS/AS/5

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

अध्यक्ष: अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा क्रमशः चलेगी। मैं श्री रविन्द्र सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि वे चर्चा में भाग लें तथा समय-सीमा में रहकर अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने नये साल का जो हमारा पहला सत्र होता है उसमें प्रथम मार्च को यहां अपना अभिभाषण पढ़ा है और जिसको यहां पर मुख्य संसदीय सचिव श्री जगजीवन पाल जी ने प्रस्तुत किया तथा इसका अनुसमर्थन श्री संजय रतन जी के द्वारा किया गया है। मैं भी उस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है, उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए

उपाध्यक्ष जी, मेरे से पूर्ववक्ता सभी ने कहा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है वह सरकार की एक साल की जो कार्य प्रणाली होती है उसका एक प्रतिबिम्ब होता है। हमें इस अभिभाषण को पढ़ने, सुनने और देखने का मौका मिला। हमें बड़ी हैरानी हुई कि एक रटा-रटाया इस सरकार का चौथा या पांचवां जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा पढ़ा गया,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

07.03.2017/1205/जेके/एस/1

श्री रविन्द्र सिंह:----जारी----

उसमें वही चीजें हैं और जैसे कि आपने इस अभिभाषण के पैरा नम्बर-2 में ही अपने चुनावी घोषणा पत्र, जो आपने वर्ष 2012 के चुनावों में दिया था, आपने कहा था कि यह हमारे लिए एक नीति दस्तावेज है। इसमें किए गए सारे के सारे वायदे पूरे कर दिए गए हैं। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी ने उसके ऊपर काफी व्याख्यात्मक टिप्पणी यहां पर की है, लेकिन हमें हैरानी होती है कि इसमें जो कहा गया, प्रदेश की जनता को गुमराह करना तो कोई आपसे सीखे और विशेष कर मुख्य मंत्री महोदय से सीखे। तीसरे नम्बर पैरे में कहा गया था कि सबका कल्याण समग्र विकास। ये जो बातें यहां पर 2 व 3 नम्बर पैराज में कही गई हैं, इनके ऊपर यह सारे

का सारा पैरा दर्शाता है। अभी प्रश्न लगा था जो श्रीमति आशा कुमारी जी का था और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित था। जिला सिरमौर और चम्बा को सबसे पिछड़ा जिला गिना जाता है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा दुर्गम व कठिन क्षेत्र चम्बा और सिरमौर जिला है। चम्बा जिला में आप देखेंगे इस प्रश्न के जवाब में जो कि इस विभाग के माध्यम से जिले कि सारी की सारी पोस्टों की जितनी क्रियेशन थी उसमें मुझे नहीं लगता कि 50 प्रतिशत पोस्टें भी भरी गई हों। यह सरकार कितनी संवेदनशील है और कितनी इसमें काम करने की क्षमता है, वह अपने ही पार्टी के एक विधायक जिन्होंने यहां पर यह प्रश्न किया और फिर भी उससे सन्तुष्ट नहीं हुई। मंत्री जी ने जवाब दिया तो उसके उत्तर में जो चीजें सामने आई हैं उससे मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में उस जिले में उस विभाग की वे पोस्टें भरी जाएं। मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय इसमें आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय महामहिम् राज्यपाल जी से पैरा नम्बर-4 से लेकर पैरा नं० 9 तक सारे का सारा शिक्षा के क्षेत्र में ही व्याख्यान करवाया गया है। यह सही है कि आपने नये संस्थान खोल दिए। 46-47 कॉलेज आपने खोल दिए। विद्यालयों को स्तरोन्नत किया जा रहा है। आज के दिन में हमारी क्या वस्तुस्थिति है? वस्तुस्थिति यदि आप देखेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय आपके समक्ष सारे का सारा मामला जब यहां पर आएगा और वैसे भी मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मैं जुगाड़ से अपनी सरकार चला रहा हूं। वैसे मुख्य मंत्री जी जुगाड़ करने में बड़े माहिर हैं। पता नहीं कब से उन्होंने जुगाड़ करना सीखा। जब वे फील्ड में जाते हैं तो कहीं न कहीं आप देखते हैं कि चार साल में उनका एक बहुत बड़ा रटा रटाया सा क्षेत्र में जा कर बात करने का

07.03.2017/1205/जेके/एएस/2

तरीका रहा है। वहां पर किसी न किसी विपक्ष के विधायक के ऊपर या हमारे सांसदों के ऊपर कोई न कोई टिप्पणी कर देते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि वे अपने आपको पता नहीं क्यों भूल जाते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, ज़रा वे अपने गिरेबान में भी झांके। यह जिला शिमला का गजेटियर है। अगर इज़ाजत है तो मैं इसको पढ़ कर सुनाता हूं। ये जुगाड़ तो बचपन से करते आए हैं। मुख्य मंत्री महोदय बचपन से ही जुगाड़ में फिट हो गए। इसको जला दिया

गया था लेकिन मैंने इसकी ऑरिज़नल कॉपी ढूँढ निकाली। गेजटियर शिमला की जो ओरिज़नल कॉपी है, उसको मैंने ढूँढ निकाला है। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। मैं तो टिप्पणी उसी के ऊपर करूंगा जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय फील्ड में जा करके टिप्पणी करते हैं। उन्होंने क्या-क्या बातें कही। कभी हमारे सांसदों के बारे में, फैसला न्यायालय करता आया है और मुख्य मंत्री जी बयान देते हैं कि सांसद को तो फलां जिले में बैठ कर दुकान खोलनी चाहिए। क्या करोबार करना आपको बुरा लगता है? दूसरे सांसद के प्रति आपने कह दिया कि सारे का सारा मण्डी का ब्राह्मण समुदाय इनके साथ हो गया और वे सांसद बन गए। उनके पड़ोस वाला चाय बेचने वाला भी उन्हें नहीं जानता है। कभी आपने विधायकों के ऊपर टिप्पणी करनी कि बी०जे०पी० के विधायक यहां विधान सभा में आने के लायक भी नहीं है। यह टिप्पणी करना माननीय मुख्य मंत्री को शोभा नहीं देता। हम बार-बार कहते हैं कि हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। ये अपनी आयु तो देखें कि मैं किसके बारे में कौन सी बात कर रहा हूं। जब ये बोलने लगते हैं तो इनको पता ही नहीं लगता कि मैं क्या बोल रहा हूं। अखबार में लिखा है कि चार्जशीट बनाने वाले भाजपा के एलान पर गुस्साए मुख्यमंत्री और गुस्से में जो मुंह में आता है वह कहना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं कि इनको तो म्युनिसिपल कमेटी में सफाई की डियूटी करनी चाहिए। अभी दो तारीख को देहरा विधान सभा चुनाव क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय गए थे।

श्री एस०एस० द्वारा जारी----

07.03.2017/1210/SS-DC/1

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागत:

साढ़े चार साल में आपको दूसरी बार देहरा विधानसभा क्षेत्र में आने का मौका मिल गया। वहां वनखंडी स्थान पर जनसभा थी। वहां मेरे प्रति बड़ी टिप्पणी की है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। काश मुख्य मंत्री महोदय सदन में होते। - (व्यवधान)-- आप (बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री) ज़रा चुप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं फिर आपकी वस्तुस्थिति पर आऊंगा। तो वहां मेरे ऊपर टिप्पणी करते हैं कि यह व्यक्ति तो फलांन कारोबार करता था। फिर यहां पर पहली तारीख को आकर मेरे

कान में कहा कि मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं न तो मुझे साइन का इतिहास मालूम पड़ता है। हमने भी इतिहास को सीखने की कोशिश की है और हम सारी-की-सारी कॉपियां लेकर आए हैं। मुख्य मंत्री महोदय, न तो मेरे पीछे कोई सी0बी0आई0 लगी है, न मेरे पीछे कोई ई0डी0 लगा हुआ है और न मेरे घर पर कोई छापा पड़ा, हम ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं और ईमानदारी करके यहां पहुंचे हैं। हमारे ऊपर कभी कैसेट नहीं बनी। हमने कभी यह नहीं कहा कि यह जो गड्डी फलांनी इंडस्ट्री वाला लाला दे कर गया, उस गड्डी में एक-एक लाख रुपये में से 10-10 हजार रुपये कम पाए गए हैं। यह कहा गया। यह किसने किसके बारे में कहा। यह इतिहास बन चुका है मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। बेशक कोर्ट ने आपको फैसला दे दिया है, उसका फैसला आ चुका है लेकिन अगर मुख्य मंत्री महोदय आपमें हिम्मत है तो उस कैसेट को जो आपकी ही सरकार के मंत्री ने रिलीज की थी इस रिज के मैदान पर जनता को सुनाएं। जनता उसका फैसला करे कि आवाज़ किसकी है। हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाईये। यह टिप्पणी करना मुख्य मंत्री महोदय आपको शोभा नहीं देता है। यह मैं कहना नहीं चाहता था। पिछले दो साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने आपको संयम में रखूं लेकिन किसी के प्रति ऐसे विचार व्यक्त करना कि मैं अंडर-गारमेंट बेचता था, ठीक बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं कृषक परिवार में पैदा हुआ हूं। वहां से निकल कर यहां पहुंचे हैं। क्या ईमानदारी का कारोबार करना गलत बात है? आपकी तरह मैंने सेब या कोई सामान स्कूटर पर नहीं ढोया है। मैं किराया देकर ढुलाता था। सेब को मैं रामपुर से परवाणू तक ऐसे ही नहीं लेकर गया। इसलिए आपकी जुगाड़ से कैसे सरकार चल रही है यह आपका इतिहास है। केवलमात्र यही नहीं है।

07.03.2017/1210/SS-DC/2

उपाध्यक्ष महोदय, कल भी इसकी चर्चा हुई थी। क्षेत्रवाद का नाम देना माननीय मुख्य मंत्री महोदय के जींस में है। यह हर जगह जाते हैं तो कौन-सी बात करते हैं। यह Report of Malhotra Commission of Enquiry है। यह 4 सितम्बर, 1990 को यहां पर ले की गई है। उस समय विपक्ष के नेता श्रीमान् वीरभद्र सिंह जी थे। कल इसको यह कहना कि मैं मानता नहीं। अरे भाई, उस समय आप यहां बैठते थे तो उस समय जब इस कमीशन की रिपोर्ट ले की गई तो आप इस पर चर्चा की मांग करते। यहां क्या कहा गया है? कल भी यह

रिकॉर्ड पर आया है। शिमला के केवल मात्र एक स्पैसिफिक एरिया में यह हुआ है। सारे जिले में नहीं हुआ, केवल मात्र यह रोहडू में हुआ है कि रोहडू के 22 दुकानदारों को मार-मार कर भगा दिया। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है - आलू सेब खायेंगे कांगड़ियों को भगायेंगे। इसकी सारी-की-सारी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। उस समय कितना नुकसान हुआ है। 1990 से पहले जब यह घटना घटी तो 32,48,017/- का नुकसान कारोबार करने वालों या सरकारी क्षेत्र में हुआ। प्राइवेट प्रॉपर्टी का 10,75,040/-, पब्लिक प्रॉपर्टी (एच0आर0टी0सी0) का 6,93,790/-, हिमफैड का 4,58,016/-, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड अदर्ज मु0 6 लाख 16 हजार का नुकसान हुआ। आज 26 साल के बाद आकर कहना कि मैं इस रिपोर्ट को मानता नहीं। क्षेत्रवाद मुख्य मंत्री के जींस में है। मुख्य मंत्री महोदय, आप भूल जाते हैं। आपको याद नहीं रहता। अपना 2003 का चुनाव घोषणा पत्र याद करिये जब आपने प्रदेश की जनता के साथ वायदा किया था कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। जब सरकार बन गई और पांच साल आपकी सरकार रही तो हमने भी प्रश्न किये कि कितने हमारे बेरोजगार पढ़े-लिखे भाइयों को नौकरी मिली तो आपका जवाब था कि 3380 लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिली। आपको याद होना चाहिए कि हिमाचल का इतिहास क्या है। हिमाचल में जो आज भी आप क्लास-IV भर्ती करेंगे, चीफ सैक्रेटरी तक तीन लाख के लगभग कर्मचारी-अधिकारी हैं उन सब की छुट्टी कर दो, नई भर्ती आप करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में लगभग 12 लाख नाम दर्ज हैं तो ही तीन लाख भर्ती होंगे और

जारी श्रीमती के0एस

07.03.2017/1215/केएस/डीसी/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी----

9 लाख फिर भी बेरोजगार रहेंगे। यह वायदा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। वर्ष 2012 में आप फिर आए, फिर प्रदेश की जनता को, नौजवानों को गुमराह कर दिया और आज आप क्या कहते हैं कि मैं तो उस वक्त था ही नहीं जिन्होंने घोषणापत्र बनाया था, उनको पूछो। वे आपके केन्द्र के मंत्री है जिन्होंने यह सारा घोषणापत्र बनवाया। यहां के मंत्री

जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, बार-बार कह रहे हैं कि हमने वायदा किया है। साढ़े चार साल आपकी सरकार के हो गए हैं, हो सकता है आप अब बजट में डाल दें जैसे आप झूठी-सच्ची घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन यह होना कब चाहिए था, उन हमारे पढ़े-लिखे बेरोज़गार नौजवानों को इंतज़ार था कि आज मिलता, कल मिलता। हम यह नहीं कहते लेकिन अगर आपने वायदा किया है तो आपको देना चाहिए। आपने जो वायदा किया था उसके बारे में आपको सोचना चाहिए था लेकिन आज आप उससे मुकर रहे हैं। अभी आपने एक और घोषणा कर दी राजधानी बनाने की और मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सुधीर शर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूँ लेकिन एक शब्द भी स्मार्ट सिटी के बारे में नहीं कहा, सारे का सारा पैसा भारत सरकार दे रही है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में आयुर्वेदिक अधिकारियों के द्वारा हर क्षेत्र के विधायक या कोई सीनियर मंत्री हैं, उनका फट्टा लगा रहे हैं। मण्डी में जाओ तो कौल सिंह जी का फट्टा लगा हुआ है, कांगड़ा में सुधीर भाई का लगा है, सुजान सिंह पठानिया जी का, बाली जी का फट्टा लगा हुआ है। बनीखेत में आशा कुमारी जी का फट्टा लगा हुआ है। सारे प्रदेश में ऐसा है। अरे, भाई उसमें आपने दो शब्द लिख दिए होते कि हम नरेन्द्र भाई मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। हम केन्द्र के वैकैया नायडू जी, जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। स्मार्ट सिटी, एक नई सोच पूरे देश में पैदा की तो नरेन्द्र भाई मोदी जी ने पैदा की है। आपने नगर निगम भी धर्मशाला में बना दिया, आपको बधाई हो। यह प्रोजेक्ट हमारे समय का था।

उपाध्यक्ष महोदय, धर्मशाला को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। मैं कांगड़ा से हूँ तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैंने यह उस समय भी कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय बताएं कि कब-कब कौन-कौन से कार्यालय वहां पर गए? माननीय मुख्य मंत्री की आदत हैं वे एकदम से खड़े हो जाते हैं? मैं सारी सूचना ले कर आया हूँ। जब इन्होंने धर्मशाला में, कांगड़ा में घोषणा की थी तो उस समय मैंने इनको कहा कि आपको

07.03.2017/1215/केएस/डीसी/2

कागज जारी करने की बड़ी पुरानी आदत है, जैसे कल भी यहां पर भाई राकेश कालिया जी बोल रहे थे। जब मुख्य मंत्री किसी विधायक के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो सभी मांग करते हैं कि यह भी कर दो, वह भी कर दो, कर दिया सब कुछ लेकिन कुछ चीजें छूट

जाती है। मुझे याद है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी का खूंडिया का दौरा था। वहां पर लगडू नामक स्थान पर प्रोग्राम हुआ। संजय भाई ने मांग रखी, वहां पर मुख्य मंत्री जी का भाषण हुआ। वे भाषण दे कर बैठ गए। जो इन्होंने मांगा, कुछ नहीं दिया। बैठ गए, कुछ नहीं कहा। जनता बड़ी पेशान हो गई, संजय जी भी पेशान हो गए। स्वभाविक है कि इन्होंने जो मांगें रखी, कहा जाता है कि ये तो मुख्य मंत्री जी के दत्तक पुत्र है और ये जो कहें मुख्य मंत्री जी को वह देना पड़ता है। मुख्य मंत्री जी चौकड़ी मार कर बैठ गए फिर ये उठे और मुख्य मंत्री जी के साथ बैठ गए और बाद में मुख्य मंत्री जी के कान में इन्होंने कुछ कहा, इसका लोगों ने विडियो बनाया हुआ है। उनके कान में कुछ कहा और फिर खड़े हो गए और कहने लगे कि राजा साहब सब मान गए, राजा साहब ने कह दिया कि यह डिविज़न भी दे दिया, वह भी दे दिया। मुख्य मंत्री ने नहीं कहा, संजय भाई ने यह कहा। ये मेरे सामने यहां पर बैठे हैं, मैं पीछे से नहीं कह रहा हूं। फिर एक चीज़ रह गई।

श्री संजय रतन: रवि जी, अगर आप मुझे वह विडियो दिखा दें, I will quit politics और अगर नहीं होगा तो आप छोड़ देना।

श्री रविन्द्र सिंह: ठीक है, मैं दिखा दूंगा। उसके बाद फिर इनको एक बात और याद आ गई कि खूंडिया में आर.ओ. ऑफिस चाहिए। ये फिर मुख्य मंत्री जी के पास जाकर बैठ गए और तुरन्त खड़े हो गए कि राजा साहब मान गए आर.ओ. ऑफिस भी दे दिया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

7.3.2017/1220/av/ag/1

श्री रविन्द्र सिंह----- जारी

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश में क्या हो रहा है? हमारा एक छोटा सा प्रदेश है, यहां किस ढंग से अनाउंसमेंट हो रही हैं? हमने शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किए थे।

हमारे समय में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में लगातार एक नम्बर पर आता रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमें 85 अवार्ड प्राप्त हुए थे। वह होता है काम करने का तरीका। यह क्या काम है? मैं आपके समक्ष यह लाना चाहता हूँ कि धर्मशाला में कौन-कौन से कार्यालय कब-कब गये। सबसे पहले वहाँ लोक निर्माण विभाग का चीफ इंजीनियर गया था जो कि वर्ष 1978 में गया था, वह किसी की देन नहीं है। उस समय आई0पी0एच0 और पी0डब्ल्यू0डी0 साथ ही थे। अगला शिक्षा बोर्ड का कार्यालय गया जिसके लिए वर्ष 1979 में यहां कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी। कैबिनेट की अप्रूवल होने के बाद जाने की तैयारी हो गई मगर यहां पर सरकार टूट गई। सरकार टूटने से वह मामला बीच में लटक गया इसलिए वह हो नहीं पाया मगर वर्ष 1979 की अप्रूवल है। उसके बाद 3 जनवरी, 1983 को जब राम लाल जी मुख्य मंत्री थे तो उनके द्वारा उसको 43 कर्मचारियों सहित धर्मशाला भेजा गया और वह रिकॉर्ड में है। उसके बाद जो आई0पी0एच0 का नया विभाग खुला उसका चीफ इंजीनियर जोन आपके समय में हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ष 1990 में शांता कुमार जी मुख्य मंत्री थे उस समय बिजली बोर्ड का चीफ इंजीनियर वहां भेजा गया। (--- व्यवधान---) बधाई हो आपको (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री)। किस चीज का मिला, जो पांच अधिकारी सस्पेंड हो गये उस चीज का मिला? (---व्यवधान---) उपाध्यक्ष जी, मैं ये सारी चीजें रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ। यहां पर जो राजधानी की घोषणा की गई है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आवेदन करना चाह रहा हूँ। हमारा प्रदेश छोटा सा है और यहां पर आवश्यकता नहीं थी लेकिन राजनीति करने के लिए इन्होंने 2003 के गिनाए, मैंने 2012 के गिनाए और आज 2017 है। चुनाव सर पर है और आपने घोषणा कर दी। हमारी मांग है कि जिस ढंग से जम्मू-कश्मीर के लिए 6 महीने श्रीनगर और 6 महीने जम्मू में सारे-के-सारे कार्यालय सचिवालय सहित शिफ्ट किए जाते हैं उसी तरह यहां पर भी किए जाएं फिर हम मानेंगे कि माननीय मुख्य महोदय ने

7.3.2017/1220/av/ag/2

कुछ काम किया है। (---व्यवधान---) हमने इनसे (श्री प्रेम कुमार धूमल) करवा लिया जो करवाना था (---व्यवधान---)। आज वहां पर भवन बनाकर तैयार किए हैं वह धूमल जी की देन है। वहां पर पहला भवन जहां मंत्री बैठते थे वह मिनि सैक्रीटेरिएट का भवन चार करोड़ रुपये की लागत से धूमल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बनाया था और उसका उद्घाटन भी हमने किया था। दूसरा भवन 12 करोड़ रुपये की राशि खर्च करके धूमल जी ने बनाया और उसका टाइम रहते उद्घाटन भी कर दिया नहीं तो आपने कहना था कि हमने बनाया। हमने जो करना था, वह किया। विधान सभा का भवन आपके समक्ष है, यह भी बनाया। हालांकि इसमें दोनों पार्टियों की सरकारों का योगदान रहा है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ऐडिशनल डायरेक्टर(एग्रिकल्चर) को धर्मशाला में धूमल जी ने बिठाया। ऐडिशनल डायरेक्टर(होर्टिकल्चर) को भी धूमल जी ने बिठाया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि केवल कागजी कार्रवाई करने के उपरांत एक शब्द लिख कर धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित कर दिया। सुधीर जी, आपने काम करवाया, आपको बहुत-बहुत बधाई। लेकिन जम्मू-कश्मीर की तर्ज के ऊपर क्योंकि अभी तक जी0ए0डी0 ने नोटिफिकेशन नहीं की है। क्या वहां के कर्मचारियों को राजधानी भत्ता मिलेगा? अभी तक कुछ पता नहीं है कि मिलना है या नहीं मिलना है। ये सारी-की-सारी चीजें आपके समक्ष है। (---व्यवधान---) मैंने आपको (श्री संजय रतन) पहले भी कहा है कि बीच में मत बोलो नहीं तो बात ज्यादा बढ़ जायेगी। मैंने बच्चे की फाइल ही बंद कर दी है इसलिए चुप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। (---व्यवधान---) मैं आपको कॉपी दे दूंगा। (---व्यवधान---) नहीं, नहीं। मैं प्यार से समझा रहा हूं। यह संवेदनशील सरकार, इसका नाम जो आपने लिखा है यह बड़ी संवेदनशील है। (---व्यवधान---) यह आपकी उत्तरदायी सरकार है। दृष्टिबाधित बैकलॉग का पुनः होगा आकलन, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है उनको भी अपनी मांग पूरी करवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। धरने पर बैठे तब जाकर सरकार की आंखें खुली। फिर मुख्य मंत्री महोदय ने उनको बुलाया कि आप आइए और मेरे से बात कीजिए। संवेदनशील सरकार का इस तरह का रवैया होता है? वे अब विधान सभा का घेराव कर रहे हैं। इसमें मुख्य मंत्री महोदय बीच में शामिल हुए लेकिन अभी तक भी उनको कोई आश्वासन नहीं मिला है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

07/03/2017/1225/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

श्री रविन्द्र सिंह...जारी

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपने निवेदन है, अभी तो थोड़ा और समय चाहिए। इसी तरह से धर्मशाला में सैनिक कैफे जो भाजपा के कार्यकर्ता के पास लीज़ पर दिया हुआ था, वह बन्द करवा दिया गया। हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिये थे, फिर भी आपने जबरदस्ती वहां पर प्रशासन को लगा दिया कि उसको उखाड़ दो, ताले तोड़ दो या चाहे कुछ और कर दो लेकिन यहां पर प्रशासन की मोहर लगनी चाहिए। क्या यही संवेदनशील सरकार है? शिमला में जब-जब कोई आपदा आती है, तो माननीय मुख्य मंत्री शिमला छोड़कर भाग जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक युग प्रकरण हुआ था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह पिछले साल यहां (शिमला) पीलिया फैला और मुख्य मंत्री जी कांगड़ा के दौरे पर चले गये। इन्होंने यह श्री कौल सिंह जी के ऊपर छोड़ दिया कि इस पीलिया को आप देखो और यदि पीलिया रोक सकते हो, तो रोको। इसके अलावा मैडम विद्या स्टोक्स जी के ऊपर यह जिम्मेवारी छोड़ दी कि शिमला को पानी दे सकते हो, तो दो वरना शिमला को अपने रहमोकरम पर छोड़ दो। इस बार भी यही हुआ, शिमला में बर्फ पड़ गई और मुख्य मंत्री जी हेलीकॉप्टर से धर्मशाला (कांगड़ा)/ दिल्ली चले गये। ये शिमला से भाग गये और डेढ़ महीना शिमला वालों के हालचाल तक नहीं पूछे। ये संवेदनशील सरकार है, ये ऐसा कर सकती है। संवेदनशील सरकार के बारे में एक और बात सुनिए, सिरमौर के एक गांव में न सड़क और न स्कूल है, लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो गये हैं। जिस क्षेत्र में सबसे लम्बा समय आपकी पार्टी का विधायक रहा है, सबसे ज्यादा अन-डेवैल्पड वह इलाका रहा है और आज के दिन में हिमाचल प्रदेश का यदि कोई अन-डेवैल्पड इलाका है, तो हमारे भाई तोमर जी का निर्वाचन क्षेत्र शिलाई है। यहां के लोग घरबार छोड़कर प्लाईन कर गये हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण देते हैं कि मेरा सिरमौर के साथ वैसा ही नाता है, जैसे मैं शिमला को चाहता हूं। आज यह स्थिति है कि सारे-का-सारा गांव खाली हो गया है। वहां पर लोगों के पास आने-जाने के साधन नहीं हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी यही हाल है। मेरा गांव धार है, जो देहरा बना है, उसमें पुराने जसवां विधान सभा क्षेत्र की 26 पंचायतें आई है और जहां आजादी के 70 साल में से 55

साल एक परिवार का राज रहा है। धार पंचायत का सपडू गांव भी खाली हो गया है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है। ये आपकी संवेदनशील सरकार है। श्री जगजीवन पाल जी आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर इस माननीय सदन में धन्यवाद

07/03/2017/1225/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

प्रस्ताव प्रस्तुत कर शुभारम्भ किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके मंत्री कितने हैं? माननीय मुख्य मंत्री सहित 12 हैं, लेकिन क्या ओ0बी0सी0 का कोई मंत्री नज़र आता है?

Deputy Speaker: Please wind-up now. 16 लोग अभी और बोलने वाले हैं।

श्री रविन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने परमिशन ली थी और मैंने उस ढंग से शुरू किया है। मैं वाइंड-अप करने की कोशिश करता हूँ। ये सरकार ओ0बी0सी0 की हितैषी बनती है और कहते हैं कि ओ0बी0सी0 तो हमारा बोट बैंक है। लेकिन साढ़े चार साल में एक भी मंत्री ओ0बी0सी0 का नहीं बना है। मैं प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। चुराह की सड़कों पर आतंकवादी आकर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाकर चले जाते हैं, सबाथु/बंजार में आई0एस0आई0 के आतंकवादी का मिलना, शिमला शहर में सैक्सरेक्ट का भंडाफोड़ होना। ये सारे-की-सारी ऐसी घटनाएं हैं, जिनको सोचकर रौंगटे खड़े होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने पी0टी0ए0,एस0एम0सी0 और आउटसोर्स में कितना रॉस्टर लागू किया है? इसमें अनुसूचित जाति/ओ0बी0सी0 के कितने-कितने लोग भर्ती हुए हैं?

श्रीमती एन0एस0- - - द्वारा जारी।

07/03/2017/1230/ ns/as /1

श्री रविन्द्र सिंह ----- जारी

मुख्य मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो उनको यह बताना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर बात में आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश बरूरी लिमिटेड, एल-1 के आपने ठेके बंद कर दिए और सरकार ने शराब बेचना शुरू कर दी। ड्रग माफिया के ऊपर

में नहीं जाऊंगा उसके ऊपर मेरे बाकी मित्र बोलेंगे। अभी हाल ही में नगरोटा में एक घटना घटी, जिसके अंतर्गत नगरोटा में 1800 पेटी शराब गायब हो गई जिसकी सप्लाई सरकार करती थी। यहां से विभाग का आदेश आया कि जो 1800 पेटी हैं जहां-जहां नगरोटा वाले शराब सप्लाई करते हैं उन सभी ठेकों को एक-एक पेटी डाल दी जाए। एल-1 वाले कारोबारी तो आपने ऐसे ही मार दिए। आज उनकी हालत आत्महत्या करने वाले परिवारों की तरह हो गई है।

Deputy Speaker: Hon'ble Member, please wind up now. It is last one minute. 27 मिनट हो गए अब आप वाईड अप कीजिए। आपका सिर्फ एक मिनट बचा है।

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाईड अप कर दूंगा। अब मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं केंद्रीय विश्व विद्यालय का सारा इतिहास ले कर आया हूं। जिसकी नोटिफिकेशन 23 अप्रैल, 2010 को हो चुकी है और जिसके निर्माण की सारी कापियां यहां पर पड़ी हुई हैं। मेरा और श्री बिक्रम जी का यहां पर प्रश्न भी था, जिसके माध्यम से हमने जानना चाहा था कि इसके लिए सारी की सारी फॉर्मैलिटीज़ पूरी कर दी गई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम देहरा में 3400 करनाल ज़मीन चढ़ चुकी है। भरवाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने मांग की है कि जल्दी-से-जल्दी demarcation of land allotted in favour of Central University of Himachal Pradesh for establishment of its South Campus at Dehra. यह जो जमीन 3400 करनाल दे दी गई है उसकी डिमार्केशन के लिए 25 नवम्बर, 2016 को कहा गया है। जब मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री महोदय गए थे और उन्होंने मेरे बारे में कहा तो मेरी मांग भी यही थी कि मुख्य मंत्री महोदय मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और वे यहां घोषण

07/03/2017/1230/ ns/as /2

करके जाएं कि जो जमीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दे दी गई है इसकी डिमार्केशन अतिशीघ्र करवा दी जाए। यह मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं यह सारा मुख्य मंत्री जी के जवाब में

कहा गया है। मेरा उनसे निवेदन है कि वे इसे जल्दी-से-जल्दी पूरा करें। अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि उपाध्यक्ष महोदय प्रदेश में नई तहसीलें खोली जा रही हैं। आप जो तहसीलें खोल रहे हैं उसमें आपने मुझे आश्वासन भी दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो आपने डाडासीबा तहसील खोली है उसमें आपने मेरे दो कानूनगो सर्कल डाल दिए हैं और वे जाने को तैयार नहीं हैं। आपने एक नई रक्कड़ सब-तहसील खोली है वहां पर ढलियारा-कानूनगो जाने को तैयार नहीं है। वैसे ही आपने हरिपुर सब-तहसील खोल दी है। बणखंडी के लोगों को देहरा सूट कर रहा है क्योंकि देहरा छः किलोमीटर है और हरिपुर के लिए तीन बसें बदलनी पड़ती हैं लेकिन उनको हरिपुर में डाल दिया गया है। आप लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं या जनता की सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या यह सरकार संवेदनशील है? उपाध्यक्ष महोदय, जो चार्जशीट हमने दी थी उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने, श्री सुरेश भारद्वाज और श्री सतपाल जी ने तीन संशोधन दिए थे उन तीनों के ऊपर (चौहदवें वित्त आयोग) के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है और नेशनल हाईवे के ऊपर अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की है तथा साथ में जो हमने आरोप पत्र दिया था उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक नई "यथावत मैगज़ीन" निकली है जिसमें कांग्रेस पार्टी का इतिहास लिखा हुआ है।

07/03/2017/1230/ ns/as /3

मुख्य संसदीय सचिव (श्री नन्द लाल): उपाध्यक्ष महोदय, 1 मार्च, 2017 को इस मान्य सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया है। जिसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) जी और उसका समर्थन माननीय विधायक श्री संजय रतन जी ने किया है। मैं भी इस चर्चा में अपने आप को शामिल करता हूँ।

श्री आर०के०एस०---- द्वारा जारी ।

07/03/2017/1235/RKS/AS/1

श्री नन्द लाल.....जारी

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण में अपनी सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों को बताते हैं। I am using the word "अपनी सरकार" और यह कन्वेंशनल है कि महामहिम राज्यपाल हर वर्ष जब इस माननीय सदन को अड्रेस करते हैं तो उसमें अपनी सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों को बताते हैं। उन्होंने अपने अभिभाषण में he made an earnest appeal to all of us to cooperate the Government, so that the development can take a boost. इसलिए उन्होंने सबसे अनुरोध किया था कि कॉओपरेट करें और जो हिमाचल प्रदेश के अन्दर विकास हो रहा है for the well being of mankind here उसमें हम अपना-अपना योगदान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, देखने में यह आया कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट के लिए एक नोटिस सर्व किया। पहला था 'भ्रष्टाचार' कि इस दस्तावेज़ में भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। दूसरा था, 'नेशनल हाईवे' कि नेशनल हाईवे का कहीं जिक्र नहीं है। तीसरा था कि 'केंद्र सरकार का कोई धन्यवाद नहीं किया गया'। उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और अभिभाषण के पेज नम्बर 126 में यह दर्शित भी है।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

I would like to read here क़प्शन पर इतनी डिस्कशन/डिबेट यहां पर होनी ही थी My Government is determined to eradicate corruption from the State at every level and has adopted the policy of Zero Tolerance to achieve the goal. The Anti

Corruption Bureau has computerized all its 12 Police Stations under the Crime Criminal Tracking Network System. During the year, 35 cases were registered against corrupt government servants. Do they want the list of those 30 persons to be given here. It is already in this document. दूसरा, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 61 बहुत बड़ा हल्ला हो रखा है कि केन्द्र सरकार ने नेशनल हाईवे अनाउन्स किए। अध्यक्ष महोदय, जो नेशनल हाईवे 61 की बात की गई है उसमें इस तरह

07/03/2017/1235/RKS/AS/2

के नेशनल हाईवे हैं जैसे पगडंडियां होती हैं not known even. नम्बर दो, इसकी डी.पी.आर. बनाने के लिए जो पैसा खर्च होगा, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी वह भी केन्द्र सरकार से मिलनी है। Exact 285 crore or something इतने का जो प्राक्कलन है it is already with the Central Government डी.पी. आर. बनाने के लिए अभी केंद्र सरकार से पैसा नहीं आया and you are talking about the National Highways. Is that feasible? फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, कई और चीजें होती हैं, उसमें मुझे यह कहना है। तीसरी बात जो इन्होंने कही कि 'केन्द्र सरकार का धन्यवाद नहीं किया।' मैं यह कहना चाहता हूँ कि State like Himachal जिसके अपने बड़े मीग्र रिसॉर्सिज़ है, विकास के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर करना पड़ता है। सेंट्रली सपोसर्ड स्कीम्ज़ जिसकी 90:10, 60:40 इस तरह से जो लोग बताते हैं उसमें It is an obligatory payment they have to make.

यह कोई एहसान नहीं हो रहा है। सिस्टम है for a particular scheme, हमको कितना पैसा केन्द्र से मिलना है, कितना हमको लगाना है so it is a system. उनका धन्यवाद तो करना ही है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आज हम क्या देख रहे हैं? कितनी ऐसी स्कीम्ज़ हैं जिनमें कटौती पाई गई। विधान सभा के अंदर विपक्ष के जो माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं we expect them to contribute something विकास के लिए कोई अच्छे सुझाव देंगे लेकिन हम देख रहे हैं जो राज्यपाल का अभिभाषण था उसको किस तरह से यहां पर बताया गया कि 'असत्य को सत्य' बोलना है। I don't know. 'तमसो मां

ज्योतिर्गमय' जो उन्होंने कहा। यह कहा गया कि असत्य बुलाया गया, इस तरह का फील लोगों में दिया गया, यह बड़े अफ़सोस की बात है।

श्री एस० एल० एस० द्वारा जारी...

07.03.201/1240/SLS-DC-1

श्री नन्द लाल (माननीय मुख्य संसदीय सचिव)...जारी

We have to respect the Chair, rather it is disgrace to the institution. Constitutionally Office of the Governor, is very important institution. वह हमारे संवैधानिक हैड हैं। This kind of comment is not acceptable at all.

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जिस तरह से यहां चर्चा चल रही है, जैसे कि अभी माननीय रविन्द्र रवि जी was targeting particular individual. Our Chief Minister, he has not thrown any light on this particular document. लोग एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन का अभी बहुत बुरा हाल है। चार या पांच साल पहले क्या था, we know the condition. Nothing new. ये जो डिटिरियोरेंट होने की बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ़ कहने की बातें होती है because it is their compulsion, they have to say something. इसको अपोज करना और इसके बारे में कहना, it is their compulsion.

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि ये लोग मुद्दा विहीन हो चले हैं। अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी यहां पर डिसकशन के नाम पर ये लोग कांग्रेस के मैनिफ़ेस्टो के पीछे लगे हुए हैं। That's all. I will give you small example. अभी 2017-18 को बजट पेश होगा। ठीक है कि जो कुछेक और कमिटमेंट्स हैं, वह भी पूरी हो जाएंगी। मैं एक छोटा-सा अग़जांपल देता हूं। That is about the pension. पेंशन केसिज हिमाचल के अंदर which were suppose to be enhanced. 2017-18 का जो बजट होगा, उसके अंदर पेंशन के

केसिज बढ़ने थे। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो 2016-17 का बजट था, उसके अंदर ही पेंशन केसिज को बढ़ा दिया। आज वृद्धा पेंशन 650 rupees, widow pension 650 rupees और इसी तरह जो दूसरी पेंशंज हैं, उनको बढ़ाया गया है और अप्रैल, 2016 से हिमाचल में लोगों को उसका लाभ मिला है। इसी तरह से जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन को 1100 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है और

07.03.2017/1240/SLS-DC-2

अप्रैल 2016 के बाद वह पेंशन भी सबको मिल रही है। इसलिए कमिटीमेंट में कमी कहाँ रही? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा मैनिफैस्टो है, उस मैनिफैस्टो के बहुत सारे काम हो चुके हैं। लगभग सारे हो चुके हैं। फिर 2017-18 का जो बजट आएगा, you will see to yourself और फिर न्यूज पेपर की कटिंग से कोट करते हैं। I don't know what authenticity that paper has got. न्यूज पेपर कटिंग के बड़े-बड़े जत्थे लेकर यहां आते हैं कि उसने यह कहा, उसने वह कहा। यह लोगों को गुमराह करने के लिए होता है। केवल न्यूज लगाने के लिए कि what all we are speaking here. इसके सिवा मुझे इनका और कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जस्टिस मैहरोत्रा के बारे में चर्चा हुई। वर्ष 1990 में जस्टिस मैहरोत्रा कमीशन बिठाया गया, so than what happened जब कमीशन बिठाया गया तो जो उसकी रिकोमेंडेशन हैं why Government has not implemented that recommendation. आपको मालूम होगा कि बागवानों और किसानों का 1990 का वह ऐजिटेशन शांतिपूर्ण था। उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कितने लोग मारे गए? कोटगढ़ के अंदर 6 लोग गोलियों से मारे गए हैं। इसी तरह से हमारा जो कर्मचारी वर्ग है, उसी दौरान उनके साथ क्या हुआ, यह भी जग जाहिर है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि इस डिसकशन और डिबेट में जो इस तरह का विंडिक्टिव ऐट्टिट्यूड है और targeting a particular individual, किसी की इमेज खराब करने से बेहतर होता कि we would have discussed the things on development. What all activities are under going here और जो हो रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए I don't know कि कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है या अनुभव की ज़रूरत है।

अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रवाद की बड़ी बातें होती हैं कि क्षेत्रवाद बढ़ाया। मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि 2007 से लेकर 2012 तक, I was in opposition. हमारे क्षेत्र में हमने कोई डवलपमेंट नहीं देखी। Barring my MLA land. कोई भी फंड्स की अलौटमेंट नहीं हुई जिससे कि कोई डवलपमेंट हो पाए। हम कभी नहीं कहते कि भेदभाव हुआ। और जब माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की बात हो, we should not forget जो आपका

जारी ...श्री गर्ग जी

07/03/2017/1245/RG/DC/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री नन्द लाल) की अंग्रेजी के पश्चात---क्रमागत

हमीरपुर का बमसन का क्षेत्र है, वहां एक वाटर सप्लाई स्कीम 73 करोड़ रुपये की है। वहां लोग खातियों में पानी पीते थे और वहां से उन्हें पानी मिलता था। Now we are thankful to Hon'ble Chief Minister, that area was without drinking water.

एक सबसे बड़ी स्कीम--(व्यवधान)--- Please let me speak . If you want say something you can say later. उस क्षेत्र में इतनी बड़ी स्कीम को चलाया और आज सब लोग वहां अच्छा पानी पी रहे हैं, तो यह भेदभाव की बात नहीं है।

डॉ. राजीव बिन्दल : माननीय धूमल साहब ने वह स्कीम चलाई।

Chief parliamentary Secretary(Sh. Nand Lal) : You are forgetting. You are badly mistaken. Mr. Bindal you can speak later I am ready to answer your any query. Let me finish. ---(interruption)---.I am not misguiding the House like you do it. let me finish I will reply to your query later.

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सब बौखलाहट है। This is frustration. वर्ष 2012 में जब यह सरकार बनी, तो सरकार बनने के पश्चात माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कार्यभार संभाला और प्रदेश के विकास की चाल इन्होंने बनाई और इसको पटरी पर लाया। यह सवाल कि सर्वांगीण विकास कहने के लिए ये मुकर रहे हैं। मैं

इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं जिस तरह का विकास पिछले चार सालों में हुआ वह अपने आप में एक इतिहास है और आप भी इस बात को समझते हैं। but again the same thing it is your compulsion that we have to negate it.

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि यह जो वित्तीय वर्ष चल रहा है और इसमें जो विकास हुआ, यह अपने आप में एक इतिहास हो गया और इस विकास के कारण हम अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हैं कि अपने मेगा रिसोर्सिज के साथ जो भी उपलब्ध है उसमें इन्होंने विकास किया है। अपना वित्तीय प्रबन्धन और अपने एक तजुर्बे के कारण जो हम सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, it is all because of that. हम अपने मुख्य मंत्री महोदय को इसके लिए बधाई देना चाहेंगे और इनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस

07/03/2017/1245/RG/DC/2

वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश में जो विकास हुआ है, वह अपने आप में एक इतिहास है और इस बात को आप सब जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष के लोगों ने जैसे अभी बीच में बोलना शुरू कर दिया था, अब ये मुद्दाविहीन हो चुके हैं। I am telling you. ये मुद्दाविहीन हैं और इनके पास कहने को कुछ नहीं है। तभी तो ये जो समाचार-पत्र हैं या जो हमारा चुनाव घोषणा-पत्र है, इनका इनचीजों के सहारे काम चल रहा है। मैं यहां एक बात और बताना चाहूँगा कि यहां बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उन्होंने कहा कि अब चुनाव का समय है, तो इस समय इस तरह से इनकी फ्रस्ट्रेशन का होना लाजिमी है। मैं आज यहां दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में लोगों ने एक मन बना लिया है कि यह कांग्रेस की सरकार वर्ष 2017 के चुनाव में रिपीट करेगी। I will tell you why. मैं आपको बताता हूँ। पहली बात विकास की है। जिस तरह यहां विकास हो रहा है वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, दूसरी बात यह है कि लोग अपने आपको माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के संरक्षण में प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं यह सारे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यह एक या दो जगह की बात नहीं है। लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं और तीसरी बात यह कि अब यह फाइनली डिसाइडेड है कि जब चुनाव होंगे, तो उसके बाद मुख्य मंत्री भी इनको ही बनना

है। तो ये इस तरह के कुछ फैक्टर्ज हैं कि यह सरकार रिपीट होने वाली है और अब मैं इस बारे में फैक्ट्स पर बात करना चाहूंगा। अब रही बात विकास की, तो मैं ज्यादा विस्तार में न जाता हुआ यही कहूंगा कि जो यह हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें सारी चीजें बहुत विस्तार से लिखी हुई हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, उद्योग, ऐग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, पीने-का-पानी इत्यादि के क्षेत्र में जितना विकास हुआ है वह इसमें दिखाया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में विकास के बारे में पूरा लिखा हुआ है, तो मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, अब केन्द्र का धन्यवाद करने की बात रही, तो आज केन्द्र में जो स्कीम्ज चल रही हैं जो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हम यहां हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित कर रहे हैं उनका यह आलम है

एम.एस. द्वारा जारी

07/03/2017/1250/MS/AG/1

श्री नन्द लाल (मुख्य संसदीय सचिव)जारी-----

जैसे यू0पी0ए0 सरकार ने एक "मनरेगा" स्कीम शुरू की थी वही स्कीम आज चल रही है। हम डॉ0 मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने यह स्कीम चलाई। It is not a scheme only. It is an Act. यह कानून है। उस कानून में लिखा है कि 100 इम्प्लॉयमेंट ग्रांटिड है। और तो और यहां तक सोच है कि अगर तीन किलोमीटर के बाहर आदमी काम करने को जाता है तो he will get 10 per cent extra allowances. चार बहनें अगर बच्चे वाली हैं they go for work तो पांचवीं बहन को उसके लिए वेजिज मिलना है। देखो, ऐक्ट में क्या-क्या प्रावधान है।

सर्वशिक्षा अभियान के अंदर crores of rupees are being pumped into the State for better infrastructure. एजुकेशन में। -(व्यवधान)- Just a second. उसको चलाने के लिए और अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए वह पैसा दिया जाता है। बस, वही स्कीमें आगे चल रही हैं। यहां तो खाली मन की बात हो रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में जो चुनाव हुए थे उस समय हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री

हैं वे कैसे प्रधानमंत्री बनें। उनके प्रधानमंत्री बनने की जो दो-तीन वजहें मैं समझता हूँ वे ये हैं। पहली, उस समय बड़ा भ्रामक प्रचार पूरे हिन्दुस्तान के अंदर हुआ। इतना भ्रामक प्रचार for which they are trained. उसके लिए क्या हुआ कि भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह कर दिया That is one. ऐसे लुभावने सपने दिखाए कि लोग गुमराह हो गए। (Interruption) I have got every right to say this thing.

डॉ० राजीव बिन्दल: अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

Speaker: He is making a speech, you see. There is no Point of Order when he is speaking. When your turn will come, you can speak your point.

डॉ० राजीव बिन्दल: अध्यक्ष जी, हमने केवल महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोला है। हमने हिमाचल से हटकर एक भी शब्द नहीं बोला है।

Shri Nand Lal (Chief Parliamentary Secretary): And you can speak against the Chief Minister. And you have every right to speak against the Chief Minister.

07/03/2017/1250/MS/AG/2

अध्यक्ष: आप भी ऐसे ही बोल रहे थे। (Interruption) Let him speak.

श्री नन्द लाल (मुख्य संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। शिक्षा की यहां बड़ी बात हो रही है। हमारा एक स्कूल काशापाठ के अंदर था। उस सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में no teacher, एक टीचर था he got promoted, वह भी बाहर चला गया। काशापाठ के स्कूल से बच्चों को विद्धो करके उनको बोर्ड के एग्जाम के लिए बाहर जाना पड़ा और उन्होंने बाहर से एग्जाम दिए। इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती है? This is in the education. आज शिक्षा की ये लोग ऐसी बात करते हैं कि शिक्षा का बहुत बुरा हाल है as if during their time it was much better. ये किस बात की बात कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी के प्रयास हैं कि नये स्कूल खुले और स्कूलों को अपग्रेड भी किया जाए। You have accessibility to education. आज हिमाचल के लोगों को शिक्षा का जो सबसे बड़ा असर हुआ है वह है असैसिबिलिटी। आपको

एजुकेशन तक असैसिबिलिटी मिली। दूर-दराज के गांवों में स्कूल मिले। आप आज राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें पढ़ने का हक है लेकिन स्कूल भी उपलब्ध होने चाहिए। हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतने स्कूल बनें और इतने स्कूलों को अपग्रेड किया और इतने कॉलेजिज बनें। जो इंटीरियर में संस्थान खुले, उनके लिए भी हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए। इसके अलावा स्कूलों में जो सुविधाएं हैं, जैसे बच्चों की वर्दी की बात करो, बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की बात करो या मुफ्त में यात्रा की बात करो। जो बेसिक एमीनिटीज जैसे टायलेट्स हैं, पीने-का-पानी everything is made available. मैं आपको बता दूँ कि प्राइमरी स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेट है that is less than one per cent. इसी तरह से जो आपका इनरोलमेंट रेट है between 16 to 14 years of age, it is 99.9 per cent which is highest in the country. It is a record itself. इसी तरह से ग्रांट जो पी0टी0ए0 या दूसरे टीचर्स को जो मिलती है उसको एन्हांस किया गया। Thousands of people have been promoted. उनको प्रमोट किया गया और नई भर्तियां हो रही हैं। इसलिए इस तरह से शिक्षा के बारे में कहना अनुचित होगा। अगर आप हैल्थ की बात करो तो We are number one in the country today.

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

07.03.2017/1255/जेके/एजी/1

श्री नन्द लाल (मुख्य संसदीय सचिव)-----जारी-----

इन्होंने कहा कि इनको भी 4 अवार्ड मिले, अच्छी बात है। That's good. हालत तब भी देखनी थी कि अवार्ड मिलते हुए what was the condition? हैल्थ की अगर बात करो कि हमारे यहां पर कितने नये हैल्थ सब सैन्टर्ज, प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज, सी0एच0सी0 खुले और आप डॉक्टर्स की बात करते हैं कि डॉक्टर कम थे, सरकार ने एक साल के अन्दर 155 डॉक्टर, 426 स्टॉफ नर्सिज, 16 स्पेशलिस्ट अंगेज किए हैं और 40 ऑपेशन थियेटर अटैंडेंट अंगेज किए हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। There was a time हमारे रामपुर में जो रैफरल हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के अन्दर it has got a

sanction of 31 Doctors. और वहां कभी भी 10-11 से ऊपर डॉक्टर नहीं गए हैं। They have to work round-the-clock. अध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत थी कि we didn't have Gynaecologist for good three years. तीन सालों से वहां पर गाईनाकोलोजिस्ट नहीं थी। उसके बाद यहां से डैपुटेशन में कोई जब जाता था उस तरह से वहां पर काम होता था। The kind of suffering the people had there, particularly, ladies. जो हमारी बहनें थी। वहां इस तरह का आलम था। आज हम यह कह रहे हैं कि डॉक्टरों की भर्ती वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से हो रही है। जिस तरह से भी अंगेंज किया जा रहा है इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी क्रांति आई है। उसके लिए भी हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब जो सब चर्चा कर रहे हैं नाहन, चम्बा, हमीरपुर, उसके लिए भी 150 करोड़ रूपए is being released. और इसके साथ ही बर्थ रेट कैसे इम्प्रूव हुआ। हिमाचल में बर्थ रेट 16.4 और नेशनल का 6.21 It is less than that. जो मॉर्टैलिटी रेट है वह 28 है जो नेशनल का है वह 42 है। फर्टिलिटी रेट 1.7 नेशनल लैवल पर 2.8 है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन सभी फील्ड में इस तरह की बात हुई है। अब मैं होर्टिकल्चर की बात करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि होर्टिकल्चर में यह जो पायलट प्रोजैक्ट चलाया है जिससे कि एंटी हेल गन लगाई गई। तत्कालीन जो बागवानी मंत्री थे अंधा बांटे रेवड़ी, मुड़-मुड़ अपनों को दे। तीन की तीन मशीनें इन्स्टॉल की गई in

07.03.2017/1255/जेके/एजी/2

that particular area. Why not in Kinnaur, Rampur, Rohru and Mandi? वे भी तो सेब उगाते हैं। तीन के तीन प्रोजैक्ट वहां पर लगा दिए गए। फिर उसके बाद दो मशीनें उसमें खराब थी और एक मशीन शायद आज भी फंक्शनल है। रॉडार भी खराब हो गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा(व्यवधान)..... मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। I will come to that. Hold on. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी यह सोच है कि जो एंटी हेल नैट्स है that is the solution to the problem. क्योंकि जो

एंटी हेल गन है, लोग लगा रहे हैं, कर रहे हैं। जो एंटी हेल गन है, मैं आपको बताना चाहूंगा it has got an umbrella in that. तीन किलोमीटर के बाहर का जो एरिया है उसको तो सफ़र करना ही है। जो एंटी हेल नैट्स पर जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है 80 प्रतिशत सबसिडी के साथ उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे। वह भी एक बहुत बड़ा काम है और लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। उनको इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। हमारी जो ट्रांसपोर्ट की फ्लीट है, वह बहुत बढ़ गई है। ट्रांसपोर्ट की फ्लीट के अन्दर आज 2,700 एक्स्ट्रा बसिज का फ्लीट है। 300 नई बसें इसमें आई है। 88 सुपर डिलक्स कोचिज बसें हैं। 20 लग्जरी बसिज हैं। इस तरह से बहुत सारा विकास हर तरफ से होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ यह जो महामहिम् राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था उसका पुरज़ोर समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

07.03.2017/1255/जेके/एजी/3

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवादी हूं कि माननीय सदस्य ने मेरे चुनाव क्षेत्र का भी ध्यान रखा और बमसन लगवालती, पूरा नाम उसका बमसन-लगवालती वॉटर स्कीम है। उसका जिक्र किया। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि उसकी पहली स्टेज का उदघाटन वर्ष 1978 में श्री शांता कुमार जी ने किया था।

श्री एस०एस० द्वारा जारी-----

07.03.2017/1300/SS-AS/1

प्रो० प्रेम कुमार धूमल क्रमागत:

वह जनता पार्टी गवर्नमेंट में लगी थी और जिस अपग्रेडेशन का आप ज़िक्र कर रहे हैं वह हमारी सरकार ने करवाई थी। महेशक्वाल, ऊहल, मतलाना, संगरोह चार स्टेजिज़ पर हो गया था। संगरोह के उद्घाटन के बाद, सरकार बदलने के बाद मुख्य मंत्री महोदय और आई०पी०एच० मिनिस्टर गए और वहां से आधा किलोमीटर आकर एक और पत्थर अवाहदेवी में लगा दिया। इतना ही योगदान है पत्थर लगाने का। आप अपना चुनाव क्षेत्र भूल गए। आपने कहा कि पिछली सरकार ने मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ नहीं किया। दत्तनगर आपके चुनाव क्षेत्र में है। वहां करोड़ों रुपये का मिल्क चिलिंग प्लांट लगा। जो दूध आप आनी, रामपुर, कुमारसैन से इकट्ठे करके पाऊंडर बनाने के लिए पंजाब लेकर जाते थे, वह चिलिंग प्लांट हमने वहां करोड़ों रुपये का स्थापित किया। शुरू भी हमने किया और उद्घाटन भी हमने किया। ननखड़ी में कॉलेज दिया। --(व्यवधान)-- क्या तैयार हो गई थी? उसका फाउंडेशन और उद्घाटन भी मैंने ही किया था, तब आपने क्या तैयार किया? --(व्यवधान)-- प्लीज़ बैठिये, अभी मैं बोल रहा हूं। मेरे बाद आप बोलयेगा। आई०पी०एच० का डिवीजन हमने बनाया। ननखड़ी में कॉलेज हमने दिया। तुमने कैंसल किया और दो महीने के बाद फिर नोटिफाई किया। रामपुर का हॉस्पिटल शहर से बाहर था। शहर के लोगों ने एवं आप एम०एल०ए० होते हुए उनके साथ थे और डिमांड रखी कि हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, ऑटो करके जाएं या कैसे जाएं तो हमने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रामपुर शहर में दिया। आपने सैंट्रली स्पोर्ट्स स्कीम्ज़ का ज़िक्र किया कि वह तो देना ही पड़ता है। आपको यह याद नहीं होगा कि स्पेशल कैटेगिरी का स्टेट्स कांग्रेस सरकार ने हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर का छीना था, जिसमें 90:10 का शेयर मिलता था। यह मोदी सरकार ने आकर हमें फिर से दिया है और 17 सैंट्रली स्पोर्ट्स स्कीम्ज़ में मिलता है। --(व्यवधान)-- तब ये एम०एल०ए० नहीं थे जब बाढ़ आई थी। जब सतलुज त्रासदी हुई थी तब आप एम०एल०ए० नहीं थे, तब आप सोनिया जी के साथ सर्विस करते थे। लेकिन बहुत कुछ हुआ है। इस तरह नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। यह तो मैंने मोटे-मोटे काम गिनाये हैं लेकिन आप भूलियेगा नहीं, धन्यवाद।

07.03.2017/1300/SS-AS/2

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जो भी सरकार होती है वह अपने वक्त में काम करती है। जब आपकी सरकार हुई तो उसने भी कुछ काम किया है। मगर मैं यह कहना चाहता हूँ, जहाँ तक आपने स्पैसिफिक बमसन-लगवालती स्कीम के बारे में कहा, उसका कंट्रैक्ट हमारे वक्त में हुआ। हाँ, हमारे वक्त में हुआ और हमारे वक्त में स्कीम बनी। He may have conceived this Scheme, I don't know. Question is the construction work, the contract tendering process and the construction work; and I was very happy that two young people from the Hamirpur took the contract and they did a wonderful work. It is the first scheme जोकि कम्प्यूराइज्ड है और समय पर उन्होंने तैयार की है। --(व्यवधान)-- यह कम्प्यूराइज्ड है और वह भी होगी। It is computerized. I don't want to listen और उसके बाद उद्घाटन हुआ। इस स्कीम का शिलान्यास भी मैंने रखा और जब श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने उद्घाटन किया तो मेरा जो शिलान्यास का पत्थर सड़क पर अवाहदेवी के पास लगा था, उसे उखाड़कर ढाल के ऊपर जहाँ पानी के बड़े-बड़े टैंक बने थे उसके बीच में लगा दिया।

जारी श्रीमती के0एस0

07.03.2017/1305/केएस/एस/1

मुख्य मंत्री जारी---

मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारी सरकार फिर आई, खुद विभाग ने धार के ऊपर दो टैंक्स के बीच में जो मेरा शिलान्यास का पत्थर लगा रखा था, उसको उठाकर मेन रोड़ के ऊपर लाया। यह फैक्ट है परन्तु मैं यह कहता हूँ कि may be he conceived the scheme, I don't say that but it was tendered in my time, it was completed in

my time, it was ready in my time और जब उसके उद्घाटन का समय आया Hon'ble Member became the Chief Minister and he inaugurated it. It is a fact.

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री को दोष नहीं देता, मैमरी कई बार ऐसा ट्रिक प्ले करती है। मैं आज चुनौती देता हूँ कि एक कमेटी बनाएं जो पता करें कि इनके शिलान्यास का पत्थर वहां लगा है या उद्घाटन का पत्थर लगा है। ये कह रहे हैं कि मैंने शिलान्यास किया था।

मुख्य मंत्री: शिलान्यास मैंने किया, उद्घाटन आपने किया और जो मेरा शिलान्यास का पत्थर था जो अवाह देवी के पास मेन रोड़ पर लगा था, उसको वहां से उखाड़कर आपने जो स्कीम बनी उसके लिए धार पर जो बड़े-बड़े टैंक बने थे, दो टैंकों के बीच में उसको लगाया जहां पर कोई उसको न देख सके। I prepared to say in your presence in Hamirpur itself, I saw it so many times but I don't mind जो आपने किया, वह आपकी अपनी इच्छा है। I am not against it परन्तु जो मैं कह रहा हूँ। I am saying on oath that what I have said is true.

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी को ये ही पता नहीं है कि इन्होंने किया क्या था? शिलान्यास किया था या उद्घाटन किया था। यह स्कीम हमारे समय में शुरू हुई और इनके जो मंत्री उस समय साथ थे, श्री कौल सिंह जी कह रहे हैं कि आपने उद्घाटन किया था और ये कह रहे हैं कि मैंने शिलान्यास किया था।

07.03.2017/1305/केएस/एस/2

मुख्य मंत्री: नहीं, नहीं। आपने उद्घाटन किया था और मैंने शिलान्यास किया था। It is fact of history. All right let the Speaker enquire into this matter.

Prof. Prem Kumar Dhumal: Yes, I challenge . Let there be a Committee of the House, अध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है कि वाटर का सोर्स क्या है? (व्यवधान)

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं तो उस सोर्स तक भी जा कर आया हूँ। मुझे पता है कहां से पानी आया है। वहीं से सरकाघाट को भी पानी गया है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: आप हाऊस को इस तरह मिसलीड मत करें। वह पानी जंगलबैरी से आता है, ब्यास के किनारे से लेकिन नदी से नहीं आता। वहां ट्यूबवैल हमने खुदवाएं। ट्यूबवैल का वह प्योर पानी है और मैंने जैसे कहा महेशक्वाल ऊहल, मतलाना और संगरोह, अवाहदेवी से आधा किलोमीटर पहले तक मैंने उद्घाटन कर दिया हुआ था। ये गए, इन्होंने उद्घाटन कर दिया, पत्थर लगाया जो इन्होंने कहा। वह पत्थर वहां से हटा और बिल्कुल हटा क्योंकि वह जहां बस स्टैंड बना था उसके बीच लगा दिया। वाटर टैंक सड़क के किनारे लगा हुआ है। आज भी वहीं है जहां पहले था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री को ऑब्सेशन है। यह कोई कांगड़ा सेंट्रल कॉप्रेटिव बैंक, धर्मशाला का पत्थर थोड़े ही है कि काट कर छोटा कर दो।

Chief Minister: Let's hold this discussion here. I request Hon'ble Speaker to send a Committee from here to enquire into this matter. I stand by it, what I have said.

Prof. Prem Kumar Dhumal: Yes, you can have. Just enquire into it you have the Government and judiciary at your disposal आपने शिलान्यास नहीं किया, आपने अवाहदेवी में आ कर उद्घाटन का पत्थर लगाया।

07.03.2017/1305/केएस/एस/3

मुख्य मंत्री: बिल्कुल नहीं। बमसन लगवाल्ती स्कीम का शिलान्यास मैंने किया और जब बना तो आपने उसका उद्घाटन किया। जिसका पत्थर आज भी लगा है और जो मेरा शिलान्यास का पत्थर था आपने धार के ऊपर दो बड़े-बड़े टैंकों के बीच में लगाया और उसके बाद आई.पी.एच. डिपार्टमेंट ने वहां से उठाकर मेन रोड के ऊपर लाया है।

प्र० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, इनको यही पता नहीं है कि शिलान्यास कहाँ होता है और उद्घाटन कहाँ होता है? जो लास्ट स्टेज होती है वहाँ उद्घाटन होता है, शिलान्यास नहीं होता। उसका शिलान्यास जंगलबैरी में है। (व्यवधान) इनको पता ही नहीं है कि पानी नदी के किनारे से आ रहा है, ट्यूबवैल से आ रहा है। तो उद्घाटन वहाँ होगा? वहाँ तो शिलान्यास होगा।

श्रीमती अ० व० द्वारा जारी---

7.3.2017/1310/av/dc/1

श्री प्रेम कुमार धूमल :----- जारी

शिलान्यास तो लास्ट स्टेज पर जहाँ आपने अवाहदेवी में जाकर किया है वहाँ से बमसन के लिए नहीं मेवा क्षेत्र को पानी जाता था, आपने उसका उद्घाटन किया है। आपको स्कीम का ही पता नहीं है। आपको नाम ही पता नहीं है और यह भी पता नहीं है कि कब शुरू हुई, क्या हुआ।

मुख्य मंत्री : मुझे पूरा पता है। मैं हिमाचल के एक-एक चप्पे को अच्छी तरह से जानता हूँ।
You can't block me like that. You can't block this House.

Speaker: Shri Nand Lal ji you want to say something.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री नन्द लाल) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने ननखड़ी कालेज की बात की है। वह कालेज शायद इलैक्शन से दो महीने पहले चालू किया गया था। जिसमें रामपुर कालेज से एक लैक्चरर को पूल किया गया तथा वहाँ पर कुछ बच्चे भी लाये गए। मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज वहाँ पर एक नियमित कालेज

बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और कालेज चल रहा है। आप (श्री प्रेम कुमार धूमल) एक बात कहना भूल गये कि आपने खड़ान में एक आईटीआई भी खुलवाया था। उसके लिए भी there was no infrastructure available, सिर्फ खाली अनाउंसमेंट हो गई। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सरकार बनने के बाद वहां जगह का चयन करके बिल्डिंग का प्रोविजन करवाया और आज वहां पर आईटीआई का काम शुरू हो गया है।

Speaker: Now this House is adjourned for lunch up to 2:15 p.m.

07/03/2017/1420/टीसीवी/एजी/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.20 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्ष: महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समय का ध्यान रखें, क्योंकि आज 20 माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेने वाले हैं। इसलिए आप 10-12 मिनट में अपनी बात रखें तो ज्यादा अच्छा है। अब श्री रणधीर शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रणधीर शर्मा: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस साल के इस पहले सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1 मार्च, 2017 को यहां पर अभिभाषण रखा, जिस पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत माननीय सदस्य श्री जगजीवन पाल जी ने और उसका अनुसमर्थन श्री संजय रतन जी ने किया। उस प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे भी समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण सरकार की एक साल की उपलब्धियों पर आधारित है और अगर इन उपलब्धियों पर नज़र दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि सही दृष्टि से प्रदेश में जो विकास होना चाहिए था, वह विकास करने में यह सरकार असफल रही है। हमारे देश के प्रधान मंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री बनने पर कहा था कि हमारा देश तभी विकसित माना जाएगा, जब हमारे गांव विकसित होंगे और गांव तभी विकसित माने जाएंगे, जब गांव सड़कों से जुड़ेंगे।

श्रीमती एन0एस0- - - द्वारा जारी।

07/03/2017/1425/ ns/ag /1

श्री रणधीर शर्मा----- जारी

इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में देश के बड़े गांव से लेकर छोटे गांव तक हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' दी। मैं यह समझता हूँ कि यह एक योजना ही नहीं बल्कि देश के लिए एक नई सोच थी। देश की सरकारें गांव को सड़क से जोड़ने के लिए प्राथमिकता दें और इस दृष्टि से कार्य करें कि जल्दी-से-जल्दी हमारा हर गांव सड़क से जुड़े। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें तो इस दृष्टि से यह सरकार नाकाम रही है। हालांकि घोषणा पत्र में इन्होंने वायदा किया था कि हम पांच साल में 7500 किलोमीटर सड़क बनायेंगे। परन्तु चार साल पूरे होने पर इन्होंने उपलब्धियों पर जो बुकलैट छापी है, उसमें चार साल में मात्र 1721 किलोमीटर सड़क बनी है। जो यह दर्शाता है कि गांवों को सड़कों से जोड़ना इनका एजेंडा ही नहीं है। गांव का विकास करना इनके एजेंडे में ही नहीं है। इसलिए हम विधायकों की चार साल की विधायक प्राथमिकताओं की डी0पी0आर्ज़0 नहीं बनी हैं। चार साल में हमने आठ-आठ सड़कें विधायक प्राथमिकता में डाल दीं परन्तु एक भी डी0पी0आर0 मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो नहीं बनी है। अधिकतर विधायकों का यही हाल है। इसी तरह गांव के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, पीने का पानी, सिंचाई इन सभी सुविधाओं का होना अति आवश्यक है। परन्तु इस दृष्टि से भी यह सरकार काम करने में असफल रही है। क्योंकि इस दृष्टि से भी जो हमने विधायक प्राथमिकताएं दी हैं उसमें किसी की भी डी0पी0आर0 यह नहीं बना पायें हैं। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक सिंचाई योजना का शिलान्यास मेरे विधान सभा क्षेत्र में किया है। मुझे लगा कि शायद एक विधायक प्राथमिकता को तो पैसा मिल गया होगा। परन्तु अभी इस विधान सभा

सत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक प्रश्न के जवाब में आया तो मुझे पता चला कि उस सिंचाई योजना की डी0पी0आर0 भी 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' में भेजी हुई है और वह डी0पी0आर0 भी ठीक नहीं बनी है इसलिए वह वापिस आ गई है। उसमें भी कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है।

07/03/2017/1425/ ns/ag /2

इसका अर्थ यह है कि चार सालों में एक भी योजना को एक भी पैसा इस सरकार ने उपलब्ध नहीं करवाया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सरकार विकास करने में पूरी तरह से असफल रही है। मेरा इस सरकार पर यह आरोप है। जो यह सरकार काम कर रही है मुझे लगता है कि उसे विकास मानना सही नहीं है। यह लोग फील्ड में जाते हैं तो लोग मांग करते हैं कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमारा मिडल स्कूल है पर यहां पर अध्यापक नहीं हैं और यह वहां अध्यापक देने की बजाए उस मिडल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल कर देते हैं। लोग मांग करते हैं कि हमारी पी0एच0सी0 में डॉक्टर नहीं है आप डॉक्टर उपलब्ध करवाओ। मुख्य मंत्री जी वहां की पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 प्रमोट कर देते हैं। जिसके कारण समस्या का समाधान नहीं हो रहा है बल्कि समस्याएं ओर उलझ रही हैं क्योंकि आप बिना मांग के स्कूल, स्वास्थ्य संस्थान अपग्रेड कर रहे हैं और वहां पर न आप टीचर दे रहे हैं तथा न ही आप डॉक्टर दे रहे हैं। जितने ज्यादा आप इंस्टीच्यूट खोलेंगे उतनी ही ज्यादा मांग होगी। अध्यक्ष महोदय, पटवार सर्किलों में पटवारी नहीं हैं। हम पटवारी मांगते हैं तो यह तहसीलें खोल देते हैं, एस.डी.एम. ऑफिस खोल देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनका तो यह हाल है कि लोगों को चाहिए लंगोटी यह देते हैं टोपी। अब लंगोटी का काम टोपी तो नहीं कर सकती है। जहां लोगों को टीचर चाहिए वहां टीचर ही काम करेगा वहां स्कूल अपग्रेड करके कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है उसको उलझा रही है। यह सरकार बिना डिमांड के एस.डी.एम. ऑफिस खोल रही है। दूसरी राजधानी की चर्चा हो

रही है। कैबिनेट से अप्रूवल हो गई है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा-सा राज्य है और यहां पर दूसरी राजधानी का होना कितना जरूरी है इसका हम सबको पता है। हम कोई राजधानी का विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री आर०के०एस०---- द्वारा जारी ।

07/03/2017/1430/RKS/AS/1

श्री रणधीर शर्मा....जारी

आपकी आर्थिक स्थिति मज़बूत है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप धर्मशाला ही क्यों, मण्डी में भी राजधानी खोल सकते हैं। लेकिन एक तरफ आप प्रदेश को कर्जा लेकर चला रहे हैं, कर्ज की मार से डूबो रहे हैं। कर्मचारियों को तनखाह देने के लिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। दूसरी तरफ बिना मांगे तहसीलें बनाई जा रही है। बिना जरूरत के स्कूल अपग्रेड किए जा रहे हैं। बिना जरूरत के पी.एच.सीज. और यहां तक कि दूसरी राजधानी भी खोल दी गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दूसरी राजधानी किस तरह की खोली जाएगी। दूसरी राजधानी का मतलब आज सुबह माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी ने बताया। मैं भी जम्मू-कश्मीर में रहा हूं। वहां 6 महीने श्रीनगर में राजधानी रहती है और 6 महीने बाद दरबार मूव होकर जम्मू आ जाता है। मुख्य मंत्री, मंत्री, सभी डायरेक्टर 6 महीने जम्मू में ही रहते हैं। पूरी-की-पूरी राजधानी श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट हो जाती है। क्या आप ऐसी राजधानी बनाने वाले हैं? आप स्पष्ट करें कि क्या आपकी राजधानी एक अधिसूचना है? आप उसी पुरानी बिल्डिंग को जो डी.सी. के अंडर है, जी.ए.डी. के अंडर लेने का प्रयास करेंगे और राजधानी बनाने का क्रेडिट ले लेंगे जोकि लोगों के साथ एक धोखा है। यह लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। मुख्य मंत्री जी का राजनीति में बहुत बड़ा अनुभव है और आप छठी बार के मुख्य मंत्री हैं। विचार कीजिए कि क्या हमारा प्रदेश इस तरह के

खर्च को बर्दाश्त कर सकता है? आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे आज एक बिल्डिंग, कल दूसरी, परसों तीसरी बिल्डिंग। शिमला और धर्मशाला के मौसम में भी कितना अंतर है। इन चीजों पर भी आप जरूर विचार कीजिए। मेरा मानना है कि यह दूसरी राजधानी लोगों के लिए नहीं खोली जा रही है, लोगों की कोई मांग नहीं थी। यह दूसरी राजधानी वोटों के लिए खोली जा रही है। जो आरोप आपको क्षेत्रवाद के लगते रहे हैं, मल्होत्रा कमीशन की रिपोर्ट में आपके विधान सभा क्षेत्र में जो क्षेत्रवाद आपके द्वारा फैलाया गया या आपके मुख्य मंत्री रहते हुए आपकी नीतियां जो क्षेत्रवाद के आधार पर रही, उन पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के लॉलीपॉप

07/03/2017/1430/RKS/AS/2

कांगड़ा जिला को देते रहे। आप सोचते हैं कि लोग इस तरह से गुमराह होकर आपको वोट डाल देंगे? मुख्य मंत्री जी मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि आप वर्ष 1993 से 1997 में भी मुख्य मंत्री रहे। उस समय भी आपने कांगड़ा के लोगों को बरगलाने के लिए शीतकालीन प्रवास शुरू किया। आपको लगा शीतकालीन प्रवास से हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। वर्ष 1998 में विधान सभा का चुनाव हुआ। इतिहास गवाह है आप सरकार से बाहर चले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। उसके बाद आप वर्ष 2003 में दोबारा सत्ता में आए। आपने फिर दोबारा वही रणनीति खेली। आपने धर्मशाला में विधान सभा का सत्र लगाना शुरू कर दिया। आपने इस सत्र को कॉलेज में शुरू किया परन्तु आज विधान सभा परिसर पर 50 करोड़ रुपये प्रदेश का खर्च हुआ है। उस विधान सभा परिसर का कितने दिन उपयोग होता है। साल में पांच दिन। पांच दिन प्रयोग करने के लिए सरकार का 5-7 करोड़ रुपये खर्च हो जाता है। उसका कितना यूज़ है, यह आप जाने। आपने यह क्या सोचकर किया, यह भी आप जाने। सच्चाई यह है कि वर्ष 2003 और 2007 के बीच यह विधान सभा वहां पर खोली और वर्ष 2007 के विधान सभा चुनाव में भी आप सत्ता से बाहर हो गए। यह आपने वोटों के लिए किया होगा। अब आपने राजधानी की नोटिफिकेशन कर दी और लोग आपको सत्ता में आने नहीं देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं जब विधान सभा चुनाव होंगे तो पहले की तरह फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप उधर से इधर आएंगे। आप जो काम करते हैं उससे लगता है कि आप क्षेत्रवाद की

राजनीति करते हैं। यही नीतियां आपके क्षेत्रवाद को प्रमोट करती हैं। कल यहां चर्चा हुई और आपने खड़े होकर कह दिया। I love Kangra more than Shimla. मुख्य मंत्री जी का ब्यान ही क्षेत्रवाद पर आधारित है। मुख्य मंत्री जी के लिए हर जिला एक समान है। मुख्य मंत्री कहेगा। I love Kangra क्योंकि वहां की 16 सीटें हैं। हमारे बिलासपुर जिला का क्या दोष है, अगर वहां पर 4 सीटें हैं? क्या मुख्य मंत्री जी सीटों के हिसाब से विकास करेंगे? क्या मुख्य मंत्री सीटों के हिसाब से प्यार करेंगे? आपने कांगड़ा जिला से प्यार की बात कर दी, बिलासपुर जिला से आपको क्या दुश्मनी है?

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

07.03.2017/1435/SLS-AS-1

श्री रणधीर शर्मा ...जारी

क्यों नहीं आपने बिलासपुर से कोई मंत्री बनाया? राजेश धर्माणी जी न तो सी.पी.एस. हैं, न एम.एल.ए. हैं। वह कहते हैं कि मैंने त्यागपत्र दे दिया जबकि आप कहते हैं कि मैंने त्यागपत्र स्वीकार ही नहीं किया। वह अपनी गाड़ी लेकर घूमते हैं। लोग हैरान हैं कि उनको सी.पी.एस. माने या न मानें। बम्बर जी आपके चेहते हैं। उनको भी आपने कुछ नहीं दिया और वह अपने ढंग से लगे हुए हैं। इसलिए बिलासपुर से दुश्मनी क्यों? आप कहते हैं कि मैं क्षेत्रवाद नहीं करता जबकि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र के बरसी से आई.पी.एच. की चंगर एरिया मिड इरिगेशन प्रोजैक्ट की डिविजन उठाई और ठियोग के मतियाणा में शिफ्ट कर दी। क्या यह क्षेत्रवाद नहीं है? क्या यह नहीं दिखाता कि आपको किस जिला से प्यार है? क्या यह नहीं दिखाता कि आप कहां अन्याय कर रहे हैं? आप कांगड़ा से प्यार दर्शाते हैं लेकिन कांगड़ा को देते क्या हैं? लॉलीपाप से जनता खुश नहीं होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं तब मानूं अगर आप कांगड़ा के नेता को मुख्य मंत्री प्रोजैक्ट कर दें। तब तो कहते हैं कि मुख्य मंत्री मैंने ही बनना है। सातवीं बार भी मैंने ही बनना है चाहे हालात जो मर्जी हों।

कांगड़ा वाले लड़ा दिए; आपस में उनको लड़ाते रहे क्योंकि मुख्य मंत्री मैंने ही बनना है। मैं न बनूं तो मेरा बेटा बने पर और कोई न बनें। ये व्यवस्था आप कर रहे हैं और ऐसी राजनीति चला रहे हैं। कांगड़ा से मुख्य मंत्री भी हमने दिया है और केंद्र का मंत्री भी हमने दिया है। कांगड़ा में विकास भी हमने किया है। गलती से आपको पिछली बार सीटें आ गई होंगी, इस बार कांगड़ा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा और हमारी सरकार बनेगी।

मुख्य मंत्री : आप ये सुनैहरी सपने देखते रहें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने यह अभिभाषण पूरा पढ़ा है। इस अभिभाषण को अगर ढंग से पढ़ें तो इसकी 75 प्रतिशत उपलब्धियां केंद्र सरकार के सहयोग से हैं। कहीं स्टेट का 10 प्रतिशत है, कहीं 25 प्रतिशत है और बाकी सारा पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से है। आप इसे पढ़ लें। परंतु एक भी लाइन,

07.03.2017/1435/SLS-AS-2

एक भी लाइन आप धन्यवाद की नहीं लिख सके। हालांकि जो इसमें लिखा है वह बहुत कम है। इसके अलावा और बहुत कुछ है। चाहे वह नेशनल हाईवेज हैं या स्पेशल कैटेगिरी स्टेट का स्टेटस है, चाहे वह रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा है या चाहे वह 234 परसेंट की फाइनेंशियल बढ़ोतरी है। उसका धन्यवाद तो क्या करना, आप जिन उपलब्धियों का जिक्र करते हैं उनका भी धन्यवाद नहीं करते। फिर आप कहते हैं कि संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है और इसमें मदद करनी पड़ती है। हमने तो मदद कर दी, आप क्या कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि क्लास-3 और क्लास-4 के इंप्लॉईज की रिक्तमैंट में इंटरव्यू नहीं होंगे। जब केंद्र सरकार निर्णय लेती है तो प्रदेशों को उस निर्णय पर चलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार क्यों आपने वह निर्णय नहीं लिया? क्यों आज

आप क्लास-3 और क्लास-4 की भर्तियों इंटरव्यू के माध्यम से कर रहे हैं? इसलिए कि अपने भाई-भतीजों को भरना है। इसलिए कि उसमें करप्शन करनी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से इस सरकार में भर्तियां हो रही हैं। हालात आपके सामने हैं। यहां पर नर्सिज की भर्तियां हुईं और उन भर्तियों में पोस्टें 314 ऐडवर्टाइज होती हैं। उसके बाद 116 नर्सिज के लिए और एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है। चलो आप भर्ती कर रहे हो, इसलिए 430 की कर लो। जब रिजल्ट निकलता है तो चोर दरवाजे से 553 नर्स भर्ती कर दी जाती हैं और लोगों को पता ही नहीं है। यह भर्तियां कैसी और किस ढंग से हो रही हैं।...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। जो भी अप्वायंटमेंट होती है वह नोटिफाई होती है so many posts are being filled. यह आप गलत बात कर रहे हैं। जिस आदमी को बेसिक रूलज मालूम नहीं हैं उसे इस विषय पर बहस करने का कोई अधिकार नहीं है।

07.03.2017/1435/SLS-AS-3

श्री रणधीर शर्मा : आपने कोई खंडन नहीं किया। यह दसतक में छपा और आपने यह सारा कारनामा किया। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, आंकड़े इसके गवाह हैं। आर.टी.आई. की सूचना आपके अधिकारियों की दी हुई है। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : जो भी भर्तियां होती हैं, they are notified और भर्तियां चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होनी हैं चाहे वह सुबोर्डिनेट सर्विसिज बोर्ड, हमीरपुर के द्वारा होनी हैं, they are all notified. उसके आधार पर ही प्रार्थना-पत्र दिए जाते हैं। भर्तियां नियमों के मुताबिक होती हैं। उनके लिए इम्तहान और इंटरव्यू होते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रणधीर शर्मा : नर्सिज की और गार्डों की भर्ती डिपार्टमेंट कर रहा है।

जारी...श्री गर्ग जी

07/03/2017/1440/RG/DC/1

श्री रणधीर शर्मा----क्रमागत

सर्विस सलैक्शन बोर्ड कहां से भर्ती कर रहा है? आप अपनी सरकार का तो ध्यान रखें।

मुख्य मंत्री : बात ऐसी है कि सरकार का जो प्रोसीजर है कि कौन सी भर्ती लोक सेवा आयोग और कौन सी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग और कौन सी भर्ती विभागीय समिति के द्वारा की जानी है, इसके लिए नियम बने हुए हैं। ये नियम पहले भी थे, आज भी हैं और जब आपकी सरकार थी तब भी यही नियम थे।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब यह समय मेरे समय में न जोड़ें। मैं गाड्ज की भर्ती की बात कर रहा था। गाड्ज की भर्ती वन विभाग ने की। मैं बिलासपुर के परिणाम आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं यह अटैस्ट करके कॉपी सदन में रख दूंगा। आप नौकरियों में इन्टरव्यू क्यों कर रहे हैं यह आपकी पोल खोलता है।

अध्यक्ष महोदय, 13 सामान्य वर्ग के गाड्ज भर्ती हुए। इसमें जो ऐकैडमिक मार्कज और ऐक्स्ट्रा करिकुलर ऐक्टीविटीज के मार्कज थे उसमें जिस उम्मीदवार के ऐकैडमिक और ऐक्स्ट्रा करिकुलर ऐक्टीविटीज के नंबर 64 बनते थे उसे तो इन्टरव्यू में साढ़े तीन नंबर देकर उसके कुल 67.5 नंबर बनाकर बाहर कर दिया गया और जिसके ऐकैडमिक और ऐक्स्ट्रा करिकुलर ऐक्टीविटीज में 59-60-61-62 या 63 नंबर बनते थे ऐसे 13 में से 10 लोग आपने गार्ड भर्ती कर लिए। जो गाड्ज ऐकैडमिक रिकॉर्ड और ऐक्स्ट्रा करिकुलर ऐक्टीविटीज में 59 से ऊपर नंबर वाले हैं वे 8 हैं। 8 लोगों को आपने इन्टरव्यू में ज्यादा नंबर देकर उनको सुपरसीड कर दिया और 8 जो मैरिट में योग्य उम्मीदवार थे उन्हें आपने बाहर कर दिया। उनका क्या कसूर था? इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन्टरव्यू खत्म किए क्योंकि इसमें भाई-भतीजावाद होता है। जैसे यह 58 नंबर वाला सलैक्ट हो रहा है और 64 नंबर वाला बाहर हो रहा है। तो यह कैसे और किस तरह से सलैक्शन हो रही है? मुख्य मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इसकी जांच करवाएं और आप देखें कि किस तरह से ये भर्तियां हो रही हैं? यह तो पूरे प्रदेश में होगा। 13 गाड्ज में से

10 गाड्ज जो आठ ऐकैडमिक रिकॉर्ड में अच्छे थे उनको बाहर करके आपने भर्तियां कीं। यहां इस प्रकार से भर्तियां हो रही हैं। इसलिए इन्होंने केन्द्र के निर्णय को नहीं माना। तो इस तरह से आपकी सरकार काम कर रही है।

07/03/2017/1440/RG/DC/2

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में लिखा जाता है कि कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार का वर्ष 2011-12 में अन्तिम वर्ष था। तब प्रदेश में 12,000 एफ.आई.आर. दर्ज हुई थीं और इस अभिभाषण के अनुसार 17,249 एफ.आई.आर. दर्ज होने का आंकड़ा आपने स्वयं लिखकर दिया है। ये कानून-व्यवस्था के आंकड़ें हैं और कानून-व्यवस्था कैसे चल रही है? हालात क्या हैं? मंदिरों में चोरियां हो रही हैं, लेकिन चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं, घरों में और दुकानों में दिन-दिहाड़े चोरियां हो रही हैं, चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं और हत्याओं को आत्म-हत्याओं में बदलकर केसिज को खत्म किया जा रहा है। इस तरह से कानून-व्यवस्था कैसे सुधरेगी? आपने तो पूरा-का-पूरा पुलिस प्रशासन अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ षडयंत्र रचने में लगाया हुआ है। उनको कानून-व्यवस्था बनाए रखने का तो समय ही नहीं है। वे तो हमारे ही खिलाफ षडयंत्र रचने में लगे हैं। किसी के खिलाफ एस.सी. ऐट्रोसिटी का मामला बना दो, किसी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस बना दो, किसी के खिलाफ और कोई झूठा मुकदमा बना दो। इसी में आपने पुलिस को उलझा रखा है। अगर कोई पुलिस वाला कुछ करता है, तो आप उस पर दवाब डालते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसा ही उदाहरण यहां पेश करना चाहता हूं। मण्डी में दिसम्बर में गाड़ियों की चोरी का मामला ध्यान में आया। पुलिस ने गाड़ियों की चोरियों का सारा रैकेट पकड़ा। सदर मण्डी का ए.एस.आई. जिसने मेहनत करके वह काम किया, पहले तो आपने उसको प्रशस्ति-पत्र दिया, 400/-रुपये का कोई इनाम भी दिया। लेकिन जब उसने उससे उत्साहित होकर जांच आगे बढ़ाई, तो पुलिस का एक और कर्मचारी जांच के दायरे में आ गया। वह भी गाड़ियों को चोरी करने और उनको फर्जी नंबर देने और आर.सी. देने में संलिप्त था। मैं यहां पर आंकड़े दूंगा। यह कागज आपकी ही सरकार के हैं

मुख्य मंत्री : आपके आंकड़े सब गलत होते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये दस बातें करते हैं जिनमें से एक सच होती है और बातें इनकी झूठी होती हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बीच में इधर-उधर न बोलें। अभी 20-22 सदस्यों को बोलना है।

एम.एस. द्वारा जारी

07/03/2017/1445/MS/DC/1

श्री रणधीर शर्मा जारी-----

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये इनका ही रिकॉर्ड है। मेरे को तो न मानो लेकिन रिकॉर्ड को तो मानो। जिस ए0एस0आई0 ने यह काम किया उसको आपके एक पुलिस ऑफिसर ने फोन किया कि इस जांच को बन्द करो। उसने यह लिखकर दिया है।

Chief Minister: I know you. I never speak to any Officer at district level, if I have to talk, I will talk to DGP Police, not below.

श्री रणधीर शर्मा: आप सुनो तो सही, अभी मैंने आपको तो बोला ही नहीं। एक आई0जी0 रैंक के ऑफिसर ने ए0एस0आई0 को फोन किया कि इस जांच को बन्द करो। उस पुलिस कर्मचारी का नाम उसमें नहीं आना चाहिए। उसको सस्पेंड तक करने की धमकी दी गई। एक "दैनिक जागरण" अखबार ने उसको छाप दिया। उसके बाद फिर उसको फोन किया गया कि तेरे समेत मैं सारी चौकी को सस्पेंड कर दूंगा नहीं तो इस जांच को बन्द कर दो। अध्यक्ष जी, उस ए0एस0आई0 ने दुःखी होकर रेजिग्नेशन दिया। यह रेजिग्नेशन की कॉपी है। (रेजिग्नेशन की कॉपी दिखाते हुए)।

मुख्य मंत्री: आप जो कह रहे हैं लिखकर दीजिए। I will hold a Judicial enquiry into it.

श्री रणधीर शर्मा: विधान सभा लिख रही है। मैं विधान सभा में बोल रहा हूँ।

मुख्य मंत्री: आप जो कह रहे हैं उसको सर्टिफाई करके दीजिए। मैं उस पर न्यायिक जांच करवाऊंगा।

श्री रणधीर शर्मा: मैं विधान सभा में बोल रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं।

मुख्य मंत्री: मुझे पता है कि आपकी जिम्मेवारी कितनी है।

श्री रणधीर शर्मा: ये आपकी पुलिस चौकी का रिकॉर्ड है। (कागज दिखाते हुए)

07/03/2017/1445/MS/DC/2

मुख्य मंत्री: मैं आपसे उलझना नहीं चाहता।

श्री रणधीर शर्मा: अगर उलझना नहीं चाहते तो बैठ जाइए और मुझे बोलने दीजिए।

मुख्य मंत्री: जो आप आरोप लगा रहे हैं आप इसे अपने हल्फिया बयान के साथ मुझे भेजिए। मैं दूसरे दिन ही इस पर न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के जज या सेशन जज के द्वारा करवाऊंगा।

श्री रणधीर शर्मा: बिल्कुल करवाइए। मैं कह रहा हूं। आप तथ्य तो सुनिए।

Chief Minister: We can't hear your lies, your stories, your fibs.

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी आप कितना समय और बोलेंगे?

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष जी, समय की क्या बात है। अभी मैंने बोला ही कहां है? हर बार तो मुख्य मंत्री जी खड़े हो जाते हैं। आप उनको रोकिए। ये गलत बात है। अभी मैं केवल पांच मिनट ही बोला हूं।

Speaker: This is wrong.

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष जी, आप बोलने के लिए टाइम की लिमिट फिक्स कीजिए। एक ही आदमी बोलता जा रहा है। हमारे लोगों ने भी बोलना है।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष जी, मैं फैक्ट्स दे रहा हूँ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिए।

07/03/2017/1445/MS/DC/3

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष जी, वाईडअप कैसे करूँ जब अभी शुरू ही नहीं किया है?

अध्यक्ष: आपको बोलते हुए 20 मिनट का समय हो गया है।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष जी, आधा समय तो मुख्य मंत्री जी ने बोलने में ले लिया है।

Chief Minister: I challenge you on the Floor of this House जो आपने आरोप लगाए हैं आप अपने एफेडेविट के साथ उनको मुझे भेजिए। इस पर फैसला मैं नहीं करूँगा बल्कि इसके ऊपर न्यायिक जांच बिठाऊँगा। सच का सच और झूठ का झूठ साबित हो जाएगा।

श्री रणधीर शर्मा: सर, आप बात तो सुन लीजिए। अभी तो एलिगेशन आपने सुने ही नहीं हैं। इसका मतलब आपके दिमाग में है और आपको पहले से ही पता है।

मुख्य मंत्री: मुझे पता है कि आपको अंट-शंट बोलने की आदत है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वाईडअप कीजिए। -(व्यवधान)- ये एक-आधा मिनट बोले होंगे।

श्री रणधीर शर्मा: आधा मिनट कहां, आधा टाइम तो यही बोले हैं।

Speaker: Leader of the House has a right to speak.

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष जी, उस ए0एस0आई0 ने रेजिग्नेशन दिया और यह लिखकर दिया कि मुझे इस तरह से धमकी दी गई है इसलिए इस वातावरण में मैं काम नहीं कर सकता तथा मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यह रेजिग्नेशन की कॉपी है इसको मैं यहां ले करूंगा।

07/03/2017/1445/MS/DC/4

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य अंट-शंट बोल रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं। This House is not meant for such debates. जो इनके आरोप हैं ये उसको लिखित रूप में भेजें और साथ में अपना हल्फिया बयान लगाएं। I promise on the Floor of this House I will hold a judicial enquiry into these matters. Why are you afraid of that. आप न्यायिक जांच के खिलाफ क्यों है?

श्री रणधीर शर्मा: सर, आगे तो बहुत कुछ है। आप तो जल्दी ही गुस्सा हो गए।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिए।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष जी, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं आप उधर बोलिए। मैं क्या फिर न बोलूँ? ये तो फिर तानाशाही है।

अध्यक्ष: आप बोलिए, ये नहीं बोल रहे हैं।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष जी, यही नहीं उस ए0एस0आई0 का त्यागपत्र स्वीकार नहीं हुआ। एक महीने के बाद उसकी ट्रांसफर आई0आर0बी0 बटालियन बनगढ़ को की गई और 5 बजकर 55 मिनट पर उसके ट्रांसफर ऑर्डर मिलते हैं और 6 बजकर 55 मिनट पर उसको रिलीव कर दिया जाता है। यह पुलिस चौकी के रिकॉर्ड में दर्ज है। फिर वह ए0एस0आई0 ट्रिब्यूनल जाता है और वहां से स्टे लेकर आता है। लेकिन स्टे के बाद भी काफी दिनों के

बाद उसकी ट्रांसफर कैंसल की जाती है और फिर उसको चौकी में नहीं बल्कि पुलिस लाइन में लगाया जाता है।

जारी श्रीजे०एस० द्वारा-----

07.03.2017/1450/जेके/एजी/1

श्री रणधीर शर्मा:-----जारी-----

अब शिवरात्रि का बहाना बना करके जब कन्टैम्प्ट ऑफ कोर्ट की धमकी मिली तो जा करके अस्थाई रूप से ऑर्डर पुलिस चौकी के किए , यह हालत कानून-व्यवस्था की है। इस स्थिति में कौन पुलिस अधिकारी काम करेगा? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जांच करें। मैं यह रिकॉर्ड दे रहा हूं। यही जांच नहीं करनी है जांच यह भी करें कि(व्यवधान).....

अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी ने बोल दिया है।

Chief Minister: We can't be bullied by you. We are not going to be bullied. These are baseless allegations. If he says, he has no right to say anything. अगर वे सोचते हैं कि वे सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं उनको इस शिकायत को ऐफिडेविट के साथ सभा पटल पर रखें। The Government will inquire into this. I will hold a judicial inquiry into this matter. आपको बिना किसी तथ्य के किसी भी चीज के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह अभी दे दूँ। प्लीज उनको यह दे दो। आप अभी पढ़ लो।

Chief Minister: Speaker, Sir, I take serious objection. This man is abusing his rights as a Member and trying to fool this House by his fictions/stories. आप बात सुनिए। अगर यह सच है और अगर ये कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ ये ऐफिडेविट के

साथ, अपने हल्फिया बयान के साथ उसको सभा पटल पर रखें और the Government will hold judicial inquiry into this matter. I will hold judicial inquiry into this matter. He has no business to waste the time of the House.

07.03.2017/1450/जेके/एजी/2

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं भी दूसरी बार चुना हुआ विधायक हूँ। मुझे पता है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मैं on the record with facts बोल रहा हूँ। मेरे पास कागज है।

अध्यक्ष: आप फेक्ट्स पर बोलें उसका ये ज़वाब दे देंगे।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, तो जब जवाब देना होगा दें। अभी तो सुनें। अभी क्यों बोल रहे हैं?

अध्यक्ष: इनका हक भी है। Leader of the House and Leader of the Opposition have a right to intervene.

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, राईट तो है लेकिन ये तो मेरे से ज्यादा बोले हैं यह तो राईट नहीं है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी बात रखें। आप बात करिए और देखें कि 26 मिनट हो गए हैं। आप थोड़ा वाईड अप करने की कोशिश करें।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की चार सालों की मानें तो उपलब्धि सिर्फ भ्रष्टाचार है। एक साल में भी इन्होंने भ्रष्टाचार के बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं। हमने उस भ्रष्टाचार को ले कर जब इस सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो महामहिम् राज्यपाल महोदय को चार्जशीट पहुंचाई थी। उस चार्जशीट में मुख्य मंत्री समेत सरकार के 41 लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, परन्तु चार्जशीट को महामहिम् राज्यपाल

महोदय ने सरकार को कार्रवाई के लिए भेजा है। अभिभाषण में यह तो लिख दिया कि zero tolerance on corruption पर ये बताएं कि उस चार्जशीट का इन्होंने क्या किया? किस एजेंसी से जांच करवाई? कौन से आरोप का क्या निकला? ये जानकारी हाउस को दें तो अच्छा रहेगा। यह जीरो टोलरेंस कहने से नहीं होती। ये दिखनी चाहिए। मैं उन आरोपों को दोहराना नहीं चाहता हूं। आरोप बहुत ज्यादा है। उनको रिपीट करने लगूंगा तो बहुत टाईम लगेगा। परन्तु सच्चाई यह है कि सरकार का कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार

07.03.2017/1450/जेके/एजी/3

नहीं हो। हर जगह भ्रष्टाचार है। मुख्य मंत्री के कार्यालय से लेकर पटवारी के कार्यालय तक। सस्ता अनाज मिलता है उसमें भी घोटाले हैं। बसें खरीदते हैं उसमें भी घोटाले हैं। जो बीज मिलता है, खाद मिलती है उसमें भी घोटाले हैं। मीटर दिए जाते हैं उसमें भी घोटाले हैं। इन्होंने कोई छोड़ा ही नहीं है। जिस तरह से माफिया इस प्रदेश में चला है वह तो सब लोगों ने देखा है। मैं उन आंकड़ों को दोबारा नहीं बोलना चाहता क्योंकि समय के बारे में बार-बार बोला जा रहा है। परन्तु सब जानते हैं कि इन चार सालों में किस तरह से वन माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया और तबादला माफिया सक्रिय हैं। यह ठीक है कि वन माफिया चम्बा में ज्यादा है क्योंकि उनको वन मंत्री जी का आशीर्वाद है। शिमला में मुख्य मंत्री जी का आशीर्वाद है। सरकार की रिपोर्ट आती है कि 1800 देवदार के पेड़ कटे और 499 देवदार के पेड़ कटे और कार्रवाई कोई नहीं होती है। अवैध खनन में नूरपुर देख लो, ऊना देख लो, बद्दी-बरोटीवाला देख लो।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

07.03.2017/1455/SS-AG/1

श्री रणधीर शर्मा क्रमागत:

रामपुर देख लो, किन्नौर देख लो, सब कुछ चार्जशीट में बोला है। आप जांच करवाएं। इसी तरह से ड्रग माफिया सक्रिय है। रिकॉर्ड प्रश्न के उत्तर में आया है। ये कहते हैं कि कोई माफिया नहीं है। चीफ सैक्रेटरी और डी०जी०पी० एक ही मुद्दे को लेकर मीटिंग करते हैं, उनकी मीटिंग ही इस बात को साबित करती है कि आज प्रदेश ड्रग माफिया के अन्तर्गत है। उसको रोकने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि उसमें सरकार का ही कसूर है। यह सामाजिक समस्या भी है। परन्तु सरकार दिल से एक्सैप्ट करेगी तो उसको दूर किया जा सकता है। अगर सरकार के कर्णधार ड्रग माफिया को संरक्षण देंगे तो ये नौजवान बच्चे, जोकि नौजवानी में होते हैं, इनके बिगड़ने में समय नहीं लगता। इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार इस बात को दिल से समझे कि यह समस्या है और इसको हमने दूर करना है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज तक प्रदेश में कोई ड्रग डि-एडिक्शन सेंटर क्यों नहीं है? क्या आप ड्रग माफिया को रोकेंगे? जो बच्चे ड्रग की लत में पड़े हैं अगर उनका किसी ने इलाज करवाना है तो उनको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। प्रदेश में एक भी ड्रग डि-एडिक्शन सेंटर तक नहीं है। सरकार कर क्या रही है? सिर्फ अखबारों में ही बोलकर सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सामाजिक समस्या है तो सामाजिक जागरूकता भी लानी होगी। कुछ नौजवान भटक गए हैं तो उनको सुधारने के लिए ड्रग डि-एडिक्शन सेंटर भी खोलने पड़ेंगे। वह सब काम सरकार करे, उसकी ज़रूरत है।

Speaker: Please wind up now.

श्री रणधीर शर्मा: इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अलग-अलग जिलों में अलग-अलग माफिया होंगे। परन्तु हमारा बिलासपुर है जहां हर तरह का माफिया है उसको सरकार के कर्णधार चला रहे हैं। इसलिए माफिया राज की असली राजधानी तो बिलासपुर बननी चाहिए। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से

07.03.2017/1455/SS-AG/2

कहूंगा कि जब आप राजधानियां बांट ही रहे हैं तो थोड़ा बिलासपुर की ओर भी ध्यान कर लें। बाकी, अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की बहुत-सी बातें हैं।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप फिर टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वाइंड अप प्लीज। I will not allow you. You have been speaking for the last 31 minutes.

श्री रणधीर शर्मा: सर, आधे से ज्यादा टाइम तो मुख्य मंत्री जी बोले हैं।

अध्यक्ष: आधे से ज्यादा नहीं है। मुझे पता है कि कितना टाइम लिया है।

श्री रणधीर शर्मा: सर, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि में जो मंदिरों के क्या हालात हैं?

अध्यक्ष: आप वाइंड अप करेंगे या नहीं otherwise I will have to stop you.

श्री रणधीर शर्मा: सर, आप ही मुझको बोलने नहीं दे रहे, इतनी देर में तो मैंने बोल भी लेना था।

अध्यक्ष: आप वाइंड अप करिये। अभी 17 आदमी बोलने वाले हैं। (Interruption) I will not allow.

श्री रणधीर शर्मा: सर, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। सर, मंदिरों की हालत क्या है। आज नैनादेवी मंदिर में सोना-चांदी गिल्ट के नाम पर नीलाम हो रहा था, अगर एक ट्रस्टी उसको देख न लेता। चिन्तपुरनी मंदिर में मुकुट तक चोरी हो गए। ज्वालामुखी मंदिर में किस तरह से रसोई की रिपेयर पर लाखों रुपये खर्च होते हैं, एक नई रसोई बनाने के लिए भी 7 लाख खर्च हो रहे हैं। किस तरह से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। रेन शैल्टर बन रहे हैं। हैंडपम्प बन रहे हैं। --(व्यवधान)-- आप (श्री संजय रतन) बैठिये। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मैं कोई लम्बी बात नहीं कर रहा। आप मुझे बोलने दें। यह हमारे लिए सबसे

दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश में मंदिरों के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जब से यह मंदिरों का अधिग्रहण हो रहा है उस नियम के तहत मंदिर के ट्रस्ट का चेयरमैन

07.03.2017/1455/SS-AG/3

एस0डी0एम0 होता है। कमिश्नर डी0सी0 होता है परन्तु हमारे भीमाकाली मंदिर है जिनके आजीवन अध्यक्ष ट्रस्ट के माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी हैं। किस नियम के तहत हैं? कौन-सा नियम है? आज प्रदेश का पैसा उन मंदिरों के रख-रखाव पर खर्च हो रहा है जबकि विधायक निधि में से कोई मंदिर को पैसा दे नहीं सकते। परन्तु मुख्य मंत्री जिस मंदिर में इच्छा होती है लाखों रुपया सरकार का दे देते हैं। आज टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से लगभग 19 करोड़ रुपये रामपुर-बुशहर के साथ गांव की रेनोवेशन के लिए दिया गया। उसका टैंडर हुआ और किसको दिया गया? मैसर्ज तेनजिन कंस्ट्रक्शन कम्पनी को।

मुख्य मंत्री: आप यहां पर फैक्ट्स रखिये।

श्री रणधीर शर्मा: और कम्पनी कौन-सी, जो इनके होली लॉज का गैस्ट हाउस बना रही है, उस कम्पनी को टैंडर दिया। अब शक तो उठेगा ही।

मुख्य मंत्री: आप यह हाउस के बाहर कहिये। I will file a defamation suit against you. यह बिल्कुल गलत है।

श्री रणधीर शर्मा: परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तरह से जो सरकार के पैसे का दुरुपयोग है उसकी भी और जो मंदिरों के ट्रस्ट के पैसे हैं --(व्यवधान)--

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सारे टॉपिक आज ही बोल लेंगे। I have asked you to wind-up. No more recording. Not to be recorded. (Interruption) If you don't agree, I will not get it recorded. (Interruption) . . .

Continued by ks/AS . . .

07.03.2017/1500/केएस/एस/1

श्री रणधीर शर्मा : मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये गुस्सा न करें। मैंने इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं।

अध्यक्ष: आप अपनी बात कीजिए, समय बर्बाद न करें।

मुख्य मंत्री: रणधीर जी, आपने शुरू से लेकर अन्त तक सिवाय झूठ के कुछ भी नहीं बोला और मुझे इसी बात का अफसोस है। आपने अपने भाषण से इस माननीय सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ऐसा भी मैम्बर हो सकता है जो हाऊस के अंदर इस तरह की बकवास करें? यह गलत बात है। (व्यवधान) इस हाऊस की अपनी गरिमा है। जो आपने यहां बोला है, जरा बाहर बोलकर देखिए। You speak it.

श्री रणधीर शर्मा: हम बोलेंगे। क्या कर लेंगे आप? आप हमें धमकी दे रहे हैं?

Chief Minister: I will file a defamation suit against you and your colleagues.

(व्यवधान) यह धमकी नहीं है। आप झूठ बोलते हैं।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। धन्यवाद।

07.03.2017/1500/केएस/एस/2

अध्यक्ष: अब श्री राम कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम कुमार: अध्यक्ष महोदय, 1 मार्च, 2017 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस माननीय सदन में जो अभिभाषण दिया, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं पिछले कल से सुन रहा था, हमारे दोस्त माननीय सदस्य विपक्ष की तरफ से कह रहे थे कि इन चार वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने कोई भी विकास के कार्य नहीं किए और यह अभिभाषण केवल झूठ का पुलिन्दा है लेकिन आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक

नहीं है। सरकारें आती है। माननीय धूमल साहब जब मुख्य मंत्री रहे तो इन्होंने भी अनेकों कार्य किए होंगे लेकिन इस समय की मौजूदा सरकार राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसका इतिहास और लोग गवाह हैं। वे ऐतिहासिक कार्य जो आमजन से जुड़े थे, जो किसानों के हितों से जुड़े थे उनमें से एक जीता-जागता उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारी तहसीलों में निशानदेही के अनेकों मामले काफी लम्बे समय से लटके रहते थे। लोग अपना मकान नहीं बना पाते थे, अपनी भूमि का आबंटन नहीं कर पाते थे इसके लिए एक तहसील में एक दफ्तर कानूनगो, एक फील्ड कानूनगो होता था इस समस्या के निवारण के लिए मैं मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने 154 नए फील्ड कानूनगो सर्कल की स्वीकृति दी और पटवारियों को पदोन्नत करके कानूनगो तैनात किए गए। पटवार सर्कलों में उनको भेजा जिससे हमारे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। किसानों की फाइलें जो 6-7 महीनों में निपटती थी, आज 15 दिन या एक महीने की उनको डेट मिलती है और उनका निपटारा होता है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कॉलेजों की भरपूर भर्त्सना की, प्रदेश सरकार ने अनेकों कॉलेज वहां की जरूरत को, वहां के विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए कि किस क्षेत्र में कितने +2 स्कूल हैं, उसका पूरा सर्वेक्षण करवाकर माननीय विधायकों और पंचायत प्रधानों की डिमांड पर कॉलेज खोले। केवल कॉलेज ही नहीं खुले इसके साथ-साथ उन कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए लगभग 40 करोड़ रु० इस सरकार ने दिया जो विकास

07.03.2017/1500/केएस/एस/3

के लिए अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। इसी तरीके से छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदेश भर में 01,41,724 पात्र छात्रों को 82 करोड़ 40 लाख रुपये छात्रवृत्तियां दी गईं। वह किसी अमीर छात्र को नहीं मिलती बल्कि वह गरीब परिवारों के बच्चों को मिलती है जो पढ़ाई में या किसी अन्य क्षेत्र में अक्ल होते हैं।

श्रीमती अ० व० द्वारा जारी---

7.3.2017/1505/av//1

श्री राम कुमार----- जारी

इसी तरीके से प्रदेश सरकार ने जरूरत और डिस्टेंस के हिसाब से जहां पर बसें नहीं जाती हैं, दूरदराज के इलाके हैं जहां पर हमारी बच्चियां पढ़ नहीं पाती हैं वहां जरूरत के हिसाब से स्कूलों को अपग्रेड किया। कई जगह मिडिल स्कूल दिए, कई जगह हाई स्कूल दिए और कई जगह प्लस टू स्कूल दिए। इन स्कूलों के भवनों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 39.19 करोड़ रुपये की राशि सैंक्शन की जो खर्च की जा रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में विभिन्न वर्ग के अध्यापकों की भर्तियां जो पिछले काफी समय से लम्बित पड़ी थी। जिन बच्चों ने टैट क्लीयर कर रखा था, जिन्होंने जे०बी०टी० कर रखी थी; वर्ष 2000 बैच तक के बच्चे जो ओवर एज हो रहे थे सरकार ने उनकी ओर ध्यान दिया। हजारों जे०बी०टी०, पी०जी०टी०, सी० एण्ड वी० और अनुबंध के आधार पर भर्ती किए जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। मैं मानता हूं कि स्कूलों में आज भी अध्यापकों की कमी है लेकिन अध्यापकों की कमी पूरी करने के लिए उसकी भर्ती प्रक्रिया है। प्रदेश सरकार उस प्रक्रिया के तहत कमिशन को अपनी डिमाण्ड भेज चुकी है और यह भर्तियां बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगी। सभी स्कूलों में अध्यापकों की पूरी भर्ती कर ली जायेगी। इस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों जैसे प्रधान, सदस्य (पंचायत समिति) और जिला परिषद के सदस्यों को पहले केवल 400-500 रुपये या दो हजार रुपये मानदेय मिलता था उस मानदेय में इन्होंने बहुत बड़ी बढ़ोतरी करके उनका सम्मान किया है। हिमाचल प्रदेश में 3243 पंचायतें हैं और मैं समझता हूं कि इससे आमजन का सम्मान हुआ है। प्रदेश सरकार ने उनकी सुध ली है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने यह कदम उठाया। यही नहीं

इस सदन के माननीय सदस्यों का दो बार मानदेय बढ़ाया गया जिसके लिए सामने से भी टेबल थपथपाई थी। यहां पर सभी सदस्यों की मांग थी कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारा भी मान रखा और हमारे मानदेय में दो बार बढ़ोतरी की जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवादी हूँ।

7.3.2017/1505/av//2

हिमाचल प्रदेश के बेड़े में जहां रोज पता लगता था कि ऐक्सिडेंट हुए और लोग मरे, पुरानी खट्टारा बसों को बदलने के लिए 800 नई बसें हिमाचल प्रदेश के परिवहन बेड़े में शामिल की जिसके लिए मैं समझता हूँ कि (---व्यवधान---) केंद्र के अलावा भी आई है। केंद्र की अलग है और उसके अलावा 800 नई बसें आई हैं। (---व्यवधान---) कृपया व्यवधान मत डालिए। प्रदेश में 22 बड़े पुल बनाये गये जिसमें से मेरे चुनाव क्षेत्र में चार पुल बनें। एक वैली ब्रिज के नाम से दो करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल का नींव पत्थर हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी रख कर आए हैं। इन्होंने पैसा भी सैंक्शन किया इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। दून क्षेत्र में पेयजल की बहुत ज्यादा कमी थी उस समय हमारी माननीय सदस्या श्रीमती विनोद चन्देल जी वहां के लिए न तो कोई नई स्कीम ला पाई और न ही कोई नया स्कूल खोल पाई थी। उनके वक्त में केवल जी0पी0एस0, सुआ के नाम से सैंक्शन हुआ था मगर उसमें अध्यापक का एक भी पद सृजित नहीं किया गया था। उस स्कूल को चलते हुए सात साल हो गये थे और उसमें अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पदों का सृजन भी किया तथा वहां पर अध्यापक भी दिए। इसके साथ-साथ 22 स्कूल अपग्रेड किए और 3 नये स्कूल दून क्षेत्र के लिए दिए। इसके अतिरिक्त हमारे दूरदराज के क्षेत्र साई व घरेड़ पंचायतें और बडलग जो एक पहाड़ी पंचायत है वहां साईस और कॉमर्स की क्लासिज शुरू करवाई जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूँ। इसके अतिरिक्त चंडी पेयजल योजना जिसके अंतर्गत 15 पंचायतें और 301 गांव कवर हो रहे हैं। यहां पर माननीय सदस्य श्री गोविन्द राम शर्मा जी बैठे हैं। मैंने इनको कहा कि आप इसको अपनी प्राथमिकता में डालें मगर इन्होंने मना कर दिया। इसमें तीन पंचायतें अर्की की हैं

और यह स्कीम 22 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2013 में इसका नींव पत्थर रखा था। इसके सारे टैंडर हो चुके हैं तथा अब इसके 5-5 लाख लीटर के टैंक बन रहे हैं।

श्री वर्मा द्वारा जारी

07/03/2017/1510/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री राम कुमार- जारी

मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ, क्या यह विकास नहीं है। इसके अलावा गोयला पेनर को भी बद्दी से ही पानी दिया जा रहा है। साईं क्षेत्र को 3 ट्यूब वेल लगाकर 8 करोड़ रुपये की पेयजल स्कीम माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस क्षेत्र को दी है। इसके लिए भी मैं इनका धन्यवादी हूँ और निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्कीम लगभग तैयार हो गई है। मैं चाहूंगा कि इसी महीने में इस स्कीम का उद्घाटन अपने कर कमलों से करने की कृपा करें, ताकि लोगों को इस स्कीम की सुविधा मिल सके। इसके अलावा पट्टा क्षेत्र के लिए पट्टा-भढेरी नाम से लिफ्ट सिंचाई स्कीम बनी है, जिसकी लागत 8 करोड़ रुपये हैं। इस सरकार ने मुझे लगभग 54 पेयजल और सिंचाई के ट्यूबवेल दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम माननीय मुख्य मंत्री जी ने सिंचाई एवं पेयजल क्षेत्र में उठाया है। इसके अतिरिक्त दो आई0टी0आईज0 पट्टा और कुठाड़ के नाम से चल रही है। इनके भवनों के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी धनराशि स्वीकृत की हैं। बरोटीवाला में एक डिग्री कॉलेज, जिसकी बहुत बड़ी मांग थी, जब रामशहर का क्षेत्र दून में था, तो कॉलेज खोलने के लिए रामशहर और बरोटीवाला दोनों का सर्वे हुआ था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पहले बरोटीवाला कॉलेज दिया। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने रामशहर का कॉलेज भी अनाउंस कर दिया है, जिसकी नोटिफिकेशन भी हो चुकी है। इससे दोनों क्षेत्रों को फ़ायदा होगा। इसके साथ-साथ इन कॉलेजों के भवनों के लिए भी इन्होंने 5-5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, मैं इसके लिए भी इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में CIPET (Plastic Engineering College) कॉलेज खुला है, जो देश का 18वां कॉलेज है। केन्द्र सरकार ने कहा कि जो सरकार इसमें अपना 50 प्रतिशत अंशदान देगी,

वहां पर यह कॉलेज खोला जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए 25 बीघा ज़मीन उपलब्ध करवाई और यह कॉलेज भी बद्दी में फंक्शनल हो चुका है। यह अपने तौर का एक प्लास्टिक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसके लिए मैं केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार का धन्यवादी हूं। एक टूल-रूम जो बी०जे०पी० के शासन में केवल 15 बीघा ज़मीन में खुला था, लेकिन इन्होंने उसका नाश कर दिया था, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 115 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 100 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई है। जैसे एच०एम०टी० हमारे प्रदेश के बच्चों को प्रशिक्षण देकर उद्योगों के काबिल बनाता था, यह टूल-रूम

07/03/2017/1510/टी०सी०वी०/डी०सी०/2

भी इसी तरह का कार्य वहां पर करेगा। एक बहुत ही बड़ी संजीवनी नालागढ़ और बद्दी क्षेत्र के लिए बी०बी०एन०डी०ए०, जो भाजपा के टाईम में एक सफेद हाथी बनकर रह गई थी, इसका गठन 2002 में हुआ था। लेकिन इनके शासन में उसका बजट कभी 2 करोड़ या 5 करोड़ होता था, इससे ज्यादा इसका कभी बजट नहीं आया। इसका पैसा केवल उद्योगों की सड़कों के ऊपर लगता था। मैंने माननीय मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री जी से निवेदन किया कि जो उद्योग लगे हैं, उनको जो सड़कें गुजरती हैं, वह पहले गांव से गुजरती हैं। इसलिए पहले गांव की सड़क पक्की होनी चाहिए, उसके बाद उद्योग की सड़क को पक्का किया जाना चाहिए। इन्होंने इस बात पर अमल करते हुए 105 करोड़ रुपये की राशि पिछले 2 वर्षों में सेंक्शन की और वह राशि खर्च भी की जा चुकी है। पिछले दिनों माननीय उद्योग मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये के कामों के उद्घाटन किए और 9 करोड़ रुपये की और घोषणा की है। इसके अलावा 25 करोड़ रुपये नये बजट में देने का आश्वासन भी दिया है। बद्दी-बरोटी-नालागढ़ का क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है, क्योंकि हिमाचल का सबसे ज्यादा रैवन्यू इस क्षेत्र से आता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री जी का धन्यवादी हूं कि उन्होंने समय और डिमाण्ड के हिसाब से वहां कार्य करना शुरू किया। जो कार्य भाजपा सरकार वहां पर नहीं कर पाई, वे कार्य हमारी सरकार ने वहां पर किए हैं। अब वहां पर पार्को का बड़ा निर्माण हो रहा है। वहां पर हिमाचल की शैली के आधार पर 25-25 लाख रुपये की लागत से रेनशल्टर बनाये जा रहे हैं और बद्दी की सड़कों को शहरनुमा तर्ज़ पर डेवैल्प किया जा रहा है। वहां पर जो सड़कें हैं, उनमें 25

करोड़ रुपये की लागत से लाईट्स लगाई जा रही है। इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवादी हूँ। मैं अपने भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह विकास नहीं है? जो ये कहते हैं कि यह झूठ का पुलिंदा है। बद्दी और नालागढ़ में लगभग 100 किलोमीटर सड़कें हैं, जिन पर टारिंग और इंटर-लाकिंग टाईल्ज वर्क माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। मैं इसके लिए भी इनका धन्यवादी हूँ। इन्होंने गांव की गलियों के साथ-साथ वहां के जो लिंक रोडज़ हैं,

श्रीमती एन0एस0- - - द्वारा जारी।

07/03/2017/1515/ ns/ag /1

श्री राम कुमार----- जारी

उन पर इंटरलोकिंग टाईल्ज लगाने का कार्य चल रहा है। कई प्रकार के छोटे पुल और पुलियां बी0बी0एन0डी0ए0 के माध्यम से लगाई जा रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो मॉडर्न स्कूल दिए हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र में और दूसरा मैदानी क्षेत्र बरोटीवाला के लिए दिया है। इसी तरीके से इन्होंने मांग के आधार पर दो साईंस लेबोरेटरीज़ दी हैं। इन्होंने हमें दो सी0एच0सीज0 दिये हैं उनमें से एक सी0एच0सी0 बद्दी और दूसरा चण्डी में दिया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी बद्दी गये थे और वहां पर इन्होंने कहा कि बद्दी की जनसंख्या को देखते हुए शीघ्र ही यहां पर 50 बैड का सिविल अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए मैं इनका धन्यवादी हूँ। एक पी0एच0सी और सात आयुर्वेदिक डिसपेंसरीज़ बनने वाली हैं। पिछले गर्मी सीज़न में 50 किलोमीटर तक की सड़क की टारिंग केवल पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के माध्यम से हुई है। गर्मी सीज़न के टारगेट के लिए पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के नालागढ़ और कसौली डिवीजन के टैंडर लगाए गए हैं उसमें केवल दून क्षेत्र की 50 किलोमीटर सड़क की टारिंग अभी गर्मी में होने वाली है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवादी हूँ। इससे पहले जब हम एस.डी.ओ. या एक्सियन को फोन करते थे तो हमें जवाब मिलता था कि हमारे पास पैचवर्क के लिए बिच्चूमन नहीं है। मैं प्रदेश सरकार का धन्यवादी हूँ कि इन्होंने प्रदेश स्तर पर बिच्चूमन की

एक बड़ी खेप ले करके डिवीजन वाईज डिस्ट्रिब्यूशन किया जिसमें कसौली और नालागढ़ डिवीजन को 1000-1000 ड्रम बिच्चूमन के मिले हैं। उससे सड़कों की दशा सुधरी है। मैंने पिछली असेम्बली में भी प्रश्न उठाया था कि हमारी ग्रामीण सड़कें पंचायतों द्वारा निर्मित हैं और उनकी रिपेयर के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के समय से ले करके पिछले सात वर्षों से ये सड़कें बंद पड़ी हुई थीं, बरसात के दो महीने के अन्तराल के बाद उनकी बहाली के लिए केवल मेरे क्षेत्र में 500 घंटे जे.सी.बी. मशीनें चला करके सभी पंचायत रोडज़ को

07/03/2017/1515/ ns/ag /2

बहाल किया गया है। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं। भाजपा के शासनकाल में जो रोडज़ बंद हुए थे उनको भी हमने खोला है। बद्दी तहसील के कानूनगो का सर्वे हमारे शासनकाल में हुआ था लेकिन वर्ष 2007 में सरकार बदल गई थी और भाजपा ने इसकी नोटिफिकेशन की। इन्होंने उसमें तहसीलदार को पांच साल तक एक कानूनगो के कमरे में बिठा करके रखा। वहां पर न तो कोई टॉयलैट की सुविधा थी और न ही कोई स्टॉफ का सृजन किया गया था। वहां पर नायब तहसीलदार की पोस्ट भी नहीं दी गई थी। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री महोदय और रैवन्यू मिनिस्टर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बद्दी तहसील भवन के निर्माण के लिए 40 लाख की राशि दी है और एक नायब तहसीलदार की पोस्ट का सृजन भी किया है। अन्य जो पद खाली पड़े थे उनका सृजन भी इन्होंने किया है। इससे हमारे वहां के लोगों का काम भी आसान हुआ है। इसके साथ-साथ वेलफेयर या वृद्धा पेंशन के कार्य के लिए कसौली या नालागढ़ जाना पड़ता था लेकिन जब मैंने मुख्य मंत्री महोदय के सामने मांग रखी थी तो इन्होंने वहां पर वेलफेयर के कार्यालय की घोषणा की और 15 दिन के अंदर उसकी नोटिफिकेशन करके उसको फंक्शनल किया। इसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मेरे क्षेत्र बद्दी में कोई भी रोजगार कार्यालय नहीं था। इन्होंने इसकी भी घोषणा की और नोटिफिकेशन की और वहां

पर स्टॉफ भी दिया है। इसके लिए मैं इनका धन्यवादी हूँ। इसके अतिरिक्त बद्दी क्षेत्र के उद्योगपतियों को छोटे फंक्शन के लिए चण्डीगढ़ जाना पड़ता था, 13 करोड़ की लागत से चण्डीगढ़ क्लब की तर्ज पर बद्दी में ट्रेड सेंटर का निर्माण बी0बी0एन0डी0ए0 के माध्यम से किया गया है। यह प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं समझता हूँ कि बद्दी के जो उद्योगपति हैं वे उस क्लब में अपनी मीटिंग आदि कर सकते हैं। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 करोड़ की लागत से इनडोर स्टेडियम का नींव पत्थर रखा है उसका कार्य भी शुरू हो गया है। जिले का पहला इनडोर स्टेडियम 10 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। 10 करोड़ की लागत से ही एक

07/03/2017/1515/ ns/ag /3

ऑडिटोरियम का निर्माण अभी होना है। उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पैसे दे दिये हैं। केवल उसका स्टोन ले करना बाकी है। इसके लिए भी मैं इनका धन्यवादी हूँ। हमारे क्षेत्र में बिजली की कमी हो गई थी, कमी को दूर करने के लिए 100 करोड़ की लागत से तीन सबस्टेशनज़ का निर्माण कर दिया गया है और एक का निर्माण होना अभी बाकी है। आज बद्दी से बिजली परवाणु के लिए जा रही है। बद्दी से बिजली पूरे हिमाचल के लिए सप्लाई हो रही है। बद्दी के उद्योग क्षेत्र में बिजली सरप्लस हो रही है क्योंकि उद्योगपतियों की मांग थी कि बिजली की कमी हो रही है तो प्रदेश सरकार ने तुरन्त उसका नोटिस लेते हुए चार बड़े सबस्टेशनों का निर्माण किया है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ।

श्री आर0के0एस0 ----जारी

07/03/2017/1520/RKS/AG/1

श्री राम कुमार.....जारी

जो महिला थाने खोले गए हैं यह भी एक सराहनीय कदम है। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उनको रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने यह पहल की कि प्रदेश में महिला थाने खोले जाएं। बद्दी के लिए भी एक महिला थाना मिला है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूँ। पिछले कल माननीय सदस्य डॉ० राजीव बिन्दल जी ने कानून-व्यवस्था पर एक बात कही कि मेरे घर पर हमला हुआ और पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। मैं यह बताना चाहूँगा कि एक सनकी टाइप शराबी आदमी था जोकि शराब के नशे में धुत था। वहाँ पर गेट खुला हुआ था और उसने दो गाड़ियों के शिशे तोड़ दिए। मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस की मुस्तैदी को दाद देता हूँ कि इन्होंने तीन घंटे के भीतर उस आदमी को पकड़कर अरैस्ट किया। बाद में मैं भी उस आदमी से मिला और मैंने कहा कि इस मामले में थोड़ी ढील दी जाए क्योंकि उस आदमी की मनोस्थिति ठीक नहीं थी। यह बात मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि यह कोई हमला नहीं था। मैं एक बार फिर माननीय मुख्य मंत्री जी और प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन चार वर्षों में अथाह विकास प्रदेश सरकार ने किया है। माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने हरेक क्षेत्र में जाकर वहाँ की जो उचित मांग थी उसको मध्यनज़र रखते हुए पूरा किया है। कल आदरणीय राकेश कालिया जी के मुँह से एक बात स्लिप कर गई थी। इन्होंने यह कहना था कि जो मांगों की लिस्ट होती है उसमें से पहले के 4-5 नम्बरों को ही माननीय मुख्य मंत्री जी अनाउन्स करते हैं। लेकिन इनके मुँह से कुछ और ही बोला गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में तीन दौर किए हैं और तीनों दौरों में जो इन्होंने घोषणाएं की थी वे सब पूरी हो गई हैं। केवल एक स्कूल की नोटिफिकेशन शेष है, बाकि सभी घोषणाएं 100 प्रतिशत पूरी हो गई हैं। सभी स्कूल फंक्शनल हो गए हैं। सभी स्कूलों/कॉलेजों में अध्यापकों/प्रोफैसर्स की तैनाती हो गई है। अन्य जो भी संस्थान खुले हैं उनमें भी स्टाफ की तैनाती हो गई है।

मैं राज्यपाल अभिभाषण का समर्थन करता हूँ और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सभी सराहनीय कार्यों के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

07/03/2017/1520/RKS/AG/2

अध्यक्ष: माननीय सदस्य राकेश कालिया जी आप कुछ बोलेंगे क्या?

श्री राकेश कालिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी ने कहा कि कालिया जी के मुंह से एक बात स्लिप हो गई थी। मेरे मुंह से कुछ नहीं स्लिप हुआ था। मैंने यह कहा था कि जनता के दबाव में विधायक मुख्य मंत्री के सामने हर तरह की डिमांड, हर गांव का नाम लेना चाहते हैं। विपक्ष के जो मुनीम पत्रकार मित्र सामने बैठे होते हैं वे सारी लिस्ट अखबार में छाप देते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने सभी घोषणाएं कर दी। सीरियस तो 4-5 ही घोषणाएं होती है जिनका पता विधायक और जनता दोनों को होता है।

07/03/2017/1520/RKS/AG/3

अध्यक्ष: अब श्री बिक्रम सिंह जी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप समय का ध्यान रखें।

श्री बिक्रम सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज इस अभिभाषण पर शुरू में ही सभी ने 'सबका कल्याण, समग्र विकास' की दास्तां सुनाई। मेरे कांग्रेसी मित्रों ने बड़े तारीफ के पुल यहां पर बांधे हैं कि शिक्षण संस्थानों, कॉलेजिज के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं यह कहूंगा कि जो एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्ज़, कॉलेज हैं उनको खोलने पर जोर दिया जा रहा है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

07.03.2017/1525/SLS-AG-1

श्री बिक्रम सिंह...जारी

कॉलेज के अंदर लैक्चरर नहीं हैं, स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं हैं। आप क्षेत्रवाद की बात करते हैं लेकिन मैं तो यह कहता हूँ कि स्कूलों के अंदर अध्यापक न होना, और कॉलेज के अंदर लैक्चरर का न होना, यह भी एक सोची-समझी चाल है ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चों को उन इंस्टिट्यूशंस में से क्वालिटी एजुकेशन न मिल पाए। फिर वह किस प्रकार से कंपीटिशन दे पाएंगे? आप बड़े मेज थपथपा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मेरे पास डिटेल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो यह मादक पदार्थों की तसकरी हो रही है, यह एक स्लो प्वाजनिंग की जा रही है। अध्यापक न देकर, लैब न देकर, लैक्चरर न देकर हमारे इन संस्थानों के अंदर भी स्लो प्वाजनिंग हो रही है। वहां से जो विद्यार्थी निकलेगा, निश्चित तौर पर उसके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह से हमारे क्षेत्रों के साथ बेइंसाफी हो रही है। कल भी मैंने एक प्रश्न किया था। माननीय मुख्य मंत्री जी चले गए। इन्होंने स्वयं माना कि हमारे कॉलेज प्राइमरी स्कूलों के अंदर चल रहे हैं। जो कॉलेज प्राइमरी स्कूलों में चल रहे हैं, उनकी हालत क्या होगी? डाडासिबा के अंदर जो कॉलेज चल रहा है उसमें पोलिटिकल साइंस का, इंगलिश का और हिस्टरी का लैक्चरर नहीं है, पियन नहीं है, चौकीदार नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है और सीनियर असिस्टेंट भी नहीं है। जिस कॉलेज के अंदर यह स्थिति होगी, आप बताएं कि वहां का बच्चा क्या करेगा? पिछली बार जो रिजल्ट आया है उसमें 80 परसेंट बच्चों की कंपार्टमेंट है, केवल 20 परसेंट बच्चे पास हुए हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र के संस्थानों की इस प्रकार से स्लो प्वाजनिंग की जा रही है। लैक्चरर न भेजकर, स्टॉफ न देकर और इंफ्रास्ट्रक्चर न देकर यह सब किया जा रहा है। आपने रक्कड़ के अंदर कॉलेज खोला है और कल आप बहुत खुश हो रहे थे। कल

कइयों ने कहा कि आपको तो 3 कॉलेज मिले। ऐसे कॉलेजों से जो प्राइमरी स्कूलों के अंदर चल रहे हैं, अगर कोई कॉलेज न ही मिले तो अच्छा है। जहां अध्यापक नहीं है, लैक्चरर नहीं है, हम ऐसे कॉलेजों का क्या करेंगे? आप केवल नंबरिंग पर लगे हैं।

07.03.2017/1525/SLS-AG-2

यहां पर श्री कौल सिंह ठाकुर जी भी बैठे हैं। मैं इनसे भी 4 चीजें पूछूंगा।

अभी रक्कड़ के अंदर पोलिटिकल साईंस, हिस्ट्री, कौमर्स के लैक्चरर नहीं हैं और प्रिंसिपल भी नहीं है। जो हिंदी का अध्यापक वहां लगाया है वह गवर्नमेंट कॉलेज ढलियारा से डैपुटेशन पर लाया गया है। नॉन टीचिंग स्टाँफ के अंदर चौकीदार नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है, सीनियर असिस्टेंट नहीं है, कलर्क नहीं है और पियन भी नहीं है जबकि आप सारे लोग मिलकर इनका धन्यवाद कर रहे हैं। आप बड़े खुश हो रहे हैं कि बहुत सारे संस्थान खुल गए और बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा होता कि इस अभिभाषण के अंदर आपने यह भी लिखा होता कि हम जसवां-प्रागपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक कॉलेज को बंद करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रही है कि कोटला-बैड़ के अंदर कॉलेज न खुले। लेकिन मैं यहां पर सदन में यह बता देना चाहता हूं कि वह कॉलेज खुलेगा और हम सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। आपने जो-जो किया है, चाहे हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी के ऊपर केस बनाए हों या आदरणीय धूमल जी के ऊपर केस बनाए हों, सरकार हर जगह पर उलटी गिरी है और हम सुप्रीम कोर्ट में हर बार जीते हैं। जहां हमारे साथ अन्याय हुआ है वहां कोर्ट ने हमें न्याय दिया है। मुझे लगता है कि हम इस केस में भी जीतेंगे क्योंकि आजकल उसकी बहस चल रही है।

सुबह रवि जी देहरा में सेंद्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। हम सेंद्रल यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं और मुख्य मंत्री वहां पर कॉलेज दे रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने भी कालेज नहीं मांगा। वहां सभी नेता और जनता सेंद्रल यूनिवर्सिटी मांग रही है और आप कॉलेज दे रहे हैं।

वहां 6 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज खुला है। वहां पर बच्चे बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आने वाले 4-5 सालों में आपने देख लेना कि वहां पर 100 से भी कम बच्चे रहेंगे क्योंकि वहां पर कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है।

सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में यहां पर लंबी चर्चा हुई। देहरा की 3500 कैनाल ज़मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम है। मैंने सुधीर भाई जी को कई बार बोला है कि इस

07.03.2017/1525/SLS-AG-3

सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर कांगड़ा को ठगा जा रहा है। न तो वह यूनिवर्सिटी धर्मशाला के अंदर खुलेगी और न वह देहरा में खुलेगी। आदरणीय रणधीर जी यह सही बात बोल रहे थे कि अभी कांगड़ा वाले नहीं समझेंगे, अभी तक इनको होश नहीं आएगा। वहां से जो मेरे साथ वाले विधायक हैं जो मेरे मित्र हैं, प्रेमी हैं, उनको भी अभी जानकारी नहीं है कि देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्या महत्ता है। वह सत्ता के नशे में चूर हैं। लेकिन मैंने बता दिया कि समय खराब आएगा। मुझे बड़ा दुःख होगा जिस समय लोग इनसे पूछेंगे कि हां भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करो।

जारी...श्री गर्ग जी

07/03/2017/1530/RG/AS/1

श्री विक्रम सिंह-----क्रमागत

मुझे लगता है कि यदि कल को जिले बन गए जैसे आज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऐट धर्मशाला है, तो मेरे वाला भी डिस्ट्रिक्ट देहरा ऐट ज्वालाजी होगा। क्योंकि जिस प्रकार का वहां काम चल रहा है, उससे मुझे ऐसा लगता है लेकिन जो-जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय के ऊपर चुप होकर बैठे हैं, मैं मानता हूं कि इन्होंने अपने क्षेत्रों में बहुत काम करवाया है, लेकिन केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर बिल्कुल चुप होकर बैठे हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं कहता

कि वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि हम बहुत ही qualitative education दे रहे हैं, तो मैं उस बारे में दो-तीन बातें यहां सदन में रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूजा कपूर नाम से एक हैं जिन्होंने पी.एच.डी. किया है और हिन्दी के पद के लिए उन्होंने आवेदन किया था। बेसिकली वे आपके चुनाव क्षेत्र से हैं, लेकिन शादी हमारे यहां हुई है। वह मेरीटोरियस है और टॉप आई हैं। जिस समय वहां उनके डॉक्यूमेंट्स लिए गए, तो उनके नंबर 57.54 थे, लेकिन वहां जो स्टाफ और विश्वविद्यालय में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने उस टेली शीट से अपने हाथ से उनके नंबर काटकर -3 करके उसको 54.54 कर दिया। इन्टरव्यू हो गया और उसके पश्चात उनका चयन नहीं हुआ। वह कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने यह डायरेक्शन दी कि जो इसके तीन नंबर काटे हैं, इसको तीन नंबर दिए जाएं। वह राज्यपाल महोदय के पास भी गई और कुलपति महोदय के पास भी गई। लेकिन उसे आज तक न्याय नहीं मिला।

उसको न्याय क्यों नहीं मिला क्योंकि वहां पर एक उम्मीदवार और है जो सामान्य वर्ग से है, लेकिन उस उम्मीदवार ने किसी अनुसूचित जाति के भाई से अन्तर्जातीय विवाह किया है। वहां क्या हुआ कि सामान्य वर्ग की उम्मीदवार ने जो नेट क्वालीफाई किया है वह अनुसूचित जाति वर्ग से किया, उसके बाद यू.जी.सी. पी.जी. स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति वर्ग से किया और उसके बाद उसने 'नेट' पास किया वह अनुसूचित जाति वर्ग से किया और इस सारी कैटागिरी के बारे में वहां पर काम करने वाले और वहां पर काम करने वाले रजिस्ट्रार या बड़े अधिकारी किसी ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। तो पूरा-का-पूरा घपला करने के बाद अब ऐसे उम्मीदवार की वहां नियुक्ति की गई है। आप कहते हैं कि हम बहुत पारदर्शी हैं और हम समग्र विकास करवा रहे हैं। इतनी बड़ी धांधली बिल्कुल नाक के नीचे यहां विश्वविद्यालय में हो रही

07/03/2017/1530/RG/AS/2

है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में पूरी चर्चा होनी चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यहां मेरे एक भाईसाहब कह रहे थे कि आप जाते-जाते कॉलेज खोल गए और उनमें छात्रों की संख्या बहुत कम थी। तो मैं इस बारे में यहां थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013 के बाद जो-जो कॉलेज खोले गए हैं उनमें जरा छात्रों की संख्या देखिए कि आज भी क्या है।

गवर्नमेंट कॉलेज, ननखड़ी -कुल छात्र 64, गवर्नमेंट कॉलेज फाईन आर्ट्स, शिमला- 55 छात्र, गवर्नमेंट कॉलेज, टिक्कर- छात्र 33, गवर्नमेंट कॉलेज, कोठी-छात्र 46, गवर्नमेंट कॉलेज, मझीण-छात्र 72, गवर्नमेंट कॉलेज, रक्कड़-छात्र 46, गवर्नमेंट कॉलेज, निरमण्ड-कुल छात्र 40. आप हमें यह बताते हैं कि आपने जो स्कूल-कॉलेज खोले थे उनमें बच्चे बहुत कम थे। आपने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आपका कॉलेज पिछले तीन सालों से प्राईमरी स्कूल में चल रहा है। उसमें कौन सा इन्फ्रास्ट्रक्चर है? अध्यापक और प्रवक्ता आपके पास नहीं हैं। इसलिए जो ये झूठी तालियां बज रही हैं और जो यहां सातवीं बार वाले सपने लिए जा रहे हैं, मैं ठाकुर कौल सिंह जी का बहुत आदर करता हूं, मैं इनसे कहूंगा कि आप इनके साथ (माननीय परिवहन मंत्री) जितना मर्जी जुड़कर बैठते रहें, ये बहुत चतुर्मुखी मंत्री हैं, लेकिन आपका हाथ ये नहीं लगने देंगे। आप इनके साथ बहुत जुड़कर बैठे हुए थे और इनकी बात आपने नहीं मानी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : आपको क्या फिक्र है?

श्री विक्रम सिंह : आप हमारे बड़े हैं, हमें आपकी फिक्र क्यों नहीं होगी? हम आपके शुभचिन्तक हैं, लेकिन आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही है और न ही आएगी। इधर नहीं आना आपने। हिन्दू संस्कृति में कहा जाता है कि जिस समय लड़के और लड़की की शादी होती है, तो उनके टिप्पणे बनाए जाते हैं, लेकिन जब आपके टिप्पणे में मुख्य मंत्री बनना लिखा ही नहीं है, तो मैं भी क्या करूं?

माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग के बारे में यहां बहुत चर्चा हुई है। कई बार मुझे लगता है-बाली साहब, आपको कौन सा बना रहे हैं, आप तो चुप होकर बैठे रहो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मेरे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को यह भी ध्यान में नहीं होगा कि मेरे क्षेत्र में कितनी सी.एच.सी. हैं? क्योंकि उनको पता नहीं होगा,

एम.एस. द्वारा जारी

07/03/2017/1535/MS/AG/1

श्री विक्रम सिंह जारी-----

क्योंकि उनसे कोई पूछता नहीं है और जिस समय यहां पर जवाब देना होता है कि फार्मासिस्ट्स कितने हैं और क्यों कम हो रहे हैं तो ये उनको सैटिस्फाई कर देते हैं लेकिन सारे-के-सारे मंत्रालय में इनका नाम जरूर है। कौल सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री जरूर हैं लेकिन स्वास्थ्य संस्थानों में क्या हो रहा है इसकी जानकारी इनको शायद नहीं है। जसवा-परागपुर विधान सभा क्षेत्र में पहले एक सी०एच०सी० थी, अब आपने चार वहां बना दी हैं। उसमें पैमाना रखा है कि 1 लाख 20 हजार के ऊपर एक सी०एच०सी० होगी। वह पैमाना भारत सरकार ने क्यों रखा था? सी०एच०सी० के ऊपर पैमाना इसलिए रखा है ताकि उस सी०एच०सी० के अंदर पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूरे डॉक्टर, फार्मासिस्ट्स और स्टाफ नर्सिज सहित पूरा स्टाफ हो। लेकिन मुख्य मंत्री जी यहां सोये हुए होते हैं और यहां से एक बन्दा भाषण देता है और वह कहता है कि सी०एच०सी० चाहिए और ये कह देते हैं कि ठीक है और बस हो गया। तो इस प्रकार से मेरे क्षेत्र के अंदर चार सी०एच०सी० हो गई हैं। अगर ये चार सी०एच०सी० काम करे तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद लिखकर भी करूंगा और पब्लिकली भी करूंगा लेकिन हालात क्या है? जो सी०एच०सी० कस्बा-कोटला की है जहां पर मेरा घर है, वहां पर सी०एच०सी० में कोई डॉक्टर ही नहीं है। -(व्यवधान)- अगर अब सी०एच०सी० बनी है तो क्या पहले वहां पी०एच०सी० में डॉक्टर नहीं होना चाहिए था? आप बताइए? -(व्यवधान)- वहां नहीं है, यह बात मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। यहां पर जो भी व्यक्ति बात करता है वह जिम्मेवारी के साथ करता है। जो आदरणीय रणधीर जी ने यहां पर फैक्ट्स एण्ड फीगर्स रखे हैं उसमें से एक भी गलत नहीं है लेकिन समस्या उनकी (मुख्य मंत्री जी की सीट की ओर इशारा करते हुए) यह है कि आप लोगों ने ऐसा जाल बुना हुआ है कि उनको आप कुछ भी पता ही नहीं लगने देते। इसलिए जो रणधीर जी ने बोला है वह बिल्कुल ठीक बोला है। वहां पर पुलिस ने क्या किया और पुलिस वालों ने क्या किया, वह सही बात है। जो ये चार सी०एच०सी० मेरे वहां पर खोली हैं इनमें से कस्बा-कोटला में डॉक्टर नहीं है। इसके अण्डर जो तीन सब-सेंटर्स आते हैं उनमें भी स्टाफ का एक मैम्बर नहीं है। इसी तरह से पूरे जसवा-परागपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर नौ सब-सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें एक भी स्टाफ मैम्बर नहीं है जैसे मेल हैल्थ सुपरवाइजर या मिड वाइफ या अन्य कोई भी नहीं है। -(व्यवधान)- स्वास्थ्य मंत्री जी, आप हर बार वहां से ऐसे ही हाथ हिलाकर कहते रहते हैं

07/03/2017/1535/MS/AG/2

जबकि आपसे कुछ नहीं होता है। इसी तरह से सी०एच०सी० डाडासीबा की बात करूंगा। वहां पर बी०एम०ओ० साहब बैठते हैं। उन्होंने 110 किलोमीटर के एरिये में जाना होता है लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं है। इन चीजों को आप यदि नोट करेंगे तो अच्छा होगा। वहां कोई हेल्थ एजुकेटर नहीं है। मेल हेल्थ सुपरवाइजर न डाडासीबा में है, न ही पीरसलूई में है और न ही परागपुर में है। सी०एच०सी० पीरसलूई में क्लास फोर और स्वीपर नहीं है और सी०एच०सी० रक्कड़ में भी स्वीपर नहीं है। पीरसलूई, डाडासीबा और कस्बा-कोटला में कोई भी रेडियोग्राफर नहीं है जबकि मशीनें हैं। आपने पोस्टें ही क्रिएट नहीं की हुई हैं। इसी तरह से संसारपुर टेरेस में ई०एस०आई० है लेकिन वहां पर न तो लैब है और न वहां पर कोई एक्सरे है। आप कल यहां बोल रहे थे कि आप यहां मेरे पास 500 डॉक्टर लाओ, मैं सभी को एप्वायंटमेंट दे दूंगा। यहां डॉक्टर ने आकर मार थोड़े ही खानी है। आपके लोग अगर डॉक्टर को डराएंगे, आपके लोग अगर काम करने वाले लोगों को डराएंगे तो क्या डॉक्टर आपके पास यहां आएंगे? जबकि यहां तो उलटा हो रहा है। जो डॉक्टर यहां लगे हैं वे यहां से रिजाइन देकर जा रहे हैं। आप अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर उनको अच्छा वातावरण नहीं देंगे तो डॉक्टर को जाने के लिए और भी स्थान हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन रहेगा कि आप एक अच्छा वातावरण लाइए। -(व्यवधान)-स्वास्थ्य मंत्री जी, कानून कहां से लाएंगे। उन्होंने (मुख्य मंत्री जी की सीट की ओर इशारा करते हुए) आपको कानून लाने ही नहीं देना। आपके पास कुछ भी नहीं है। सड़कों के ऊपर भी यहां बहुत अच्छी बातें हुई कि सड़कें बहुत अच्छी हैं लेकिन जसवां-परागपुर के अंदर कोई सड़क अच्छी नहीं है। जसवां-परागपुर के अंदर जो विधायक प्राथमिकता देता है उन प्राथमिकताओं के ऊपर कुछ नहीं होता है। आज चार वर्षों के अंदर जितनी भी मैंने प्राथमिकताएं दी हैं उनमें से किसी एक की भी डी०पी०आर० नहीं बनी है। जो यहां मैंने प्रश्न किए हैं उनमें से भी किसी एक की फॉरैस्ट क्लीयरेंस नहीं हुई है। आप कह रहे हैं समग्र विकास, समान विकास और बहुत बड़ा विकास? कहां विकास हो रहा है? यहां पर नेशनल हाइवेज के ऊपर चर्चा हो रही थी। वहां से हाथ उठते हैं कि नेशनल हाइवे तो है ही कुछ नहीं। यहां पर नोटिफाइड हुए हैं मेरे पास पूरी-की-पूरी चिट्ठी है। आपने हमारे

यहां की सड़कों की हालत सुधारने के लिए जो तीन-तीन नेशनल हाइवेज दिए उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हालांकि काम तो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर

07/03/2017/1535/MS/AG/3

कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपकी नीयत ऐसी है कि आपको लगता है कि यदि काम अच्छा होगा तो उस कारण से लोग मोदी जी की जय-जयकार करेंगे। लेकिन आप काम को कितनी देर रोक कर रखेंगे? इसी प्रकार से आदरणीय पंचायती राज मंत्री जी यहां बैठे हैं। आपके विभाग में भी यही हो रहा है। आपको यह लगता है कि यदि पंचायतों को शक्तियां दे दी,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा"-----

07.03.2017/1540/जेके/डीसी/1

श्री बिक्रम सिंह:-----जारी-----

पंचायतों को सीधा पैसा केन्द्र से आ रहा है, अगर यह पैसा गलियों में लग गया, अगर गलियों में सोलर लाईट लग गई, अगर गलियों के अन्दर स्वच्छता अभियान हो गया और जिस समय पंचायतों के अन्दर बैठ करके यह बात होगी कि यह सारे का सारा पैसा 14वें वित्तायोग के अन्दर आया है, आपने हर तरीके का फार्मूला लगा करके 14वें वित्तायोग के पैसे को रोका है। 14वें वित्तायोग का पैसा गांवों के विकास के लिए न लगें, आपने बार-बार उसके लिए रोड़े अटकाए हैं। कभी एक नोटिफिकेशन करवाई कभी दूसरी नोटिफिकेशन करवाई। आपके पास सबसे पहले यह किश्त 5 मार्च को आई, अगर मैं गलत बोलूंगा तो बाद में उसको बता दें। जो पहली किश्त आई है वह 5 मार्च, 2016 को आई है। दूसरी किश्त 3.9.2016 को आई है। तीसरी किश्त 23.13.2016 को आई है और चौथी किश्त 18.01.2017 को आ गई। 80-80 लाख रूपया सीधा केन्द्र सरकार से पंचायतों को जाएगा और उससे पंचायतों का विकास होगा। मुझे समझ ही नहीं आता है कि पंचायतों के अन्दर इस प्रकार से काम क्यों हो रहा है? आपने एक और पता नहीं कौन सा फरमान जारी कर दिया पंचायती राज पत्र संख्या: 13-13688, दिनांक 13 .01.2017 ये आपने कोई नई चीज

निकाली है। इसके अनुसार काम ही नहीं हो सकता है, विकास बन्द हो जाएगा। मैं तो बाकी विधायकों से भी निवेदन करूंगा कि इस नोटिफिकेशन को क्वेश करवाएं। पैरा नम्बर-2 में लिखा है कि यदि विकास कार्य निजी भूमि पर होने हैं तो इसके लिए सर्वप्रथम निजी भूमि के मालिक से आग्रह किया जाए कि वह अपनी निजी भूमि राज्य सरकार के नाम वैध प्रभार दस्तावेज यानि वैलिड गिफ्ट डीड द्वारा समर्पित करें। निजी भूमि के मालिक द्वारा वैध प्रभार दस्तावेज खंड विकास अधिकारी को सौंपने के पश्चात यह सुनिश्चित किया जाए कि इस वैध प्रभार दस्तावेज में प्रविष्टि राज्य सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में हो गई है। आप मुझे बताएं कि यदि किसी गांव के अन्दर रास्ता बनना होगा तो उस रास्ते को बनाने के लिए प्राईवेट लैंड में से अगर कोई रास्ता देता है, उससे एफिडेविट तो आप लेते हैं, आप उसकी गिफ्ट डीड कराएंगें? यह दर्ज है 13.01.2017 । मैं चाहूंगा कि पंचायती राज मंत्री इसकी ओर ध्यान दें। इसके कारण सारे का सारा पैसा रुक जाएगा। अभी बी0डी0ओज0 ने जो पैसा एम0एल0ए0 फंड का आया है, एम0पी0 फंड का आया है उसके ऊपर काम करने के लिए रोक लगा दी है। बाकी जगह क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे यहां पर तो यह शुरू हो गया है। फिर मैंने कहा कि कहीं अपनी मर्जी तो नहीं कर रहे हैं तो हमने

07.03.2017/1540/जेके/डीसी/2

पत्र निकाला तो वह पत्र सही निकला। मेरा निवेदन पंचायती राज मंत्री जी से रहेगा कि वे इसकी ओर ध्यान दें। यहां पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही थी और कहा गया कि मुख्य मंत्री जी ने दूसरी राजधानी बना दी। बहुत सी चर्चा इसके ऊपर चलती है। ये तो ऐसे मुख्य मंत्री हैं, यदि इनको कहीं मौका मिल जाए कि देश की राजधानी तो नहीं बनानी तो यह देश की राजधानी हिमाचल प्रदेश में बना दें। ये कुछ भी कर सकते हैं। मुख्य मंत्री जी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर ये प्राईमरी स्कूल को सीनियर सैकंडरी स्कूल बना सकते हैं, सिविल डिस्पेंसरी को सी0एच0सी0 बना सकते हैं तो ये देश की राजधानी भी घोषित कर सकते हैं। इसलिए गट्स नहीं चाहिए इसके लिए दिमाग चाहिए। वो इनके पास नहीं है। ये उल्टा चलेंगे। आप कभी नहीं चाहेंगे कि विकास हो। आपका तो बस यही है कि किसी न किसी तरीके से नारा लगाया जाए और उससे शायद हमारी सरकार आ जाएगी। इस बार इन बातों की तरफ ध्यान दें इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूं। आप सभी हमारे मित्र हैं, हम चाहते हैं कि आप यहां वापिस आए लेकिन जैसे कारनामों आप प्रदेश के अन्दर कर रहे हैं,

इस तरह से आपका निशान नहीं मिलेगा। जैसे हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस का निशान मिट रहा है, हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी वही हालात होने वाले हैं। आप झूठी बातें करेंगे, झूठी घोषणाएं करेंगे, झूठे इंस्टिच्यूशनज़ देंगे, झूठे हैल्थ इंस्टिच्यूशनज़ खोलेंगे तो निश्चित तौर पर लोग इन चीजों को देख रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अभी भी थोड़ा इन चीजों को ठीक करें। मेरे मित्र यहां पर बैठे हैं। आदरणीय श्री अग्निहोत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, सिर्फ पांच मिनट में मैं खत्म कर दूंगा और सभी को आपने काफी टाईम दिया है।

अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें क्योंकि बोलने वाले माननीय सदस्य अभी बहुत हैं।

श्री विक्रम सिंह: मैं अग्निहोत्री जी का बड़ा-बड़ा धन्यवाद करता लेकिन ये चले गए। बरोटीवाला में काम हुआ है। बंदी में काम हुआ है अच्छी बात है। लेकिन मेरे क्षेत्र में संसारपुर टैरेस इंडस्ट्री एरिया पड़ता है और आप मेरे बड़े अच्छे मित्र भी है और बड़ा पुराना हमारा रिश्ता है। पता नहीं आपके दिमाग में क्या चीज है। वहां पर कोई ऐसा बन्दा इलैक्शन भी नहीं लड़ रहा है जो आपका मित्र है। वहां पर इंडस्ट्री एरिया के अन्दर एक भी अच्छी इंडस्ट्री पिछले चार वर्षों में नहीं लगी

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

07.03.2017/1545/SS-DC/1

श्री विक्रम सिंह क्रमागत:

और आप जिस समय बोलते हैं तो बड़े-बड़े दावे करते हैं। उद्योग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के समय में चार वर्षों के अंदर 16163 करोड़ का निवेश हुआ था जबकि कांग्रेस सरकार के समय में चार वर्षों के अंदर 13263 करोड़ का निवेश हुआ है। आपने (उद्योग मंत्री) एक बात और समझा कर जाना, शायद आपने बोलना है तो उस समय जवाब देना। आपकी सीमेंट की बोरी वाला फंडा हमारे समझ नहीं आया है। आप यहां पर बैठकर बोलते हैं कि मैं बड़ी जल्दी सीमेंट वालों के साथ बैठकर बातचीत करूंगा। पंजाब के अंदर सीमेंट

की बोरी का रेट 300 रुपये है और हमारे यहां जहां सब कुछ बनता है वहां पर सीमेंट की बोरी का रेट 375 रुपये है। अब इसके पीछे क्या बातचीत है, वह आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या टैक्निकल प्रॉब्लम है। किस कारण से ऐसा है। लेकिन मैं यह चाहूंगा, आप बड़े योग्य मंत्री हैं, सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, आप बड़े दूरदर्शी हैं, यह जो समस्या है आप हमें इससे निजात दिलाइये। पंचायत के अंदर विकास करना है और बाकी लोगों ने अपने घर बनाने हैं या कोई अन्य काम करना है तो उसके लिए यह सीमेंट की बोरी बहुत महंगी है। हमारे बिल्कुल साथ के क्षेत्र में इसमें 75 रुपये का फर्क है, इससे ब्लैकमेलिंग भी होती है, इसको आप ठीक करेंगे इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। एक बात यहां बहुत जोरों से बार-बार कही गई। मैं तो जनरल कैटेगिरी से आया हूं यहां पर हमारे ओबीसी/एससी/एसटी भाई बैठे हैं वे भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मुझे बताइये कि जब पीटीए की भर्तियां होती हैं तो उस पर क्यों खुश होते हैं? एसएमसी की भर्ती होती है तो उस पर क्यों खुश होते हैं? आउटसोर्स पर भर्ती हो रही है तो उसके ऊपर भी आप ताली लगा रहे हैं। आज मेरे आदरणीय श्री किशोरी लाल चाचा जी यहां नहीं हैं वे कल बड़े ज्यादा खुश थे। बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। इन तीनों कैटेगिरीज के अंदर रोस्टर नहीं लग रहा। आज आप यहां पर इकट्ठे होकर बोलते हैं, अब यहां पर बात आती है कि आउटसोर्स पर नीति बनायेंगे। एक कम्पनी के किसी जनरल मैनेजर ने बैठकर इंटरव्यू किया, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की

07.03.2017/1545/SS-DC/2

बात नहीं आई, जिसके अंदर कोई रोस्टर नहीं लगा, जिसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर मैरिट नहीं बनी, वह कम्पनी यहां पर भर्ती के लिए बंदे भेज रही है, आप कह रहे हैं कि आप उसके ऊपर नीति बनायेंगे। काहे की नीति बनायेंगे? आपकी तो यहां इंवोल्वमेंट नहीं है। आपके सर्विस कमिशन और सबोर्डिनेट सर्विस कमिशन की कोई इंवोल्वमेंट नहीं है। बाकियों के लिए भर्ती करनी हो तो एजुकेशन बोर्ड है लेकिन यहां पर

आपने सारा काम आउटसोर्स पर रखा हुआ है। यह सारा काम पिछले दरवाजे से भर्तियां करने की बात है। इसलिए जिस समय पिछले दरवाजे से भर्तियां की जाती हैं और बात होती है तो आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बड़ा बुरा लगता है। अभी माननीय सदन में वे उपस्थित नहीं हैं। नहीं तो उन्होंने बोलना था कि आप एफिडेविट दें। इसमें क्या एफिडेविट देना? आप कर रहे हैं और आउटसोर्स किस आधार पर हो रहा है? इसलिए यह जो बातें हैं चाहे वह आउटसोर्स का विषय हो, चाहे कोई दूसरे विषय हों, चाहे वह पी0टी0ए0 है या एस0एम0सी0 है, अगर उसके ऊपर रोस्टर नहीं लग रहा तो मेरे मित्रों जो उनके नाम पर वोटें लेकर आए हैं वे चुनाव हारने के लिए तैयार हो जाओ। उनको कोई नहीं बख्शेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जो बातें कही गई हैं, बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं। अच्छा होता अगर इस अभिभाषण के अंदर यह भी लिखा होता कि हम कॉलेज बंद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे। इसमें यह लिखा होता कि हमने फॉरैस्ट की क्लीयरेंसिज़ नहीं की हैं। इसमें यह लिखा होता कि आपके क्षेत्र के अंदर हम इंडस्ट्री नहीं लगा सके। इसमें यह लिखा होता कि 14वें वित्तायोग का पैसा हमने जान-बूझकर रोका है। इसमें यह लिखा होता कि जो हैल्थ इंस्ट्र्यूशन्ज़ हैं उनकी पॉजिशन बड़ी पूअर है तो मुझे लगता कि हम इसका समर्थन करते। ऐसा कोई विषय इसमें नहीं है इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। बहुत-बहुत धन्यवाद।

07.03.2017/1545/SS-DC/2

अध्यक्ष: अब श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक मार्च, 2017 को इस माननीय सदन में अभिभाषण दिया, जिस पर धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री जगजीवन पाल जी, जोकि अभी सदन में उपस्थित नहीं है, ने यहां पर रखा है और जिसका अनुमोदन श्री

संजय रतन जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बोलना नहीं था, मगर इसलिए बोलना पड़ रहा है

जारी श्रीमती के0एस0

07.03.2017/1550/केएस/एजी/1

श्रीमती आशा कुमारी जारी----

क्योंकि मेरे भाई-बन्धु जो उस तरफ से बोल रहे हैं, उनके या तो पढ़ने की क्षमता में कमी आ गई है या समझ में कमी आ गई है। यह जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, यहां पर सदन में बहुत से ऐसे साथी हैं जो बहुत लम्बे अरसे से इस माननीय सदन के सदस्य हैं और कुछ नए साथी भी हैं। नए साथी और जो पुराने साथी हैं, उनके आचरण का फर्क भी नज़र आता है। बात पुराने साथी भी करते हैं परन्तु बात करने का एक तरीका होता है। यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पांचवी-पांचवी, छठी-छठी बार सदस्य बन कर आए हैं वे काफी होमवर्क भी करते हैं। हमारी तरफ से भी आए हैं और वीरभद्र सिंह जी तो शायद तेरह बार जीतें हैं पार्लियामेंट और विधान सभा को मिला कर। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है तेरह या ग्यारहवीं बार जीतकर ये आए हैं लेकिन जो भी जीतकर आए हैं, वे चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के सदस्य हों, उनका अपना अच्छा आचरण रहा होगा, उन्होंने अच्छे काम किए होंगे और वे सरकार में भी बैठे हैं और विपक्ष में भी बैठे हैं। कुछ जो नए माननीय सदस्य आए हैं, हमारी तरफ आए हैं वे सरकार में बैठे हैं और कुछ आपकी तरफ पहली बार आए हैं तो वे विपक्ष में बैठे हैं। आगे किसका क्या होता है, यह समय बताएगा।

अध्यक्ष महोदय, यह जो अभिभाषण यहां राज्यपाल महोदय ने पढ़ा, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे सदस्य जिन्होंने कल भी बोला, पहले दिन भी बोला और आज भी बोला, यह कहा गया कि राज्यपाल महोदय से यह पढ़ा दिया, वह पढ़ा दिया। गवर्नर साहब हमेशा चाहे देवव्रत जी हैं, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, चाहे कोई और गवर्नर थे। सरकार जो अपनी केबिनेट में, धूमल जी आप भी केबिनेट मंत्री रहे हैं, मुख्य मंत्री रहे हैं, जो आप अभिभाषण तैयार करते हैं, गवर्नर यहां आकर उसको डिलीवर करते हैं which is based on the facts and figures given by the Government. इसमें जो कुछ भी लिखा

हुआ है, ये फैक्ट्स और फीगर्ज विभागों के हैं जो यहां पर अलग-अलग विभागों ने अपनी अचीवमेंट्स की है। मैं मुख्य मंत्री और इनकी सरकार को बधाई देना चाहूंगी,

07.03.2017/1550/केएस/एजी/2

विशेषकर एच.पी. युनिवर्सिटी को लेकर जिसको ग्रेड-ए का एक््रेडिटेशन मिला यह कोई छोटी बात नहीं है। बिक्रम सिंह जी बोल रहे थे कि युनिवर्सिटी में कोई सिलैक्शन हुई जिसमें नम्बर ही आगे-पीछे कर दिए गए। तो बिक्रम जी, युनिवर्सिटी के हैड व चांसलर महामहिम होते हैं। It is well within his right. अगर आप उनके पास यह बात रेज़ कर दें और वे ऐक्शन न ले तो उसके लिए आप इस सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं युनिवर्सिटी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहती मगर आपकी सरकार के ऐसे भी मंत्री थे जिन्होंने अपनी पत्नी को भी ऐसे ही लगाया है। मैं उस बारे में चर्चा नहीं करूंगी और वे मेरे मित्र भी है। मैं चर्चा इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि वह व्यक्ति आज इस माननीय सदन का सदस्य नहीं है। अगर वे यहां होते तो मैं उनका नाम ले कर बोलती। वे आपकी सरकार में मंत्री थे परन्तु वे आज इस माननीय सदन में नहीं है। आप खुद जानते हैं कि वे कौन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी इसलिए इस तरह की बातें आप रेज़ न करें तो बेहतर होगा।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बड़ी चर्चा की गई कि स्वास्थ्य सेवाएं चर्मरा गई है। मैं तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। आपने तीन मैडिकल कॉलेजिज़ को खोलने के लिए जिसमें से कि नाहन का ऑलरेडी वर्किंग है और उसमें फर्स्ट बैच बैठ गया है। आपको उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। चम्बा कॉलेज के लिए आपने बहुत प्रयास किया। आपने मुझसे भी बात की। हम सभी ने मिल कर आपको अखंड चंडी पैलेस को यूज़ करने के लिए पर्मिशन दी। फैकल्टी के लिए आपने दिल्ली में पूरा जोर लगाया हुआ है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

7.3.2017/1555/av/AG/1

श्रीमती आशा कुमारी----- जारी

मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि जो दिल्ली में (---व्यवधान---) भारत सरकार का धन्यवाद मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली में भारत सरकार में हमारे ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनको तो चाहिए था कि वे आगे आकर फैकल्टी को मन्जूर करवाते न कि उस फाइल के ऊपर बैठ जाते। हमने आपको जगह दे दी है। हमने आपको पूरा महल दे दिया है। उसमें पहले कालेज चल रहा था। अब कालेज की नई बिल्डिंग बन गई है। महल की रेनोवेशन के लिए ए0डी0बी0 से 5 करोड़ रुपये की राशि आई। स्वास्थ्य मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर जी ने कहा कि हमें यह महल मेडिकल कालेज चलाने के लिए चाहिए और हमने इनको वह हैंड ओवर कर दिया। आप इनसे पूछ लीजिए और मेडिकल काउंसिल ने उसको अप्रूव भी कर दिया है। लेकिन फैकल्टी के लिए आपके गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया में बैठे हुए हैं और हमीरपुर में (---व्यवधान---) किसका? (श्री प्रेम कुमार धूमल जी से पूछा।) हम एम0सी0आई0 का धन्यवाद करेंगे, केंद्रीय मंत्री ने क्या किया? वह तो फैकल्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। (---व्यवधान---) उन्होंने इसलिए भेजा क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने उसको पहले से अप्रूव किया हुआ था, उनको मजबूरी में भेजना पड़ा। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमीरपुर मेडिकल कालेज के लिए लैंड तथा बाकी चीजों के लिए अपने सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों का फायदे उठाते हुए हमें केंद्र सरकार से पैसा दिलवाएं ताकि हमारा यह कालेज चालू हो सके। मैं ठाकुर कौल सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारी डलहौजी के होस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार ने इससे पिछली टर्म में यानि वर्ष 2003 से 2007 के दौरान पैसा दिया। बिल्डिंग का काम चालू हो गया मगर बीच में सरकार बदल गई और पांच साल उसमें एक ईंट तक नहीं लगी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने उसके लिए तीन करोड़ रुपये दिए और आज वह बिल्डिंग इनोग्रेशन के लिए तैयार है। We are highly grateful to you. डलहौजी में मेरे ख्याल से यह 50 बैडिड होस्पिटल शायद प्रदेश का सैकिण्ड सेंटरली हीटिड होस्पिटल होगा जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने बाथरी में सी0एच0सी0 दी है और हमें डॉक्टर दिए हैं। हमारे दूरदराज के एरिया में आपने डॉक्टर भेजे हैं। यह ठीक है कि आपके पास 500 डॉक्टर की कमी है और आप कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ऐसी चीज नहीं है कि आप

उनके स्थान पर किसी को भी लगा दें। आप एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारक को ही डॉक्टर लगा सकते हैं। आप प्रयास कर रहे हैं इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। यहां पर दो-

7.3.2017/1555/av/AG/2

तीन दिन से, जब से चर्चा शुरू हुई है यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि मेरे विपक्ष के माननीय साथियों का राजधानी को लेकर के क्या रवैया है। Are you for Dharamshala or are you against Dharamshala? आप अपना स्टैंड (---व्यवधान---) Let me speak, Mr. Hans Raj. Let me speak. सिर्फ रविन्द्र रवि जी ने धर्मशाला में राजधानी के लिए कहा कि मैं स्वागत करता हूं। मगर आपने भी किन्तु-परन्तु; काफी सारे लगाये। (---व्यवधान---) आपने किन्तु-परन्तु लगाये मगर आपने धन्यवाद किया। लेकिन जो आपके पीछे बैठे हैं इनका मुझे लगता है कि राजधानी बंद करवाना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं कि वहां पर राजधानी हो। (---व्यवधान---) आप अपना रवैया स्पष्ट कीजिए। Are you for the capital or are you against the capital? मुझे वह दिन याद है। मैं भी इस सदन की सदस्य थी। यहां से महेन्द्र सिंह जी उठकर चले गये हैं। रवि जी, मुझे याद नहीं है जब धर्मशाला में प्रयास भवन में विधान सभा का पहला सत्र हुआ था क्या आप थे? आप थे, उस समय गुलाब सिंह जी थे और महेन्द्र सिंह जी थे। प्रयास भवन में जब विधान सभा का पहला सत्र हुआ तो ये सारे लोग कहते थे कि इसका क्या फायदा। अब काजल जी यहां पर माननीय सदस्य हैं। वहां पर सात महीने के अंदर विधान सभा की बिल्डिंग बन कर तैयार हुई। सात महीने में तैयार हुई और उसी का नतीजा है कि आज ये यहां विधान सभा में बैठे हुए हैं। इन्होंने ही उस विधान सभा भवन का निर्माण किया। मैं आपको यह बात इसलिए कह रही हूं कि वह विधान सभा उस वक्त बनी और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप लोक सभा के साथ मिलकर उस विधान सभा में नेशनल ट्रेनिंग इनस्टिट्यूट लाना चाह रहे हैं जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पूरे हिन्दुस्तान के लैजिस्लेटर्स ट्रेनिंग करने के लिए धर्मशाला के विधान सभा भवन में आयेंगे।

श्री वर्मा द्वारा जारी

07/03/2017/1600/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

श्रीमती आशा कुमारी .. जारी

उसकी बातचीत आपके माध्यम से लोक सभा से चल रही है। -(व्यवधान)- आपका (विपक्ष) तो यह है कि जो अच्छा है, वह मैंने किया और जो बुरा हुआ वह तुमने किया। आपका जो स्टैंड है, आप उसको क्लीयर रखो और क्लीयर करो। आपका राजधानी के बारे में स्टैंड आपकी पार्टी में ही क्लीयर नहीं है। आप उसका समर्थन कर रहे हैं और आपके पीछे बैठें, उसको अपोज कर रहे हैं। -(व्यवधान)- श्री विजय अग्निहोत्री जी आप पहली बार आये हैं, हम चाहते हैं आप बार-बार आये। आप जरा रूल्ज़ का ध्यान रखें। Please, don't interrupt. अध्यक्ष महोदय विक्रम जी ने एक और बात कही थी कि वीरभद्र जी कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने ये कहा कि वीरभद्र सिंह जी कि अगर चले तो वे हिमाचल प्रदेश को देश की राजधानी बना सकते हैं। It will be the proudest day for Himachal Pradesh अगर देश की राजधानी एक फिर हिमाचल आये। हिमाचल प्रदेश देश की राजधानी पहले भी थी और जिस दिन फिर से आयेगी, उस दिन हम श्री सुरेश भारद्वाज जी से पूछेंगे कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ये कोई लम्बी/बड़ी सोच वाला व्यक्ति ही हिन्दुस्तान की राजधानी को वापिस शिमला में ला सकता है और ऐसा करने की क्षमता सिर्फ वीरभद्र सिंह जी में ही है, आपमें नहीं है। अध्यक्ष महोदय, श्री रणधीर जी कह रहे थे कि एक राजधानी शिमला हो गई है और दूसरी राजधानी धर्मशाला हो गई है। वे कह रहे थे कि बिलासपुर को माफिया राजधानी घोषित किया जाये। I am really amazed that an elected member from a district can call his district a Mafia. ये इमेजिंग बात है। -(व्यवधान)- हंसराज जी आप पहली बार आये हैं, हम चाहते हैं कि आप फिर रिपीट हो।,..(Interruption).. Don't do this. This not a game going on here. बास्केट में टाईम आउट होता है, ये विधान सभा है। इसलिए सीखिये। अध्यक्ष महोदय, रणधीर जी अपने भाषण में कह रहे थे और ड्रग्स को लेकर बड़ी चिन्ता जता रहे थे। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि इन पिछले चार सालों में 2000 लोग अरेस्ट हुए और 3000 एफ0आई0आरज0 रजिस्टर्ड हुई है। प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ़ एक अभियान चला हुआ है। मुझे इसलिए भी बड़ी हैरानी हुई कि उस पार्टी के लोग ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जो पड़ोसी राज्य में ड्रग लॉर्ड/ड्रग माफिया के साथ सरकार में मंत्री बनकर बैठे हुए थे। सबको मालूम है कि पंजाब में ड्रग्स का सरगना कौन है? ये आप सब जानते हैं। प्राइवेटली

आप मेरे से एडमिट भी करते हैं। आप लोग उस सरकार में हैं, जहां पर चिट्टे का चलन है और पंजाब में चिट्टा-वार- लॉर्ड और ड्रग माफिया कौन है? ये सारी दुनियां जानती हैं।

07/03/2017/1600/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

जब आपकी पार्टी/सरकार के मंत्री जफ्फी डालकर बैठते रहे, वहां रोकने के लिए आपने प्रयास क्यों नहीं किया? -(व्यवधान)- मुझे तो लगता है कि चिट्टा हिमाचल का है ही नहीं। यह पंजाब से ओवर-फलो होकर यहां आया है। -(व्यवधान)- - No, again I don't want to name that person. Because he is not a member of this House. ये सब पंजाब से आ रहा है। -(व्यवधान)- अध्यक्ष महोदय, दूसरी स्टेट का कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए एस्पशर्न्ज कॉस्ट करें it has no legal binding.

श्रीमती एन0एस0- - - द्वारा जारी।

07/03/2017/1605/ ns/as /1

श्रीमती आशा कुमारी----- जारी

अगर हिमाचल प्रदेश का डी0जी0 कहता है कि these drugs are going from Himachal Pradesh than we believe it. दूसरे स्टेट का आदमी अपनी चमड़ी बचाने के लिए हिमाचल को बदनाम कर रहा है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इस एफिडेविट को और हमारे कानून मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, आप इस एफिडेविट को मंगवाईए और पता कीजिए कि किसने इसको फाईल किया है? You kindly file an affidavit on behalf of the Government of Himachal. यह हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। हरियाणा का क्या है? (व्यवधान) You sit please. I am not yielding to you. You are an old parliamentarian (व्यवधान) उसको रोकने के लिए करना कोई बुरी बात नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय रणधीर जी ने मंदिरों के

बारे में चर्चा की। इन्होंने कहा कि मंदिरों का पैसा मिसयूज़ हो रहा है। मैं नहीं समझती कि मंदिरों का पैसा मिसयूज़ हो रहा है। मंदिरों का पैसा जन-कल्याण के लिए यूज हो रहा है और अगर बाईचांस रणधीर जी के पास किसी स्पैसिफिक केस में कोई इनसाईड इनफॉर्मेशन है तो इसे सरकार के ध्यान में अवश्य लाएं तथा निश्चित तौर पर सरकार उस पर एक्शन लेगी। मगर जनरलाईज़ करके यह कहना कि सारा पैसा मिसयूज़ हो रहा है ENG मंदिरों का पैसा बहुत अच्छे कामों के लिए भी लग रहा है। मेरे यहां एक छोटा मंदिर है और वहां पर इतने पैसे नहीं हैं जितने श्री नैना देवी या ज्वाला जी में हों लेकिन फिर भी काफी धनराशि वहां आती है। वहां पर लड़कियों को सिलाई मशीन दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और उनकी शादियों के लिए पैसे दिये जाते हैं। अगर किसी के घर में छोटा-सा फंक्शन हो उसके लिए भी पैसे दिए जाते हैं। इस तरह के काम मंदिर करते हैं। वहां पर फ्री लंगर लगता है। मंदिर नियास वाले वहां पर जो लोग आते हैं उनको बर्तन आदि भी देते हैं। मगर इस तरह से जनरलाईज़ करना श्री बिक्रम जी आपकी बात नहीं चलेगी। आपने कहा कि मेरे यहां तीन कॉलेज खोल दिए हैं और चार पी0एच0सीज0 खोल दी हैं। आप लिख करके दीजिए। I assure you कि आज शाम तक चारों के चारों डिनोटिफाई करवा देंगे। आप अभी लिख कर दीजिए। (व्यवधान) आप बोल रहे थे मैं नहीं

07/03/2017/1605/ ns/as /2

बोल रही थी। Speaker, Sir, I don't yield to him. अगर आपको बंद करवाने हैं तो अभी लिख कर दीजिए। माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी यह कह रहे थे कि वीरभद्र जी आप किसी ओर जिले से मुख्य मंत्री क्यों नहीं बना देते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं कि पता नहीं आपकी पार्टी में क्या चलन होगा पर हमारी पार्टी में सबसे काबिल और सबसे वरिष्ठ और जो व्यक्ति सबको साथ ले करके चलता है तथा हिमाचल का कल्याण करता है, उसको हम सब मिल करके मुख्य मंत्री बनाते हैं। हमारी पसंद वीरभद्र जी हैं आपको क्या तकलीफ है? (व्यवधान) मैं अपने मन से नहीं बल्कि मैं 39 के मन से बोल रही हूं। आप चिन्ता मत कीजिए। चुनाव के बाद आप वहां घटी हुई दरों में होंगे और हम यहां पर ओर

बढ़ करके आएंगे तथा निश्चित तौर पर हमारे मुख्य मंत्री वही होंगे। (व्यवधान) जिस तरह की राजनीति हमारे देश में हो रही है यह कोई अच्छी बात नहीं है। हम जब खड़े हों just criticism for the sake of criticism क्षेत्रवाद की बातें और हमेशा क्रिटीसाईज़ करना तथा जो अच्छा काम हुआ है उसकी भी चर्चा नहीं करना यह अच्छी बात नहीं है।

श्री आर०के०एस०-----जारी

07/03/2017/1610/RKS/DC/1

श्रीमती आशा कुमारी....जारी

अध्यक्ष जी, हमने अपने राजनीतिक, छात्रा और हाउसवाइफ के जीवन में बहुत लोगों से प्रेरणा ली। शायद राजनीति में हमारी यह कमी रह गई कि हमने कभी 'गधे' से प्रेरणा नहीं ली। हमारी पार्टी में यह कमी रह गई कि हमारी पार्टी ने कभी 'गधे' से प्रेरणा नहीं ली। (व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, इनको क्या परेशानी हो गई। (व्यवधान)... मैंने तो सिर्फ यह कहा कि हमने अपने जीवन में महापुरुषों, ऋषि-मुनियों, गीता व कुरान से प्रेरणा ली। (व्यवधान)... Mr. Hans Raj, don't take names. (व्यवधान)... आप क्या कह रहे हैं you took a name sitting there. Don't you do that? --(Interruption)-- No, no. Tell him to withdraw his words.--(Interruption)-- How dare you?-- (Interruption)--. You, sit down.

अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। (व्यवधान)... This is a wrong thing.

श्रीमती आशा कुमारी: (व्यवधान)... मैंने तो किसी को नहीं कहा (व्यवधान)... मैंने बोला इनको (व्यवधान)... बैठो। You sit down व्यवधान)... क्या हुआ (व्यवधान)।

Speaker: You all are commenting. --- (Interruption) --- Why did you comment? --- (Interruption) --- Let her Speak.

Smt. Asha Kumari: I am standing; I am not going to sit... (व्यवधान)... आपकी ऑब्जेक्शन क्या है। ---(Interruption)---. What is your objection?--- (Interruption)---. Tell him to sit down. ---(Interruption)--- No, I am on my legs, I am speaking. I am not going to sit down. Tell him to sit down.

अध्यक्ष: आप प्लीज बैठ जाइए, let her speak (व्यवधान)...

Shri Suresh Bhardwaj: Speaker, Sir, Point of Order.

07/03/2017/1610/RKS/DC/2

श्रीमती आशा कुमारी: मैं अकेली महिला हूँ। (व्यवधान)... क्या आप महिला विरोधी हो? अध्यक्ष महोदय, this is very unfortunate. मैं यह कह रही हूँ कि शायद अपने राजनीतिक जीवन में मैंने 'गधे' से प्रेरणा नहीं ली। (व्यवधान)... तो इसमें इनको क्या तकलीफ है। (व्यवधान) मैंने नहीं ली। (व्यवधान)...

श्री एस० एल० एस० द्वारा जारी...

07.03.2017/1615/SLS-DC-1

श्रीमती आशा कुमारी...जारी

अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : भारद्वाज जी, आप पहले अपने पक्ष के सदस्यों को चुप कराइए। ...(व्यवधान)... भारद्वाज जी, अब आप बोलिए। ...(व्यवधान)... आप बाकी सब लोग बैठ जाएं। ...(व्यवधान)...

Shri Suresh Bhardwaj: Sir, I am on point of order, आप मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर तो सुन लीजिए। ... (व्यवधान) ... क्या आप हाऊस नहीं चलाना चाहते?

अध्यक्ष : मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बोलिए जबकि आप कह रहे हैं कि हाऊस नहीं चलाना चाहते। आप बोलिए।

Smt. Asha Kumari: Shri Suresh Bhardwaj Ji, I am willing to yield to you --- (interruption)--- Bhardwaj Sahib, you want to speak---(interruption)--- If you say I will yield to you. But no shouting like that.

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में सभी सदस्य बराबर हैं। यहां पर जुनियर और सीनियर का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। फिर नाम लेकर बार-बार यह कहना कि मिस्टर तुम जुनियर हो, बैठ जाओ, तुम क्यों बोल रहे हो, यह कोई शोभनीय बात नहीं है। हम आशा कुमारी जी की बहुत ही रिसपैक्ट करते हैं। ये नेशनल लीडर है और बहुत अच्छी लैजिस्लेटर भी है। लेकिन इनको भी शब्दों का प्रयोग बहुत देखकर और सोचकर करना पड़ेगा कि every Member in this House is equal. ये (सत्ता पक्ष के सदस्य) सारे-के-सारे खड़े होकर अपनी बात कहने लगे हैं। इसलिए क्योंकि ये हाऊस को चलाना ही नहीं चाहते। ये पहले भी कह रहे थे कि आज कैबिनेट की बैठक है इसलिए ज़रा जल्दी खत्म कर दो। इसलिए ये हाऊस को चलाना ही नहीं चाहते, विधान सभा में कोई प्वायंट लाना नहीं चाहते और कोई डिस्कशन करना ही नहीं चाहते। तभी मुख्य मंत्री जी हाऊस

07.03.2017/1615/SLS-DC-2

शुरू होने से पहले ही विधायकों को कुछ भी बोल देते हैं और यहां पर भी बोलना शुरू करते हैं जो ठीक बात नहीं है। अगर इस प्रकार से हाऊस चलेगा और हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर यह हाऊस नहीं चलेगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) ... Please you should have patience. यहां पर LED screen चल रही है जिसमें टाइम भी रिकॉर्ड

हो रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि बोलने नहीं देना चाहते। I can count that how many times the one side of the Opposition has spoken and how many times the other person has spoken. You have spoken three times, a time then other side the Ruling party has spoken. Still you say बोलने नहीं देना चाहते, इसका क्या मतलब हुआ? And one comment by certain person, don't disturb that person from speaking. You can speak when your turn comes. आप उसको काउंटर कर सकते हो लेकिन यह ठीक नहीं है कि बीच में सब खड़े हो जाओ। एक आदमी को बात रखनी चाहिए। 10 आदमी बोलेंगे तो पता ही नहीं चलता कि आप क्या कहना चाहते हैं। This is not the way. आप असैंबली को नहीं चलाना चाहते।...(व्यवधान)...आप इसको adhere कीजिए। This is a wrong presence. माननीय धूमल जी।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, जो भी सदस्य इस हाऊस में बोलता है, वह आपकी अनुमति से बोलता है। जब आप अनुमति नहीं देते तो बंद हो जाता है या आप रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। जैसे रणधीर शर्मा जी जो लॉस्ट में बोले, उनका वह कुछ मिनट का भाषण आपने रिकॉर्ड में नहीं आने दिया। मैं किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए गया था। फिर जो माननीय सदस्य श्रीमती आशा कुमारी जी बोल रही थी, वह मैंने सुना। वह अच्छा बोलती है। बीच में कटाक्ष काफी करती है। मैंने एस.एस.पी. का ऐफेडैविट कोट किया था, ...(व्यवधान)... मैंने उसे वहां पर सुना। मैंने एक बात मीटिंग में भी क्लियरली सुनी कि आपने गधे से प्रेरणा नहीं ली। हर चीज़ से कुछ-न-कुछ मिलता है। किसी ने गधे से प्रेरणा ली होगी, आपने कुछ और लिया होगा।

07.03.2017/1615/SLS-DC-3

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय धूमल जी ने जो कहा, मैंने गधे से कुछ भी नहीं लिया, न ही मेरी पार्टी और मैं गधे और गाय की राजनीति करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने दो-तीन बातें कहीं। मैं वैसे भी धूमल साहब

का बहुत आदर करती हूँ because he is very fine parliamentarian and he is very good leader.

जारी...श्री गर्ग जी

07/03/2017/1620/RG/AG/1

श्रीमती आशा कुमारी की अंग्रेजी के पश्चात----क्रमागत

वास्तव में ये सदन में नहीं थे। अगर ये पूरी बात सुनते, तो अच्छा होता। इन्होंने तो वह सुना जो इन्हें पीछे से बताया गया। लेकिन बात यह नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारद्वाज साहब ने कहा कि जूनियर व सीनियर। तो मैं जूनियर-सीनियर की कभी बात नहीं करती। अगर ऐसा होता, तो मैं राम कुमार जी की बात नहीं बोलती। I am a legislator. You are a legislator. We are all legislators. We are all equal. But I am simply saying कि जो लंबे अर्से से सदन में होता है उसको नियमों के बारे में ज्यादा पता होता है। जैसे आपको है। आप बिना बताए भी हर नियम के बारे में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ रिमाइन्ड कर रही हूँ। आप (श्री सुरेश भारद्वाज) प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के लिए खड़े हुए, तो अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के रूलज इसमें भी हैं और विधान सभा की एक किताब भी है कि Point of Order can only be raised by quoting the rule. You can't just get up and do like this and say that it is Point of Order. आदरणीय धूमल साहब ने जिस तरह से कहा i.e. you ask that you want to say something, I will yield. You have been in Parliament. He has been in Parliament. Others may not have been in Parliament. If you ask that you want to say something, the other Member may or may not yield. Mr. Dhumal often tells the Chief Minister that he will not yield. If you wanted to speak, I said I will yield. Where is the question? But I am simply saying that no names were being taken. If some Member tries to take names तो फिर बात बिगड़ती जाएगी। नाम मत लीजिए। देखिए, एक स्वस्थ प्रजातंत्र में पक्ष एवं विपक्ष की चर्चा इसी तरह से चलती है। अगर हम नाम लेकर बात करेंगे, अभी यहां पर श्री रणधीर शर्मा जी नहीं हैं, उन्होंने मुख्य मंत्री के बेटे को भी ड्रैग किया। हम बच्चों को सदन में ड्रैग न करें, तो बेहतर होगा। पता नहीं हम में से किस-किस के बच्चे कहां-कहां पहुंचेंगे? हम बच्चों की क्यों चर्चा कर रहे हैं? अगर वे लायक होंगे, तो

अपनी जगह बनाकर वे पहुंचेंगे और यह बात आप पर भी लागू होती है और हम पर भी लागू होती है। हम क्यों इस तरह की बातें करते हैं? कभी आपने सुना है कि डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर बन जाए, तो कोई कटाक्ष हो, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाए, तो कोई कटाक्ष हो और हम यहां सदन में बैठकर अपने ही बच्चों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। यह पब्लिक लाईफ में करने की बिल्कुल गलत प्रथा है।--(व्यवधान)---आप और हम इस प्रथा को चेन्ज क्यों नहीं करते? हमारे बच्चे भी उतने ही ऐन्टाइटिल्ड हैं अगर वे लायक

07/03/2017/1620/RG/AG/2

हैं? वे सांसद बनने और विधायक बनने के भी लायक हैं। ----(व्यवधान)----हंसराज जी कम-से-कम आप तो न बोलो।

Speaker, Sir, in any case I am winding up my speech. I am simply saying please let us not talk about the future of our children. I hope कि हम सब के बच्चों में से कई इतने लायक निकलें कि वे हमसे भी ज्यादा बुलन्दियों पर पहुंचें। मेरी तो एक ही बेटी है। She is not in politics. I am sorry, Mr. Saizal. I have only one daughter and she is not in politics. हम सबके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं।

डॉ. राजीव सैजल : यहां बच्चों की चर्चा किसने की?

श्रीमती आशा कुमारी : यहां पर मिस्टर रणधीर शर्मा जी ने इस बारे में चर्चा की। अगर आप सदन में नहीं थे, तो यह मेरी गलती नहीं है। मैं सिम्पली यह कह रही हूँ कि हम अपने बच्चों के ऊपर कटाक्ष न करें। न उधर से करें और न इधर से करें। हम सब भी किसी के बच्चे हैं और हमारे भी आगे बच्चे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूँ कि राज्यपाल महोदय ने यहां सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं उनका जिक्र अपने अभिभाषण में किया है जिस पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री जगजीवन पाल, माननीय मुख्य संसदीय सचिव ने रखा और जिसका अनुमोदन हमारे माननीय सदस्य श्री संजय रतन ने किया, मैं इसका पुरजोर समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

07/03/2017/1620/RG/AG/3

श्री विक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। इन्होंने मेरा नाम यहां पर लिया है।

Speaker: This is not a debate.

श्री विक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा। आप कह रहे थे कि आपको बहुत ज्यादा संस्थान दे दिए हैं और फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं। मेरे जैसे संस्थान जिनकी ये बात कह रही हैं।

अध्यक्ष : इसमें क्या है इन्होंने तो चर्चा में भाग लिया था। क्या आप उसका जवाब देंगे?

श्री विक्रम सिंह : मैं कौन सा कह रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक मिनट दीजिए।

अध्यक्ष : ऐसे तो कोई भी सदस्य बोलेगा, तो दूसरा सदस्य उसका जवाब देने लग जाएगा।

श्री विक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि आप (मैं) संस्थानों के बारे में बोल रहे हैं कि इतने-इतने संस्थान दे दिए। इस प्रकार के संस्थान यदि इनको चाहिए, तो मैं लिखकर दे देता हूँ इसी स्थिति में कि उनको ऐसे ही रखो। अगर प्राथमिक विद्यालय में कॉलेज चलाना है, तो उनको ऐसे ही रखो। मैं संस्थानों को इंप्रूव करने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज, कॉलेज भवन में चले और जो अस्पताल हैं वे ठीक तरीके से चलें। मेरा तो इनके आगे यह विषय है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उनको डि-नोटिफाई कर दो। धन्यवाद।

एम.एस. द्वारा जारी

07/03/2017/1625/MS/AG/1

अध्यक्ष: मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन रहेगा कि कृपया कोई व्यक्तिगत आर्ग्यूमेंट न करें और समय भी बर्बाद न करें क्योंकि अभी काफी सारे माननीय सदस्य बोलने को शेष हैं। If you want to spend the night here, I have no objection. But it is wrong that you are taking about 25-30 minutes each. How can I finish the agenda? Everybody wants to speak. Now, I will strictly say that if somebody speaks more than 12 minutes I will switch off the speech. अब चर्चा में माननीय सदस्या, श्रीमती सरवीन चौधरी जी भाग लेंगी। वे सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए अब चर्चा में श्री वीरेन्द्र कंवर जी भाग लेंगे।

श्री वीरेन्द्र कंवर: अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने जो प्रथम मार्च, 2017को अपना अभिभाषण इस सदन में पढ़ा, उसमें मुझे लगा था कि माननीय वीरभद्र सिंह जी जो इस प्रदेश के छः बार मुख्य मंत्री रहे हैं, यह उनका पिछले अनुभवों का शायद बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट होगा,

उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए

लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि यह जो अभिभाषण पढ़ा गया इसमें कोई विजन नहीं है। अगर हम पिछले तीन-चार वर्षों के अभिभाषणों की किताबों को पढ़ें तो मात्र कुछ आंकड़ों का हेरफेर है बाकी कोई नई दिशा या कोई पिछले चार वर्षों में या पिछले एक वर्ष की कोई अच्छी कार-गुजारी प्रदेश सरकार की रही है, ऐसा नहीं लगता है। जब हम पहली बार यहां चुन करके आए थे तो उस समय जब अभिभाषण के बाद बजट सत्र हुआ तो मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा बजट डॉक्यूमेंट उस समय दिया था और उसमें लिखा था कि हम उधार लेकर के घी पीएंगे यानी eat, drink and be merry, खाओ, पीओ और मौज करो। उस समय भी इन्होंने दर्शाया था कि ये ऐसी सरकार चलाना चाहते हैं और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज हमारा प्रदेश 40 हजार करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है और इस 40 हजार करोड़ रुपये के कर्ज से निपटने के लिए कि हम इसको कैसे रि-पे करेंगे, हम कैसे आत्म-निर्भर हिमाचल बनाएंगे, इसकी कोई बात न पहले हुई और न ही

इसका कोई विजन दिखता है। जब वर्ष 1993 से वर्ष 1998 तक इन्होंने सरकार चलाई और वर्ष 1998 में जब सरकार छोड़ी, उस समय 13वें वित्तायोग में इन्होंने अपनी बात रखी थी
07/03/2017/1625/MS/AG/2

कि हिमाचल बहुत आगे बढ़ गया है और उसको देखते हुए स्पेशल स्टेट्स का जो लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलता था, वह इससे डिलीट हुआ। उसके कारण पहली बार हिमाचल प्रदेश को कर्जा उठाना पड़ा था यानी सरकार चलाने के लिए कर्जा उठाना पड़ा था। जब इन्होंने सरकार छोड़ी तो 5 हजार करोड़ रुपये कर्जे में उस समय हिमाचल प्रदेश था। अब बार 40 हजार करोड़ रुपये के कर्जे में इस समय तक हिमाचल प्रदेश पहुंच गया है। लगता है कि 7-8 हजार करोड़ रुपये का कर्जा और उठाने की तैयारी की जा रही है।

उपाध्यक्ष जी, मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक गरीब किसान था और उसको बुखार चढ़ा हुआ था।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

07.03.2017/1630/जेके/एस/1

श्री वीरेन्द्र कंवर:----जारी-----

वह वैद्य के पास गया और दवाई ली, लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा था। अंत में वह देवता की शरण में गया। वह चले के पास गया उसने कहा कि तुझे खोट है तेरा बुखार तभी उतरेगा जब एक या दो तोले का छत्तर चढ़ाएगा। महाराज मैं दो तोले का छत्तर चढ़ा दूंगा लेकिन मेरा बुखार उतर जाए। बड़े दिनों के बाद उसका बुखार उतर जाता है। वह भूल गया कि उसको छत्तर चढ़ाना है। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद उसको फिर बुखार हुआ फिर देवता के पास गया। देवता ने फिर पूछ दी कि उसने कहा कि जो तेरी मन्नत थी वह तूने नहीं चढ़ाई, वह छत्तर तूने नहीं चढ़ाया। इस करके तुझे दोबारा से बुखार हो गया। उसने कहा कि महाराज मुझे बुखार चढ़ा हुआ था लेकिन आपको थोड़ा न बुखार था। उसने देवता को कहा कि आपको थोड़ा न बुखार था। आपको पता है मेरी स्थिति क्या है? मेरी

स्थिति यह है कि मैं गरीब आदमी हूँ और बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूँ, लेकिन तुमने तो छत्तर की बात कर दी। आज यह स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। आज हम कर्जा उठा करके सरकार चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार को केन्द्र से पहले से ज्यादा बजट मिल रहा है। वहाँ पर हमारे केन्द्रीय करों में से जो हमें स्टेट शेयर मिलता है वह पहले से ज्यादा मिल रहा है। जो हमें 50 हजार करोड़ रूपए पांच साल में मिलना था उसके मुकाबले 75 हजार करोड़ रूपए मिल रहा है। 90:10 के शेयर में अनेकों योजनाएं केन्द्र से स्वीकृत हो रही हैं। केन्द्र से मंत्री यहां पर आ करके आपकी सड़कों के लिए, हमारी सड़कों के लिए 62 नेशनल हाई वे दिए। यह पहली बार यहां पर ऐसा हुआ। वे 62 नेशनल हाई वे हमें दे रहे हैं, लेकिन हम उनकी डी0पी0आर0 नहीं बना रहे हैं। हम इस करके मना कर रहे हैं कि हमारे पास डी0पी0आर0 बनाने के लिए पैसा नहीं है। केन्द्र से डी0पी0आर0 बनाने के लिए पैसा भेज रहे हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज डी0पी0आर0 तक नहीं बन रही है। विपक्ष के विधायकों की डी0पी0आर0 नहीं बन

07.03.2017/1630/जेके/एस/2

रही है। वर्ष 2013 से ले करके आज तक जो आपने अपनी प्राथमिकताएं दी हैं उनकी कोई भी डी0पी0आर0 आज तक नहीं बनी है। आज हमारी डी0पी0आर0 नहीं बन रही है। केन्द्र से पैसा आ रहा है, केन्द्र से कृषि के लिए पैसा आ रहा है, प्रधान मंत्री कृषि योजना और हम उसको नहीं ले पा रहे हैं। केन्द्र से हमें फसल बीमा योजना मिल रही है। हम एजेंसी अप्वाइंट ही नहीं कर पा रहे हैं। पिछड़े वर्ग किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाया, लेकिन उनका नुकसान हुआ। सरकार की कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी जो जा करके गांवों में देख सके कि उनका कहां-कहां पर नुकसान हुआ। उनको पता नहीं चला। लोग हमसे पूछे, लेकिन हम भी बताने में असमर्थ थे कि कौन सी एजेंसी यह तय करेगी। आज केन्द्र से विभिन्न योजनाओं में पैसा आ रहा है। आज हिमाचल प्रदेश को रेलवे में बजट मिल रहा है।

पहले केवल रेलवे में बातें मिलती थी। अब हिमाचल प्रदेश को बजट मिल रहा है, लेकिन हम लैंड एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि सरकार नाम की हिमाचल प्रदेश के अन्दर कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि उसने कहा कि बुखार चढ़ा हुआ है। वीरभद्र सिंह जी को इस उम्र में चुनावी बुखार चढ़ा है। उनको लगता है कि वे 7वीं बार झूठी घोषणाएं करके मुख्य मंत्री बन जाएंगे। मुख्य मंत्री जी पूरे चार वर्षों के अन्दर मेरे चुनाव क्षेत्र में गए। न लठेनी में डॉक्टर है, न बंगाणा में डॉक्टर है, न ही थानाकलां के अन्दर डॉक्टर है और एक पी0एच0सी0 खोल दी रायपुरवदान में वहां पर डॉक्टर नहीं है। वहां पर भी ताला लगा हुआ है मैंने वहां पर 10 दिन तक धरना दिया कि वहां पर पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

07.03.2017/1635/SS-AS/1

श्री वीरेन्द्र कंवर क्रमागत:

मैं मैडम जी के पास गया, मैंने कहा मैडम जी पीने का पानी नहीं मिल रहा तो कहती हैं कि विदेशों में भी नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कि फिर क्या करें, क्या जूस पीएं। आज पीने के पानी की स्थिति हमारे क्षेत्रों में ऐसी पैदा हो गई है कि आज आई0पी0एच0 डिपार्टमेंट भगवान् के भरोसे है। मैंने आई0पी0एच0 विभाग वालों से कहा और वे बोले कि लाइनें चेंज होनी हैं। मैंने कहा कि आप लाइनें बदल दीजिये। कहते हैं कि लाइनें नहीं बदल सकते क्योंकि पाइपें नहीं हैं। ऑर्डर नहीं है, सिर्फ 25 पाइपें रखी हैं, जब मुख्य मंत्री जी आते हैं तो झंडे लगाने के लिए रखी गई हैं। इससे बुरी स्थिति विभाग की क्या हो सकती है। मैंने प्रश्न लगाया, मैडम आप ज़रा ध्यान दीजिए। यहां पर पहले एक वक्ता ने भी कहा कि एक मोटर महीने में छः - छः बार खराब हो रही है। मैंने कहा कि लॉग बुक लेकर आओ और बताओ कि कितनी बार यह मोटर खराब हुई है। मैटीनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। आज

पी0डब्ल्यू0डी0 की हालत क्या है? मेरे क्षेत्र के अंदर एक साल के अंदर दो करोड़ की झाड़ियां कागजों में कटीं। टैंडर लगता है 'Bush cutting, Bulb repair' वह कुछ नहीं होता लेकिन आजकल एक्सट्रा कांस्टीट्यूशल अथोरिटीज़ हर कांस्टीचुऐंसी में पाली हुई हैं, वे अपने नाम से टैंडर नहीं लेते बल्कि दूसरे के नाम से टैंडर लेते हैं। आज वह गोरखधंधा चला हुआ है। मुख्य मंत्री जाते और दस-दस डी0एन0आई0टी0 दुमछल्ले लेकर उड़ जाते। अधिकारियों को डराते हैं कि अगर आपने यह डी0एन0आई0टी0 पास नहीं की, इसकी पेमेंट नहीं की तो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। हद यहां तक हो गई कि स्कूल में जा करके टीचर को गालियां निकालते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बड़ा सोचनीय विषय है। उसको बोलते हैं कि तेरी बेटी को उठाकर ले जायेंगे, वह डरा और बेचारा रिपोर्ट तक नहीं करता। वह अध्यापक पी0जी0आई0 में तीन दिन तक एडमिट रहता है। इससे शर्मनाक विषय और क्या हो सकता है। कानूनगो निशानदेही देने के लिए जाता है। उसको गले से पकड़ लेते हैं। ऐसा माफिया आज प्रदेश के अंदर अगर किसी सरकार ने पैदा किया है तो इस सरकार ने पैदा किया है। आज हम 40 हजार करोड़ के

07.03.2017/1635/SS-AS/2

कर्ज में हैं। हम जुगाड़ के साथ सरकार चला रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों मुझे एक अधिकारी मिले, कहते हैं कि मैं भी मुख्य मंत्री जी के टूअर में साथ में था। गाड़ी में थे, सोये हुए उठे और बीस-तीस लोगों ने हार डाले और नारे लगाए। उन्होंने बोला कि क्या मांगते हो। लोगों ने कहा कि यहां पर तहसील चाहिए। कहते हैं कि छः किलोमीटर में तहसील दी। मेरे क्षेत्र में आए, लोगों ने कहा कि डॉक्टर नहीं हैं, बोले अरे डॉक्टर क्या करने हैं। आपके थानाकलां पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 कर देता हूं। अब वह सी0एच0सी0 कर दिया। आज ऐसी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। एक दिन मैं दुकान में बैठा था। एक बच्चा आया और कहता कि एक किलो फलाफे देना। मैंने पूछा कि बेटा लिफाफे होते हैं या फलाफे होते हैं? वह बेचारा कुछ सहम गया। मैंने पूछा कि बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो। कहता कि गड़वासड़ा में पढ़ता हूं। मैंने कहा कि बेटा तेरा कोई कसूर नहीं है। वह दसवीं

तक स्कूल है लेकिन एक टीचर है। अब तू लिफाफे को फलाफा ही बोलेगा। यह तेरा कसूर नहीं है। यह कसूर हमारा ही है। आज बिना बजट के आप ऐसे-ऐसे काम कर रहे हो, अब यहां पर मेरे पूर्ववक्ता कह रहे थे कि चौकीबनेर में कॉलेज खुल गया। अरे, तुमने कॉलेज चौकीबनेर में खोला तो आपने बंगाणा के कॉलेज का भी बेड़ागर्क कर दिया। ऊना के टीचर को वहां पर डैपुटेशन पर भेज रहे हो, तो वहां के स्टूडेंट्स भी दुखी और यहां के स्टूडेंट्स भी दुखी। आज इस तरह की स्थिति है। इस तरह के कॉलेज और स्कूल आज भगवान् भरोसे खुल रहे हैं। मैं डॉक्टर के लिए गया, अधिकारियों से बात की, कहते हैं कि हमारी भी समझ में नहीं आता।

जारी श्रीमती के0एस0

07.03.2017/1640/केएस/डीसी/1

श्री वीरेन्द्र कंवर जारी----

यहां तो डॉक्टर पूरे नहीं होते हैं दूसरी तरफ नए इंस्टिट्यूशन्ज़ खोले जा रहे हैं। आज पूरे बंगाणा के अंदर, मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 50 हजार से बढ़ाकर ग्रांट इन एड 75 हजार करोड़ की है और जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को दिया जा रहा है उसके बावजूद भी आप उल्टा कर्ज ले कर हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार चला रहे हैं। आज मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है वहां पर एक ही राजधानी है। हमारे साथ पंजाब और हरियाण की भी चण्डीगढ़ में एक ही राजधानी है, उनका एक हाईकोर्ट है क्योंकि उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे बचाए हैं और जनता के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारा भी चण्डीगढ़ के अन्दर 7.19 का शेयर बनता था। बी.बी.एम.बी. में हमारा हिस्सा बनता था लेकिन आज तक हम उस हिस्से को नहीं ले पाए। आज शिमला हमारी राजधानी है। यहां पर हमें कैसा पानी पिलाया जा रहा है? मलयुक्त पानी इस प्रदेश के लोगों को पिलाया जा रहा है। हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी में साफ पानी लोगों को नहीं पिला पा

रहे हैं और हम दूसरी राजधानी की बात कर रहे हैं? उधार उठाकर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी का यह जो विज़न है कि "eat, drink and be merry" अब मुझे समझ आया कि ये हिमाचल प्रदेश को कहां ले जाएगा? आज हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हमारे भी उस समय के तात्कालिक नेताओं ने फैसला लिया होता हम चण्डीगढ़ से अपना शेयर ले सकते थे, चण्डीगढ़ को ही अपनी राजधानी बना सकते थे। वह जब दो प्रदेशों की हो सकती थी तो छोटे से हिमाचल प्रदेश की क्यों नहीं हो सकती थी? हमारा नया टाऊनशिप डेवलप हो जाता नालागढ़, बद्दी बरोटीवाला वह हम सभी के लिए अच्छा रहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमसे पूछा जा रहा है कि हम राजधानी बनाने के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? अरे, पहले आप तो तय करो कि आप कर क्या रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की जनता को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश का ऐसा भविष्य क्यों बना रहे हैं ताकि फिर लोग हमको पहाड़िया

07.03.2017/1640/केएस/डीसी/2

कहें? आज हिमाचल प्रदेश की गिनती ईमानदार लोगों के रूप में होती है। आज हिमाचल प्रदेश की गिनती अच्छी छवि वाले लोगों के रूप में होती है। हर जगह हमारा मान-सम्मान होता है। हिमाचल प्रदेश पढ़ा-लिखा राज्य है लेकिन आज इस बीसवीं सदी में भी अगर हम ऐसे-ऐसे नौजवान पैदा करेंगे जो पढ़े तो होंगे लेकिन लिफाफे को फलाफा ही बोलेंगे। मुख्य मंत्री जी बड़े अनुभवी हैं लेकिन आपका ऐसा अनुभव लोगों को शेयर नहीं करना चाहिए। मैं यह समझता हूं कि मुगलकाल में ऐसे तुगलकी फ़रमान हुआ करते थे। एक बार तैमूर लंग थे वे अपनी राजधानी दिल्ली से देवनगरी ले जाना चाहते थे। उनको आज भी इतिहास में कहते हैं कि पिथौरियों को लेकर तैमूर लंग आए, दिल्ली के रहने वाले जानों से तंग आए। वे अपनी राजधानी बार-बार, कभी देवनगरी ले जाते थे और कभी देवनगरी से दिल्ली ले आते थे। उनके बारे में कहते हैं कि वे चमड़े के सिक्के चलाते थे। आज वही स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। एक छोटा सा राज्य जो आज हमारे पैसे में से, आज कुटलैहड़ के एक-डेढ़

लाख लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, उन स्वास्थ्य सेवाओं का जो पैसा है, माननीय मुख्य मंत्री जी उसको ऐशो-आराम में खर्च कर रहे हैं। कभी सी.पी.एस. की फौज खड़ी कर देते हैं, कभी एडवोकेट जनरल, ए.डी.जी.पी. और फिर डिप्टी बना देते हैं। 40-40 लाखों की फौजें खड़ी करके इस पैसे को हिमाचल प्रदेश के खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बहाया जा रहा है। आज केन्द्र से पंचायतों को सीधा पैसा आ रहा है।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

7.3.2017/1645/av/DC/1

श्री वीरेन्द्र कंवर----- जारी

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

आबादी के अनुसार कम-से-कम हर पंचायत को 10-10, 20-20 और 25-25 लाख रुपये की राशि आई है। लेकिन सरकार डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में यह तय नहीं कर पाई कि यह पैसा कैसे खर्च होगा। इनके मन में खोट था क्योंकि इनको लगता था कि यह पैसा मोदी जी ने भेजा है। इस पैसे से गांव के अंदर पक्की सड़कें, रास्ते व नालियां बनेंगी तथा टोटल सेनिटेशन होगी। गांव स्वच्छ होंगे और इससे कांग्रेस पार्टी का शासन डगमगायेगा। मगर गरीब जनता का जो पैसा है आज उस पैसे को बहाया जा रहा है, उसको प्रशासनिक कार्यों में ही खर्च किया जा रहा है। मैंने जैसे कहा कि लोगों को पीने का पानी चाहिए। गांव में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए और प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। आज हमारे बच्चों को प्रदेश के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। हम सरकारी स्कूल खोलते जा रहे हैं लेकिन लोगों का ध्यान प्राइवेट स्कूलों की ओर है। हिमाचल प्रदेश के अन्दर आज इस प्रकार की अव्यवस्था का आलम है। हमने पर्यटन को बढ़ावा देने बारे कोई बात नहीं की है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन के लिए तीन करोड़ रुपये से ज्यादा

राशि खर्च हुई। वहां पर थोड़ा-थोड़ा काम बचा था। भरमोती के अंदर शौचालय निर्माण के लिए मात्र दो लाख रुपये की राशि खर्च होनी थी। मैं इस सरकार से बार-बार निवेदन करता रहा मगर आपकी सरकार उस शौचालय को चालू करने के लिए केवल दो लाख रुपये की राशि नहीं दे पाई। मुझे वह व्यवस्था अपनी विधायक निधि से करनी पड़ी। वहां चमुखा और सोलहसिंघी धार के सौंदर्यकरण के लिए पैसा हुआ था। मगर सरकार बनने के बाद उस पैसे को वापिस किया गया। थानागलां के अंदर 1.25 करोड़ रुपये स्टेडियम के लिए आया था। उस स्टेडियम पर अभी 25 लाख रुपये ही खर्च हुए थे। वहां पर वीरभद्र सिंह जी आए और उस आधे-अधूरे स्टेडियम का उद्घाटन करके चले गये। थानागलां में ही डॉक्टर जैजिडेंस के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि आई थी।

7.3.2017/1645/av/DC/2

माननीय बिन्दल जी ने वहां पर भूमि पूजन किया था और उसका टैंडर भी लगा था। मगर बीच में चुनाव आ गये और उस पैसे को वहां से कहीं और दे दिया गया। हमारे बंगाणा में स्त्री और टक्का स्कूल में साईंस भवन के लिए तकरीबन 50-50 लाख रुपये की राशि आई हुई थी मगर उस पैसे को भी सरकार ने गोलमोल कर दिया। पिछले चार वर्षों के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी कुटलैहड़ विधान सभा क्षेत्र के अंदर 3-4 बार आए और वहां पर केवलमात्र सात जगह उद्घाटन तथा शिलान्यास किए। सात में से सिर्फ एक ही स्थान रायपुर बदान ऐसा है जिसकी इन्होंने घोषणा की थी और उस बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। बाकी 6 के 6 कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के थे। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि समग्र विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है; यह तो इनकी पुरानी आदत है। मगर ये देखते एक ही क्षेत्र को हैं। विपक्ष के लोग क्या इस हिन्दुस्तान के रहने वाले नहीं हैं? क्या हमारे लोग टैक्स पे नहीं करते, हमारे विधान सभा क्षेत्रों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है?

अध्यक्ष जी, मैं यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं। हमारे निचले क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय में सिंचाई के लिए 70 ट्यूब वेल लगे थे।

श्री वर्मा द्वारा जारी

07/03/2017/1650/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

श्री वीरेन्द्र कंवर - - - जारी।

जो हमारा अपर कुठलैहड़ का हिस्सा है, वहां पर ट्यूब वेल नहीं लग सकते थे। माननीय धूमल जी ने वहां (समूर) के लिए हार्वेस्टिंग स्ट्रैक्चर बनवा करके एक बहुत बड़ी स्कीम बनाई थी। उसका एक हिस्सा समूर है और दूसरा हिस्सा चिन्तपुरनी में चला गया है। इस स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए और दोनों जगह डैम लग गये थे। इसके लिए पाइपें बिछ गई थी, लेकिन चुनाव हो गये। चुनाव के बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई अब पाइपें वहां पर पड़ी-पड़ी गलसड़ रही हैं। मैंने विधान सभा के अन्दर इस विषय को बार-बार उठाया। मैं तो विपक्ष का विधायक था लेकिन जो कांग्रेस के सदस्य हैं उनके यहां भी वह स्कीम अभी तक चालू नहीं हो पाई है। आज पीने के पानी की समस्या हमारे क्षेत्र के अन्दर है। माननीय मुख्य मंत्री जी जितनी दफ़ा जाते हैं, हैंडपम्पों की घोषणा करके आ जाते हैं। लेकिन इन चार वर्षों में केवल 9 हैंडपम्प ही कुठलैहड़ क्षेत्र के अन्दर लगे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में सांस्कृतिक विभाग का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के 4 वर्षों के बाद आज वह काम कछुए की चाल से चला हुआ है। जो काम 2 वर्ष के अन्दर होना था, आज वह काम धीमी गति से चल रहा है। आज कुठलैहड़ क्षेत्र के ऐसे अनेकों कार्य हैं, जो बन्द पड़े हुए हैं। हमारे क्षेत्र की बहुत-सी योजनाओं का पैसा या तो दूसरी स्कीमों के लिए बदल दिया गया है या फिर वे योजनाएं ही बदल दी गई हैं। ॥॥॥ कुठलैहड़ के अन्दर आई थी, उसको चुराकर श्री मुकेश जी (उद्योग मंत्री) ले गये। ये तो मंत्री थी, इनकी समझदारी तो तभी होती, अगर और इंस्टीट्यूशन अपने क्षेत्र के लिए लेकर आते। हमारे यहां सैनिक कंटीन डिपो बनना था, ये सरकार उस डिपो को भी नहीं पचा पाई। जब मुख्य मंत्री जी जाते हैं, उनको कोई याद दिलाते हैं तो वे स्टेटमेंट दे देते हैं। इस तरह से हमारे इन क्षेत्रों के साथ भेदभाव होता रहा है। जैसे माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा, हमें याद है जब 2007 के चुनाव हुए थे और उससे पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं। इन्होंने प्राइमरी स्कूलों को कॉलेज बना दिया और फट्टे बदलने का काम उस समय भी हुआ, लेकिन आप सरकार फिर भी रिपीट नहीं कर पाये।

यह आपका इतिहास है, आपकी सरकार कभी रिपीट नहीं हुई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप जितना मर्जी हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव कर लो, आप जितना मर्जी प्राइमरी स्कूलों को कॉलेज बना लो। आज प्रदेश के अन्दर पटवारखाने खाली हैं और हिमाचल प्रदेश के

07/03/2017/1650/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

अंदर 35 से 38 नायब तहसीलदार की पोस्टें खाली पड़ी हैं, लेकिन आपने 20-30 और सब-तहसीलें बना दी हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता एक बार कांग्रेस और एक बार बी0जे0पी0 को चुनती है। अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है, अगली बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश के मुख्य मंत्री बनेंगे। अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूँ। आपका धन्यवाद, जयहिन्द।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने संसदीय सचिव की बात की है और जब हम लोग सरकार में संसदीय सचिव थे,

श्रीमती एन0एस0- - - द्वारा जारी।

07/03/2017/1655/ ns/ag/1

उद्योग मंत्री -----क्रमागत

तब यह लोग अदालत में गए और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने श्री अरूण जेटली जी को पेश करवा दिया। उन्होंने वहां पर कहा कि ये चोर दरवाजे की नियुक्तियां हैं और संसदीय सचिव नहीं होने चाहिए। उसके बाद इनकी सरकार बनी और इन्होंने संसदीय सचिव बना दिए। उस समय माननीय सदस्य भी संसदीय सचिव थे और श्री सतपाल सिंह सत्ती जी भी संसदीय सचिव थे। अब आज इन्होंने फिर कह दिया कि संसदीय सचिव नहीं होने चाहिए या ज्यादा बना दिए हैं। कम-से-कम यह संसदीय सचिव पर अपना रूख तो स्पष्ट कर दें

कि आगे कभी भविष्य में हम नहीं बनाएंगे क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और फिर अपने टाईम में बना दिये थे। अब कह रहे हैं कि हमने ज्यादा बना दिये हैं।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: माननीय मंत्री जी ने जो बात कही अध्यक्ष महोदय, वह अर्ध-सत्य है। यह सही है कि आप लोगों को संसदीय सचिव बनाया गया था और हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया था क्योंकि आपकी पोस्ट क्रिएट ही नहीं हुई थी। हाईकोर्ट में जस्टिस वी.के.गुप्ता के पास जब यह केस लगा और उन्होंने पूछा कि कैबिनेट ने कब पोस्टें क्रिएट कीं तब इनकी कोई प्रोसिडींग ही नहीं थी और कोर्ट ने इनको हटाया था। फिर उसके बाद इन्होंने पोस्टें क्रिएट कर दीं। आप पिछला रिकॉर्ड चैक कर लेना। आप पिछली सरकार में ही पोस्टें क्रिएट कर गए थे लेकिन आप बना नहीं पाए थे। लेकिन हमने तीन संसदीय सचिव बनाए थे और आवश्यकतानुसार आगे भी बनाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री अरूण जेटली जी इनकी पार्टी के बड़े शीर्ष नेता हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पर हैं। उन्होंने वहां पर कहा कि संसदीय सचिव की नियुक्ति चोर दरवाजे की नियुक्ति है और यह नहीं होनी चाहिए तथा हम इस सिद्धांत को मानते हैं। इसलिए वह मामला खारिज हुआ था। उसके बाद धूमल साहब ने संसदीय सचिव बना दिए और अब, जब इधर बने हैं तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि बिरादरी के पास अगर चार या पांच पोस्टें हैं तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हैं?

07/03/2017/1655/ ns/ag/2

अध्यक्ष : अब श्री मनसा राम जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मनसा राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का समय दिया। दिनांक 3 मार्च, 2017 को श्री जगजीवन पाल सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा श्री संजय रतन सदस्य द्वारा अनुसमर्थित निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा:-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 1 मार्च, 2017 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं---"

अध्यक्ष महोदय, चर्चा चली है और मुझे सदन में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मुझे वर्ष 1967 से इस मान्य सदन में बोलने का मौका मिलता रहता है। मुझे उस तरफ बैठने का और इस तरफ बैठने का भी कई बार मौका मिला है। जब सरकार इस तरफ की होती है तो उस तरफ वाले बोलते हैं कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है और जब वे उधर आ जाते हैं तो उधर वाले उनको बोलते रहते हैं। यह राजनीति है इसमें ऐसा चलता रहता है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र जी इतने दिनों से कोई मेरी कृपा से नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता की कृपा से इतने अरसे से राज परिवार में पैदा हो करके भी गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। सबने बड़ा जोर लगाया कि इनकी पार्टी न आए और इनको बदनाम किया जाए तथा कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और बाहर भी इन्होंने बहुत जोर लगाया, इन्होंने ऐसा करना ही है क्योंकि ये लोग तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। माननीय वीरभद्र जी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है और प्रभु कृपा से यह एक उच्च राजघराने में पैदा हुए हैं और लोगों की सेवा करने में रूचि रखते हैं, मेहनत करते हैं तथा दिन-रात काम करते हैं, उसके लिए आप जो मर्जी इनको बोल लीजिए लेकिन हिमाचल प्रदेश के देवी-देवताओं का इन पर आर्शीवाद है। इनको कुछ नहीं हो सकता है। इनके खिलाफ इतने झूठे केस चले और उन्हें आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि

श्री आर०के०एस० ---जारी

07/03/2017/1700/RKS/AS/1

श्री मनसा राम....जारी

वे ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं और उनके पास पैतृक सम्पत्ति इतनी ज्यादा है कि उनको कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। वे राजनीति में आए हैं इसलिए कुछ लोग उनके खिलाफ कोई-न-कोई साजिश रचते रहते हैं परन्तु वे कामयाब नहीं हुए हैं और न ही होंगे। तत्तापानी के लोगों ने मुख्य मंत्री जी के लिए एक संदेश भेजा है और कहा है कि जब

आपको कभी 5-10 मिनट बोलने का मौका मिले तो राजा साहब को यह जरूर कहना कि आपकी उम्र लम्बी हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। राजा साहब का भविष्य उज्ज्वल होगा और आप तड़पते रहेंगे यह मुझे मालूम है।

अध्यक्ष महोदय, तत्तापानी एक तीर्थ स्थान है जिसे गरीबों का हरिद्वार भी कहा जाता है। जब कोलडैम का निर्माण हुआ तो वहां पर एक बहुत बड़ी झील बनाई गई। उस झील ने उस तीर्थ स्थान को तबाह कर दिया। तत्तापानी में गरीब लोग अस्थियां प्रवाहित करते थे। लोग वहां पर गर्म पानी के चश्मों में नहाते थे, पूजा पाठ करते थे। हमें गौरव है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने वहां पर तपस्या कर गर्म पानी के चश्में निकाले थे। अभी जब वे चश्में गायब हुए तो, गांव के लोग उचाट हो गए। तत्तापानी मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है। मैंने वहां के लोगों का कहा कि जो चश्में डूब गए हैं उनके लिए मैं राजा साहब से प्रार्थना करूंगा, वे जरूर हमारी मदद करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने राजा साहब से बोर्ड की मीटिंग में प्रार्थना की और उसके बाद तेज गति से तत्तापानी में कार्य शुरू हुआ। गर्म पानी के चश्में बड़ी तेज़ गति के साथ ऊपर उठे और लोगों ने इसके लिए बड़ी खुशी जाहिर की। ऐसे व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। विपक्ष का काम तो विरोध करने का है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की तरफ से इसके लिए राजा साहब को बधाई देता हूं। राजा साहब तत्तापानी में लोगों की सुविधा के लिए होटल भी बनाएंगे। वहां पर बहुत से निजी होटल हैं परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से भी एक होटल वहां पर बनाया जाए। वहां पर पी.डब्ल्यू.डी. का विश्राम गृह था, वह भी वहां पर होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए हमारी मदद कर रहे हैं जिसके लिए मैं

07/03/2017/1700/RKS/AS/2

उनको धन्यवाद देता हूं। धर्मशाला राजधानी के लिए मुझे बहुत हंसी आती है। वह इसलिए आती है क्योंकि विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ में भी एक छोटी राजधानी होनी चाहिए थी। हिमाचल प्रदेश को डॉ० परमार जी ने पंजाब से मुक्त किया। उस वक्त मैं विधायक था और यह कहा जाता था कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला दो। डॉ० परमार ने उस वक्त कहा था कि हमारे 'मुंडु' कहां जाएंगे। ये तो बर्तन ही साफ करते रहेंगे।

यह हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉ० परमार जी की सोच थी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को अलग अस्तित्व दिलाया। पहाड़ी लोगों के लिए उन्होंने यह एक नेक काम किया है। परमार जी स्वर्ग में है, भगवान उनको वहां भी खुश रखें। हमें खुशी है कि जो कांगड़ा का एरिया पंजाब में था वह हिमाचल में मिल गया। डॉ० परमार, श्री वीरभद्र सिंह जी और हिमाचल प्रदेश के जितने भी मुख्य मंत्री रहे उनकी कृपा से इस राज्य का विकास हुआ। श्री वीरभद्र सिंह जी को हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों की सेवा करने का सबसे ज्यादा वक्त मिला और इनके वक्त ही सबसे ज्यादा काम भी हुए और ज्यादा तरक्की भी हुई। जहां तक धर्मशाला का प्रश्न है, मैं जानता हूं कि धर्मशाला राजधानी होनी चाहिए। क्योंकि इतने बड़े प्रदेश में एक जगह से राजनीति नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्मशाला को जम्मू-कश्मीर राज्य की तरह राजधानी बनाया जाए। इसके लिए भी किसी को कोई एतराज नहीं है। धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र से जो युवा मंत्री हैं मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं।

श्री एस० एल० एस० द्वारा जारी...

07.03.2017/1705/SLS-AG-1

श्री मनसा राम (माननीय मुख्य संसदीय सचिव)...जारी

वह छोटी आयु में मंत्री बने हैं। उनके पिता श्री सन्त राम जी मेरे गुरु रहे हैं। ये बहुत परिश्रमी हैं और इन पर राजा साहब का आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद से इन्होंने धर्मशाला का भविष्य बदला है। मैं कहूंगा कि अगर धर्मशाला में कोई इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो उसकी जमानत भी ज़ब्त हो जाएगी। मुझे गर्व है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने धर्मशाला को भी राजधानी के रूप में मान्यता दी है। यह इतना बड़ा प्रदेश है, इसलिए यहां दो जगह राजधानी होना सही है। गर्मियों में चाहे राजधानी शिमला में रहे और सर्दियों में धर्मशाला में जाए। चाहे जैसे भी हो लेकिन दोनों जगहों पर काम होना चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और सुधीर जी भी बधाई के पात्र हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट बैठिए।

पांच बज चुके हैं जबकि अभी बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं। अभी लगभग 8 सदस्य और बोलने वाले हैं। इसलिए मैं इस सभा की बैठक के समय को 2 घंटे के लिए और बढ़ाता हूँ।

मनसा राम जी, आप बोलिए।

श्री मनसा राम (माननीय मुख्य संसदीय सचिव) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे इस पक्ष और उस पक्ष के मित्रों को कई बार हैलिकॉप्टर से आने-जाने का अवसर मिला है। जहाज से भी कई बार गए हैं। आज हिमाचल का रूप बदला है। यहां सड़कों का निर्माण बहुत तेज गति से हुआ है। आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सड़क न हो। इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी और वीरभद्र सिंह जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी के वक्त में भी सड़कें बनी हैं लेकिन उनको केवल 10 वर्ष ही काम करने का मौका मिला जबकि कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से कार्य कर रही है। वीरभद्र जी की इसमें विशेष रुचि है। हमें खुशी है कि सड़कों के मामले में हिमाचल बहुत आगे है और आगे भी काम जारी रहेगा तथा प्रदेश का विकास होता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, आई.पी.एच. में भी बहुत सी LIS बनी हैं जिसकी हमें खुशी है। मैं बहुत पुराना आदमी हूँ। जब हम पढ़ते थे तो गांव में बावड़ियों का पानी पीना पड़ता था। आज कहीं बावड़ियों का नाम नहीं है। आज मुख्य इतना आगे बढ़ा है। शायद अभी कुछ

07.03.2017/1705/SLS-AG-2

जगहों पर काम होना बाकी है जिसके लिए सरकार ध्यान दे रही है। इसमें सब राजनीतिक पार्टियों का सहयोग रहा है।

इसी तरह से बिजली की बात है। मैं जानता हूँ कि जब 1967 में हम पहली बार विधान सभा में आए थे तो 5-7 जगह पर ही बिजली थी। शिमला और कुछ अन्य बड़े जिलों में ही बिजली थी। उसके बाद बिजली का इतना प्रसार हुआ कि कोई गांव बिजली के बिना नहीं रहा। यह सारा काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।

इसी तरह से पेंशन की योजना है। जो महिलाएं छोटी आयु में, 18 से 40 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती हैं उनकी हालत खराब थी। उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले से बढ़ाकर 1200 रुपये की दुगनी पेंशन कर दी है। इसी तरह से 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी पेंशन दी गई है। ऐसा होने से गरीब और निर्धन आदमी इनकी लंबी आयु और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

अध्यक्ष महोदय, पहले मकान बनाने के लिए गरीबों को 75,000 रुपया मिलता था जो अब एक लाख से ऊपर किया गया है। उससे गरीब लोग प्रसन्नचित्त और खुश हैं और हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में रुचि ले रह हैं।

मुझे खुशी है कि यह सरकार नौकरियां देने की बात भी सोच रही है। इस समय अधिक-से-अधिक बेकार लोगों को नौकरी दी जा रही है।

आप कह रहे हैं कि जो स्कूल या पी.एच.सी. खुले हैं, उनमें स्टॉफ नहीं है, डॉक्टरज़ और मास्टरज़ नहीं हैं। इस समय जो इतने अध्यापक और डॉक्टरज़ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वह वहां पर लगेंगे। अगर यह संस्थान खुल गए तो क्या वह बुरी बात है? अगर खुले हैं तो धीरे-धीरे उनमें स्टॉफ भी उपलब्ध होगा और हिमाचल प्रदेश में विकास होगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा।

जारी...श्री गर्ग जी

07/03/2017/1710/RG/DC/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री मनसा राम)----क्रमागत

और प्रदेश के लोग श्री वीरभद्र सिंह जी को याद करेंगे। मैं आपको बता दूं कि गरीबों के लिए काम करने की उनकी बहुत इच्छा होती है। हम देखते हैं कि और भी कई मंत्री हैं, हम भी मंत्री रहे हैं। परन्तु मुख्य मंत्री महोदय गरीब आदमी, छोटे आदमी को बहुत प्यार करते हैं। हम जैसे मंत्री बहुत हैं, इनसे समय लेना मुश्किल है। लेकिन इनके पास जब आप जाएंगे और श्री वीरभद्र सिंह जी की दिनचर्या देखेंगे, तो इनके ऊपर लोगों की कृपा है। हमारे या आपके ऊपर कोई कृपा नहीं है। ये एक छोटे से आदमी की भी सुनेंगे और उसका काम उसी समय कर देंगे। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी मण्डी में गए थे वहां इतने गरीब लोग आए।

सबको उन्होंने प्यार से सुना और वहीं पर उनका काम कर दिया। यह चीजें उनके अंदर है, भगवान की शक्ति और भगवान का उनके ऊपर आशीर्वाद है और इसके आगे कोई भी पार्टी नहीं चल सकती। आप कह रहे हैं कि इस बार आपकी पार्टी से मुख्य मंत्री बनेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप सोचते रहो, लेकिन ये सातवीं बार भी हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री होंगे। आपकी अखबार कहती है कि आपकी सरकार आएगी, लेकिन हमारे अखबार तो कहते हैं कि अब फिर से सातवीं बार भी हमारी सरकार आएगी।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ और ज्यादा समय लेने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।

07/03/2017/1710/RG/DC/2

अध्यक्ष : अब श्री नरेन्द्र ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिछले दो दिन से पक्ष और विपक्ष की तरफ से हर पहलू पर काफी चर्चा हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान सरकार है उसका लगभग चार वर्ष से अधिक का समय जा चुका है। अब यह चुनावी वर्ष है और जो इन्होंने करना था वह कर दिया। इन साढ़े चार साल में इस सरकार ने ऐसा कौन सा क्रान्तिकारी काम किया जिसके नाम से यह सरकार जानी जाए? सत्ता पक्ष वाले जहां कह रहे थे कि विपक्ष वाले आलोचना कर रहे हैं for the sake of criticism. मैं तो यह कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष वाले जो इस अभिभाषण के ऊपर बोल रहे हैं वे अभिभाषण के ऊपर कम और माननीय मुख्य मंत्री की फ्लैटरी ज्यादा कर रहे हैं। मैं इतना जरूर यहां कह देना चाहूँगा कि जो लोग फ्लैटरी करते हैं उनका मकसद सिर्फ अपना मतलब हल करना होता है, उनका किसी से लेना-देना नहीं होता और जो फ्लैटरी करने पर उनके ऊपर विश्वास करता है वह कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता और वह हमेशा अन्याय ही करता है। तो इस वर्तमान सरकार को हम क्या नाम दें और कौन सा ऐसा काम इसने किया है?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) : विकास वाली सरकार का नाम दें।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : कौन सा विकास, आप बताइए, कौन सा ऐसा क्रान्तिकारी काम इसने किया है? मैं तो यह कहता हूँ कि वर्तमान सरकार का जो साढ़े चार साल का कार्यकाल रहा, तो अब तक की सबसे पूअर परफॉरमेंस इस सरकार की रही है। हर क्षेत्र में यह सरकार टोटली फ्लॉप रही है और आप विकास की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूँगा कि आप शिक्षा विभाग को ही ले लीजिए। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। यहां बार-बार आया कि 154 प्राथमिक विद्यालय खोले गए, 109 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले, उनका स्तर ऊंचा किया गया और 17 नए कॉलेज इस साल खोले गए। बहुत अच्छी बात है और यह रूटीन मैटर है। स्कूल कोई भी सरकार आए या सरकार न भी हो, तो भी जहां जरूरत होती है वहां स्कूल खुलते हैं और जिस स्कूल का स्तर ऊंचा करना होता है उसका स्तर ऊंचा भी

07/03/2017/1710/RG/DC/3

किया जाता है। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा या मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इतना ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में नर्सरी से लेकर प्लस टू तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम क्यों हो रही है? मैं इसका उत्तर चाहूँगा। जितने भी ये सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं ये निजी विद्यालयों की ओर पलायन कर रहे हैं। क्या यह बात सत्य नहीं है? अभी 4-5 दिन पहले पेपर में आया था कि घाटी के मुसलमान घाटी से पलायन कर रहे हैं।

एम.एस. द्वारा जारी

07/03/2017/1715/MS/AG/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर जारी-----

वे अपने बच्चों के कैरियर के लिए वहां से पलायन कर रहे हैं। वहां आतंकवादियों की वजह से सारा साल स्कूल बन्द रहते हैं इसलिए अपने बच्चों के कैरियर की खातिर लोग सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे हैं। वहां तो पलायन आतंकवादियों की वजह से हो रहा है लेकिन यहां पलायन आपकी सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है। आपने तो आतंकवादियों का भी वहां का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साढ़े तीन साल से क्योंकि तीन साल तो मुझे भी यहां हो गए हैं, बार-बार इस विषय पर यहां चर्चा होती है कि एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। इस महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को आप लोग भी पढ़िए कि स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी के लिए इस अभिभाषण में क्या लिखा है? है कुछ ऐसा लिखा हुआ कि सरकार ने एजुकेशन की क्वालिटी के लिए यह कदम उठाया है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो 20 स्कूल खोल दीजिए। आप खुशकिस्मत हैं कि जो कॉलेज गॉइंग स्टूडेंट्स हैं उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है। अगर वहां भी प्राइवेट कॉलेज होते तो माननीय कंवर जी ने जैसे कॉलेजों में बच्चों की संख्या बताई है कि किसी कॉलेज में 50 बच्चे, किसी में 60 और 70 बच्चे हैं तो बच्चों की यह संख्या भी आपके इन कॉलेजिज में नहीं होती और ये खाली होते। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यदि यही सिस्टम शिक्षा का रहा, आपने कभी स्कूलों में विजिट नहीं किया तो आने वाले 5-10 सालों में आपके सारे स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान बन्द हो जाएंगे। इनको कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन इसका जिक्र न सत्ता पक्ष वालों ने और न ही महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में किया है। साढ़े तीन साल से विपक्ष के लोगों ने और श्रीमती आशा कुमारी जी ने बड़े जोरों-शोरों से हर सत्र में यह बात उठाई है कि शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए लेकिन इस सरकार के और माननीय मुख्य मंत्री जी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया और आपका ये जो पांच साल का पीरियड गया इसमें अपने बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ किया है। यह बात ठीक है कि शिक्षा संस्थान खुले, वह रूटीन वर्क है। चाहे सरकार न भी हो, तब भी वे चलते हैं लेकिन प्रौपर इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये प्राइमरी फंक्शन हैं, प्राइमरी सिच्यूएशन यह बोलती है। लेकिन सरकार के जो मुखिया हैं वे बड़े बुजुर्ग हैं और वे अपने हिसाब से ठीक हैं लेकिन the day of the demand कि आज शिक्षा की गुणवत्ता के बिना आपका संस्थान नहीं चल सकता।

07/03/2017/1715/MS/AG/2

अब मैं कृषि के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, 70 प्रतिशत राज्य की जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। अभिभाषण में लिखा है कि हमने बागवानों के लिए इटली से पौधे मंगवाए और हमने कीटनाशक दवाइयां दी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब कुछ होने के बावजूद आपका कृषि क्षेत्र दिनोंदिन कम क्यों हो रहा है? आपके बागवान की पौधे लगाने की भूमि दिनोंदिन कम हो रही है। वह कम क्यों हो रही है इसके बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में कुछ नहीं लिखा हुआ है। कृषि का कहां बढ़ावा हुआ? बागवानी का कहां बढ़ावा हुआ? जो मेन बात है वह यह है कि लोगों का कृषि के प्रति आकर्षण कम हो रहा है। लोग कृषि छोड़ रहे हैं। लोग बगीचे लगाना छोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने कीटनाशक दवाइयां दीं? आप कह रहे हैं कि हमने इटली से पौधे मंगवाए हैं लेकिन वे पौधे कहां लगाने हैं जब लोग पौधे लगा ही नहीं रहे हैं? इसके बारे में आपने क्या किया? देखिए, साढ़े तीन साल से इस सदन में बड़े जोर-शोर से चर्चा हो रही थी कि कृषि कम क्यों हो रही है। लोग बागवानी और कृषि क्यों छोड़ रहे हैं। चर्चा यह होती थी कि कृषि का सबसे ज्यादा नुकसान बंदर और जंगली जानवर कर रहे हैं। लेकिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है। इसके बारे में आपने क्या स्टेप लिया? एक आप सोलर बार्ड वायर लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। विधायक निधि से हमें गाइडलाइन्ज में यह था कि आप अपनी निधि से वहां पर बार्ड वायर लगवा सकते हैं लेकिन इस साल की जो गाइडलाइन्ज आई, उसके अनुसार वह भी बन्द कर दी है। लोग पैसे से इसे लगाना नहीं चाहते हैं और जब हम अपनी निधि से लगा रहे हैं तो सरकार ने वे गाइडलाइन्ज बन्द कर दीं हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि गाइडलाइन्ज में जो इस बार यह आया हुआ है कि विधायक निधि से तार नहीं लग सकती है उसको इसमें एड किया जाए ताकि हम लोगों की फसलों की सुरक्षा के लिए तार तो कम-से-कम अपनी निधि से लगा सके। लेकिन आपने तो वह भी बन्द कर दिया। सौर लाइट से सौर करन्ट के लिए जो तारें लगानी हैं, लोग उसको भी नहीं लगा रहे हैं।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

07.03.2017/1720/जेके/एजी/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर:-----जारी-----

क्योंकि वह मंहगी पड़ रही है। लोग जेब से पैसा नहीं लगा रहे हैं।

दूसरे, एग्रीकल्चर क्यों कम हो रही है, क्योंकि आप इरिगेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं? इरिगेशन के बारे में आप बिल्कुल साइलेंट हैं। एक भी एकड़ भूमि इन साढ़े चार सालों में इरिगेट नहीं हुई है। लोग क्यों कृषि करें? तीसरे, मौसम की मार। मौसम की मार आपके बस की बात नहीं है लेकिन माननीय प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं।

जिनकी फसल मौसम की वजह से खराब हो रही है दो परसेंट उनका लगना है उसमें 98 परसेंट केन्द्र की सरकार दे रही है, लेकिन आप उस योजना को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप किसानों के हितैषी नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि वह योजना ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए और उसका क्रेडिट केन्द्र सरकार ले जाए। लोगों का भविष्य आप खराब कर रहे हैं। उनकी फसल आप खराब कर सकते हैं लेकिन प्रधान मंत्री बीमा योजना वह आप लागू करने में शर्म महसूस कर रहे हैं। अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी यहां पर नहीं बैठे हैं। मेरा उनसे भी एक प्रश्न है। वे बड़े विश्वास से यहां पर कह रहे हैं कि मैंने इतने डॉक्टर लगा दिए, मैंने इतनी नर्सें लगा दी और मैंने इतने संस्थान खोल दिए। मैं इनको यह बता देना चाहता हूं कि उन्होंने यूनिसेफ की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि हमारे जो बच्चे हैं पैदा होने से लेकर पांच साल तक उन बच्चों की हिमाचल में कितनी पोपुलेशन है? लगभग ढाई-तीन लाख से ज्यादा नहीं है। उनमें से 56 हजार बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यह मैडिकल फैसिलिटी हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को दे रही है। जिसके वन थर्ड बच्चे पैदा होते ही शुरू में ही कुपोषण का शिकार है वे इस देश को आगे कहां ले जाएंगे? मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो वे मैडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये 56 हजार बच्चे दो-तीन लाख में से कुपोषण के शिकार हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक और

07.03.2017/1720/जेके/एजी/2

डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके मंत्री जी यहां पर नहीं बैठे हैं। वह एच0आर0टी0सी0 डिपार्टमेंट है। वह एच0आर0टी0सी0 डिपार्टमेंट नहीं रहा अब घोटालों का डिपार्टमेंट है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं। मैं इस मैटर पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन यह मैटर अब ओपन हो गया है और आपको भी मैं फैक्ट बता देना चाहता हूं कि इस ढंग से सरकार काम कर रही है, इस ढंग से आपके मुख्य मंत्री जी काम कर रहे हैं। उनको भी पता है और आप सब को पता है, लेकिन कोई स्टैप लेने को तैयार नहीं है। वर्ष 2003 और 2004 में मैंने आर0टी0आई0 के माध्यम से कुछ डॉक्युमेंट्स निकाले हैं। तब से लेकर आज तक जो एच0आर0टी0सी0 में कंडक्टरों की भर्तियां हो रही हैं सभी में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। वर्ष 2004 में एच0आर0टी0सी0 में भर्तियां हुई है। उनमें ये पांच व्यक्ति हैं। जिनके ऊपर 420 का केस रजिस्टर करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं। उनमें से कौन-कौन है वह भी आप लोग सुन लो। एक है श्री दिलजीत सिंह डोगरा वे उस समय धर्मशाला के एम0डी0 थे। दूसरे हैं, एस0के0 गुप्ता डिविजनल मैनेजर वे भी धर्मशाला, Shri Daljeet Singh Dogra, MD at the time of fraudulent recruitment of the TPAs., तीसरे है, एस0पी0 चटर्जी जी, चौथे है, एम0डी0 शर्मा जी और पांचवें हैं श्री रिंगडिंग नेगी जी। इनके खिलाफ कोर्ट ने 420 का केस रजिस्टर करने के ऑर्डर किए हैं। अब आप सुनिए कि केस क्या है? आप हैरान रह जाएंगे, वैसे हाउस में मैं इसे डिसक्लोज करना ठीक नहीं समझ रहा था लेकिन अब मजबूरी बन गई है। वर्ष 2004 में एक इन्टरव्यू कंडक्टर की भर्ती के लिए हुआ। वह इन्टरव्यू 55 मार्क्स का था। उसमें रिटन टैस्ट के 25 नम्बर थे, पर्सनल टैस्ट के 20 नम्बर थे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 10 नम्बर थे। आप हैरान होंगे जिन बच्चों ने रिटन टैस्ट पास किया जो कि 25 नम्बर का था। जिस बच्चे के 24.5 नम्बर यानि कि 98 परसेंट नम्बर थे और वह एक ही बच्चा था वह बच्चा हमीरपुर का था। जिन बच्चों के 24 नम्बर 25 में से थे वे टोटल 8 बच्चे थे। वे विभिन्न जिलों से थे, लेकिन उन 8 में से 4 बच्चे हमीरपुर के थे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

07.03.2017/1725/SS-AG/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर क्रमागत:

जिनके 94 परसेंट नम्बर, 92 परसेंट नम्बर, 90 परसेंट नम्बर और 88 परसेंट नम्बर थे, टोटल मिलाकर 305 बच्चे टॉपर थे। 305 टॉपर में से एक बच्चे की सिलैक्शन हुई, बाकी जो 304 बच्चे थे उनकी सिलैक्शन नहीं हुई। सिलैक्शन हुई किनकी, ज़रा सुन लो। 19-21 मान लिया, सभी करते हैं लेकिन कभी टॉपर को इग्नोर नहीं किया जाता है। आपने 305 टॉपर में से एक को नौकरी दी और 304 को इग्नोर कर दिया। इससे बड़ी हैरानी की बात कोई नहीं हो सकती है। सिलैक्ट कौन हुए, जिन बच्चों ने क्वालिफाइंग मार्क 50 परसेंट लिये थे। 52 परसेंट, 54 परसेंट सारे-के-सारे वहां से भर्ती कर लिये। एक आर्टिकल ऑफ चार्ज जो उनके ऊपर लगा, मैं ज़रा उनकी दो-तीन लाइनें पढ़ देता हूं। आप भी हैरान होंगे। सुन लो, टोटल 147 बच्चे भर्ती किये गये और उसमें 73 बच्चे नगरोटा कांस्टीचुऐंसी के थे और 37 बच्चे रोहडू कांस्टीचुऐंसी के थे। दो कांस्टीचुऐंसी में 100 से ज्यादा बच्चे और बाकी जो बचे वे पूरे हिमाचल को बांट दिये। आप हैरान होंगे। फिर आप कहते हैं कि पक्षपात नहीं है। फिर आप कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट चला रहे हैं। Just see. मैं आपको पढ़कर बोल रहा हूं। It has also come on record - ये कोर्ट में डाक्युमेंट लगे हैं, वह कोर्ट शिमला में ही है -in inquiry that there were 64 candidates in Dharamshala Division who had secured, just see, only qualifying marks i.e. 50 per cent marks in the written exam, who got selected as Transport Multipurpose Assistant वह कंडक्टर की बात कर रहे हैं Out of these 64 candidates, 30 candidates of them were from Nagrota Bagwan, the constituency of the then Transport Minister, Shri G.S. Bali. Moreover, out of total 147 candidates, finally selected candidates in Dharamshala Division, 73 were from Nagrota Bagwan. It has also found that there were overwriting and cutting in the broadsheets of Dharamshala HRTC Division. There were 12 candidates who finally got selected in Dharamshala HRTC Division but there were cuttings and overwriting in their marks in broadsheet. Out of these 12 candidates, 7 were from Nagrota Bagwan. अब आपको किसी का नाम लेने की

ज़रूरत नहीं बची है कि यह घोटाला कैसे हुआ, कहां से हुआ, उसमें किस-किस की सहमति थी, इसमें ट्रांसपोर्ट मंत्री और मुख्य मंत्री भी शामिल थे, तभी रोहडू से 37 और

07.03.2017/1725/SS-AG/2

नगरोटा से 73 बच्चे लगे। यह भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस आपकी सरकार कर रही है। मैं तो हैरान हूं। इस बात को तो छोड़ दीजिये, यह सब की नॉलेज में है, उसके बाद भी जो भर्तियां हुईं वे सारी-की-सारी कोर्टस में स्टे हो गई हैं। अरे, कहीं-न-कहीं तो मान जाओ। हेराफेरी भी करिये तो 19-21 करिये। लेकिन कभी टॉप कैंडीडेट को इग्नोर नहीं किया जाता है। मैं बड़ी शर्म महसूस कर रहा हूं कि जो बच्चा 98 परसेंट नम्बर ले रहा है उसको इग्नोर करके आप 50 परसेंट वाले बच्चे को रख रहे हैं। आप ऐसी पारदर्शिता दे रहे हैं। आप ऐसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं। ये हैं आपके कारनामे और यह मामला कोर्ट में चला हुआ है। इससे बढ़कर कोर्ट से फेवर लेने के लिए और आगे निकल गए। माननीय मंत्री जी हमारे चीफ जस्टिस को वोल्वो बस का उद्घाटन करने के लिए श्रीनगर ले गए ताकि कोर्ट में फेवर ली जा सके। अरे आप कोई-न-कोई कॉनर तो छोड़ो। वहां उद्घाटन हुआ या नहीं हुआ लेकिन उनको प्लीज़ करने के लिए श्रीनगर ले गए। ये तो इस गवर्नमेंट के हालात हैं। यह फैक्ट्स एंड फिगरज़ हैं। मैं ज्यादा न बोलता हुआ इतना ही कहूंगा कि जिन्होंने यह किया है यह बात ओपन हो गई है लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है कि ऐक्शन लीजिये। ऐसे-ऐसे मंत्री हैं जोकि आपकी सरकार में सरेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसी आप सरकार चला रहे हैं और बार-बार कह रहे हैं कि आप रिपीट कर रहे हैं। क्या आप इसी हालात से रिपीट करेंगे? तो मैं ज्यादा न बोलता हुआ यह जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इसमें समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार ओपन हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, इसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, धन्यवाद।

अध्यक्ष: अब श्री रवि ठाकुर जी, चर्चा में भाग लेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

07.03.2017/1730/केएस/एस/1

अध्यक्ष: अब श्री रवि ठाकुर चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रवि ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने 1 मार्च, 2017 को जो अभिभाषण दिया जिस पर धन्यवाद प्रस्ताव माननीय जगजीवन पाल जी लाए हैं और उसका अनुमोदन माननीय संजय रतन जी ने किया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। हिमाचल सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, उनके बारे में मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मैं जब किन्हीं भी कारणों से हिमाचल का दौरा करता हूँ तो देखने में यही आया है कि हर क्षेत्र में समान विकास, चहुंमुखी विकास हुआ है और मैं समझता हूँ कि हर विभाग में अच्छी गति के साथ पूरे प्रदेश में प्रगति हुई है। वह चाहे शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, लोक निर्माण विभाग है या पेयजल सिंचाई योजनाएं हैं, ऊर्जा से सम्बन्धित विभाग है और जन कल्याण के जो अन्य कार्य हुए हैं, उसमें अच्छी उन्नति हुई है। सभी वर्गों बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी का ध्यान रखा गया है। नौजवानों को नाकरियां देनी हों या बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात हो, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो, सभी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है और जहां तक मेरा क्षेत्र जो कि अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र लाहौल-स्पिति है, वहां पर खासतौर पर जो विधायक की प्राथमिकताएं हमने दीं, उनका पूरा ध्यान सरकार ने रखा और अच्छी गति से उनके कार्य हुए हैं। डी.पी.आर. बनाई गई हैं। बजट का भी प्रावधान हुआ है। जो हमारे नाबार्ड की स्कीमें उसमें आनी थी वे भी उसमें शामिल हुई है। पूरे लाहौल-स्पिति घाटी में तकरीबन 11 से 12 बड़े पुलों का निर्माण हुआ है, उनमें कुछेक की डी.पी.आर. बन गई है, सेंक्शनज़ हो गई है। सबसे ऊंचा चिच्चम गांव स्पिति घाटी में स्थिति है जो कि 13 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है, वहां पर पिछले तीन सालों में 110 मीटर लम्बा पुल बनकर तैयार हुआ है और कीरनाला जो कि स्पिति घाटी में पड़ता है, जहां पर कि सिडिशन चार्जिज़ भी लगे थे। कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए थे क्योंकि वे यह कह रहे थे कि यहां पर कार्य ठीक नहीं हो रहा है और पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। वह कीरनाला पुल हमने डेढ़ साल में ही तैयार करके उनको दिया है। इसी तरह से एक बहुत ही ऊंचा स्थान त्रिलोकीनाथ जी पूरे लाहौल-स्पिति का है, पूरे देश भर से वहां पर दर्शन करने के लिए लोग आते

07.03.2017/1730/केएस/एस/2

हैं। वहां का पुल भी बन कर तैयार हुआ है जो कि एक सर्कुलर रास्ता बना है उदयपुर के पास जो कि 85 मीटर लम्बा पुल है। इसके अलावा जैसे छालिंग पुल का निर्माण हो या प्युकर में पुल का निर्माण हो या हमारे यू.एच.ए. में पुल बन रहा है और कई जगहों पर कार्य हो रहा है। नालदा पुल बन कर तैयार हुआ है। चोखंग में पुल बन कर तैयार हो रहा है। इसी तरह से पूरे लाहौल-स्पिति घाटी में पुलों का भी निर्माण हो रहा है और सड़कों का भी जाल बिछा है। प्रत्येक पंचायत को सड़क से जोड़ा जा रहा है। कुछेक गांव जो सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं और निर्माणाधीन है वहां पर एक स्पैन लगाया गया है जो कि इलैक्ट्रिक स्पैन है उसके माध्यम से उनका सामान ईधर से उधर ले जाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्कूलों की बात है। कई भवनों का निर्माण हुआ है। नवोदय स्कूल का निर्माण हुआ है और बहुत अच्छी तरह से उसे चलाने की तैयारी की जा रही है। केलांग में भी एक बहुत बड़ा स्कूल बन कर तैयार हुआ है। काजा के पास रांगटंग में एक आई.टी.आई. भवन का निर्माण हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर गए थे और पिछले साल माननीय मुख्य मंत्री जी का वहां पर तीन दिवसीय दौरा भी रहा जिसमें उन्होंने वहां पर जितने भी कार्य चल रहे हैं, उनकी धरातल पर समीक्षा की और लोगों से पूछा गया कि उनकी क्या-क्या समस्याएं हैं?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

7.3.2017/1735/av/AS/1

श्री रवि ठाकुर ----- जारी

और जैसे-जैसे वहां की समस्याएं बताई गई उसी समय उनके समाधान करने की पूरी कोशिश की गई तथा प्रशासन को भी उस बारे में निर्देश दिए गए।

ठाकुर भरमौरी सिंह जी के पास हमारा वन विभाग है। लाहौल-स्पिति घाटी में सैंकड़ों एकड़ जमीन पर पौध रोपण किया गया। खासतौर से वाइल्ड लाइफ जो कि लाहौल-स्पिति के अंदर बहुत ज्यादा है। युनीक इलाका होने के कारण ऐसी कई नस्लें जो खत्म होने की कगार पर है उनका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है और उनके लिए अलग-अलग जगह पोंड बनाये जा रहे हैं तथा साथ ही उन इलाकों को विकसित किया जा रहा है। हमारे वहां पर जो सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटक आता है वह भी इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है कि वहां पर खासतौर से वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखा जा रहा है। हमारे वहां पर तीन हर्बल गार्डन्स को विकसित किया गया है और वहां से अन्य क्षेत्रों को भी बहुत ज्यादा हर्बल प्लांट्स जाते हैं। लाहौल-स्पिति से सिबकथोर्न का भी बहुत ज्यादा निर्यात हो रहा है तथा उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे एग्रिकल्चर और होर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वहां विशेष ध्यान रख रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसान हमारे रीढ़ की हड्डी है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने भी कहा कि प्रदेश में 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी किसानों की है। लाहौल-स्पिति में फ्लोरिकल्चर या ऐगजोटिक वैजिटेबल्स हैं और सेब का व्यापार है। वहां पर स्ट्राबरी लगाने की भी कोशिश है तथा हॉप्स की किलन भी है, हॉप्स जो वीयर में इस्तेमाल होता है। वहां पर एक टैम्परेरी मार्किटिंग यार्ड भी खोला गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा भी की है कि वहां पर एक स्थाई रूप से मार्किटिंग यार्ड खोला जायेगा जिससे कि लाहौल-स्पिति के किसानों व बागवानों को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा। पर्यटक की दृष्टि से जैसे कि हम सबको मालूम है कि पूरे देश में सबसे लम्बी सुरंग रोहतांग दर्रे के नीचे से बन रही है। उस टनल की लम्बाई लगभग 9 किलोमीटर है और उसमें दो सर्विस टनल्स दी जा रही है। उस टनल का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। माननीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधान मंत्री थे तो उनकी कैबिनेट ने 1355 करोड़ रुपये इसके लिए सैंक्शन किए थे। इस साल वह टनल थ्रू हो जायेगी और उसमें से इमरजेंसी ट्रेफिक की शुरुआत करेंगे। मगर दो सर्विस टनल्स और फाइनल फिनिशिंग को अभी लगभग दो साल लगेगे। इसके बनने से हमारे सैलानियों को लाहौल-स्पिति जाने के लिए द्वार खुलेगा। लाहौल-स्पिति की घाटी बहुत सुंदर है। वहां पर बहुत से मंदिर और बौद्ध मठ

7.3.2017/1735/av/AS/2

हैं जो कि सैंकड़ों-हजारों साल पुराने हैं। उन्हें विकसित करने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाये हैं। इसी तरह से वहां पर पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा ऐडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे रॉक क्लाइम्बिंग इत्यादि के लिए जगह आइडेंटिफाई की जा रही है। मैंने पीछे विधान सभा सत्र के दौरान माननीय सुधीर जी से एक सवाल पूछा था और इन्होंने लाहौल-स्पिति के लिए एक मास्टर प्लान दिया है, मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद करूंगा। सैलानियों की बढ़ोतरी के आंकड़े हमारे खोकसर और मनाली के बैरियर से लिए जा सकते हैं। एन0जी0टी0 ने जो बैरियर लगाया था उसमें पिछले तीन सालों में बढ़ोतरी हुई है। वहां पर हजारों की संख्या में विदेशी और देश के हर राज्य से पर्यटक आ रहा है उससे हमारे लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा; यह मेरा मानना है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

07/03/2017/1740/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

श्री रवि ठाकुर- - - जारी

माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर जी जो स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं, उन्होंने भी हेपेटाइटिस-बी0 की सुविधा हेतु कदम उठाया है। स्पिति घाटी में हेपेटाइटिस के मरीज पूरे देश में सबसे ज्यादा थे, मगर उसके इलाज के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब हेपेटाइटिस-बी के इलाज के लिए वहां पर कैंप्स लग रहे हैं और तीसरा राउंड वहां पर चल जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा। एक बहुत बड़ा केन्द्र आई0सी0एम0आर0, जिसका जबलपुर के निरथ में मेन स्टेशन है, जोकि ट्राईब्ल रूरल हैल्थ का केन्द्र है। वह हमें केन्द्र सरकार से मिला है और यह केलांग के अंदर खुला है। इसमें कर्मचारी और अधिकारी रख दिए गए हैं और वह सर्विसिज़ और रिसर्च का कार्य करेगा। फॉरेस्ट क्लीयरेंस आने के बाद इसके भवन का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल सरकार ने यह नीति बनाई है कि जो जन-जातीय इलाकों में पी0जी0 करने जायेंगे, उनका पी0जी0 2 सालों में पूरा माना जायेगा। इससे स्पिति घाटी को बड़ा फ़ायदा हुआ है। वहां पर ज्यादातर पोस्टें भर दी गई है, लेकिन स्पेशलिस्ट वहां ज्वाईन न करने की वज़ह से वहां के लोगों को परेशानी आ रही

थी लेकिन अब जगह-जगह शिवर लाये जा रहे हैं और एन0एच0आर0एम0 इसका विशेष ध्यान रख रहा है। इसके अलावा सर्दियों में जब रोहतांग दर्रा बंद हो जाता है, उस समय हेलीकॉप्टर की सेवाएं लाहौल स्पिति में सुचारू रूप से चल रही है और उसमें सैंकड़ों मरीजों/कर्मचारियों जिनको इमरजेंसी होती है, उनको लाया ले जाया जाता है। लाहौल स्पिति में जो 14 हैलीपैड है, उन सबमें यह सेवा चल रही है। इसके अलावा लाहौल स्पिति को टेलीमैडिसन के द्वारा 6000 मरीजों का इलाज करने के लिए पूरे देश में सम्मानित किया गया है। टेलीमैडिसन स्कीम में सीधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ मरीजों की बात होती है और उनका उपचार किया जाता है। केन्द्र सरकार ने ताबो में एक बहुत बड़ा बौद्ध मैडिटेशन सेंटर बनाने के लिए 40 करोड़ रुपये दिए हैं, जोकि एक Buddhist Center होगा। जन-जातीय क्षेत्र के लिए एफ0सी0ए0 केस में भी 2 साल के लिए केन्द्र सरकार से रिलैक्सेशन मिली है। इसे भी मैं राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा कदम मानता हूं, क्योंकि सन 1980 में फॉरेस्ट एक्ट लगा था और इसमें पूरे भारतवर्ष की जितनी भी भूमि थी, उसको जंगलात के अन्दर लिया गया था और यदि कोई सड़क या पुल बनाना होता था तो उसके लिए

07/03/2017/1740/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

केन्द्र सरकार से हमेशा परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन इसके बाद 1986 में पीसा एक्ट लागू किया गया जिसमें ज्यादा ताकतें प्रदेश की पंचायतों को दी गई।

श्रीमती एन0एस0- - - द्वारा जारी।

07/03/2017/1745/ ns/dc/1

श्री रवि ठाकुर -----क्रमागत।

वर्ष 2006 में पूरे देश के लिए एक फोरेस्ट राईट एक्ट भी बनाया गया था इससे काफी ज्यादा हमारे लोगों को लाभ पहुंचा था खासतौर पर अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ

पहुंचा था। पूरे देश में लगभग हमारी आबादी 13 या 13.50 करोड़ की है। अभी हाल ही में एक ओर पॉलिसी बनाई गई थी कि सभी अनुसूचित जनजाति के लोगों को समान वितरण किया जाना चाहिए और 50-50 बीघे हमोर फोरैस्ट डिवैलर्ज के हर परिवार को दिया जाना चाहिए। क्योंकि being forest dwellers they are dependent on the minor produce of forest. (घण्टी) जितनी भी हमारी स्कीमज़ हैं, वे हिमाचल सरकार ने आगे दी हैं। मैं समझता हूँ कि इससे लाहौल और स्पिति, किन्नौर, भरमौर और पांगी में नौतोड़ भी दिए जाएंगे। हमारे लोगों को इससे बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो प्वाइंट्स पर थोड़ा-सा बोलना चाहूंगा। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने हमारी कांग्रेस पार्टी की पत्रिका को पढ़ने के लिए एक मश्वरा दिया था। मैं उस पर यह बोलना चाहूंगा कि जो हमारा इतिहास है history can't be erased, so that remains and the truth remains. जो आपकी पत्रिका है मुझे मालूम नहीं है कि उसमें क्या लिखा है? उसे भी हम जरूर पढ़ेंगे लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी कांग्रेस की जो रीत या इतिहास है उसमें हमारे कई नेताओं ने जीवनदान दिया है। अपने जमीन जायदाद दान में दी है। कांग्रेस पार्टी का जो मेनिफैस्टो, आईडियोलॉजी और नीति है वह हमेशा से महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चले हैं और उन्होंने कभी भी यह जिज्ञासा नहीं रखी थी कि वे कोई विधायक या सांसद की कुर्सी लेंगे। हमारी पार्टी और पार्टी के नेता निःस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं। मैं यहां पर अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो केंद्र में हमारी सरकार है उनकी नीतियों से कई बार जनता को ठेस पहुंचती है। 26 जनवरी को एक तरफ तो इन्डायरैक्टली पोलराईजेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ ओबामा को बुलाते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि गऊ हत्या नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक-दूसरे पर निर्भर हैं। जब इन्दिरा जी प्रधान मंत्री थे तब भी अनाज़ बाहर से आया था। आज भी हम हथियार बाहर के देशों से लेते हैं। हम स्वतंत्र है और हम अपनी मर्जी से

07/03/2017/1745/ ns/dc/2

किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। पूरे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमारा O⁺, O⁻ AB⁺, AB⁻ ब्लड ग्रुप है चाहे वे किसी भी देश के मनुष्य हैं उनको परमात्मा ने एक बराबर एक समान बनाया है। यह बात जरूर है कि हमारे हिन्दू राष्ट्र में वर्ग और जातियां इसलिए बनाई गई हैं कि आर्थिक नीतियां और रहन-सहन के तरीके को और ज्यादा मजबूत किया जाए। इसमें जो भी जातियां बनी थीं वह सेवा भावना से तरखाण या सफाई कर्मचारी बनाये गये थे तब महात्मा गांधी जी ने उनको हरिजन नाम दिया था। (घण्टी) वे अपने नाम के साथ राम लगाते हैं। उसी तरह शर्मा लोग भी राम लगाते हैं। जो पोलराईजेशन कर रहे हैं यह बहुत बुरी और दुःख की बात है। ब्राह्मण लोग हमें गुरुकुल में शिक्षा-दीक्षा देते थे। शिक्षा-दीक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी चुराई नहीं जा सकती है और

श्री आर०के०एस० ---जारी

07/03/2017/1750/RKS/AG/1

श्री रवि ठाकुर....जारी

जो जीवन भर हमारे साथ रहती है।

Speaker: Hon'ble Member, please wind-up.

श्री रवि ठाकुर: इसी तरह से जो हमारे क्षेत्रीय लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप चित्तौड़गढ़ जाइए। चित्तौड़गढ़ में जब ज्वाहर हुआ था तो ज्वाहर में हजारों रानियों ने, जितनी भी सती होती हैं, जो विधवाएं पीछे रह गई थी उन्होंने इसमें छलांग लगाई थी। क्योंकि उनके जो पुरुष हैं वे लड़ाई करने के लिए तलवार लेकर गए थे। उस समय अन्य जाति के लोग आराम से घरों में सो रहे थे। जिनके बच्चों और औरतों ने अग्निकुंड में छलांग लगाई उन्होंने भी इस दुःख को सहन किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आर्थिक रूप से जो हमें अपने परिवार व बच्चों के लिए चीज़ चाहिए उसके लिए यह सारे संबंध होते हैं।

इसमें आर्थिक पॉलराइजेशन या एक-दूसरे को छोटा-बड़ा न समझते हुए हमें विकास करना है। हमें एक-दूसरे के ऊपर विश्वास रखना है।

Speaker: Please wind-up. माननीय सदस्य, बहुत लम्बा हो गया।

श्री रवि ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, मैं आर्थिक रूप से नोटबंदी के ऊपर कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष: अब आपको नहीं बोलना है। आपने बहुत समय ले लिया है। We have allotted two hours for eight persons. 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और आप 22 मिनट बोल चुके हैं।

श्री रवि ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, मैं कन्कलूड कर रहा हूँ। पूरे विश्व में हर जीव-जन्तु को सबसे प्यारी अपनी जान होती है।

अध्यक्ष: कृपया कन्कलूड कीजिए।

07/03/2017/1750/RKS/AG/2

श्री रवि ठाकुर: हर व्यक्ति अपनी खुशी चाहता है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि नोटबंदी से सैंकड़ों लोग मर गए थे। मैं एक मिशाल देना चाहूंगा। एक स्त्री झाड़ू लगाती थी और उसने 10-20 रुपये इकट्ठा करके 1000 रुपये जोड़ लिए थे। जब वह पुराने नोटों को बैंक में बदलने गई तो उसे पता चला कि पुराने नोट बंद हो गए हैं। उस स्त्री को उसी वक्त दिल का दौरा पड़ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी एक मां के दो-तीन बच्चे थे। उस स्त्री ने अपने बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा कर जान दे दी। क्योंकि उसको पैसे नहीं मिल रहे थे। मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि चंडीगढ़ के अंदर 'एक्सचेंज ऑफ नोट्स' का केन्द्र होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर पड़ती है। इससे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के लोग बहुत हराश हो रहे हैं।

जहां तक जी.डी.पी. ग्रोथ रेट की बात है। जी.डी.पी. स्टैटिस्टिकल के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स दिल्ली में हैं वे प्राक्कलन ही दे रहे हैं।

प्रोपर जी.डी.पी. ग्रोथ रेट की उन्होंने घोषणा नहीं की है। जी.डी.पी. ग्रोथ रेट पहले 8.1 थी। नवम्बर में जी.डी.पी. ग्रोथ रेट 7.1 थी। उसके बाद It is only estimates they are giving. इससे हमारे देश को आने वाले समय में भारी क्षति पहुंचेगी। क्योंकि अमेरिका में सन् 1931 में 30 प्रतिशत नोटबंदी हुई थी लेकिन भारत में 85 प्रतिशत नोटबंदी हुई है। आने वाले समय में हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। खासतौर से इस नोटबंदी के कारण बागवान और किसान को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। कच्चे तेल के दाम आधे हो गए हैं लेकिन पेट्रोल की कीमत पिछले कुछ महीनों से 10 रुपये बढ़ा दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। जो महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण दिया है मैं उसका समर्थन करता हूँ और आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री एस० एल० एस० द्वारा जारी...

07.03.2017/1755/SLS-AG-1

अध्यक्ष : अब श्री विजय अग्निहोत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री विजय अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पढ़ा और उसके ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां पर लाया गया है, उसके ऊपर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व बहुत से वक्ताओं ने इसके पक्ष और विपक्ष में अपनी बात रखी है। सुबह प्रश्न काल में प्रश्न संख्या : 3734 श्रीमती आशा कुमारी जी का लगा था जिस पर कहा गया कि कल्याण विभाग की स्थिति बहुत दयनीय है। उसके पश्चात उन्होंने अभिभाषण पर भी बहुत-सी बातें कहीं। ...(व्यवधान)... Wishes दी हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बोलना बंद कर दूँ। आशा जी ने यहां पर कुछ इसुज रेज़ किए हैं। श्री बिक्रम सिंह जी ने एक बात उठाई थी कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है तो इन्होंने कहा

कि वहां पर मंत्री की बीवी भी लगी है। मैंने सोचा कि मुकेश जी शायद उस समय यहां नहीं थे, और मैडम आपके बारे में बोल रहे थे, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। राजधानी के ऊपर भी आपने बहुत से प्रश्न पैदा किए। इसी तरह अगर हम पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल पर नज़र दौड़ाएं तो ...(व्यवधान)...

श्रीमती आशा कुमारी : आपने सुना नहीं, मैंने पूर्व मंत्री की बीवी के बारे में कहा था।...(व्यवधान)...

श्री विजय अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, राजधानी के विषय में भी बहुत-सी बातें हुई कि हमने हिमाचल प्रदेश में दूसरी राजधानी दे दी है जिसे शुरू कर रहे हैं और विधान सभा भी धर्मशाला में है। इसके बारे में हमें पूछा जा रहा था कि आप क्या चाहते हैं? आप उसके विरोध में हैं या पक्ष में हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि जैसे फुटबॉल की गेम होती है। उसमें जब किसी टीम को लगता है कि गेम हाथ से निकल गई तो वो बड़े ज़ोर-ज़ोर

07.03.2017/1755/SLS-AG-2

की हिट्स मारने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई-न-कोई वॉल पोस्ट में पहुंच जाए। लेकिन यह आपकी गलत-फहमी है। आप जितनी मर्जी राजधानियां बना लें, जितने मर्जी काम कर लें, अब वह गोल होने वाला नहीं है; आपकी वॉल पोस्ट तक नहीं पहुंचेगी। आप यह बड़ी-बड़ी हिट्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपने पिछले 4 वर्षों में इस प्रदेश में कोई विकास नहीं किया। आपका कोई विज़न नहीं है। आप इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं, यह आपने निश्चित नहीं किया। किस विषय में आपकी कौन-सी प्राथमिकताएं हैं, यह आपने निर्णय नहीं लिया। अब जब लोग विकास के बारे में पूछेंगे, काम के बारे में पूछेंगे और अब जब लोग आपसे 5 सालों का हिसाब लेंगे तो आप बोलेंगे कि हमने राजधानी बना दी है। राजधानी से लोगों का भला होने वाला नहीं है। आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। जब स्कूल के लिए अध्यापक मांगते हैं तो आप कहते हैं कि

प्लस टू ले लो, प्लस टू मांगते हैं तो कहते हैं कि कॉलेज ले लो और अब कॉलेज मांगते हैं तो आप यूनिवर्सिटी दे देंगे। आप कह रहे थे कि वहां पर CDPO नहीं है तो आपको वैलफेयर डायरेक्टोरेट दे देंगे। पिछले 4 वर्षों में यहां पर ऐसा ही माहौल बना है। आपने जहां-जहां स्कूल या कॉलेज खोले, उनकी हालत क्या है, क्या आपने कभी यह सोचा? जो प्लस टू स्कूल आपने स्तरोन्नत किए, क्या उनके लिए आपने कोई एक भी कमरा बनाया? क्या आपने कभी सोचा कि जो छात्र वहां पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमने कभी फट्टा लगाने के सिवाये कोई और सुविधा भी दी?

जारी...श्री गर्ग जी

07/03/2017/1800/RG/AS/1

श्री विजय अग्निहोत्री---क्रमागत

गवर्नमेंट हाईस्कूल की जगह, गवर्नमेंट सीनियर सैकण्डरी स्कूल दे दिया। आपने कहा कि इससे शिक्षा का स्तर ऊपर चला जाएगा। आपने यह सोचा ही नहीं कि गुणात्मक शिक्षा बच्चों को कैसे दें? आपने तो केवल यह सोचा कि हम लोगों में कन्फ्यूजन क्रियेट करके अपनी राजनैतिक रोटियां कैसे सैकें? हम लोगों को बोलें कि आप डॉक्टर मांगते हैं, लेकिन आपको सी.एच.सी. दे दी, आप सी.एच.सी. मांगो, आपको मैडिकल कॉलेज दे दिया और मैडिकल कॉलेज कहां है और किस स्थिति में आप शुरू कर रहे हैं? उन स्थितियों में आपने बच्चों को क्या सिखाना है? आपने कभी सोचा कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? अगर कॉलेज खुल गए, तो कॉलेज कहां चल रहा है? प्राथमिक विद्यालय में कॉलेज चल रहा है। कैम्पस में खड़े होने के लिए जगह नहीं है, वहां स्कूल के बच्चों को खिचड़ी खाने की जगह नहीं है, लेकिन आपने कॉलेज खोल दिया और कॉलेज के लिए आपने आज तक कोई भूमि चिन्हित नहीं की। आपने वहां उसके लिए किसी बजट का प्रावधान नहीं किया। अभी एक लाख रुपये कहीं और पहुंच गया। आज सुबह ही बात चल रही थी। इसलिए शिक्षा के स्तर को आपने जितना गिराना था, गिरा लिया और इन चार सालों में इस प्रदेश को बहुत हानि हुई है। चाहे वह 'रूसा' को बिना तैयारी के शुरू करने की बात हो, चाहे अन्य कोई सिस्टम अडॉप्ट करने की बात की हो। इस प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में स्तर बहुत नीचे गया है। अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि हमने प्रदेश को दूसरी राजधानी दे दी।

संसदीय कार्य मंत्री : आप बहुत जल्दी वहां पहुंच जाएंगे।

श्री विजय अग्निहोत्री : राजधानी शिमला पहुंचने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि धर्मशाला में हमारी विधान सभा है उस विधान सभा से उस क्षेत्र के लोगों को क्या-क्या लाभ हुए हैं? उस विधान सभा में जो पांच दिन का सत्र होता है उसका कितना खर्चा आता है और जो पांच दिन का शिमला में सत्र होता है उसका कितना खर्चा आता है? आप इन दोनों का कम्पेरीजन कर लें। आप जनता के पैसे से ऐसे ही मजे लूटने की कोशिश कर रहे हैं और वाह-वाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आप यह बताइए कि जनता को उससे क्या लाभ होने वाला है? क्या इससे जनता को कोई लाभ होगा? वहां ट्रांजिट कैम्प लगेंगे, आपके अधिकारी/कर्मचारी दस दिन

07/03/2017/1800/RG/AS/2

के लिए धर्मशाला जाएंगे, धर्मशाला वाला यहां आएगा, फिर डी.ओ. नोट्स की बोरियां भरकर इधर-उधर जाती रहेंगी। लेकिन जनता को इस सबसे कोई लाभ नहीं होगा जैसे विधान सभा का नहीं हो रहा है। इसलिए यह जो तुगलकी फरमान है और बिना सोचे-समझे आप लोगों को कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और खासकर चुनावी वर्ष में ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, यह गलत है। आप जनता को बहुत ज्यादा बरगला नहीं सकते, जनता बहुत समझदार है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि नोटबन्दी से बहुत नुकसान हो गया, तो यह चण्डीगढ़ के लोगों ने बता दिया, आपने कहा कि बहुत नुकसान हो गया और लोग मर गए, तो मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि में बता दिया और आने वाली 11 मार्च को आपको और जगह भी पता चल जाएगा कि नोटबन्दी के कारण से किसको नुकसान हुआ। रवि ठाकुर जी, उनको नुकसान हुआ जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। वे पैसा कहां खपाते और जो लाईनें लगाईं वे भी उन्होंने ही लगाईं कि चार-चार हजार लेकर आ रहे हैं, ले आओ, एक हजार आप ले लेना। आप बोलते हैं कि मोदी जी ने कहा कि 15,00,000/-रुपये हमारे खाते में आ जाएंगे, लेकिन आज तक आया नहीं। आपके खाते में

जो आया, जो ऐसे ही इधर-उधर था जो खातों में आ गया, वह वही पैसा कालाधन है। जो जनधन खातों में शून्य बैलेंस था वहां आज जहां डेढ़ लाख करोड़ रुपये जो जमा हुआ है वह कहां से आया? वह वही कालाधन वहां पहुंचा है। इसलिए ये बातें करना बन्द करो। इस नोटबन्दी के ऊपर आप जितना बोलेंगे, उतना ही आप ऐक्सपोज होते जाएंगे। जो पैसे के कारण रिश्तेदारी भूल गए थे वे पैसा छिपाने के लिए अपने रिश्तेदारों को ढूँढ रहे थे। नोटबन्दी ने यह किया। इसलिए जो यह अभिभाषण राज्यपाल महोदय के माध्यम से यहां रखने की कोशिश की है।----(व्यवधान)----मैं आपसे (श्री रवि ठाकुर जी की ओर इशारा करते हुए) नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो यहां बात रख रहा हूं। अगर डिमॉनीटाइजेशन के ऊपर बोलना होगा, तो मैं और आप इसके बाद मिल लेंगे। इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से सरकार के जो एक वर्ष के कार्यकाल का लेखा-जोखा यहां रखा गया है

एम.एस. द्वारा जारी

07/03/2017/1805/MS/AG/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी-----

उसमें बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। आपकी कोई दिशा नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र को ले लो। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, युवा, कर्मचारी या महिला वर्ग, किसी भी विषय में आपका कोई विजन नहीं है। आपने पर्यटन के लिए क्या किया? हिमाचल प्रदेश की प्रायोरिटीज क्या हैं उनके लिए क्या किया, इसके माध्यम से कुछ भी दर्शाने की आपने कोशिश नहीं की है। आपने किसान को बड़ी चीजें दर्शाने की कोशिश की कि आपकी बाड़बन्दी हो जाएगी, सोलर लाइट का करन्ट लगेगा लेकिन एक भी व्यक्ति ने इसका लाभ नहीं उठाया। आपने कहा कि ये जो जंगली जानवर हैं इनसे प्रदेश के किसान को मुक्त कर दिया जाएगा लेकिन इसके ऊपर भी कोई ज्यादा काम नहीं हो पाया बल्कि लोग और ज्यादा खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। आपने किसान और युवा को खेत तक पहुंचाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया है, यह चार वर्षों के कार्यकाल का आपका नतीजा है। आपने किसी किसान को मोटीवेशन नहीं दी कि हम खेती करने के लिए आपको ये-ये इन्सैंटिव्स देंगे या ऑर्गेनिक खेती करने के लिए

सर्टिफिकेशन की सुविधा देंगे। आपने इसके ऊपर विचार करने की कोई कोशिश ही नहीं की इसलिए जो प्रदेश का किसान है वह खेती की तरफ क्यों मुड़े? आपने युवाओं के लिए जैसे अभी ठाकुर साहब ने बताया कि कैसी-कैसी भर्तियां कीं और क्या-क्या हो रहा है यानी युवाओं के साथ कैसा छल हुआ। आपने युवाओं को कितनी नौकरियां दीं? आपने जो नौकरियां दीं वे चोर दरवाजे से दी हैं। चाहे वह पी0टी0ए0 हो, पैट हो, आउटसोर्स हो या एस0एम0सी0 हो, हर जगह आपने धान्धली की। जो बच्चे मैरिट पर आने वाले थे उनको कहीं नहीं रखा गया। हर जगह आपने कोशिश की कि हमारे कार्यकर्ता कैसे एकाॅमोडेट हो। आप कार्यकर्ताओं को एकाॅमोडेट करते-करते यह भूल गए कि हमें प्रदेश की जनता ने यहां का कार्यभार सौंपा है जिनके लिए हमें काम करना है। सड़कों की हालत देख लो। यहां से हमीरपुर जाओ तो देख लो क्या हालत है। यहां से आप चण्डीगढ़ जाओ तो देखो बुरा हाल है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि लोग अब पैदल आना-जाना पसन्द करते हैं। वहां धनेटा से रंगस की तरफ की सड़क को ले लो। धनेटा से बड़छर की सड़क ले लो। वहां से पन्याली होते हुए गलोड़ की सड़क ले लो या पन्याली से कश्मीर वाली सड़क ले लो। गलोड़ से गालियां या गण्डोली वाली सड़क ले लो या फिर टिप्पर वाली सड़क ले लो। आप रंगस से बड़ाह की तरफ चले जाओ, इतनी बुरी हालत है

07/03/2017/1805/MS/AG/2

कि आम व्यक्ति इन सड़कों पर गाड़ी चलाना अब सुरक्षित नहीं समझता है। आम व्यक्ति वहां दुःखी है। पीछे वहां पर लोगों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन भी किए। वहां के कार्यालयों में भी गए लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर सड़कों पर कुछ काम नहीं हुआ। पिछले चार वर्षों में लोक निर्माण विभाग ने एक भी डी0पी0आर0 हमारी नहीं बनाई है। आप कहते हैं कि सबका कल्याण और समग्र विकास हो रहा है। विकास पता नहीं अब रोहडू का हो रहा होगा या जहां से कन्डक्टर लग रहे हैं वहां का हो रहा होगा। इस सरकार की यदि कोई उपलब्धि है तो वह यह है कि इसके राज में माफिया का बोलबाला है। आपने यहां की व्यवस्था को जर्जर कर दिया है। यहां की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको आपने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। यहां के आपके जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वे सरकार की हैसियत के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। जो आपके पॉलिटिकल ऑफिस बियरर हैं वे हरेक चीज में इंटरफेयर करते हैं और आपकी सरकार चुने हुए लोगों को इग्नोर करती है।

इसी तरह से खनन के बारे में इस विधान सभा में और विधान सभा के बाहर हजारों बार बातें चली हैं कि फलां जगह जे0सी0बी0 के साथ खनन हो रहा है। वहां का पानी दूषित हो रहा है, सूख रहा है और खड्डे खत्म हो रही हैं। पानी के बारे में बोलो तो माइनिंग वाले बोलते हैं कि आप पॉल्यूशन में जाओ, पॉल्यूशन वालों को बोलते हैं तो वे कहते हैं कि आप रिटन में दो, आज हम किसी और जगह पर हैं। यानी यह वहां एक पूरा तामझाम चला हुआ है। इस करके इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में ड्रग और शराब माफिया बहुत जोरदार तरीके से काम कर रहा है। हमारे यहां बहुत से बच्चे अब ड्रग एडिक्ट होते जा रहे हैं।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

07.03.2017/1810/जेके/डीसी/1

श्री विजय अग्निहोत्री:-----जारी-----

और मैंने पहले भी यहां विधान सभा में कहा था कि वहां गांव धनेटा में अभी एक को केपस्यूल बेचते हुए पकड़ा गया है। वह कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है? वहां पीछे एक 26 साल के लड़के की केपस्यूल खाने से मौत हो गई। हम कहां जा रहे हैं? सिर्फ सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो पुलिस है पता नहीं वह क्या काम कर रही है और किस के लिए काम कर रही है? कोई भी क्षेत्र ले लो। आपने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया, मजदूरों के लिए कोई काम नहीं किया सिर्फ पिक एण्ड चूज के माध्यम से काम किया। माननीय उद्योग मंत्री जी आपके चुनाव क्षेत्र में भी वार्शिंग मशीनें किसी-किसी को मिल रही है। वह भी सोचते हैं कि कोई मेरी मीटिंग करवाएगा कि नहीं करवाएगा। वहां इतनी बुरी हालत है कि वहां के प्रिंसिपल को प्रेशेराइज़ किया जाता है कि उस गांव में मेरी मीटिंग करवाओ। वहां पर जो टी0जी0टी0 लगा है उसके ऊपर वह दबाव डालता है कि कांग्रेस से मीटिंग करवाओ तब आपके यहां के काम होंगे यानि तब आपके लिए कुछ मिलेगा। यह आपने पूरे चार सालों में किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में पेयजल की भी हालत ठीक नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि खनन के कारण जो वहां की दो खड्डें हैं, मान खड्डु और कुनाह खड्डु, उनके

ऊपर अनसाईटिफिक और अलिगल माइनिंग जो हो रही है उसके कारण उसका स्तर बहुत नीचे चला गया है। गर्मियों के दिनों में वहां पानी सूख रहा है, जो 12 महीने वहां पर पानी बहता था। वहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप इतना है कि मैंने विधायक निधि से हैंडपम्प लगाने के लिए पैसा दिया। उस हैंडपम्प लगाने के लिए वहां के आई0पी0एच0 डिपार्टमेंट ने जो ड्रिलिंग मशीन वहां पर भेजी जब वह मशीनें वहां स्पॉट में पहुंचती है तो वह ड्रिलिंग वाला बोलता है कि मुझे पीछे से फोन आ गया कि यह हैंडपम्प नहीं लगेगा। मैंने एक्सिअन से पूछा कि हैंडपम्प क्यों नहीं लगेगा? उसने कहा कि मेरे ऊपर सरकार का प्रेशर है कि यह हैंडपम्प नहीं लगना चाहिए। मैंने उससे कहा कि मैंने विधायक निधि से पैसे दिए हैं, आप कैसे इन्कार कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम आपकी विधायक निधि वापिस कर देंगे। उन्होंने मेरी विधायक निधि वापिस कर दी और उसमें लिखा कि हम आपके हैंडपम्प लगाने में असमर्थ है क्योंकि हमारे पास ड्रिलिंग मशीन नहीं है। जब उन्होंने यह लिखा उसी दिन वे मशीनें वहां बड़ा पंचायत की डब्बरपट्टा में खड़ी थी और 14 दिन तक वहां पर लोगों ने उनको खड़ा रखा। 14 दिन के पश्चात भी वह हैंडपम्प नहीं लगने दिया। मैंने उनसे कहा

07.03.2017/1810/जेके/डीसी/2

कि मैं जेब से पैसे देता हूं आप इस हैंडपम्प को लगाओ। मैं पैसे देता हूं मैं अपने खाते से बैंक काट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं लगेगा। हमारी 60 लाख की पेमेंट आई0पी0एच0 डिपार्टमेंट में है और हमें यह कहा गया कि अगर हमने वह हैंडपम्प लगाया तो आपकी ये पेमेंट नहीं की जाएगी। ऐसा माफिया राज वहां पर चल रहा है और पूरे प्रदेश में चल रहा है। वहां पर एक इरिगेशन की स्कीम है पोला-मझयार छेरा फेज-1, फेज-II, फेज-III। उसका काम वर्ष 2002 से चल रहा है। इस बारे में मैं तीन-चार बार प्रश्न कर चुका हूं। उसमें कहा जाता है कि थोड़ा सा काम बचा है लेकिन जल्दी हो जाएगा। उसमें करोड़ों रूपए खर्च किए जा चुके हैं उससे एक भी खेत तक पानी नहीं पहुंचा है। उस इरिगेशन प्रोजेक्ट को वहां पर जानबूझ कर लटकाया जा रहा है। जहां पेयजल की समस्या है वहां हैल्थ सर्विसिज की भी बहुत बुरी हालत है। माननीय मंत्री जी अब यहां पर पहुंचे हैं। सी0एच0सी0 की बिल्डिंग का शिलान्यास आदरणीय प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था और उसके ऊपर काम हुआ

था, जो काम उस समय का हुआ है वह काम आज भी वहां का वहां खड़ा है। मैं वहां सी०एच०सी० में गया।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य जी आप वाईड अप करिए। बहुत हो गया है। अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्री विजय अग्निहोत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं वाईड अप कर रहा हूं। अब मैं केवल दो मिनट लगाऊंगा। वहां जब ये जाते हैं और सी०एच०सी० बनाने की घोषणाएं तो यहां पर प्रदेश सरकार करती है लेकिन नादौन की सी०एच०सी० में वहां के जो मरीज हैं वे बोलते हैं कि हम यहां गैलरी में बैठे हैं और हम एडमिट होने के लिए बैड भी घर से लाए हैं। यह हालत वहां की है। वे घर से मंजा ले कर आ जाते हैं

श्री एस०एस० द्वारा जारी-----

07.03.2017/1815/SS-DC/1

श्री विजय अग्निहोत्री क्रमागत:

तब जाकर कोई रात को सीढ़ियों पर सोया और कभी कहीं सोया है। पिछले पांच-छः सालों से उस बिल्डिंग का काम चल रहा था लेकिन आपके पिछले तीन सालों से वह बंद है। उस विषय पर सोचने की आपको कभी फर्सत नहीं मिली। कांगू पी०एच०सी० की बिल्डिंग का भी उसी वक्त शिलान्यास हुआ था। उसका लगभग 95 परसेंट काम पूरा हो गया लेकिन आज तक उसको शिफ्ट नहीं कर सके। इस करके, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है जिसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव आया है इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। पिछले चार वर्ष से इस प्रदेश में दिशाहीन रूप से सरकार काम कर रही है। इसका कोई विज़न नहीं है। इसमें कहीं जाने के लिए दिशा तय नहीं है। इन्होंने कोई प्राथमिकता तय नहीं की है। पर्यटन के क्षेत्र में बुरी हालत है। हम इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं इसमें कुछ दिशा नहीं है इस करके मैं इसका विरोध करता हूं, समर्थन नहीं कर सकता, धन्यवाद।

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने माइनिंग को लेकर बात की है। ये मुझे स्पैसिफिक अपनी कांस्टीचुऐंसी की बात लिखकर दे दें मैं उसमें जांच करवा दूंगा। समयबद्ध तरीके से जांच करवा देंगे कि कौन-से क्रशर हैं जिनका कि ये कह रहे हैं कि इल्लीगल काम हो रहा है। हमारी तरफ से उनको एल0ओ0आईज़0 मिले हुए हैं लेकिन अगर इनके ध्यान में ऐसे क्रशर हैं तो उनके नाम दे दें और हम उसकी जांच करवा लेंगे।

07.03.2017/1815/SS-DC/2

अध्यक्ष: अब श्री किरनेश जंग जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री किरनेश जंग: माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक मार्च को जो अपने अभिभाषण में इस सदन को सम्बोधित किया और उसका माननीय सी0पी0एस0, श्री जगजीवन पाल जी ने धन्यवाद किया तथा माननीय सदस्य, श्री संजय रतन जी ने अनुमोदन किया, मैं भी उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महामहिम राज्यपाल ने सरकार के पिछले बजट की सराहना की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले चार वर्षों में हिमाचल में चहुंमुखी विकास हुआ है। मैं हिमाचल की बात नहीं करूंगा बल्कि सिरमौर जिला और अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूंगा। पिछले चार सालों में जिला सिरमौर में चहुंमुखी विकास हुआ। मैं माननीय सदस्य, श्री बिंदल जी से भी कहना चाहूंगा कि वे सिरमौर के विकास का समर्थन करें। पिछली 21 और 22 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का दौरा हुआ। जिसमें नाहन क्षेत्र में सात पुलों का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास ही नहीं बल्कि उनका काम भी शुरू हो गया। वहीं जिला सिरमौर में मेडिकल कॉलेज दिया गया, जिसकी क्लासिज़ भी स्टार्ट हो गई। वहां आई0आई0एम0 खोला गया, जिसकी पांवटा में क्लासिज़ शुरू हुई। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया गया। उसकी भी क्लासिज़ स्टार्ट हो गई। पांवटा क्षेत्र जोकि एक दूर-दराज का इलाका था, आज वहां डिग्री कॉलेज दिया गया, जिसकी क्लासिज़ शुरू हुई। जहां गरीब मां-बाप अपने बच्चों

को दूर नहीं भेज पाते थे आज उनके बच्चे घर पर रोटी खाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत से स्कूल अपग्रेड हुए। दो मॉडल स्कूल दिये गए। अगर बिजली विभाग की बात करें तो एक डिजास्टर सेंटर खोला गया। दो 33 के0वी0 के सब-स्टेशन खोले गए और 20 करोड़ की लागत से नए पुल तथा 100 ट्रांसफार्मर्ज़ लगाए गए। पांवटा शहर की सुन्दरता के लिए एल0ई0डी0 लाइटस लगाई गईं। हर चौराहे पर हाई मास बीम लाइट लगाई गईं।

जारी श्रीमती के0एस0

07.03.2017/1820/केएस/एजी/1

श्री किरनेश जंग जारी-----

पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में करोड़ों की लागत से सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं पांवटा की सुन्दरता के लिए 80 लाख की लागत से यमुना पथ का निर्माण कार्य चल रहा है। आई.पी.एच. विभाग में नई स्कीमों का उद्घाटन कर, चाहे पीने के पानी की स्कीम हो या सिंचाई की स्कीम हो, लोगों को समर्पित किया गया है वहीं सैंकड़ों हैंडपम्प लगाकर जहां लोगों को पीने के पानी की जरूरत थी, उनकी समस्या को दूर किया गया। स्वास्थ्य विभाग में राजा साहब और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री कौल सिंह जी के आशीर्वाद से 100 बेड के अस्पताल की बिल्डिंग बनाकर लोगों को समर्पित की गई। वहीं पी.एच.सी. खोले गए, 10 बेड का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोला गया। अगर किसानों की बात करें तो ढाई सौ करोड़ की टर्मिनल मण्डी पांवटा में दी गई। जिसमें कोल्ड स्टोर और राइपनिंग चैम्बर का कार्य शुरू हुआ है। किसान लोगों के ट्रैक्टर्ज़ पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में कमर्शियल व्हिकल में रजिस्टर हुआ करते थे परन्तु राजा साहब के आशीर्वाद से उनको एग्रिकल्चर में रजिस्टर कराया गया और किसानों के ऊपर हजारों रुपयों का लोन था, टैक्स थे उनको भी माफ किया गया। आज वे किसान खुशहाल हैं। आज केन्द्र की अगर बात करें तो जो सरकार केन्द्र में आई उसने लोगों से बहुत से वायदे किए

जिसकी वजह से केन्द्र में सरकार बनी। चाहे काला धन लाने की बात हो, उस सम्बन्ध में तो राम देव जी भी अब चुप हैं क्योंकि विदेशों से जब काला धन वापिस नहीं आया तो वे कन्नी काट गए। चाहे 15-15 लाख रु० हर आदमी के खाते में डालने की बात हो, नौजवानों को रोजगार देने की बात हो या अच्छे दिन लाने की बात हो, कोई भी चीज़ पूरी होती नज़र नहीं आती। नोटबन्दी लागू कर दी जिससे लोगों को बहुत ही परेशानी हुई और सैंकड़ों लोग ए.टी.एम. की लाइनों में, बैंकों की लाईनो में खड़े रहे जिससे कि उनकी मौत हो गई। जहां बैंकों में क्रप्शन नहीं थी, वहां भी क्रप्शन शुरू हो गई और जिस वजह से इन्होंने नोटबन्दी शुरू की थी कि आतंकवाद खत्म होगा, वहां आतंकवादियों के पास और भी ज्यादा पैसा पहुंच गया। अध्यक्ष महोदय, पांवटा में

07.03.2017/1820/केएस/एजी/2

4 मार्च को माननीय धूमल जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई। जहां पर एक भाजपा के सदस्य ने कहा कि यहां पर माफिया राज है और खनन माफिया और वन माफिया को संरक्षण दिया जाता है। उन्होंने अपने समय में वन माफिया और खनन माफिया को संरक्षण दिया था। पिछले दिनों पुलिस ने यमुना पर रेड की तो उन्हीं सदस्यों ने यमुना में जा कर एस.पी. से गाली ग्लौच की। मैं पूछना चाहता हूं कि खनन माफिया को संरक्षण ये लोग दे रहे हैं या कांग्रेस पार्टी दे रही है?

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

7.3.2017/1825/av/ag/1

श्री किरनेश जंग----- जारी

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भाजपा की सरकार थी तो इन्होंने अपने समय में कितना विकास किया? हम तो पहली बार इस सदन में चुनकर आए हैं। हम सोचते थे कि यहां पर

कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। मगर यहां पर जो हमारे चार साल गुजरे वह हमें पता है कि यहां क्या-क्या हुआ। यहां पर छोटी-छोटी बात पर वॉकआउट करना और सदन को चलने नहीं देना कोई अच्छी बात नहीं है। एक सीनियर लीडर के ऊपर अंगुली या कीचड़ उछालना कोई शोभा नहीं देता। यह पूरे हिमाचल का एक सदन है जहां के लिए हम चुनकर आते हैं और यहां बैठते हैं। अगर हम ही यहां बैठ कर इस तरह की बातें करेंगे तो इसका पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा? हिमाचल में राजा साहब की सरकार ने चहुमुखी विकास किया, यह हम सभी जानते हैं। मैं मानता हूं कि जब विपक्ष में बैठना होता है तो आलोचना जरूरी करनी पड़ती है। मगर मैं यह चाहूंगा कि जो विकास हुए हैं उनकी आलोचना न करो बल्कि उनका समर्थन करो। पब्लिक जो बाहर हमारी बातें सुन रही है वह भी जानती है कि हिमाचल में पिछले चार सालों में क्या विकास हुआ है और क्या नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ अंत में राजा साहब के लिए दो बातें कहना चाहूंगा जो कि इस प्रकार है :-

राजा साहब, आपके विकास के ऊपर किताब लिखेंगे॥

आपके विकास की हर बात लिखेंगे॥

जब पूछा जायेगा कि मुख्य मंत्री कैसा हो, तो आपका नाम लिखेंगे।

अंत में, यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो इस सदन को सम्बोधित किया गया मैं उसका समर्थन करता हूं। जय हिन्द, धन्यवाद।

7.3.2017/1825/av/ag/2

अध्यक्ष : अब श्री विनोद कुमार जी अपनी बात रखेंगे।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 1 मार्च, 2017 को महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने अपना अभिभाषण इस सदन में पढ़ा। मैं उस अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूँ। आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

अध्यक्ष जी, मैं भाई राकेश कालिया जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने पिछले कल जो किसी भी विधायक ने सच्चाई नहीं बताई मगर इन्होंने उस सच्च को बोलने के लिए यहां पर हिम्मत जुटाई है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। राकेश कालिया जी ने ठीक कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जितनी भी घोषणाएं करवाई जा रही हैं उनमें से केवल दो या तीन घोषणाएं पूरी हो रही हैं (***) मुझे लगता है कि इनके विधान सभा क्षेत्र में भी इस तरह की घटना घटी है। उसी कारण इन्होंने यहां सदन के अंदर सबके सामने अपना दर्द बयां किया है। मैं यहां पर अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी का मेरे चुनाव क्षेत्र नाचन का भी दो दिन का प्रवास कार्यक्रम था।

श्री वर्मा द्वारा जारी

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

07/03/2017/1830/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

श्री विनोद कुमार जारी

उस कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्लोहटा पंचायत में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की घोषणा की थी। इसके साथ-साथ जब दूसरे दिन लोट पंचायत के अन्दर इनका कार्यक्रम हुआ, तो वहां पर भी गराडीघाड एक जगह है, वहां पर इन्होंने आयुर्वेदिक औषधालय देने की घोषणा की। इसके अलावा प्लौटा, बाडू, नांडी, पिपलागलू, चौकड़ी आदि स्कूलों को इन्होंने अपग्रेड करने की घोषणा की, लेकिन न ही वहां पर

आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुले और न ही उन स्कूलों को आज तक अपग्रेड किया गया। उस टूर को हुए भी दो साल का समय बीत गया है। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पैरा 9 में इन्होंने लिखा है कि प्रदेश में 99.88 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में पेयजल सुविधा प्रदेश के अन्दर मुहैया करवा दी गई है। इसके साथ-साथ इसमें कहा है कि प्रदेश सरकार ने 99.79 परसेंट स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था की है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि बहुत-से ऐसे स्कूल हैं, जहां पर आज भी विद्यार्थियों को पीने का पानी मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। -(व्यवधान)-

07/03/2017/1830/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

मुख्य मंत्री: आपने यहां यह रोंगली कोट किया है, I can legal action against you.

श्री राकेश कालिया: सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विनोद जी ने मेरा नाम लिया है, मैंने कहा था कि जिस एम0एल0ए0 के क्षेत्र में मुख्य मंत्री गये होते हैं, उस पर यह दवाब होता है कि वह ज्यादा-से-ज्यादा घोषणाएं करवायें। वह जब अपनी लिस्ट पढ़ता है, तो पत्रकार अखबार में छाप देते हैं कि ये मांगें की गई हैं। उन मांगों को ये कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी की घोषणाएं हैं। ये इस बात को तोड़-मरोड़कर कह रहे हैं। ये बात सबको पता है कि पहली जो 2-3 घोषणाएं होती है, वहीं इम्प्लीमेंट होती हैं। लेकिन पत्रकार पूरी लिस्ट छाप देते हैं और आप उसको पूरे प्रदेश में ईशू बनाकर घूम रहे हैं। ये तो विधायक को भी पता होता है और डिक्लेयर करने वाले को भी पता होता है कि मैंने क्या दिया है और मांगने वाले ने क्या मांगा है। ये शब्द मैंने कहे हैं और ये मेरी बात को बार-बार कोट कर रहे हैं।

अध्यक्ष: जो शब्द श्री राकेश कालिया ने नहीं कहे हैं, उनको एक्सपंज किया जाये।

07/03/2017/1830/टी0सी0वी0/ए0जी0/3

श्री विनोद कुमार: भाई कालिया जी मैंने आपका धन्यवाद किया है। आपने सच्चाई बताई है। दूसरा, पैरा-13 में लिखा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सृजित करने के लिए मेरी सरकार ने 2016-17 में 16 विशेषज्ञ सहित 155 चिकित्सकों की भर्ती करवाई है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 4 सालों से सिविल हॉस्पिटल गोहर को लेकर कोई भी विधान सभा का सत्र ऐसा नहीं होता है, जिस सत्र के दौरान मैं सिविल हॉस्पिटल गोहर की चर्चा नहीं करता हूँ। वहां पर 8 डॉक्टरों के पद सृजित हैं, 50 बिस्तरों का हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पर 2 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो बड़े शर्म की बात है। उस हॉस्पिटल में हमारी लगभग 50-60 पंचायतों के लोग अपना उपचार करवाने आते हैं। जब हम बात करते हैं, तो हमारी बात को हंसी में उड़ाया जाता है कि आज करते हैं, कल करते हैं। परन्तु 4 सालें हो गई है, गोहर हॉस्पिटल में डॉक्टर आज तक नहीं पहुंच पाये हैं। हमारे साथ में लगती सी0एच0सी0 झगड़ है। एक नहीं अनेक बार मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन भी कहा कि विनोद निश्चित तौर पर मैं इसको करूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तो उस दिन नहीं थे, लेकिन आज लगभग डेढ़ साल हो गये हैं,

श्रीमती एन0एस0 - - द्वारा जारी।

07/03/2017/1835/ ns/as/1

श्री विनोद कुमार -----क्रमागत।

हालांकि हमारी ज्यूणी वैली जिसमें हमारी सात-आठ पंचायतें आती हैं वहां उस पी0एच0सी0 के अंदर कोई भी डॉक्टर नहीं है। यह अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर कहा गया है कि मेरी सरकार ने चुनावी घोषणा-पत्र, जो हमारे लिए एक निजी दस्तावेज़ है, में दिए गए सभी वायदों को

पूरा किया है। जब यह सरकार वर्ष 2003-04 में सत्ता में आई थी तब भी इन्होंने नौजवानों के साथ एक वायदा किया था कि हम घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे लेकिन उसमें किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया गया था। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री : ऐसा कहीं नहीं कहा गया है।

श्री विनोद कुमार : इस बार जब वर्ष 2012 में विधान सभा के चुनाव हुए उन चुनावों में भी आपने एक वायदा किया था कि हम जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे अगर रोजगार नहीं दे पाये तो बेरोजगारी भत्ता देंगे।

Chief Minister:- Sir, I have Point of Order.

अध्यक्ष: श्री विनोद जी आप बैठिए।

मुख्य मंत्री : हमन कभी भी किसी से यह नहीं किया कि हम बेरोजगार को रोजगार देंगे या हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। आप हमारा मेनिफैस्टो दिखाईए। We have never said these things. आप ऐसा अपनी तरफ से बोलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है हम रोजगार देंगे। हम गारंटी करते हैं कि हर परिवार से एक आदमी को रोजगार देंगे। We have made no such promise. आप दिखाईए हमारे मेनिफैस्टो में कहां लिखा है? आप अपनी तरफ से बोलते जा रहे हैं। यह गलत बयानी कर रहे हैं। हमने ऐसा कोई वायदा नहीं किया है। हमारी कोशिश है कि ज्यादा-से-ज्यादा रोजगार पैदा हों।

श्री विनोद कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2012 का जो इनका घोषणा-पत्र था उसमें हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उस घोषणा पत्र को पूरी जनता के समक्ष

07/03/2017/1835/ ns/as/2

और जितने भी यहां विधायक बैठे हैं, उनके समक्ष उस घोषणा पत्र को पढ़ा है। उसमें बेरोजगारों को भत्ता देने की जो बात कही थी वह भी उसी घोषणा पत्र में कही गई थी। इसके अलावा पैरा 21 में आपने लिखा है (व्यवधान) कि राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा 108 राज्य के

लोगों को बेहतरीन एवं समयबद्ध सेवाएं प्रदान कर रही है। लेकिन मैं सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहूंगा कि आज कई एंबुलेंस ऐसी एंबुलेंस हैं जिनमें टायर भी नहीं हैं। जब उनको फोन किया जाता है तब वे कहते हैं कि एंबुलेंस में टायर नहीं है इस कारण से एंबुलेंस नहीं आ सकती। कई जगह से बात आती है कि एंबुलेंस में तेल न होने के कारण आपको एंबुलेंस मुहैया नहीं करवाई जा सकती है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात के 12.00 बजे भी हमें एंबुलेंस के लिए फोन आते हैं। मैं मण्डी के सी०एम०ओ० साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं उनको रात के 12.00 बजे या 1.00 बजे भी फोन करूं तब भी वे पता नहीं कहां से एंबुलेंस की व्यवस्था करते हैं, उनके माध्यम से कुछ-न-कुछ सेवाएं लोगों को मिल रही हैं। लेकिन 108 एंबुलेंस की कहीं भी लोगों को प्रोपर सुविधा नहीं मिल रही है।

मुख्य मंत्री: आप जिस सी०एम०ओ० की तारीफ कर रहे हैं वह भी तो सरकार का अंग है। वह क्या अपने घर से गाड़ी भेज रहा है? हमने उसके पास वाहन इसलिए रखे हुए हैं कि एमरजेंसी में भेजे जाएं। आप एक तरफ से तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार की बुराई कर रहे हैं।

श्री विनोद कुमार श्री आर०के०एस०---जारी

07/03/2017/1840/RKS/DC/1

श्री विनोद कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पिछले कल एक प्रश्न किया था कि "नाचन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आयुर्वेदिक औषधालय कुटाहची में कितने समय से डाक्टर नहीं हैं।" माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया कि नवम्बर, 2011 से यह पद रिक्त पड़ा हुआ है। साथ ही मैंने यह भी पूछा था कि "क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है?" इसका उत्तर यह आया कि 'भर्ती प्रक्रिया' माननीय न्यायालय के विचारधीन होने के कारण वर्तमान में रिक्त पदों को नहीं भरा जा सकता है। यह कल का उत्तर है। राज्यपाल

महोदय जी से आपने यहां पर झूठ बुलवाया है। आपने लिखा है कि "मेरी सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 40 पद भरे गए हैं"। जब 40 पद भरे गए हैं तो हमें डॉक्टर क्यों नहीं दिया गया? मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। सरकार झूठ बोल रही है। आपने महामहिम राज्यपाल जी से भी झूठ बुलवाया है। इस तरह का काला कारनामा मैं आपके सामने बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पैरा 43 में इन्होंने कहा है "नाबार्ड ऋण सहायता योजना के अंतर्गत 2 हजार 894 करोड़ 39 लाख रुपये की 1 हजार विधायक प्राथमिकता योजनाएं स्वीकृत की गई है"। लेकिन यहां पर कुछ विधायकों ने बड़े ऊंचे स्वर में बात की कि हम ऊपर-नीचे के हिमाचल की बात नहीं करते। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि जिला मंडी के जितने भी हम 10 विधायक हैं, उन 10 विधायकों की कीतनी एम.एल.एज. प्रायोरिटीज बनकर तैयार हुई। मेरे नाचन विधान सभा क्षेत्र की एक भी एम.एल.ए. प्रायोरिटीज तैयार नहीं की गई। कोई डी.पी.आर. नहीं बनाई गई। एक बार नहीं अनेकों बार सरकार को कहा गया, हर मीटिंग में कहा गया। इसका क्या कारण है? आप कहते हैं कि भेदभाव नहीं हो रहा है। आप कहते हैं कि एक समान विकास हो रहा है। क्या यह आपका एक समान विकास है। रोहड़ू की 8, जुब्बल की 19, और शिमला ग्रामीण की 18 सड़कों की डी.पी.आर्ज. बनकर तैयार हो गई और सड़कों का काम भी शुरू होने वाला है। इस सरकार ने जिला मंडी के साथ सबसे बड़ा भेदभाव किया है। पैरा 46 में लिखा है कि "राज्य सड़क के रख-रखाव के लिए 218 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है"। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान

07/03/2017/1840/RKS/DC/2

दिलाना चाहता हूं कि जब आप जिला मंडी के प्रवास पर गए थे तो आपने अपने प्रवास के दौरान नाचन विधान सभा क्षेत्र का भी दौर किया। आपने अधिकारियों को आदेश दिए थे कि इन खस्ताहाल सड़कों की हालत को सुधारा जाए नहीं तो मैं सभी अधिकारियों की डिमोशन कर दूंगा। मैं चीफ इंजीनियर को एस.सी, एस.सी. को एक्शन, एक्शन को

एस.डी.ओ बना दूंगा। यह आपने कहा था। 2 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नाचन विधान सभा क्षेत्र में 90 से 95 प्रतिशत सड़कें ऐसी हैं जहां पर सड़क कम और गड्ढे ज्यादा हैं। मैंने प्लानिंग की बैठक में कहा कि धनोटू- रोहांडा की सड़क का बहुत बुरा हाल है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने झूठ का पुलिंदा महामहिम राज्यपाल से पढ़ाया है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

07.03.2017/1845/SLS-DC-1

श्री विनोद कुमार ...जारी

पैरा 52 में इन्होंने कहा है कि मेरी सरकार ने घरेलू बिजली खपत में कमी लाने के उद्देश्य से 30 जनवरी, 2017 तक 71,47,428 LED bulb वितरित कर 11,59,788 उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो LED bulb पूरे प्रदेश के लोगों को बांटे गए, जिनका मूल्य केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित किया गया था, इन्होंने उससे ज्यादा चार्जिज हिमाचल प्रदेश की जनता से लिए हैं। (घंटी) मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में चल रही थी, अगर आपके ध्यान में नहीं है तो मैं ध्यान दिलाता हूं कि हमारी सरकार ने 4-4 बल्ब हरेक परिवार को मुफ्त में दिए थे।

Speaker: Please wind up. अब आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है।

श्री विनोद कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ पैरा 76-77 में इन्होंने लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए इनकी सरकार ने अनेकों विकास कार्य किए हैं। लेकिन मैं इस सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहूंगा। जब पिछली बार इनकी सरकार प्रदेश में थी तो इन्होंने PTA के माध्यम से, बैकडोर एंट्री के माध्यम से अनेकों भर्तियों की थीं जिनमें रोस्टर नहीं लगा था। उस समय हमारे अनुसूचित

जाति और ओबीसी के सब लोगों को इग्नोर करते हुए इन्होंने भर्तियां की थीं। उसी तरह इस बार भी आऊटसोर्सिंग और SMC के माध्यम से हजारों भर्तियां करवाई जा रही हैं जिनमें रोस्टर नहीं लगाया गया है। फिर आप कहते हैं कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं। अगर आप हितैषी होते तो आप इसमें रोस्टर लागू करते और तब हम इस बात को मानते।

Speaker: Please wind up. आपको बोलते हुए बहुत समय हो चुका है।

07.03.2017/1845/SLS-DC-2

श्री विनोद कुमार : इसके अलावा नोटबंदी को लेकर भी यहां पर बड़ी-बड़ी बातें की गईं कि नोटबंदी के कारण कई लोगों की शादियां रुक गईं। भाई जगजीवन पाल जी के बेटे या बिटिया की शादी थी, वह तो हो गई। वह तो रुकी नहीं। ... (व्यवधान) ... लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यह बात सही है कि हो सकता है कि 500 और 1000 रुपये का नोट बदलने में आपको थोड़ी-सी दिक्कत पेश आई हो; इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन 60 सालों से बिगाड़ा हुआ देश; मोदी जी को उसको ठीक करने में कितनी दिक्कत आ रही होगी, इस बात को मैं कहना चाहूंगा। आप कहते हैं कि जनता बताएगी। जनता ने तो बता दिया है। पहला रिजल्ट चण्डीगढ़ से आया है। पूरे-के-पूरे चण्डीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहरा कर बता दिया है कि नोटबंदी का कोई असर होने वाला नहीं है। उसके अलावा आपने गुजरात में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में देख लिया... ... (व्यवधान) ...

Speaker : Please wind up. --- (Interruption) --- Now, not to be recorded. --- (Interruption) --- I must tell you this is not being recorded. This is not the way. --- (Interruption) ---. I have given you more than double the time you have consumed. अब बाकी लोग भी बोलेंगे या उन्हें न बोलने दें? एक घंटे में से आपको 12

मिनट बोलना था जबकि आपने 25-30 मिनट बोल दिया है। You should stop it now. यह टॉपिक तो इस तरह खत्म ही नहीं होगा। आप फिर कभी बोल लेना। Not now. Please sit down. This is not the way. I request every Member to adhere to the Rules otherwise there is no purpose of my sitting here. If you want to run the Assembly yourself then what is my purpose here. एक घंटे में 6 आदमी कैसे बोलेंगे? अगर 10 मिनट एक-एक व्यक्ति बोलेगा, तभी हो सकता है। You are speaking for 30 minutes and you are not the only person to speak. No, I will not allow you. --- (interruption) ---. Sh. Pawan Kajal please speak. --- (interruption) ---. This is wrong thing and I don't want to create wrong precedence here.

जारी...श्री गर्ग जी

07/03/2017/1850/RG/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी ने कहा कि गोहर अस्पताल सिविल अस्पताल बनाया, तो कम-से-कम ये धन्यवाद करते कि हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको सी.एच.सी. से 30 बिस्तर से 50 बिस्तरों का अस्पताल बनाया। वहां पहले भी दो डॉक्टर थे, अब भी दो डॉक्टर हैं।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: आप मेरी बात सुनिए, बैठो। दो डॉक्टर अब भी हैं और इसलिए यह कहना गलत है, कम-से-कम ये धन्यवाद तो करें। अगर नहीं हैं, तो डॉक्टर की मांग करें। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना और बड़े जोर से बोलने से तो ये कुछ नहीं कर सकते।

डॉ. राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने प्रदेश को अरबों रुपया दिया, तो क्या उसके लिए इन्होंने केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया?---(व्यवधान)-----ये हमें धमका रहे हैं।-----

(पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ कहने की कोशिश करने लगे।)

----(व्यवधान)-----

Speaker: Please keep order.

संसदीय कार्य मंत्री : ये कह रहे थे कि चण्डीगढ़ वगैरह इन्होंने जीत लिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश तो हम ही जीतेंगे। ----(व्यवधान)-----

डॉ. राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री हैं और सदन को प्रवोक कर रहे हैं।

श्री सुरेश भारद्वाज : संसदीय कार्य मंत्री तो सदन को चलाते हैं----(व्यवधान)-----

07/03/2017/1850/RG/AG/2

संसदीय कार्य मंत्री : आप लोगों को जितना समय मिल रहा है उतना समय कभी नहीं मिला होगा। यहां पर कुछ लोगों ने 20 से लेकर 50 मिनट तक बोला है। फिर भी ये विरोध कर रहे हैं।----(व्यवधान)-----

अध्यक्ष : श्री पवन काजल जी आप बोलिए।

श्री पवन काजल : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 1 मार्च, 2017 को जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण यहां पढ़ा, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महामहिम राज्यपाल ने जो इस बार अपना अभिभाषण पढ़ा और जो पिछला बजट सत्र था उसमें उन्होंने 'सरकार' बोला था, लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार ऐसा कहा कि 'मेरी सरकार'। उनको पता चला कि प्रदेश सरकार पिछले चार सालों से पूरे प्रदेश में एक समान विकास कर रही है। इसीलिए ऐसा उन्होंने कहा। आप कम्पेरीजन करिए कि पिछली बार

उन्होंने सिर्फ सरकार कहा था और इस बार मेरी सरकार कहा। तो सरकार ने काम किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करूंगा कि कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को भी साईड लाईन लगाया था और कांग्रेस पार्टी को भी साईड लाईन लगाया। जब मैं जीतकर यहां आया,

एम.एस. द्वारा जारी

07/03/2017/1855/MS/AG/1

श्री पवन काजल जारी-----

तो मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मेरी किस्मत अच्छी है इसलिए मैं जहां भी जाऊंगा, ठीक होगा। ऐसे व्यक्तित्व के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो प्रदेश का छः बार मुख्य मंत्री रहा हो और 54 वर्ष का जिनका राजनीति में अनुभव हो। यह जो विकास की गाथा इन चार वर्षों में लिखी है पूरा प्रदेश और प्रदेश की जनता उसको जानती है। - (व्यवधान)- जैसे जयराम जी ने कहा कि टिकट पक्का हो गया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कांगड़ा की जनता टिकट देती है न कि पार्टियां टिकट देती है। मैं आपके सामने खड़ा हूं। - (व्यवधान)- अगर ऐसा ही है तो इस बार फिर देख लेना। मुझे ऐसे व्यक्तित्व के साथ काम करने का मौका मिला जिनके बारे में पूरे प्रदेश का आमजन यह कह रहा है कि इस बार सातवीं बार माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी रिपीट करेंगे। यह ठीक है कि विपक्ष स्ट्रॉंग है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं इसलिए सभी भाषण देना जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अन्दर की रिपोर्ट आपको बताना चाहता हूं। - (व्यवधान)- मैं विपक्ष वालों से कहना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल आपके बीच से निकला हूं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने नारे आपके लगाए और काम मुख्य मंत्री जी ने किया। मेरा कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा विधान सभा क्षेत्र था जिसमें कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था। ये सभी यहां बातें कर रहे थे कि फलां कॉलेज में 45 बच्चे हैं, फलां कॉलेज में इतने बच्चे हैं। जो कॉलेज आपने चंगर क्षेत्र में दिया है आज की तारीख में उसमें 400 बच्चे पढ़

रहे हैं और 400 ही बच्चे तकीपुर कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिसमें 350 लड़कियों की संख्या है। वहां वे बच्चे पढ़ रहे हैं जो जमा दो उत्तीर्ण करके दो-तीन साल से घर पर थे। मुख्य मंत्री जी जो आपने कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में आई0टी0आई0 दी है उसमें आज 700 बच्चे पढ़ रहे हैं और 400 के लगभग उसमें लड़कियां पढ़ रही हैं। यह बात सही है कि काम हुए हैं। अध्यक्ष जी, कोसना विपक्ष का काम है। हम भी जब कभी विपक्ष में आएंगे तो हम भी आपको कोसेंगे। यह बनता है लेकिन इन चार वर्षों में जो प्रदेश में विकास हुआ है उसको आमजन जानता है। यह बात ठीक है कि पहले जब मैं जिला परिषद में था तो मैं बी0जे0पी0 से था परन्तु संस्कारी आदमी जहां भी रहे दिल से काम करते हैं। जब हम आपके नारे लगाते थे तो दिल से लगाते थे और अब हम माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के नारे लगाएंगे तो दिल से लगाएंगे। कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की मुझे याद है। आज से 20 वर्ष पहले मुझे भी पता है माननीय पूर्व मुख्य मंत्री धूमल साहब उस समय मुख्य मंत्री होते थे और चौधरी 07/03/2017/1855/MS/AG/2

विद्या सागर जी के हम वर्कर होते थे। हम वहां नारे लगाने जाते थे। उस समय चौधरी विद्या सागर जी मंत्री होते थे तो वे कहते थे कि आपने खूब नारे लगाने हैं और इस बार मैंने सब-इम्प्लायमेंट एक्सचेंज मुख्य मंत्री जी से लेना है। हमने बड़े गले फाड़े और पूरे नारे लगाए और उस समय के जो मंत्री विद्या सागर जी थे उन्होंने इनसे सब-इम्प्लायमेंट एक्सचेंज मांगा भी लेकिन पता नहीं बीच में कौन सी बात हो गई कि उन्होंने नहीं दिया। परन्तु मैंने मुख्य मंत्री जी आपसे एक ही बार मांगा और आज खुल गया है। मेरे चुनाव क्षेत्र के हजारों बच्चे धर्मशाला पढ़ने के लिए जाते थे। मेरे चुनाव क्षेत्र में 42 पंचायतें हैं। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके बच्चे आज बहुत खुश हैं कि माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी जो बोलते हैं उसको करते भी हैं। मैंने पिछले टूर में एक फरवरी को माननीय मुख्य मंत्री जी का जब धर्मशाला को राजधानी बनाने के लिए धन्यवाद किया तो वहां पर जो जन-समूह इकट्ठा हुआ, वह उस बात का गवाह था कि राजा वीरभद्र सिंह की सरकार ने इन चार वर्षों में क्या-क्या किया है। आपके सामने था। हमने 15-20 हजार कुर्सियां लगाई थीं।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

07.03.2017/1900/जेके/एस/1

श्री पवन काजल:-----जारी-----

एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। इलैक्शन ईयर है। आजकल जनता ढूँढें से भी नहीं मिलती है। अगर किसी ने काम किया हो तो जनता आती है। इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी आपने ऐसा काम किया है, एक तो जो आपने कॉलेज दिया और उसे चंगर क्षेत्र में खोल दिया। मेरे मांगने पर आपने मटौर में डिग्री कॉलेज दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी जब वह खुलेगा उसकी क्लासें हम अगले सेशन में लगाएंगे तो उसमें लगभग 800 के लगभग बच्चे होंगे। वहां पर इसकी जरूरत थी। हमारे बच्चे वहां से नगरोटा जाते थे और धर्मशाला जाते थे। माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी ने कॉलेज खोले तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? डिस्पेंसरियों को अपग्रेड कर रहे हैं तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूँ और अन्दर की रिपोर्ट है। जो एंटी इन्कम्बेंसी कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता पक्ष की होती है वह इस बार नहीं है। आगे क्या होगा भगवान जानें, लेकिन एंटी इन्कम्बेंसी अभी तक कांग्रेस पार्टी की नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी हमारे नरेन्द्र मोदी जी हैं, वे हमारे आदरणीय हैं। यहां विपक्ष वालों से मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता में आने का सारा भार आप नरेन्द्र भाई मोदी के ऊपर मत डालो। आपको पता है कि जब नरेन्द्र भाई मोदी जी बने थे तब दिल्ली के चुनाव हुए थे, क्या हुआ था? पहली बार 70 सीटों में से 67 आप पार्टी वाले ले गए। अभी 11 तारीख को क्या होने वाला है? अब 11 तारीख को जो परिणाम आने वाले हैं उसकी सभी को चिन्ता है। विपक्ष वालों को अपनी चिन्ता है और पक्ष वालों को अपनी चिन्ता है। लेकिन जो 11 तारीख को परिणाम आएंगे वे सबके सामने होंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में आपने 100 करोड़ के लगभग काम किए हैं। यहां पर विपक्ष वाले बोल रहे थे, भाई विनोद जी बोल रहे थे कि हमारी डी0पी0आर0 नहीं बनी। विनोद जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप विधायक हैं, आप जन-प्रतिनिधि हैं। आप जे0ई0, एस0डी0ओ0 और एक्सियन को बोल करके डि0पी0आर0 बनाओ तभी वे बनाएंगे। वहां पर माननीय

07.03.2017/1900/जेके/एस/2

मुख्य मंत्री जी जा करके नहीं बोलेंगे कि डीपीआर्ज बनाओ। आप जब बोलेंगे तब वे बनाएंगे क्योंकि आप जन-प्रतिनिधि हैं। आप उनको बोलो वे आपकी बात नहीं टालेंगे। आप वहां के एमएलए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में आपने आईपीएच डिविजन की घोषणा की है। हम शाहपुर में एक पानी का कनेक्शन लेने के लिए जाते थे उसके लिए हमें शाहपुर जाना पड़ता था। आपने कांगड़ा में दिया। एक आपने पीएचसी को सीएचसी की है। वह कांगड़ा से 22 किलोमीटर दूर टयारा में है, वहां पर दी है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। आप कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में कहीं पर भी जाओ और कोई भी जगह बता दो जहां पर सड़क में खड्डा है। जैसे कि यहां पर कह रहे थे कि शिमला से ले करके कांगड़ा तक जाओ, नादौन तक जाओ सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। जब हम नये-नये जीत करके आए थे तो कांगड़ा से साढ़े 5-6 घंटे लगते थे और आज वे सड़कें चकाचक हो गई हैं और शिमला से कांगड़ा के अब साढ़े चार घंटे लगते हैं।

अध्यक्ष: पवन काजल जी प्लीज एक मिनट के लिए बैठिए। अब सात बजे का समय हो गया है और बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। अब इस सभा का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया जाता है। पवन काजल जी अब आप बोलिए।

श्री एसएस द्वारा जारी-----

07.03.2017/1905/SS-AS/1

माननीय अध्यक्ष महोदय के बाद..

श्री पवन काजल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं बात कर रहा था कि कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में इन चार वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से 100 करोड़ मिले। उसमें मेरे क्षेत्र में चंगर क्षेत्र, प्लम क्षेत्र और शहर क्षेत्र कवर है। उसमें 24 घंटे पानी पीने देने वाली एक

डीपीआर 18 करोड़ 90 लाख रुपये की 2016 में बनाई और माननीय मुख्य मंत्री जी उसका विधिवत् शिलान्यास करके आए। इसी तरह चंगर क्षेत्र की 9 करोड़ की 2016 में डीपीआर बनी। आप उसका शिलान्यास करके आए। मतलब यह कि जब उसके लिए पैसे आए, तभी उसका शिलान्यास हुआ। इसी तरह से 18 करोड़ 42 लाख रुपये की स्कीम शहर को 24 घंटे पानी देने के लिए थी, वह आज 95 परसेंट कम्प्लीट हो गई है और बहुत जल्दी माननीय मुख्य मंत्री जी उसका उद्घाटन करने जायेंगे। उद्घाटन करने के साथ-साथ एक हारजलाड़ी और खल्टी को जोड़ने वाला पुल था, जिसमें कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की 22 पंचायतों की आपस में कनेक्टिविटी होती थी, चंगर और प्लम क्षेत्र में, उसकी डीपीआर 2001 में एमएलए प्रायोरिटी में पड़ी थी। 2006 में उसको वापिस लिया था। इतना महत्वपूर्ण पुल और उसको एमएलए प्रायोरिटी से वापिस लिया। मैंने 2015 में विधान सभा में प्रश्न भी लगाया था और आपने उठकर सैक्रेटरी साहब को कहा था कि आप इस पुल को देखिये। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने उसके लिए 3 करोड़ 62 लाख रुपये की स्वीकृति कर दी है, बहुत जल्दी आप उसका भी शिलान्यास करेंगे। इसी तरह आपने कांगड़ा जिला के लिए दूसरी राजधानी बना कर सौगात दी है। कुछ लोग कहते हैं कि राजधानी बनाने से क्या फायदा। यह ठीक है कि विपक्ष वाले तो ऐसा कहेंगे। आपने इतना बड़ा काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया। जिला कांगड़ा से आपको 10 सीटें मिली थीं, आपने पूरा मान-सम्मान किया कि जिला कांगड़ा की जनता ने हमें पूरा मान-सम्मान दिया तो मैं राजधानी वहां बना दूं। यह ठीक है कि राजधानी बनाकर हम जैसे एमएलए को फायदा न हो परन्तु जनता को तो फायदा होगा। जब सरकार वहां पर बैठेगी और किसी का पानी नहीं होगा तो वहां पर हर विभाग का अधिकारी

07.03.2017/1905/SS-AS/2

होने की वजह से विभाग सचेत रहेगा। तो वहां पर राजधानी बनाने का लोगों को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मैं कहता हूं कि सरकार तो वह चीज़ है, वैसे माननीय मुख्य मंत्री जी मुर्गी तो नहीं पालते लेकिन अगर सरकार की मुर्गी हो और वह उड़ जाए तो पूरा असला, मंत्री और पूरा प्रशासन उसको ढूँढता फिरेगा। इसलिए फिरेगा कि वह सरकार की मुर्गी है। इसका मतलब यह है कि आम जन के लिए जब सरकार वहां जाती है तो आम जन

को उसका फायदा होगा। हर जगह बात कर रहे हैं कि राजधानी का फायदा नहीं है। उनसे (जनता) पूछिये, जब माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गए थे, मैं कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं, मैं किसी की निन्दा नहीं करना चाहता। 2008-09 में एक स्कीम जिसका 50 लाख रुपया स्वीकृत हुआ, मैडम जी यहां पर बैठी हैं, बड़ी चिन्ता का विषय है, कई बातें तो मैं आपसे शेयर ही नहीं करता। उस स्कीम के लिए जो 40 लाख रुपया खर्चा हुआ उसके जितने टैंक बने हैं वे सब शीपेज़ कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि पीछे 15 दिन पहले ट्यूबवैल लगा दिये, वहां पर 11 एल0पी0एस0 पानी निकला, वह टैंक में पड़ा और सारा टैंक सीपेज़ हो गया।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी....

07.03.2017/1910/केएस/डीसी/1

श्री पवन काजल जारी----

उसके बाद मैं एक जग के लिए जा रहा था, पहाड़ी के आगे एक जग था वहां पर जो राइजिंग मेन डाली है तो मैं वैसे ही राइजिंग मेन में जो फ्लंजिज़ होती है उसके आठ सुराख होते हैं। गाड़ी से मेरी नज़र पड़ गई कि इसमें एक नटबोल्ट है जबकि उसमें आठ लगाने पड़ते हैं। अगर आठ को भी सही ढंग से नहीं जोड़ें तो भी लीक हो जाती है। मैंने सोचा एक में ही ऐसा होगा, आठ सुराख होते हैं तो मैंने सोचा कि एक में से किसी ने निकाल दिया होगा क्योंकि वह सड़क के किनारे हैं लेकिन पूरी की पूरी राइजिंग में आठ सुराख में एक-एक था, यह हाल था। मैं सच्चाई बता रहा हूं, किसी की निन्दा नहीं कर रहा हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी जो आपने चार, साढ़े चार वर्षों में विकास की गाथा लिखी है, यह पूरे प्रदेश की जनता जानती है और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जीत गया और आप जैसे व्यक्तित्व के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। पूरे प्रदेश में आज कर्मचारियों की प्रमोशन के लिए कोई बैन नहीं है, नौकरियों के लिए कोई बैन नहीं है। आपकी सरकार के समय में पांच वर्षों में प्रमोशन पर बैन होता था। कुल मिलाकर मुख्य मंत्री जी ने पिछले चार, साढ़े चार सालों में जो विकास की गाथा लिखी है, उसको लोग याद करेंगे और सातवीं बार भी आप मुख्य मंत्री बनेंगे। इतना कहते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

07.03.2017/1910/केएस/डीसी/2

अध्यक्ष: अब श्री सुरेश कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, 1 मार्च, 2017 को महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत किया, उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

वर्तमान सरकार का यह अन्तिम बजट सत्र है और इस अभिभाषण में पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार के क्या कार्यक्लाप रहे, उनको इस अभिभाषण में दर्शाया गया है। मुझसे पूर्व पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और मुख्य रूप से जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने बढ़ा-चढ़ाकर यहां पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया लेकिन अगर न केवल इस वर्ष अपितु पिछले चार वर्ष के कार्यकाल के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो विकास के मामले में हम पूरी तरह पिछड़े हुए हैं। सरकार ने चार वर्ष मात्र अपनी कुर्सी बचाने में ही निकाल दिए। जुगाड़ करके ही सरकार को चलाते रहे। जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं हो सके। कांग्रेस सरकार जब भी सत्ता में आई, चाहे इससे पूर्व वर्ष 2003-04 में या अभी 2012-13 में, हर बार प्रदेश की जनता को धोखा देकर आई। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में अनेक वायदे किए और 2012-13 का जो वायदा नौजवानों के साथ किया, चार वर्ष तक नौजवान जिसका इंतज़ार करते रहे, आज तक वह वायदा पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा बेरोज़गारी भत्ते का वायदा युवाओं से किया। युवा इन्तज़ार करते रहे लेकिन सवा चार साल बीतने के बाद भी वह वायदा पूरा नहीं हुआ। मुख्य मंत्री जी कहते रहे कि घोषणा पत्र में हमने ऐसा कोई वायदा ही नहीं किया। माननीय बाली जी, जो घोषणा पत्र बनाने वालों में थे, उन्होंने कहा कि हमने वायदा किया था। इसी प्रकार श्रीमती विप्लव ठाकुर और सुखु जी ने भी इस बात को दोहराया परन्तु बार-बार मुख्य मंत्री इस मुद्दे को नकारते ही रहे। अब समाचारपत्रों और मिडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

7.3.2017/1915/av/1

श्री सुरेश कुमार----- जारी

शायद सरकार इस ओर अंतिम वर्ष में ध्यान दे रही है। अब भी शायद कुछ युवाओं या कुछ विशेष वर्ग को लेकर ही विचार किया जा रहा है। इसके बारे में तो तभी पता चलेगा जब कुछ सामने आयेगा। सरकार का पिछले चार वर्ष का कार्यकाल केवलमात्र पट्टिका चिपकाने तक सीमित रहा। प्रदेश में आधे-अधूरे कार्यों के उद्घाटन किए गए और बिना बजट के शिलान्यास किए जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र की बात की जाए उसमें चाहे शिक्षा की बात हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो या सरकारी नौकरियों की बात हो आपकी सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। अभिभाषण में शिक्षा क्षेत्र के बारे में काफी बढ़ा-चढ़ाकर विवरण दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में वैसे तो पूरे प्रदेश में ही एक जैसी स्थिति है मगर मेरे चुनाव क्षेत्र में शिक्षा के संदर्भ में बहुत गम्भीर स्थिति बनी हुई है। मैं मानता हूँ कि अनेक स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया मगर उन स्कूलों में स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं की गई। नये अपग्रेड किए गए स्कूलों में पुराने चल रहे स्कूलों से स्टाफ नियुक्त किया जा रहा है जिससे पहले से चल रहे स्कूलों का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। आज स्थिति बहुत गम्भीर बनी हुई है। अनेकों स्कूल अपग्रेड किए गए हैं लेकिन क्योंकि वहां पर अध्यापक नहीं दिए गए इसलिए बच्चे उस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक प्राइमरी स्कूल रूग जो कि राजगढ़ ब्लॉक में पड़ता है। वहां पर कोई टीचर नहीं है इसलिए वहां पर जिन बच्चों ने ऐडमिशन ली हुई थी वे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, दयोठी-मजगांव में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुलह-जलोट है। वहां पर अध्यापक नहीं है और बच्चों को मजबूर होकर गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल गलानाघाट में जाना पड़ रहा है। इसी प्रकार से अनेक ऐसे स्कूल हैं जहां पर अध्यापक न होने के कारण बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है। अभिभाषण में बताया है कि सरकार ने एक साल में 17 कालेज खोले हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सराहां में भी हमारी सरकार के समय में एक डिग्री कालेज खुला था। मगर इस सरकार ने सत्ता में आते ही उसको बंद कर दिया था जबकि उस समय बच्चों के सैकेंड सैमेस्टर के इग्ज़ाम चल रहे थे। वहां के लिए पद सृजित किए गए थे और बजट का प्रावधान भी किया गया था। उसके लिए 32 बीघा जमीन का

चयन किया गया था उसके बावजूद उस कालेज को इसलिए बंद किया गया था कि वह कालेज तीन कमरों में चल रहा है। इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस कालेज को दोबारा खोला है। चार साल का कार्यकाल बीत गया मगर

7.3.2017/1915/av/2

वह कालेज आज भी तीन कमरों में ही चल रहा है। उस कालेज के लिए जो भूमि दी गई थी वहां क्योंकि उस समय आदरणीय मुख्य मंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने शिलान्यास कर दिया था इसलिए उस भूमि पर कालेज का निर्माण न करके दूसरी जगह एक ढांक के ऊपर कालेज का निर्माण किया जा रहा है। वहां एक पहाड़ी को काटकर उस कालेज की बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। उस भूमि को समतल करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इससे पहले जो भूमि उस कालेज के लिए दी गई थी वह बहुत ही बेहतरीन भूमि थी। वहां केवलमात्र कुछ झाड़ियां थीं। उनको दरख्त बताकर तथा उसके लिए फॉरैस्ट क्लीयरेंस का बहाना लगाकर के उस जगह से कालेज शिफ्ट कर दिया गया। चार वर्ष का समय बीत जाने के बाद आज भी उस कालेज का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि प्रदेश के 98.98 प्रतिशत स्कूलों में पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे अनेकों स्कूल हैं जहां पीने का पानी अभी भी नहीं है। एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलोटी है वहां पर पीने का पानी अभी भी नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल करैंजी है तथा एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोटला-बंझोला है। मैं अभी उन स्कूलों की स्थिति बता रहा हूं जहां पर मैं पिछले एक महीने के दौरान गया था।

श्री वर्मा द्वारा जारी

07/03/2017/1920/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

श्री सुरेश कुमार - - - जारी।

ऐसे अनेक स्कूल हैं, जहां अभी भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं हैं एक गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल मनोटी है, वहां पर पीने का पानी नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल करैंजी हैं और मिडल स्कूल कोटला मंजौला है, उसमें भी ये सुविधायें नहीं है। ऐसे अनेकों स्कूल हैं, जहां अभी भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं हैं। यहां पर खुले में शौचमुक्त की बात की जाती है, जिसमें हिमाचल प्रदेश को प्राइज भी मिला है। जब स्कूलों में पीने का पानी ही नहीं होगा, तो कैसे विद्यार्थी शौच जायेंगे। ऐसी स्थिति आज मेरे विधान सभा क्षेत्र की है। इसके अलावा अब गर्मी का सीज़न आ रहा है, पिछले साल भी मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत समस्या थी। मैं पानी की कमी को लेकर बार-बार माननीय आई0पी0एच0 मंत्री से मिला था। मैंने 100 हैंडपम्प एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में डाले थे और जब एम0एल0ए0 प्रायोरिटी की मीटिंग हुई थी, तो माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में भी लाया था। उसकी डी0पी0आर0 भी बन गई थी, लेकिन बार-बार उस डी0पी0आर0 के ऊपर आब्जेक्शन्ज़ लगाये जाते हैं। मुझे नहीं मालूम किस वज़ह से इस डी0पी0आर0 को अप्रूव नहीं किया जा रहा है। सरकार को लगता है कि यदि ये हैंडपम्प लग जायेंगे तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जायेगा, लेकिन मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध रहेगा कि इन हैंडपम्पों को शीघ्रातिशीघ्र लगा दिया जाये। ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिल सके। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी सदन में नहीं है। मैंने यह मुद्दा एम0एल0ए0 प्रायोरिटी की मीटिंग में भी माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष रखा था। मेरे यहां सिविल हॉस्पिटल राजगढ़ है, जोकि 30 पंचायतों को कवर करता है। वहां पर डॉक्टरों के 8 पद सृजित हैं, जिसमें 6 पद खाली चल रहे हैं, केवल मात्र 2 पद भरे हुए हैं। ये पद लम्बे समय से खाली चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों उस क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंप लगा था। इस प्रकार के कैंप अवश्य लग रहे हैं लेकिन वहां डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। कैंप केवल मात्र इसलिए लगाये जा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान इससे भटक सके। कैंपों में डॉक्टर मात्र एक दिन के लिए आते हैं और एक दिन में किस प्रकार से लोगों का उपचार होगा? इसी प्रकार से सिविल हॉस्पिटल सरांह है, जहां पर 4 पोस्टें हैं, लेकिन वहां पर केवल मात्र 2 डॉक्टर हैं और 2 पोस्टें खाली चल रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11

07/03/2017/1920/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

पी०एच०सी० हैं और 11 में से 8 पी०एच०सी० ऐसी हैं, जिनमें डॉक्टर नहीं हैं। करोड़ों रुपये खर्च करके पी०एच०सी० की बिल्डिंग बनी है, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं है, केवल मात्र एक क्लास-IV आज के समय में वहां पर है। यही हाल पी०एच०सी० कोटि-बदोग, डिम्बर, धाम्ला, नैनाटिक्कर, ठाकरद्वारा, नारग, मानगढ़ और अनेक पी०एच०सी० हैं, जिनमें डॉक्टर नहीं हैं। इनमें चाहे सरांह का हॉस्पिटल है, चाहे राजगढ़ का हॉस्पिटल है, केवल मात्र रैफरल हॉस्पिटल बनकर रह गये हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल मेरे चुनाव क्षेत्र में हैं। पिछले चार सालों में जितनी भी भर्तियां हुई है, पी०टी०ए०/एस०एम०सी०/आशा वर्कर/पुलिस की भर्ती या आउट सोर्स के माध्यम से आज अनेकों पद भरे जा रहे हैं। इन पदों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। चोर-दरवाजे से भर्तियां की जा रही है और इसमें रोस्टर का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मैंने इसी सदन में इससे पूर्व 2-3 बार विशेष रूप से पी०टी०ए० और एस०एम०सी० की भर्तियों के संबंध के बारे में प्रश्न किए थे। उसमें पूछा था कि क्या इनमें रोस्टर का ध्यान रखा जा रहा है। उसमें सरकार की ओर से एक ही जवाब आया, क्योंकि ये भर्तियां एस०एम०सी० कर रही है, इसलिए इनमें रोस्टर नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम एस०एम०सी० और आउटसोर्स के द्वारा जितनी भर्तियां की गई है, उनके लिए हम नीति बना रहे हैं। जब उसमें रोस्टर नहीं लगाया जायेगा तो जो एस०सी०, एस०टी० या ओ०बी०सी० वर्ग हैं, उनको किस प्रकार से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें रोस्टर नहीं लगा है और भर्तियां चोर-दरवाजे से हो रही है।

श्रीमती एन०एस० - - द्वारा जारी ।

07/03/2017/1925/ns/ag/1

श्री सुरेश कुमार --- जारी

मेरा सरकार के ऊपर सीधा-सीधा आरोप है कि सरकार चोर दरवाजे से भर्तियां कर रही है। इसमें रोस्टर का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। एस.सी. और एस.टी. के अधिकारों का हनन हो रहा है। आज के समय में मेरा क्षेत्र हरियाणा के साथ का क्षेत्र है। यहां पर शराब माफिया पूरी तरह हावी है। हरियाणा से शराब मेरे क्षेत्र में चोर दरवाजे से आ रही है और

अनेक घरों को बर्बाद कर रही है। मेरे क्षेत्र में आज राशन की दुकानों में भी शराब मिल रही है। प्रतिदिन अखबारों की सुर्खियां बनती हैं कि आज 10 पेटियां, 20 पेटियां पकड़ी गई हैं। मेरे क्षेत्र में अवैध धंधा सरकारी सरंक्षण में हो रहा है। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में सैंकड़ों पेड़ देवदार के काटे जा रहे हैं और वन माफिया सरकारी सरंक्षण में कार्य कर रहा है। आज ऐसी दयनीय स्थिति मेरे क्षेत्र की है। इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में बिजली को ले करके भी समस्या है।

वन मंत्री : जो आपने वन माफिया की बात कही है आप उसको मुझे लिख करके दें ताकि मैं इन्कवायरी करवा सकूं।

श्री सुरेश कुमार : मैं आपको लिख करके दूंगा। (घण्टी) मेरे क्षेत्र में एक ओर समस्या बिजली के बारे में है।

Speaker: Please wind up now.

श्री सुरेश कुमार : आज भी मेरे क्षेत्र में बिजली की तारें हरे पेड़ों के ऊपर लटकी हुई हैं। वहां के पूर्व विधायक आज भी कहते हैं कि पच्छाद एक आदर्श विधान सभा क्षेत्र बन गया है लेकिन ऐसी स्थिति आज भी मेरे क्षेत्र की है जहां बिजली की तारे हरे पेड़ों पर लटकी हैं। मैं पिछले दिनों अपने गांवों में गया था तब वहां घरों में 200 वाट का बल्ब जल रहा था लेकिन रोशनी इतनी थी जैसे पुराने समय में एक दीया जलता था। हम उसकी रोशनी में एक-दूसरे की शकल को नहीं देख सकते

07/03/2017/1925/ns/ag/2

थे। ऐसी स्थिति आज भी पच्छाद विधान सभा क्षेत्र की है। मैंने पिछले दिनों विधान सभा सत्र में प्रश्न भी किया था उसमें यही जवाब मिला था कि कुछ क्षेत्रों में वोल्टेज की समस्या है। इसके लिए मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया था। उस समय इन्होंने कहा था

कि वहां 33 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि जल्दी-से-जल्दी इस पर ध्यान दिया जाए। इसके अतिरिक्त ओर भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। आज सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है। केंद्र सरकार ने 61 नेशनल हाईवे सैंक्शन किए हैं उसमें से 5 नेशनल हाईवे मेरे क्षेत्र के हैं। लेकिन सरकार उनकी डी0पी0आर0 नहीं बना रही है। कई सड़कें ऐसी हैं जिनमें भूमि अधिग्रहण भी नहीं होना है। वहां पर पहले सड़क बनी हुई है और सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया हुआ है लेकिन फिर भी उसकी डी0पी0आर0 नहीं बनाई जा रही है। मेरे क्षेत्र के तीन पुल ऐसे हैं जिनको मैंने विधायक प्राथमिकता में डाला है, उसमें भी कोई अधिग्रहण नहीं होना है लेकिन उसकी भी डी0पी0आर0 नहीं बनाई जा रही है। इससे पहले माननीय सदस्य श्री किरनेश जंग जी कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र में अथाह विकास हो रहा है। शायद जानबूझ कर ऐसा कह रहे हों। हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। हमारी डी0पी0आर0 नहीं बन रही हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बस कीजिए। आपने बहुत समय ले लिया अभी ओर भी सदस्य बोलने वाले हैं। You wind up in a minute. This is wrong.

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जो अभिभाषण यहां पर माननीय महामहिम राज्यपाल से पढ़ाया गया उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका मैं समर्थन कर सकूँ। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

07/03/2017/1925/ns/ag/3

अध्यक्ष : श्री रोहित ठाकुर जी अब अपनी बात रखेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव(श्री रोहित ठाकुर) : अध्यक्ष महोदय, 1 मार्च 2017 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर अभिभाषण दिया है, मैं उसके संबंध में बोलने के लिए इस मान्य सदन में खड़ा हुआ हूँ। इस विषय में हमारे कांग्रेस पार्टी के चीफ विहिप, श्री

जगजीवन पाल जी तथा श्री संजय रतन जी का धन्यवाद प्रस्ताव भी आया है। इस अभिभाषण के माध्यम से जो माननीय मुख्य मंत्री वीरभद्र जी और कांग्रेस पार्टी की जो वचनबद्धता थी, पूरे हिमाचल प्रदेश में संतुलित विकास की, हर क्षेत्र में विकास के जो नये आयाम पिछले चार सालों में स्थापित हुए हैं यह ब्लूप्रिंट उसका आयना है। इन चार वर्षों में

श्री आर०के०एस० -----जारी।

07/03/2017/1930/RKS/AS/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री रोहित ठाकुर)..... जारी

चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें हर क्षेत्र में अभुतपूर्व विकास हुआ है। मैं कृषि और बागवानी की बात करना चाहता हूं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश गांव में बसता है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा यह प्राथमिकता रही है, चाहे हमारी केन्द्र की सरकार हो या प्रदेश सरकार हमारा हमेशा यही प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता मिले। हमारे किसान-बागवान को प्राथमिकता मिले। इन चार वर्षों के दौरान जहां हर क्षेत्र में नए-से-नए विकास के आयाम स्थापित हुए उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो हिमाचल प्रदेश के लिए 1134 करोड़ रुपये का होर्टिकल्चर प्रोजैक्ट किसानों और बागवानों के लिए आया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और बागवानी मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस प्रोजैक्ट के माध्यम से आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को फायदा होगा। बागवानी का अर्थ सिर्फ सेब ही नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष का 'फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया' के रूप से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉ० यशवंत सिंह परमार जी की जो एक वचनबद्धता थी उसे माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में नई गति मिली है। जहां जुब्बल-कोटखाई विधान सभा क्षेत्र की बात आती है, हमारे क्षेत्र का संबंध माननीय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी और पूर्व में दिवंगत नेता ठाकुर राम लाल जी के साथ रहा है। हमारे क्षेत्र में बागवानी के लिए एक अलग आयाम

स्थापित हुआ है। ऊपरी शिमला में ठियोग-खड़ापत्थर-हाटकोटी रोड़ जो मुख्य जीवन रेखा थी, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारी सरकार के लिए थी। वर्ष 2007 में सत्ता परिवर्तन हुआ। जहां हमेशा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जुब्बल-कोटखाई के साथ जुड़ा रहा। दो-दो मुख्य मंत्री हमारे क्षेत्र से रहे लेकिन 2007 में एक नया प्रयोग हुआ। जनता-जनार्दन का फैसला सिर-माथे होता है। नई उम्मीदें हमको उस समय की सरकार से थी। लेकिन मैं समझता हूं उन पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल की तुलना अगर हम वर्तमान के 4 सालों से करें तो मात्र घोषणाएं या 'जुमला' जो एक नया शब्द भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने हमें दिया है, वही था। किसी भी क्षेत्र में हमारा क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाया। जो हमारी ठियोग-खड़ापत्थर-

07/03/2017/1930/RKS/AS/2

हाटकोटी रोड़ जीवन रेखा थी, जिसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2007 में वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 1135 करोड़ का प्रोजैक्ट, पूरे हिमाचल प्रदेश की भिन्न-भिन्न सड़कों की अपग्रेडेशन के लिए स्वीकृत करवाया था। वर्ष 2007 में नई सरकार आई। पहला शिलान्यास हमारे विधान सभा क्षेत्र में या मैं कहूं ऊपरी शिमला में पहला फाउंडेशन स्टोन धूमल साहब जी ने रखा था। उस वक्त हमारे क्षेत्र से पूर्व बागवानी मंत्री जी हमारे नुमाईदे थे। ठियोग-खड़ापत्थर-हाटकोटी रोड़ का हुल्ली में पहला फाउंडेशन स्टोन रखा गया। पांच वर्ष में जुब्बल-कोटखाई, रोहडू और चौपाल की जनता की बहुत दुर्दशा हुई। मैं समझता हूं कि जो कुप्रबंधन भाजपा सरकार के समय में रहा है उससे श्री सुरेश भारद्वाज जी भी कुछ हद तक सहमत होंगे। 2010 में जो क्षति किसानों और बागवानों को हुई वह भी एक बहुत बड़ा कुठाराघात किसानों -बागवानों के साथ हुआ है। मेरे साथी मोहन लाल ब्राक्टा जी कह रहे थे 25 दिसम्बर 2012 को हमारी सरकार ने शपथ ली। माननीय मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्यों ने शपथ ली। उसके उपरान्त 30 दिसम्बर, 2012 को प्रथम बैठक माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें एक पूरा प्रारूप तैयार किया गया कि आने वाले समय में हम किस तरह से ठियोग-खड़ापत्थर-हाटकोटी रोड़ को

फिर से पटरी में लाएंगे। यह हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और पी.डब्ल्यू.डी के अधिकारी/कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से एक समय में इसको

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

07.03.2017/1935/SLS-AG-1

श्री रोहित ठाकुर (माननीय मुख्य संसदीय सचिव) ...जारी

एक शापित प्रोजेक्ट कहा जा रहा था। आज कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है कि 80 प्रतिशत के लगभग यह कार्य पूर्ण हो चुका है। जहां तक भाजपा की बात है, पूरे पांच वर्ष में मात्र 18 प्रतिशत कार्य हुआ था। जब शिलान्यास हुआ तो उसके बाद ये कुंभकर्णी नींद में सो गए और 4 वर्षों में उस दौरान नए-से-नए शगूफे छोड़े।

धूमल साहब ने भी यहां पर बागवानी के बारे में बातें रखीं। विशेषकर इन्होंने CA Stores की बात की। आज हिमाचल प्रदेश में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित है, उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। इसकी पूरा श्रेय हमारे मुख्य मंत्रियों डॉ० परमार, ठाकुर राम लाल जी और वीरभद्र सिंह जी को जाता है। इस कार्यकाल के दौरान APEDA के माध्यम से 7 CA Stores हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुए थे। खेद का विषय है, आज बात हो रही है कि केंद्र से बहुत पैसा मिल रहा है लेकिन इसके विपरीत एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हिमाचल प्रदेश और विशेषकर यहां के किसानों और बागवानों के साथ हो रहा है। जो 7 में से 3 CA Stores थे, जिनमें से एक खड़ा पत्थर में, एक मेरे छोटे भाई हंस राज जी जो कि नटखट हैं, इनके विधान सभा क्षेत्र चुराह में और तीसरा पतली कूहल, जिला कुल्लू में स्थापित होना था। इनके MOU साईन हो गए थे। हिमाचल प्रदेश सरकार का शेयर अमाउंट HPMC के द्वारा APEDA को जमा होना था, वह जमा हो चुका था। लेकिन खेद का विषय है कि उसके बावजूद भी APEDA के इतिहास में यह प्रथम बार हुआ है कि यह

तीनों CA Stores, जिनसे किसानों और बागवानों की बहुत मदद होनी थी, वह कैंसिल कर दिए गए हैं।

मैं इसी तरह का दूसरा उदाहरण इस माननीय सदन में देना चाह रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश, जो सदैव अपनी शांति के लिए जाना जाता है, विकास के लिए जाना जाता है, खेद का विषय है कि जब मोदी जी सरकार के द्वारा बागवानी क्षेत्र में पैसा मिल रहा था, तो इस वित्तीय वर्ष में केवल 25 करोड़ रुपया ही हिमाचल प्रदेश

07.03.2017/1935/SLS-AG-2

को मिला है। अगर हम साथ लगते राज्य जम्मू-काश्मीर की बात करें, आज वहां बीजेपी और पीडीपी का अलाईस है। मुझे याद है कि चुनाव से पहले पीडीपी को भारतीय जनता पार्टी के नेता एक फिरकापरस्त पार्टी कहा करते थे, लेकिन अब वहां एक अनहोली अलाईस है। यह 500 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट आपने जम्मू-काश्मीर को दिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, जहां से चारों सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीतकर आए, यहां के लिए मात्र 25 करोड़ रुपया दिया गया।

आज पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम हार्टिकल्चर क्षेत्र में आया है। यह अपने आपमें एक बहुत बड़ी बात है। जहां में बागवानी क्षेत्र की बात कर रहा था, कुछ शिगूफ़े और जुमले, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल हुए, उनकी भी कुछ बातें रखना चाहूंगा।

हमारी उपलब्धि है कि हमने हार्टिकल्चर क्षेत्र में 1134 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए लाया। इसमें लगभग 2,23,000 फ़ौरेन इंपोर्टिड प्लांटिंग मैटेरियल, जिसमें सेव ही नहीं बल्कि पीयर, पिचिज, प्लम्ज और दूसरी वैराइटीज के प्लांट्स शामिल हैं, वह किसानों और बागवानों को उपलब्ध होंगे। अब एक नया शिगूफ़ा निकाल दिया कि इसमें वायरस है। मैं समझता हूँ कि इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे 5 वर्ष के आंकड़े देख रहा था, इनके पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान

मात्र 10,000 के आसपास फौरेन इंपोर्टिड प्लांटिंग मैटरियल प्रदेश में आया। आज जब संख्या लाखों में पहुंच चुकी है, इन्होंने कहीं-न-कहीं मीन-मेख निकालने की बात की है कि इसमें वायरस आ गया है। मैं समझता हूं कि वह वायरस इस बात का नहीं है। वह क्षेत्रवाद और जातिवाद का है। मैं समझता हूं कि यह सब राजनीतिक बातें हैं जिनको हिमाचल की जनता-जनार्धन बखूबी जानती है।

मैं कृषि और बागवानी क्षेत्र की बात कर रहा था। मुझे याद है कि अप्रैल 2000 में यहां पर एक बहुत बड़ा MOU हिमाचल प्रदेश विधान सभा के परिसर में ही साईन हुआ था कि हिमाचल के सेव से वाईन बनाई जाएगी। उस वक्त जय राम ठाकुर जी, रवि जी, हमारे सभी वरिष्ठ विधायक और मंत्रियों की उपस्थिति में MOU Sign हुआ

07.03.2017/1935/SLS-AG-3

था जिसके तहत मण्डी जिले के नगवांई में एक वाइनरी स्थापित होनी थी। इसी तरह से जुब्बल-कोटखाई विधान सभा क्षेत्र के प्रगतिनगर में भी एक वाइनरी स्थापित होनी थी। वाइनरी तो दूर की बात, इन्होंने एक और शिगूफ़ा निकाल दिया। जहां से आज से कोई 15-16 साल पहले आप सेव से वाईन निकालने की बात कर रहे थे, शैंपेन निकालने की बात कर रहे थे, आज उसके विपरीत आप कहते हैं कि हमने सेव से केंचुआ खाद बनानी है। इस तरह से मैं समझता हूं कि जो इनके दोहरे मापदंड हैं वह जनता के सामने हैं। यही कारण रहा कि जो 2012 में हिमाचल प्रदेश की जनता-जनार्धन ने कांग्रेस पार्टी को जिताया और

जारी... श्री गर्ग जी

07/03/2017/1940/RG/AS/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रोहित ठाकुर)-----क्रमागत

माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने फिर से प्रदेश का नेतृत्व संभाला।

अध्यक्ष महोदय, यदि आज हम सड़कों की बात करें, तो मैं पीछे एक समाचार-पत्र 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में पढ़ रहा था कि एक इन्डिपेन्डेंट एजेन्सी ने भी जो हमारी लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं, वैल मेन्टेन्ड हैं और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। अभी हमारे भाई श्री विजय अग्निहोत्री जी कह रहे थे और हमीरपुर की सड़कों की वे बात कर रहे थे। अभी हाल में ही दो महीने हुए हैं कि हम धर्मशाला से वापस आए हैं, तो वहां की सड़कें कैसी हैं वह सब हम जानते हैं। इसी तरह यदि आज हम अपने पूरे क्षेत्र की बात करें, तो हर क्षेत्र में सड़कों के मामले में एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है। मैंने चोगले की वाइनरी की बात की।

अध्यक्ष महोदय, यहां से डॉ. राजीव बिन्दल उठकर चले गए, मुझे याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी, तो उस समय पतंजलि के साथ पीटर हॉफ में एक एम.ओ.यू. साईन हुआ था कि हिमाचल का जितना भी सेब का कन्स्ट्रेंट जूस है जो एच.पी.एम.सी. का है, बाबा रामदेव जी का बयान मुझे याद है जो दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला में प्रकाशित हुआ था, यह वर्ष 2010 की बात है, उन्होंने कहा था कि जितना भी हिमाचल का सेब है वह सारा पतंजलि पीठ ले जाएगी। पतंजलि पीठ सौ बीघा जमीन साधूपुल में तो ले चुकी थी, लेकिन जहां तक ऐपल जूस कन्सन्ट्रेट लेने की बात थी, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान एक लीटर भी पतंजलि पीठ ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हमारे ऐपल जूस कन्सन्ट्रेट को रिजेक्ट किया है। तो इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों-बागवानों की बात कर रहा हूं। डॉ. राजन सुशांत जी की नीति भी सबके संज्ञान में है जिसके तहत लगभग कोई 1,67,000 लोगों ने अपने शपथ-पत्र दिए कि हमारे पास ऐनक्रोचमेंट्स हैं और आज हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि विशेषकर जो हमारे लघु और सीमांत किसान हैं उनके हितों की रक्षा हो। इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ठाकुर कौल सिंह जी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था उन्होंने भी अपनी सारी बातें कही हैं और हमारा स्ट्रेस है कि जो हमारे लघु और सीमांत किसान हैं, उनके हितों की रक्षा हो।

07/03/2017/1940/RG/AS/2

मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय न्यायालय भी इस बारे में मानवीय दृष्टिकोण रखेगा। नहीं तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें वर्ष 2002 में शपथ-पत्र दाखिल किए और वर्ष 2011 में जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उस समय सभी किसान-बागवान बैठे हुए थे कि अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है जो हमने 1,67,000 शपथ-पत्र दिए थे, अब ये सारी-की-सारी जमीनें हमारे नाम हो जाएंगी। लेकिन उसके विपरीत एफ.आई.आर. हुई हैं वह भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2011 में हुईं और जो इजैक्टमेंट हुई, वह भाजपा कार्यकाल के दौरान हुई। जहां किसानों-बागवानों को जमीनें मिलनी थीं उनको एक तरह से मुजरिम बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के समय में ऐसा दोहरा मापदण्ड रहा है और बहुत ही कुठाराघात एवं विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी का रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यदि इन चार वर्षों के दौरान मैं जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र की बात करूं, तो जैसे कर्नल साहब ने कहा और मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई 19 सड़कों की बात कही। मेरे विधान सभा क्षेत्र से दो-दो मुख्य मंत्री रहे हैं, ठाकुर रामलाल जी और श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री रहे हैं। सड़कों के मामले में सर्वाधिक घनत्व हमारे क्षेत्र में है जिसकी सीमा टियोग से लगती हुई जॉन्सारबाबर जो उत्तराखण्ड के साथ हमारा विधान सभा क्षेत्र आता है वहां तक लगती है। सड़कें हमारी जीवन रेखा है और हमारे जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। इस कारण से हमारी ये प्राथमिकता रही हैं। वर्ष 2007 में भारतीय जनता पार्टी के समय में जिला शिमला में एक नया सूत्रपात हुआ कि हमारे यहां से जुब्बल-कोटखाई विधान सभा चुनाव क्षेत्र से एक विधायक बने, लोगों को उनसे बहुत सी आशाएं थीं और हमारा विधान सभा का क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के समय में एक तरह का मॉडल हुआ और हमारे साथी कह रहे हैं कि सड़कों के मामले में जुब्बल-कोटखाई अग्रणी है। जहां तक मुझे इस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना है कि विधान सभा क्षेत्र जुब्बल-कोटखाई में सड़कों के घनत्व में सर्वाधिक है। अगर हम बात करें और भाजपा सरकार की तुलना करें, तो पूरे पांच वर्ष के दौरान सर्वाधिक बदला-बदली राजनीति आधार पर जो तबादले हुए वे जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र से हुए जिनकी संख्या कई सौ है। जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में सैंकड़ों प्रधानों को निलम्बित किया गया और लोगों ने अगले चुनावों का इन्तजार किया। वर्ष 2012 के चुनाव में जो परिणाम आया

07/03/2017/1940/RG/AS/3

उसका यही कारण था कि झूठ से बातें नहीं बनतीं। मुझे याद है कि धूमल साहब हमारे चुनाव क्षेत्र में आए थे, एक स्टेटमेंट आ गई कि हिमाचल प्रदेश में जुबल-कोटखाई विधान सभा चुनाव क्षेत्र के लिए 1600 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। मैं उस साल का वार्षिक प्लान पढ़ रहा था, तो उस साल का वार्षिक प्लान मात्र 3200 करोड़ रुपये का था। तो इस तरह ये झूठी बातें रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान रही हैं।

एम.एस. द्वारा जारी

07/03/2017/1945/MS/AG/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री रोहित ठाकुर).....

यहां पर चुनाव की बातें आई कि कांग्रेस यहां हारी है, वहां हारी है। हमारे साथियों को यह भी याद रखना चाहिए कि वर्ष 1984 में भारतीय जनता पार्टी के आपके दो सांसद हुआ करते थे और यहां तक कि वाजपेयी जी जिनका हम बहुत आदर करते हैं जिनको हम स्टेट्समैन मानते हैं और आडवाणी जी, ये दोनों ही हमारे नेता हार चुके थे। हम सब तो कांग्रेस के डी0एन0ए0 के हैं और मजबूत दृढ़ निश्चयी है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जरूर निश्चित रूप से मजबूती के साथ उभरेगी। सभी 11 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। मैं यहां पर जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण हुआ, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। इन चार वर्षों में हर तरह से मैं समझता हूं कि विकास के नये आयाम स्थापित हुए हैं। यहां पर जो वायरस की बात आई है जिसके बारे में धूमल जी, बिन्दल जी और अन्य विपक्ष के साथियों ने भी कहा है। मैं समझता हूं कि यह मात्र दुष्प्रचार है। जैसाकि मैंने पहले भी कहा कि अपने कार्यकाल में उपलब्धि दिखाने को कुछ नहीं है तो इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। लाखों की संख्या में जो पेड़ आए हैं, मैं समझता हूं कि दत्तनगर में उनमें पांच पेड़ों में वायरस था। उसकी अभी पूरी जांच हो रही है जिसके बारे में डिटेल में माननीय बागवानी मंत्री और सैक्रेटरी हॉर्टिकल्चर ने अपना सारा मामला

दिया है। अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर से, क्योंकि काफी समय हो गया है, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और जो यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण प्रथम मार्च को हुआ है, उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

07/03/2017/1945/MS/AG/2

अध्यक्ष: अब चर्चा में श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो इस सदन में अभिभाषण दिया है और उसमें जो धन्यवाद प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है, उसमें हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जहां तक प्रदेश का सनेरियो है यहां हमारे जो नेता प्रतिपक्ष और अन्य जो वरिष्ठ वक्ता हैं उन्होंने काफी विस्तृत रूप से इस पर चर्चा की है और आंकड़ों के साथ सारे तथ्य भी पेश किए हैं। माननीय धूमल जी ने तो कांग्रेस सरकार के मैनीफेस्टो को जिसको सरकार कहती है कि यह हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, उसके हरेक बिन्दु को टच करते हुए कम्पेरीजन किया है कि कौन-कौन से वायदे पूरे हुए हैं। इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता सिर्फ नालागढ़ चुनाव क्षेत्र तक ही केन्द्रित रहूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है।

मैं सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की बात करूंगा। लोक निर्माण विभाग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वैसे सड़कों का पूरे प्रदेश में बुरा हाल है लेकिन जो नालागढ़ की सड़कें हैं तो जैसे ही हम पंजाब या हरियाणा से नालागढ़ में एंटर करते हैं हमें एकदम से पता चल जाता है कि हम कहां आ गए हैं। हमें बड़ी शर्म आती है। हमारे बहुत से सम्माननीय सदस्य वहां से होकर आते हैं तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है। चाहे नेशनल हाइवेज की बात हो। जो सो कौल्ड नेशनल हाइवे हमारा नालागढ़ से लेकर स्वारघाट तक

है इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए और बहुत ज्यादा धरने/प्रदर्शन किए तथा केन्द्र से पैसे की स्वीकृति करवाई परन्तु जो प्रदेश सरकार है यह ठेकेदारों से काम करवाने में पूरी तरह से असफल रही है। बहुत प्रयासों के बाद एक जो ठेकेदार था उसके काम को रिसीन्ड करके दुबारा ठेका हुआ है। अभी भी वह काम थोड़ा धीरे चला हुआ है। जो एक सड़क का काम पूरा हुआ है वह भी संतोषजनक नहीं है। मुझे लगता है कि बरसात आने पर वह सड़क भी टूट जाएगी। इससे तो लगता है कि लोक निर्माण विभाग की कार्य-प्रणाली एटलिस्ट नालागढ़ में पूरे संदेह के घेरे में है। लगता है कि विभाग का ठेकेदारों पर कोई कन्ट्रोल नहीं है और ठेकेदार अपनी मनमर्जी करते हैं और

07/03/2017/1945/MS/AG/3

उसकी वजह से बहुत बुरा हाल है। चाहे दूसरी बातें ले लें। जैसे मेरे साथी विधायक जो दून से हैं वे अभी सदन में बैठे नहीं हैं। उन्होंने कोट किया कि इस बार 30-40 किलोमीटर रि-कारपेटिंग बड़ी-भारी हो गई है। हर जगह हुई है परन्तु उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वह लगभग 2-3 महीने में ही टूट जाती है। तो नालागढ़ में यह स्थिति है और शायद पूरे प्रदेश में भी यही स्थिति है। एनुअल रि-सर्फेसिंग कोट के लिए जो बिचुमैन डालते हैं उसकी क्वालिटी बिल्कुल पुअर है। उसकी स्पेसिफिकेशन की भी बात कई बार चली थी कि इसकी स्पेसिफिकेशन इम्प्रूव की जाए। उसमें कम-से-कम 32 एम0एम0 थिकनेस होनी चाहिए क्योंकि इसमें अनइवननेस होती है। इसमें न तो राइडिंग क्वालिटी आती है और न ही इसकी लाइफ होती है। उसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो दो नेशनल हाइवे हमारे चुनाव क्षेत्र के लिए डिक्लेयर हुए हैं उनके भी कोई टैण्डर कॉल नहीं हुए हैं। टैण्डर में कन्सल्टेंट नहीं आ रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसा वातावरण नहीं है कि बाहर से अच्छे-अच्छे कन्सल्टेंट आएँ। जो प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली है उसकी वजह से कन्सल्टेंट यहां नहीं आते हैं। इसके लिए भी प्रदेश सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। यहां पर कन्सल्टेंट इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पेमेंट समय पर नहीं होनी है और भी इसके अलावा कई दिक्कतें हैं। तो यह लोक निर्माण विभाग का हाल है। जितने भी हमारी सड़कें बन रही हैं उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है। हमें बड़ी शर्म आती है जब हम हिमाचल में प्रवेश करते हैं। यह लोक निर्माण विभाग का हाल है जो माननीय मुख्य मंत्री जी के पास विभाग है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

07.03.2017/1950/जेके/एस/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर:-----जारी-----

दूसरे, हम आई0पी0एच0 को ले लें तो उसका हाल उससे भी खराब है। अगर हम वाटर सप्लाई की स्कीम लें तो एक साल के लिए नार्मली आऊट सोर्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ठेकेदार एक साल किसी तरीके से निकाल देता है, जैसे कि जुगाड़ लगा करके एक साल निकाल देता है। वह स्कीम जब डिपार्टमेंट को हेंडओवर होती है तो वह टूटी-फूटी होती है। मेरा एक सुझाव है कि इसमें आऊट सोर्सिंग तो करनी पड़ेगी लेकिन यहां पर स्टाफ कम और स्कीम में ज्यादा है। इसलिए आऊट सोर्सिंग कम से कम 5 साल के लिए होनी चाहिए ताकि जो ठेकेदार है उसकी एक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उसको यह स्कीम पांच साल चलानी है और वह उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर ढंग से करेगा। इसका मिनिमम पीरियड पांच साल होना चाहिए जो आऊट सोर्स करना है, मेंटेन करना है। एक साल के लिए तो इन स्कीमों का भट्टा बैठ जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या हमारी यह है कि इरिगेशन का मास्टर प्लान पूरी स्टेट का नहीं बना है। नालागढ़ में भी नहीं बना है। वह बन भी नहीं पाया क्योंकि जो आई0पी0एच0 डिपार्टमेंट है उसके पास तीन-तीन काम हैं। एक तो वाटर सप्लाई व सीवरेज है, एक इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है और एक रूरल वाटर सप्लाई है। जो हमारे ऑफिसर्ज हैं इसलिए मैं उनको दोष नहीं देना चाहता हूं क्योंकि उनका मेनली फोकस वाटर सप्लाई पर ही रहता है। वाटर सप्लाई पर फोकस रहता है तो इरिगेशन इग्नोर होती है, फ्लड इग्नोर होता है और जिस डिविजन में अर्बन वॉटर सप्लाई पड़ती है तो उसको अर्बन में ज्यादा कान्स्ट्रेंट करते हैं, इससे रूरल वाटर सप्लाई इग्नोर होती है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि जो नई-नई घोषणाएं होती हैं, बड़े-बड़े दफ्तर खुलते हैं और जैसे कि केपिटल बनाने की बात चली हुई है तो इनके बजाए जो आई0पी0एच0 विभाग है, क्योंकि इससे लोगों की हैल्थ जुड़ी हुई है, जो इरिगेशन फ्लड

सप्लाई है इससे इकोनोमी जुड़ी हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। मेरा यह कहना है और सुझाव है कि इसको ट्राईफरकेट करें। अर्बन वाटर सप्लाई और सीवरेज अलग हो

07.03.2017/1950/जेके/एस/2

डिपार्टमेंट, जैसे कि दूसरी स्टेटों में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड जितनी भी स्टेट हैं तो उसमें अर्बन वाटर सप्लाई व सीवरेज अलग होता है। उसमें रूरल वाटर सप्लाई अलग होती है और इरिगेशन एण्ड फ्लड कंट्रोल अलग होता है। इसमें कोई कमेटी बिठा करके इसमें एक्सपर्ट व्यूज़ ले करके और दूसरे राज्यों में भी डिस्कस किया जा सकता है, इसलिए इसकी तरफ ध्यान दें ताकि अभी नहीं तो कम से कम आने वाले समय में इसके ऊपर कुछ किया जा सके। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हमारे यहां पर है, जो 62 ट्यूबवैल हमने नॉबार्ड में सेंक्शन करवाए हैं, दुख की बात यह है कि उनमें 30-31 तो ट्यूबवैल लगने हैं परन्तु जो बाद में उसकी राईजिंग मेन, पम्पिंग मशीन या डिस्ट्रीब्यूशन की डी0पी0आर0 बनानी है उसमें स्टाफ नहीं है और उसके लिए आऊट सोर्स करना पड़ रहा है। वे 30 ट्यूबवैल अभी लगे नहीं है। ये जो सारी समस्याएं हैं इसमें हमारा जो फील्ड स्टाफ है वह ओवर लोडिड है। इसलिए इसकी ट्राईफरकेशन यानि तीन विभागों में बांटना आई0पी0एच0 का बहुत ही जरूरी है। मैं इस सुझाव की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा एक और बड़ी बात है जो आई0पी0एच0 में पार्टिकुलरली इरिगेशन वाटर सप्लाई की जो स्कीमें सेंक्शन हुई है, नार्मली स्कीमें नॉबार्ड से होती है उसमें श्री ईयर कम्प्लिशन शड्यूल होता है। तीन साल में फंडिंग करनी होती है। वह स्कीम तीन साल में कम्पलीट करनी होती है। हमारे नालागढ़ डिविजन में जो बजट दिया गया है वह जो बजट है थोड़ा-बहुत तो मैं मान सकता हूं कि माइनरटी बेस पर हो सकता है। मान लो जितने एज़ पर शड्यूल नॉबार्ड के हैं उसमें 80 या 75 परसेंट दे रहे हैं but there is a significance difference. It is around 40 per cent of the sanctioned schedule. इससे क्या हो रहा है एक तो स्कीमें लेट बनेंगी। लेट बनने से उसमें कॉस्ट भी बढ़ेगी और

जो सुविधा लोगों को तीन साल में देनी है हो सकता है वह पांच साल में दें। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इसकी तरफ भी मैंने कई बार प्रश्न के माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी बात कही है। इसमें भी जो फंडिंग का गैप है वह बहुत ज्यादा है। इसकी तरफ भी ध्यान देने की बात है। इसके अलावा आईपीएच और पीडब्ल्यूडी

07.03.2017/1950/जेके/एस/3

दोनों ही एट पार हैं। अब अगर बीबीएन की हम बात लें। बीबीएन में इसालिए बोलना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी विधायक, श्री राम कुमार जी ने कहा है कि बीबीएन में बहुत ज्यादा काम हो गया है। बड़ी डिवैल्पमेंट हो गई है। हम मंत्री जी के आभारी हैं, अग्निहोत्री जी के आभारी हैं, शायद वे भी यहां से चले गए हैं और मुख्य मंत्री जी के आभारी हैं। मैं इसकी पहले की बैक ग्राउंड बताना चाहता हूँ कि बीबीएन की डिवैल्पमेंट कहां से शुरू हुई थी। ये जो वर्ष 2003 में इंडस्ट्रियल पैकेज हिमाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेट केटेगरी में जो पैकेज मिला था उस समय वर्ष 2002 में स्टेट में माननीय प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में हमारी बीजेपी की सरकार थी। इन्होंने केन्द्र में मुद्दा उठाया। केन्द्र में बीजेपी की एनडीए की सरकार थी। तब तीन स्टेटों के साथ हिमाचल प्रदेश को भी जो इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था उसकी वजह से डिवैल्पमेंट हुई थी लेकिन उसके बाद वर्ष 2003 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी तो उनको तो करना यह चाहिए था कि उसका मास्टर प्लान बनाते कि कहां पर इंडस्ट्री लगनी है और कहां पर ग्रीन एरिया होना है और कहां पर रैजिडेंशियल होना है। उन्होंने ये न करते हुए अंधाधुंध तरीके से बिल्कुल

श्री एसएस द्वारा जारी-----

07.03.2017/1955/SS-AG/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर क्रमागत:

अनट्रेंड वे से इंडस्ट्री लगवा दी, मुझे लगता है कि उसमें वैस्टिड इंटरस्ट इंवोल्व होंगे। इंडस्ट्री लगा दी और उसका बहुत बुरा हाल कर दिया। एरिया का बहुत बुरा हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बिल्कुल कमी है। उसके बाद अब मास्टर प्लान एप्रूव किया है। अब जब सब कुछ वहां डिवैल्पमेंट हो चुकी और अपने ढंग से हुई है तो मुझे लगता है कि जो मास्टर प्लान रिसेंटली चार-छः महीने पहले एप्रूव किया है उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाती है। इसलिए बी०बी०एन०डी०ए० का जितना विकास हुआ भी है वह सारा बी०जे०पी० की वजह से है। अब क्या होता है? अब हो यह रहा है कि बी०बी०एन०डी०ए० का जो पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू स्टेट को बी०बी०एन० एरिया से जा रहा है। यह प्वाइंट डिबेट वाला नहीं है। मुझे लगता है कि सभी सम्माननीय सदस्य इसके बारे में जानते हैं। एक तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहां से जाता है। दूसरे बी०बी०एन० में नक्शे पास करने के लिए एन्फॉर्मली बहुत हाई फीस है। तो वह भी बी०बी०एन० अकाउंट में जाती है। तो वहां पर जो थोड़ी बहुत डिवैल्पमेंट हो रही है वह नालागढ़ और दून के लोगों के लिए खैरात की बात नहीं है। यह उनका हक है। मैं तो कहता हूं कि डिवैल्पमेंट हक से भी कम हो रही है। नालागढ़ का जो क्षेत्र है उसमें दून के मुकाबले पंचायतें और पापुलेशन ज्यादा आती है तो इस करके नालागढ़ में डिवैल्पमेंट कम हो रही है और जो डिवैल्पमेंट होती भी है उसमें भी कांग्रेस के इम्पोर्टिड लोग कोशिश करते हैं कि यह उनका अपना पैसा है जैसे कि वे बाहर से लेकर आए हैं। यह नालागढ़ और नालागढ़ के लोगों का पैसा है, विधायक होने के नाते मैं वहां रिप्रेजेंट करता हूं तो हमारा पैसा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में जो डिवैल्पमेंट हो रही है वह कम हो रही है। वहां डिवैल्पमेंट और होनी चाहिए। साथ में मैं दो-तीन प्वाइंटस कहना चाहता हूं कि बी०बी०एन०डी०ए० के काम में क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उसके मैं दो-तीन एग्जाम्पल देता हूं। ये जो टी०सी०पी० के नॉर्म्ज़ हैं वे सरकारी विभाग पर भी बराबर

रूप से इम्प्लीमेंट होने चाहिए। प्राइवेट लोगों को तो इतना परेशान किया जाता है कि वे एक मीटर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह ठीक है

07.03.2017/1955/SS-AG/2

कि नॉर्म्ज इम्प्लीमेंट होने चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ परन्तु दो-तीन बिल्डिंगें इन्होंने ऐसी बना दी हैं जो नॉर्म्ज के हिसाब से नहीं हैं। एक तो नालागढ़ का जो एस0डी0एम0 कम्प्लैक्स है उसके साथ जो पार्किंग बनाई है उसमें कोई नॉर्म्ज फोलो नहीं किये। तो जिस टाइम उसका उद्घाटन करने माननीय मंत्री जी गए, तो जो जजिज़ थे उन्होंने मंत्री जी को उद्घाटन नहीं करने दिया। कितने शर्म की बात है। वे कहते हैं कि बिल्डिंग गलत बनी है। एक तो इससे हमारे मिनी सचिवालय का व्यू डिस्टर्ब हो रहा है और दूसरा निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं है। तो उसका उद्घाटन रोका गया जबकि नेम प्लेट लगी थी और माननीय मंत्री जी उद्घाटन नहीं कर पाए। एक यह बात है। उसके बाद रेन शैल्टर की बड़ी भारी बात की गई कि बड़े पहाड़ी स्टाईल से 25-25 रेन शैल्टर बनाए जाएं। उसमें भी टी0सी0पी0 के नॉर्म्ज फोलो नहीं किये जा रहे हैं। वे मैक्सिमम सड़क में आ रहे हैं। मेरे ख्याल में जब वाइडनिंग होगी तो वे तोड़ने पड़ेंगे। बी0बी0एन0 का जो खर्चा हो रहा है वह सिर्फ खर्च करने के लिए हो रहा है और मुझे लगता है कि उसका लॉग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक नालागढ़ से रामशहर को सड़क जाती है। एक रामशहर चौक है, वहां जो डिवैल्पमेंट का काम किया गया, उसमें तकनीकी खामी है। उसमें काफी खर्चा किया गया लेकिन उसके हिसाब से रिजल्टस सामने नहीं आए। उसमें टैक्निकैल्टी नहीं देखी गई है। ऐसे और भी बड़े काम हैं। रातोंरात ऐसे काम किये जाते हैं जिसमें क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाता। बी0बी0एन0 के बारे में मेरा यही कहना है कि इसमें प्लान्ड वे में काम हो। जिसका लॉग लास्टिंग इम्पैक्ट हो, ऐसे काम करने चाहिए। ऐसे ही इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बात है। नालागढ़ की पॉजिशन यह है कि पूरे बी0बी0एन0 से उद्योगपति भाग रहे हैं। उद्योगपति दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं। हर इंडस्ट्री में उनकी कॉमर्शियल प्रोडक्शन कम होती जा रही है क्योंकि उसमें एक तो सरकार की तरफ से

इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को और भी रियायतें देनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री प्रदेश में टिकी रहे। नयी इंडस्ट्री आए और पुरानी टिकी रहे। हिमाचल न तो इंडस्ट्री को बेनिफिट दे रहा है और लोकल लोगों को भी फायदा नहीं है। वहां यह हो रहा है कि 70 परसेंट

07.03.2017/1955/SS-AG/3

हिमाचलीज़ को रोज़गार देने की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसके बावजूद जो सैलेरी पैकेज है मुझे लगता है कि जो लड़के बी0टैक हैं उनको पांच से सात हजार रुपया दिया जाता है जोकि बड़े शर्म की बात है। इसकी तरफ भी हमने कई बार सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की परन्तु हुआ कुछ नहीं। भेदभाव की बात जैसे पूरे स्टेट में हो रहा है वैसे नालागढ़ के साथ भी हो रहा है। उस समय स्टेट गवर्नमेंट ने तीन इंडस्ट्रियल एरियाज़ घोषित किये थे। एक कांगड़ा जिला में कंदरोडी था, ऊना में पंडोगा और नालागढ़ में दबोटा था। दो इंडस्ट्रियल एरिया डिवैल्प हो गए, मुझे लगता है कि शायद वे फाइनल स्टेज पर होंगे लेकिन अभी तक दबोटा सरकार ने लटकाया हुआ है। इसके बारे में मैंने बार-बार प्रश्न भी किया है। इससे ही इनका भेदभाव प्रूव होता है। जहां इनका वश चलता है वहां भेदभाव किया जाता है। अब अगर हम अन्य दूसरे सैक्टर्ज़ लें, जैसे राम कुमार जी के रामशहर में कॉलेज दे दिया गया है तो कॉलेज जो दिया गया है मुझे लगता है कि वह कॉलेज

जारी श्रीमती के0एस0

07.03.2017/2000/केएस/एएस/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर जारी---

तीन साल पहले देना चाहिए था। वह पिछली जो धूमल सरकार थी, उसमें लगभग वह अनाऊंस हो चुका था और बदकिस्मती से हमारी सरकार नहीं आ पाई तो इन्होंने उसको करने के लिए साढ़े तीन साल लगा दिए। मेरा अब यही निवेदन है कि वहां पूरा स्टाफ

भेजकर उसको अप्रैल से फंक्शनल कर दें। सी.एच.सी. जो राम शहर में दी है वह भी साढ़े तीन साल लेट दी है उसकी नोटिफिकेशन हुए छः महीने हो गए हैं परन्तु अभी तक एक भी डॉक्टर एक्स्ट्रा नहीं आया है। जितनी भी नोटिफिकेशनज़ होती हैं, उसका फिज़िकल इम्पैक्ट जो फील्ड में आना चाहिए, न तो वह आ रहा है और न लोगों को सुविधा मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र पंजाब के साथ लगता है। वहां ड्रग माफिया बड़ा सक्रिय है। इसके लिए सरकार के प्रयास न के बराबर हैं। सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए नहीं कर रही है। पूरे ही राज्य में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति खराब है। बी.बी.एन. एरिया में चाहे माइनर रेप की बात हो, चेन स्नैचिंग की बात हो, चाहे चारी की घटनाएं हों। यहां तक कि गांव के अन्दर भी चारियां हो रही हैं। सड़क के साथ लोग असुरक्षित महसूस करते हैं परन्तु गांव के बीच में जाकर रात को ताले तोड़े जाते हैं। जब यह पोजीशन है तो मुझे लगता है कि इस तरफ ध्यान न देकर सरकार के टारगेट कुछ और है। पोज़िटिविटी कम है और नैगेटिविटी ज्यादा है। किसी को कैसे तंग करना है और कैसे किसी इंडिविजुल को बैनिफिट देना है, मुझे लगता है उसी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट। अभी कुछ लोग और भी बोलने वाले हैं तो इस माननीय सदन का समय 45 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। पिछले तीन साल की तरह इस ओर सरकार का ध्यान शून्य है। कोई विज़न सरकार का नहीं है। सरकार केवल केन्द्र

07.03.2017/2000/केएस/एस/2

सरकार के पैसों पर निर्भर है। केन्द्र सरकार से आप पैसा भी लेते रहते हैं और साथ में उसको गालियां भी देते रहते हैं।

(सभापति महोदया, श्रीमती आशा कुमारी पदासीन हुई)

इसको तो कृत्घन कहते हैं। जिस थाली में खाते हैं, उसी को धिक्कारते भी हैं। इसी तरह से आप एच.आर.टी.सी. की बात ले लीजिए। एच.आर.टी.सी. के रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन की बात हो तो बार-बार लोग हमारे पास आते हैं कि हमें चार-चार महीनों से पेंशन नहीं मिलती है। पहले तो जब रिटायरमेंट होती है तो दो-तीन साल उनको पेंशन लगने में लग जाते हैं उसके बाद तीन-तीन, चार-चार महीने उनको पेंशन नहीं मिलती है तो उनमें रिज़ेन्टमेंट है। बसें जो आती है लेकिन क्योंकि कंडक्टर और ड्राइवर नहीं हैं तो बसें ऐसी ही खड़ी रहती है और जो भर्ती हो रही है, उसमें तो आदरणीय नरेन्द्र ठाकुर जी ने जो आंकड़े पेश किए, बहुत ही शर्मिन्दा करने वाले हैं। एच.आर.टी.सी. में ही नहीं, दूसरे विभागों में भी ऐसा ही है। चाहे शिक्षा विभाग में भर्तियां है, एस.एम.सी. व पी.टी.ए. के माध्यम से हैं, जो स्टूडेंट्स डिज़र्व करते हैं, उनसे दिन प्रतिदिन अन्याय होता जा रहा है। इसके अलावा पर्यटन के बारे में भी नालागढ़ में कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई देती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे स्टेट में अराजकता का माहौल है। जो सरकार के आदेश हैं, चाहे केबिनेट के डिसिज़न हैं चाहे किसी भी मंत्री के आदेश हैं, मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है या फील्ड स्टाफ है वह उनको सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनको पता है कि ऊपर से भी काम ढीला ही हो रहा है। मुझे याद है कि जब धूमल जी की पिछली सरकार थी तो एक बार पोलीथिन बैन की थी उसका इतना ज्यादा असर हुआ था कि पोलीथिन लेने से लोग डरते थे लेकिन अब तो जुगाड़ वाली बात है। जुगाड़ से सरकार चल रही है। जुगाड़ जनता के लिए करना चाहिए लेकिन यहां अपने लिए जुगाड़ किया जा रहा है। अपने आप को बचाने के लिए जुगाड़ किया जा रहा है। जुगाड़ करना चाहिए और यदि कोई गलत काम भी करना है तो आम जनता के लिए जनहित में होना

07.03.2017/2000/केएस/एस/3

चाहिए, वह भी माफ है परन्तु यहां अपने आपको और लम्बे समय तक चलाने के लिए जुगाड़बाज़ी चल रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बोलने से कोई ज्यादा लाभ भी नहीं होने वाला है क्योंकि यहां संवेदनशीलता तो दिखाई ही नहीं दे रही है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

7.3.2017/2005/av/ए०एस/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर ----- क्रमागत

अभी बजट आने वाला है और मेरा ख्याल है उसमें भी कुछ नहीं होगा। हमने एक और मुद्दा उठाया था। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो पंचायतें रोड बनाती हैं वह अलग-अलग फंड से बनाती हैं। वे रोड्स बरसात के मौसम में टूट जाती हैं। उसके रखरखाव की हर बार प्रोब्लम आती है। अब चलो उसके लिए एम०एल०ए० फंड अलाउ कर दिया है मगर वह भी सीमित ही होता है। हमारा सबका यह मानना था कि जो रोड पंचायत बनाती है उसके रखरखाव के लिए लम्पसम ग्रांट ब्लॉक स्तर पर दे दें ताकि जैसे ही बरसात खत्म होती है उन रोड्स को एकदम ठीक करवाया जा सके। अभी तो रिक्वेस्ट करने वाली बात है चाहे एक्सियन से रिक्वेस्ट कर लो या डी०सी० से रिक्वेस्ट कर लो। ये पंचायती रोड्स जो हैं

they are very significant in numbers क्योंकि एम०एल०ए० फंड, डी०सी० फंड, एम०पी० फंड; इनके माध्यम से हम रोड कनेक्टिविटी तो कर रहे हैं मगर वह रोड बहुत कम चलती है। खर्च करने के बाद रोड बंद रहे तो इसका लोगों में एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए इसके रखरखाव के लिए ब्लॉक स्तर पर कुछ लम्पसम बजट का प्रावधान कर

दें तो ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि आपने यह प्वाइंट इस बार भी बजट में नहीं डाला होगा और आपका बजट तो अब प्रिंट हो रहा होगा। अगर अभी नहीं किया गया है तो इसके बारे में बाद में ऐड कर लें क्योंकि यह बहुत जरूरी है। (---घंटी---) दूसरे में यह कहना चाह रहा हूं कि स्कूलों में क्वालिटी ऐजुकेशन बिल्कुल मिसिंग है। हम स्कूलों की संख्या बढ़ा रहे हैं मगर इनफ्रास्ट्रक्चर, अध्यापक और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। अगर किसी स्कूल में दो बच्चे होंगे तो मुझे लगता है कि उनका आपस में कोई कम्पीटिशन नहीं होगा। अगर वार्तालाप या कम्पीटिशन नहीं होगा तो उन बच्चों की पर्सनेलिटी भी कैसे डेवलप होगी। पहले सरकार कहती थी कि हम एक स्टुडेंट पर भी स्कूल खोलेंगे मगर अब कह रही है कि कम-से-कम दस बच्चों पर एक स्कूल होगा। मुझे लगता है कि इस तरह के निर्णय अपनी ईगो को सैटिसफाई करने वाले लिए जा रहे हैं। इनसे किसी

7.3.2017/2005/av/ए0एस/2

प्रकार का लाभ तो मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार 'रूसा' की बात है। रूसा के पीछे भी एक हठ लेकर अड़े हुए हैं। हम किसी भी कालेज में जाएं तो देखेंगे कि सारे स्टुडेंट परेशान है। मुझे लगता है कि लगभग 90 प्रतिशत बच्चों को इस रूसा के कारण परेशानी आ रही है। इन बच्चों को दूसरी स्टेटों में जाना है तो ऐडमिशन में प्रोब्लम आती है। इसी प्रकार नौकरियों में भी मुश्किल आ रही है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते की बात की जा रही है। यह भत्ता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए यह डिबेटेबल है। मैं नहीं कहता कि यह देना चाहिए। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने उस समय यह अनाउंस क्यों किया? प्रदेश के यूथ ने आपको उस बेस पर वोट डाली है। हम नहीं कहते आप दे दो या न दो; यह आपकी मर्जी है। यह आपकी पार्टी का फैसला है। लेकिन यह एक सेंसिटिव इशू था और इस पर उस समय डिबेट होनी चाहिए थी in view of the financial health of the State तब कुछ नहीं देखा गया केवल वोटों के लिए अनाउंस कर दिया। हमारे काजल भाई के पास पता नहीं कौन सी एजेंसी की रिपोर्ट है? मुझे लगता है कि इनके पास कोई इन्टरनल

रिपोर्ट आ गई है that there is no anti-incumbency this time. लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हर पांच साल बाद सरकार बदलती है। मैं राजनीति में नहीं था मगर मुझे यह पता है कि यहां पर हर बार सरकार बदलती है। जनता को सैटिसफाई करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि चाहे विकास का मामला हो या गवर्नेंस का मामला हो यह सरकार दोनों मोर्चों पर पूरी तरह से विफल रही है। इस बार रिपीट करने की बात तो छोड़ो मगर यह सरकार 20-25 साल तक सत्ता में आने वाली नहीं है। इसलिए मुझे काजल जी की रिपोर्ट बिल्कुल गलत लग रही है। शायद इन्होंने मुख्य मंत्री महोदय को खुश करने के चक्र में यह सब कहा है। आप सिर्फ मुख्य मंत्री जी को खुश कर रहे हैं पार्टी को नहीं कर रहे हैं। काजल जी, आपने काम तो शायद बहुत करवाये हैं मगर लोग काम भी भूल जाते हैं। मुख्य बात आचरण की होती है। हमारे हिसाब से इंटरनल रिपोर्ट यह है कि प्रदेश की आम जनता बहुत दुखी है।

श्री टी0एस0वी0 द्वारा जारी...

07/03/2017/2010/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर - - - जारी।

इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सरकार में संवेदनशीलता जीरो है। इसमें न तो कोई एक्शन होता है, इसलिए ज्यादा बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि आपने करना कुछ नहीं है। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने बताया कि प्रदेश में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है। उसके बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको जो पढ़कर सुनाया जाता है, आप उस पर भी विश्वास नहीं करते हैं और उसको भी झूठ मानते हैं। चलो 6-8 महीने और मान लीजिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आपने 5 साल में लोगों को परेशान करके अपनी इग्गो सेटिसफाई कर दी है, अब आप काफी समय तक इंतजार करेंगे। यह जो अभिभाषण है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, जिसका समर्थन किया जाये। ये तो सरकार की औपचारिकता होती है, इसको महामहिम राज्यपाल को भी पढ़ना होता है और उन्होंने इसको पढ़ा। लेकिन इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूँ। धन्यवाद, जयहिन्द।

07/03/2017/2010/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

श्री विक्रम सिंह जरयाल: सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय, ने जो अभिभाषण पढ़ा उसमें कुछ था नहीं, इसलिए मैं वह बुक भी साथ लाया हूँ। सत्तापक्ष के सीनियर लोग बैठें हैं, मैं आपकी सरहाना करूंगा कि आपने 4 सालों में बहुत आयाम स्थापित किए हैं। यदि मैं गलत बोलूंगा तो आप मुझे रोक लेना।

सारी कायनात लगी है, एक शक्स को झुकाने के लिए,
खुदा भी सोचता होगा, जाने किस मिट्टी का इस्तेमाल किया है,
मैंने इसको बनाने के लिए।

सारी कायनात लगी है, एक शक्स को झुकाने के लिए,
खुदा भी सोचता होगा, जाने किस मिट्टी का इस्तेमाल किया है,
मैंने मोदी जी को बनाने के लिए।

मैं गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि माननीय सदस्य श्री जगजीवनपाल ने भी अपना भाषण सेंटर से शुरू किया था और उसका समर्थन श्री संजय रतन ने किया था। आज चायन मोटी के खिलाफ, आई0एस0आई0 मोदी के खिलाफ, पाकिस्तान मोदी के खिलाफ, कांग्रेस मोदी के खिलाफ, जे0डी0यू0 मोदी के खिलाफ, सपा मोदी के खिलाफ, सी0बी0आई0 मोदी के खिलाफ, आप पार्टी मोदी के खिलाफ है।

जो व्यक्ति अमेरिका को झूका सकता है, झूठे पाक में हड़कंप मचा सकता है, चीन जैसे गद्दार देशों को लाईन पर ला सकता है, तो भाईयों इस भारत को विश्व गुरु भी बना सकता है।

ये बात पक्की है, देश की ज़रूरत है मोदी,

कहते हैं राहुल गांधी मैं मुफ्त में भोजना दूंगा।
कहते हैं, केजरीवाल मैं मुफ्त में पानी, बिजली दूंगा।

07/03/2017/2010/टी0सी0वी0/डी0सी0/3

मोदी जी कहते हैं, मैं न तो मुफ्त में भोजन दूंगा, न मुफ्त में पानी, न मुफ्त में बिजली दूंगा, मैं देश में युवाओं को रोज़गार दूंगा। मैं देश को इतना सक्षम बना दूंगा कि हर व्यक्ति स्वाभिमान से कह सके कि मैं भारतवर्ष का निवासी हूँ।

पत्थर फलदार वृक्ष को ही मारते हैं, जिस वृक्ष में फल नहीं लगते उसको कोई पत्थर नहीं मारता है।

श्रीमती एन0एस0 ...द्वारा जारी।

07/03/2017/2015/ns/dc/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल -----जारी।

मैं अपनी कलम से मोदी न लिखूँ तो क्या लिखूँ ,

अब आप ही बताओं इस जलती कलम से मैं क्या लिखूँ।।

कोयले की खान की बात करूँ तो क्या आदरणीय मनमोहन सिंह जी बेईमान लिखूँ ,

पप्पू पर जोक न लिखूँ तो क्या मुल्ला मुलायम लिखूँ,

सी0बी0आई बदनाम लिखूँ या जस्टिस गांगुली महान लिखूँ।।

शीला की विदाई लिखूँ या लालू की रिहाई लिखूँ,

आप की रासलीला लिखूं या कांग्रेस का प्यार लिखूं॥
भ्रष्ट पिछली सरकार लिखूं या प्रशासन बेकार लिखूं ,
मंहगाई की मार लिखूं या गरीबों का बुरा हाल लिखूं॥
भूखा इन्सान लिखूं या कविता बेईमान लिखूं,
आत्महत्या करता किसान लिखूं या शीश कटे जवान लिखूं॥
विधवा का विलाप लिखूं या अबला की चितकार लिखूं,
दिगी की टचमार लिखूं या करप्शन विकराल लिखूं॥
देश हत्या शोषण की बात लिखूं या टूटे हुए मन्दिरों का हाल लिखूं,
गद्दारों के हाथों में तलवार लिखूं या हो रहा भारत का गाना लिखूं॥
लोकतन्त्र का बंटधार लिखूं, या पी0एम0 की कुर्सी पर मोदी का नाम लिखूं,
अब आप ही बताओ इस जलती कलम से मैं क्या लिखूं॥

07/03/2017/2015/ns/dc/2

सही बात है आप ने बहुत आयाम स्थापित किये हैं, उसका मैं यहां पर वर्णन करना चाहता हूं। सही बात है मोदी जी ने काम कुछ नहीं किया। देखो काँग्रेस ने साठ सालों में कितना काम किया था। 1987 बोफोर्स घोटाला-960 करोड़, 1992 शेयर घोटाला 5000 करोड़, 1994 में चीनी घोटाला 650 करोड़, 1995 प्रोफेशनल अलॉटमेंट घोटाला 5000 करोड़ । यह सुनते रहिये आपके समय का है अगर इसमें कुछ गलत है तो बता देना। 1995 कस्टम टैक्स घोटाला 4300 करोड़, 1995 में जिन्दार हवाला घोटाला 400 करोड़, 1995 मेघालय वन घोटाला 300 करोड़, 1994 उरवरक आयात घोटाला 1300 करोड़, चारा घोटाला 950 करोड़, यूरिया घोटाला 133 करोड़, बिहार मूवी घोटाला 400 करोड़, म्यूचल फण्ड घोटाला 1200 करोड़, सुखराम टेक्निकल घोटाला 1500 करोड़, एस0एन0सी0 पॉवर प्रोजैक्ट

घोटाला 374 करोड़ और उदयपुर कृषि उपज़ घोटाला 210 करोड़, बोफर्स घोटाला 8000 करोड़, डालमिया शेयर घोटाला 495 करोड़, केतन पारिक प्रतिभूति घोटाला 1000 करोड़, यू.टी.आई. घोटाला 32 करोड़, कोलकता स्टॉक एजेंट्स घोटाला, 120 करोड़, स्टॉम्प घोटाला 20,000 करोड़, आईपीओ ओओ होल्लिंग घोटाला 17 करोड़, सोर्टिंग पनडुब्बी घोटाला 18978 करोड़, तारकोल घोटाला 175 करोड़, सैन्य शासन घोटाला 5000 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र घोटाला, 95 करोड़, हसनाली हवाला घोटाला 39120 करोड़, उड़ीसा खाद्यान्न घोटाला 7000 करोड़, चावल निर्यात घोटाला, 2500 करोड़, झारखंड खाद्यान्न घोटाला 4000 करोड़, आदर्श घर-घर घोटाला 900 करोड़, खाद्यान्न घोटाला 35000 करोड़, स्पैक्ट्रम घोटाला 2 लाख करोड़, कॉमन वैल्यु घोटाला 70 करोड़, माईनिंग घोटाला 17 हजार करोड़ ये सभी कांग्रेस के कार्यकाल के घोटाले हैं।

सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपा करके राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही बोलिए।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल: माननीय महोदया, मैं उसी पर आ रहा हूँ। लेकिन मैंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां बताई हैं।

सभापति: जो आप बोल रहे हैं

श्री आरकेएस --- जारी।

07/03/2017/2020/RKS/AG/1

सभापति जारी

इसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आप राज्य सरकार के बारे में जो मर्जी बोलिए। माननीय भारद्वाज जी आप बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्सिंग रिफरेंसिज कोई करें कोई मनाही नहीं है परन्तु पूरी स्पीच आप इस पर बेस नहीं कर सकते You also know it. You want to make passing references, you make. Nobody is stopping you. But at least आप जो विषय है उस पर बोलिए।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल: आप मोदी सरकार की योजनाओं को तो सुन लीजिए। 'प्रधान मंत्री जन धन योजना', 'अटल आवास योजना', 'सुकन्या समृद्धि योजना', 'मुद्रा बैंक योजना', 'जीवन ज्योति योजना', 'सुरक्षा बीमा योजना', 'अटल पेंशन योजना', 'फसल बीमा योजना', 'ग्राम कृषि सिंचाई योजना', 'गरीब कल्याण योजना', 'जन-स्वास्थ्य औषधी योजना', 'स्वच्छ भारत मिशन योजना', 'किसान विकास योजना', 'ओ.आर.ओ.पी. योजना', 'स्कील इंडिया योजना', 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना', 'सम्राट सिटी योजना', 'उज्ज्वल योजना', (व्यवधान...) 'राष्ट्रीय ग्राम स्वरोज अभियान', 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'डिजिटल इंडिया', 'स्कील इंडिया' इत्यादि।

सभापति: माननीय सदस्य प्लीज टॉपिक पर बोलिए। अदरवाइज हम जानते हैं that you are wanting to go to Parliament.

श्री बिक्रम सिंह जरयाल: सभापति महोदया, गपे मारने से सरकार नहीं चलेगी। आउटसोर्स, जुगाड़ और माफियों के बल पर सरकार चल रही है। इस सरकार को हारे हुए लोग चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, रिटायर्ड ऑफिसर्ज और माफिया लोग चला रहे हैं। क्योंकि मुख्य मंत्री जी को अपने मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिव, विधायकों और जो प्रेजेंट आफिसर्ज हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं है। पिछले चार वर्षों में यह सरकार डी.पी.आर. बनाने में फेल रही है। मेर विधान सभा क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी., आई.पी.एच. की एक भी डी.पी. आर. नहीं बनी है। एनुअल मीटिंग में

07/03/2017/2020/RKS/AG/2

मैंन माननीय मुख्य मंत्री जी को डी.पी. आर. बनाने के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि डी.पी. आर. बनाने के लिए पैसा नहीं है। आप कैसी सरकार चला रहे हैं? आपको रिज़ाइन देना चाहिए। यदि आपसे सरकार नहीं चलती है तो दूसरों को मौका दीजिए। माननीय सभापति महोदया भी मेरे जिला से हैं और आप भी दिल में हाथ रखकर कहिए कि जिला चम्बा में सड़कों की वास्तविक स्थिति क्या है? कांगड़ा से मेरे छोटे भाई पवन काजल जी

बोल रहे थे। नूरपुर से चुवाड़ी जाओ, नूरपुर से गंगथ टैरिस की तरफ जाते हो तो रोड़ों की हालत देखो। नूरपुर से शाहपुर की तरफ आते हो तो रोड़ों की हालत देखो। कहते हैं कि कांगड़ा के रोड़ चकाचक है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो दिन का प्रवास मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किया। द्रमण से सिहंता रोड़ का उद्घाटन किया गया जोकि माननीय धूमल जी के कार्यकाल में हुआ था। ग्राउंड का उद्घाटन किया जिसे विधायक प्राथमिकता में मैंने डाला था, जिसके लिए सेंटर से 'खेलो इंडिया' के तहत पैसा आया था।

श्री एस0एल0एस0 द्वारा जारी..

07.03.2017/2025/SLS-AG-1

श्री विक्रम सिंह जरयाल...जारी

कॉलेज का उद्घाटन किया गया। यहां बड़ी बातें हुई कि हमें सब-कुछ दिया गया। मैंने मुख्य मंत्री जी से पहले ही आग्रह किया कि इस कॉलेज को कन्या स्कूल में या गौशाला में न खोलना। वही किया गया और उसको कन्या गर्ल स्कूल में खोल दिया। कन्याओं को डिस्टर्ब किया और उनको प्लस टू ब्वायज स्कूल में भेजा गया। बाद में भूमि की स्लैक्शन कहां की? जो अपने को कैबिनेट मंत्री बताते हैं, पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर बोलते हैं या कहते हैं कि आई.पीएच. मिनिस्टर हूं, ऐसा कहकर लोगों को डराते हैं और कहते हैं कि मेरे आगे तो मिनिस्टर भी कुछ नहीं है, जरयाल तो क्या है, उसने अपनी ज़मीन के स्लाइडिंग एरिया के साथ उस भूमि का चयन किया। क्यों? ताकि मेरी ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाए। जितना भी फंड वहां गया, वह सब उसने अपने बगीचे में लगाया। यहां IPH Minister नहीं हैं। उसने 4 इंच की पाईप सरकारी खर्चे पर अपने बगीचे में लगाई हुई है। 40 टैंक वहां मिड हिमालयन की तरफ से अब बनकर तैयार हो गए हैं। बड़ी-बड़ी क्रेट लगाकर वहां उसने रोड बनवाया है। फिर लोगों का विकास कहां से होगा?

संजय रतन जी, मेरा गला थोड़ा बैठा है और मैं आज मूड़ में भी हूं। संजय रतन जी ने कहा कि मैं पिछले कार्यकाल के खर्चे बता रहा हूं। आपने यह नहीं बताया कि जो हारे हुए लोग

हैं, रिटायरी ऑफिसर्ज़ हैं, जो इनकी इतनी बड़ी फौज़ खड़ी कर रखी है, उनके ऊपर पिछले साल में कितना खर्च हुआ। इसकी विस्तृत जानकारी आपने नहीं दी है। ... (व्यवधान)... मेरी पीड़ा नहीं है बल्कि यह प्रदेश की जनता की पीड़ा है क्योंकि प्रदेश की जनता का पैसा उन लोगों पर खर्च किया जा रहा है। (घंटी) माननीय सभापति महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूँ।

कल आपने पेपर पढ़ा होगा जिसमें लिखा था कि विधायक बिक्रम सिंह जरयाल अनियमितताओं के तहत टी.ए.डी.ए. ले रहे हैं और विधायक बिक्रम सिंह जरयाल गाड़ी के ऊपर बत्ती लगाकर घूमते हैं। क्यों, क्या उसी को हक है? उसको आदत पड़ी है। चोर को चोर ही दिखाई देते हैं, मैं तो यही बोलूंगा। भ्रष्टाचारी को

07.03.2017/2025/SLS-AG-2

भ्रष्ट ही दिखाई देते हैं। जो चार्जशीट हमने दी है उसमें लिखा हुआ था कि 35 करोड़ का स्कैम जो माड्यूल, जो फर्नीचर खरीदा है उसमें हुआ। क्या उसका कुछ हुआ? उसके ही विभाग के अधिकारी पत्र लिखते हैं कि हर महीने एक करोड़ रुपये हमारे से मांगता है। ऊना से इतने, बदी से इतने, बरोटीवाला से इतने, नालागढ़ से इतने और कांगड़ा से इतने। मुझे दुःख है और वह इस बात का है कि वह सरकार का पैसा है। पीछे उन्होंने मुख्य मंत्री जी को खुश करने के लिए 51 लाख रुपया मुख्य मंत्री कोष में दिया। वह कहां से आया? वह बताएं कि वह पैसा कहां से आया। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा पर मुझे दुःख इस बात का है कि उसे खाने की आदत पड़ गई है और अब खाने को कम मिल रहा है क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा। इसलिए उसकी तड़प बढ़ चुकी है। इसलिए ही ये सब मोदी के विरुद्ध हैं।

अब मैं स्कूलों के ऊपर आता हूँ। मुख्य मंत्री जी चले गए हैं। स्कूलों में कार्यक्रम बाई ऑर्डर होते हैं। प्रिंसिपल को कहते हैं कि अगर प्रोग्राम नहीं रखाया तो कल को तेरी बदली हो जाएगी। बच्चों से पैसे मंगवाओ, मेरे लिए धाम लगाओ और हारों का बंदोबस्त करो। जनता

में जाता नहीं है। वह स्कूलों तक ही सीमित रह गया है। स्कूलों की हालत देखो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 13 ऐसे स्कूल हैं, जिनके पास अपनी छत नहीं हैं। 77 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है और उनकी संरचना हम नहीं बढ़ा सकते। तकनीकी शिक्षा मंत्री भी यहां पर नहीं हैं। ITI धरनेटा को कागज़ों में माड़न ITI घोषित कर दिया। ... (व्यवधान) ...

सभापति : माननीय सदस्य, आप एक सैकिंड के लिए बैठें। रात के 8.30 बज चुके हैं। आप और कितना समय लेंगे? अब इस सदन की बैठक 5 मिनट के लिए बढ़ाई जाती है। आप 25 मिनट पहले ही बोल चुके हैं। ... (व्यवधान) ... आप 5 मिनट के अलौटिड टाइम में अपनी बात पूरी करें अन्यथा हाऊस को एडजर्न कर दिया जाएगा।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल जारी ..श्री गर्ग जी

07/03/2017/2030/RG/AS/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : यहां माननीय मंत्री बैठे हैं ट्रेड लेकर भरमौर और चंबा में चले गए। क्योंकि भरमौर से चंबा नजदीक है क्योंकि उस आइडिये को भारतीय जनता पार्टी ने खोला। जो वे तीन ट्रेड्स हैं वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाए थे। आज वहीं पर है, मैं आपको बता दूंगा और कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी बहुत दयनीय स्थिति है और बच्चों को बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। ब्लॉक की भी वही हालत है, सभापति महोदया भी जानते हैं कि झण्डुता पंचायत एक सकरेला पुल है, मिडिल स्कूल के लिए रास्ता जाता है और मेरे चुनाव क्षेत्र के वहां बहुत लोग जाते हैं। मैंने उसके लिए साढ़े चार लाख रुपये दिए, लेकिन आज तक वह पुल नहीं बना। यह बहुत दुःख की बात होती है जब काम नहीं होते। विधायक निधि या सांसद निधि के कार्यों को भी ब्रेक लगाकर रखा हुआ है।

सभापति महोदया, मैं यहां कहना चाहूंगा कि बिना फॉरेस्ट क्लीयरेंस के रोड बन रहे हैं। मैंने फॉरेस्ट को 32,00,000/- रुपये दिए, उन्होंने सब वापस कर दिए। डी.एफ.ओ. ने पैसा वापस कर दिया, कहता है कि मैंने नौकरी करनी है, मुझे डराया और धमकाया जा रहा है इसलिए मैं आपके पैसे वापस कर रहा हूं। मैंने परछोड़ में जो आदर्श गांव है वहां डी.एफ.ओ. को भी बोला था और बिल एवं पेपर्ज भी बताए थे कि तुमने चिट्ठी लिखी वापस

कर दी। एक व्यक्तिगत बन्दा जो अपने आपको कैबिनेट मंत्री बनता है उसने क्रशर लगाया है और उसके लिए रोड बना दिया है, खड्डु को रोड बनाया है। जब मैंने पूछा तो दस हजार रुपये जुर्माना कर दिया।

वन मंत्री : यदि फॉरेस्ट में ऐसी बात हो रही है, तो आप लिखकर दें।

श्री विक्रम सिंह जरयाल : मैंने लिखकर दिया, आप डी.एफ.ओ. को पूछ सकते हैं, कंजरवेटर और आर.ओ. को आप पूछ सकते हैं और मैं आपको यहां भी बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त मेरी ककीरा पंचायत में एक रोड अभी बनाया है वह देवी गांव से भैंकर तक, लेकिन उसकी कोई फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं है। एक रोड और बनाया है मेन रोड से विलेजधार नगाली पंचायत में और उसकी भी कोई फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं है। जब हम पंचायत या कहीं फॉरेस्ट में पैसे देते हैं, तो फॉरेस्ट वाले रात को डण्डा लेकर और पुलिस लेकर आ जाते हैं कि काम को बन्द करो। यह विकास है।

सभापति महोदय, अब मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा। पी.एच.सी., समोह को अपग्रेड करने के लिए उसको सी.एच.सी. बनाने के लिए करीब चार साल हो गए हैं कहते हुए, परन्तु नहीं

07/03/2017/2030/RG/AS/2

बनाई। यहां पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में सिविल हस्पिटल, चुवाड़ी है वहां डॉक्टर की आठ पोस्ट्स हैं, लेकिन आज वहां तीन ही डॉक्टर्स हैं। वहां मशीनें पड़ी हुई हैं आदरणीय शान्ता जी ने तीन मशीनें दी थीं वे धूल फांक रही हैं और उनको चलाने वाला विशेषज्ञ कोई नहीं है और पैरामैडिकल स्टाफ नहीं है। वे लिख देते हैं कि refer to Tanda, refer to PGI and refer to IGMC, उन अस्पतालों का इतना ही काम है।

सभापति महोदय, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य में मेरे चुनाव क्षेत्र में 174 ग्रेविटी लाईन की स्कीम्ज हैं और वहां आज तक कोई भी फिल्टर बेड नहीं लगा है। मैंने पिछली विधान सभा में प्रश्न लगाया था और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि फिल्टर बेड लगाएंगे, परन्तु आज तक नहीं लगे। दो WSS हैं जिनमें ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया है और लोग वही गन्दे नाले का पानी पी रहे हैं। तो वे बीमार होंगे ही। श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी ने

ठीक कहा है कि सबसे बड़ा विभाग सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य है। इसका ज्यादा पानी पीने से सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आप कहते हैं कि समग्र विकास, सभी का विकास।

सभापति महोदया, जो हाइड्रिल प्रोजेक्ट्स हैं, आपने बुरा नहीं मानना। वे कहते हैं कि बीस लाख रुपये हमने नेताओं को दिया है, हम अपनी मन-मरजी से इस नाले का पानी उठाएंगे, इस जगह से पानी उठाएंगे। इसके लिए ज्ञापन हमने राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, उपायुक्त एवं एस.डी.एम. को भी दिया है, परन्तु आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक हाइड्रिल प्रोजेक्ट शक्ति-काड़ी, उसका एम.डी. लोगों के सामने बोलता है, डी.एस.पी. उधर है, एस.एच.ओ. और तहसीलदार उधर है और सामने 300 जनता बैठी है, लेकिन वह बोलता है कि I have given 29 lac Rs. to Bhatiyat leaders. तो ऐसा भटियात का नेता कौन है जो 20-20 लाख रुपये ले रहा है?

सभापति महोदया, अब मैं ट्रांसफर की बात करना चाहता हूँ। ट्रांसफर के लिए पैसा बढ़ा दिया है। मुझे दुःख हो रहा है, मेरा एक भाई है अंग्रेज सिंह दयाल, वह जे.बी.टी. है वे दोनों पति-पत्नी थे। उनकी ट्रांसफर हो गई, तो वे मेरे पास आए। मैंने कहा कि उधर ही जाओ। तो उन्होंने पचास-पचास हजार रुपये दिए। तब जाकर उनकी ट्रांसफर रुकी नहीं, बल्कि एक रोड पर ही आने-जाने के लिए उनकी एडजस्टमेंट हो गई। अभी हाल ही में एक
07/03/2017/2030/RG/AS/3

जे.बी.टी. टीचर का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इधर से ऑर्डर कर दिए, लेकिन दो महीने तक चंबा में उन ऑर्डर को रोककर रखा। क्योंकि उसकी अदायगी नहीं हुई थी इसलिए उसके ट्रांसफर ऑर्डर को रोक दिया गया। जब मैंने फोन किया, तो रेफर बैक इधर कर दिए। जब मैं स्वयं निदेशक से मिला तब जाकर उनको ट्रांसफर ऑर्डर दिए। वह बेचारा हैण्डिकैप हो चुका है। वह सलूणी लाचकोटी, जी.पी.एस. में साढ़े तीन साल से लगा हुआ था।

एम.एस. द्वारा जारी

07/03/2017/2035/MS/AG/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल जारी----

यह हालत है सरकार की और फिर आप बोलते हैं कि आप बहुत संवेदनशील हैं? तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। सभापति महोदया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन मुख्य मंत्री जी के दौरे के समय भी मेरे क्षेत्र में केवल पट्टिकाएं ही लगीं और कुछ नहीं हुआ।

सभापति(श्रीमती आशा कुमारी): माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए। समय हो गया है।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल: मैं समाप्त ही कर रहा हूं। अन्त में मैं एक शेर बोलूंगा। मैं आपका, सत्ता पक्ष और विपक्ष का धन्यवाद करता हू।

*खेलने का मन करता है तो कमलाड़ी याद आते हैं,
पढ़ने का मन करता है तो जे०एन०यू० याद आ जाता है,
रौने का दिल करता है तो सोनिया जी का बाटला हाऊस वाला आंसू याद आ जाता है,
सोचता हूं कि पागल हो जाऊं तो दिग्विजय सिंह याद आ जाते हैं,
सोचता हूं कि मुंह बन्द कर लूं तो मनमोहन सिंह जी याद आ जाते हैं,
सोचता हूं कि नाते-रिश्ते की ओर मुंह मोड़ लूं तो रॉबर्ट वाड्रा याद आ जाते हैं,
सोचता हूं कि लोगों की सेवा करूं तो झूठे केजरीवाल याद आ जाते हैं,
सोचता हूं कि कांग्रेस को भूल जाऊं तो मां भारती के जख्म याद आ जाते हैं,
सोचता हूं आशा की आखिरी किरण तो भाई नरेन्द्र मोदी जी याद आ जाते हैं।*

अब आप ही बताओ मोदी न कहूं तो क्या कहूं? सभापति महोदया, जो यह महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण था, यह एक ड्रामेबाजी थी इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Himachal Pradesh Vidhan Sabha Debates

Uncorrected and unedited/Not for Publication

Dated: Tuesday, March 07, 2017

07/03/2017/2035/MS/AG/2

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी): अब इस मान्य सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 08 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

**सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव।**

शिमला-171004

दिनांक: 07/03/2017